Fourth Series, Vol.II, No.13

Thursday, November 30, 1967
Agrahayana 9, 1889 (Saka)

LOK SABHA DEBATES

(Third Session)

(Vol. II contains Nos. 1 to 10)

LOK SABHA SECRETARIAT

NEW DELHI

Price : Rs. 2. 00

CONTENTS

No. 13—*Thursday, November* 30, 1967/*Agrahayana* 9, 1889 (*Saka*)

	COLUMNS
Oral Answers to Questions—	
*Starred Questions Nos. 361 to 367	3665—97
Short Notice Question No. 6 .	3697—3703
Written Answers to Questions—	
Starred Questions Nos. 368 to 378 and 380 to 390 . .	3703—16
Unstarred Questions Nos. 2410 to 2558, 2560 to 2578 and 2580 to 2591	3716—3848
Re. Senapati Bapat	3848
Calling Attention to Matter of Urgent Public Importance New Policy of Import and distribution of wool . . .	3848-49
Papers Laid on the Table	3849—55
Statement *Re.* Independence of the People's Republic of South Yemen	3855-56
Shrimati Indira Gandhi . . .	3855-56
Statement *Re.* Situation in West Bengal	3856—63
Shri Y. B. Chavan	3856
Constitution Amendment Bill—	
Extension of time for presentation of Report of Joint Committee	3863
Motion *Re.* Food Situation in the Country	3863—3916
Shri P. K. Dao . .	3863—70
Shri K. N. Tiwari . .	3871—79
Shri Yajnik	3879—85
Shrimati Sucheta Kripalani . . .	3885—93
Shri J. B. Singh	3893—96
Shri Changalraya Naidu	3896—3901
Shri Ram Sevak Yadav	3901—10
Shri Bhagvati	3910—16

*The sign + marked above the name of a Member indicates that the question was actually asked on the floor of the House by that Member.

	COLUMNS
Motion *Re*. Pakistani Infiltration into Kashmir .	3916—4026
Shri Prakash Vir Shashtri . . .	3916—31 4021—26
Shri D. N. Patodia	3932—35
Shri Amrit Nahata	3935—38
Shri Yajna Datt Sharma	3938—43
Shrimati Sushila Rohatgi	3943—47
Shri Ghulam Mohammed Bakshi . . .	3947—75
Shri M. Shafi Qureshi	3975—89
Shri S. M. Joshi	3989—92
Shri Yogendra Sharma	3992—94
Shri P. Ramamurti	3995—98
Shrimati Tarkeshwari Sinha	3998—4001
Shri Hem Barua	4001—04
Shri Mahant Digvijai Nath	4004—05
Shri J. B. Kripalani	4006—10
Shri Y. B. Chavan	4010—21

LOK SABHA

Thursday, November 30, 1967/ Agrahayana 9, 1889 (Saka)

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock.

[MR. SPEAKER *in the Chair*]

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

INCOME-TAX ARREARS

*361. SHRI MADHU LIMAYE: Will the Minister of FINANCE be pleased to state :

(a) whether it is a fact that he held special consultations with the Income-Tax Commissioners and other top officers of the Department with a view to speed up collection of Income-tax arrears;

(b) if so, the details thereof;

(c) whether any action under Sections 147-49 of the Income-tax Act has been recommended; and

(d) if not, the reasons therefor?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI K. C. PANT): (a) Yes, Sir. The question of speeding up of collections of Income-tax arrears was discussed during the last Commissioners' Conference held in August, 1967.

(b) The details of the decisions taken are :—

(i) Responsibility for appropriate action in cases where arrears are outstanding, has been fixed on particular officers, *viz* :—

Income-tax Officers:	Cases of arrears of below Rs. 1 lakh.
Inspecting Assistant Commissioners:	Cases of arrears of over Rs. 1 lakh and below Rs. 5 lakhs.
Commissioners:	Cases of arrears of over Rs. 5 lakhs.

(ii) In respect of demand locked up on account of Court proceedings, the Officers were asked to instruct the Departmental counsels to take adequate steps to enable the recovery of arrears by early finalisation of the court matters.

(iii) Action regarding taking over of recovery work from the State Governments should be expedited.

(iv) The process of writing off of irrecoverable demands should be expedited.

(c) and (d). Sections 147-149 deal with re-opening of cases where income chargeable to tax has escaped assessment. As these sections have no direct bearing on the recovery of Income-tax arreas, the question of recommending action under the aforesaid sections does not arise.

श्री मधु लिमये : क्या वित्त मंत्री जी यह बतलाने की कोशिश करेंगे कि रामनारायण ऐंड संस के बारे में जो पुराने इनकमटैक्स का मामला है और जिनके कि बारे में मैंने उन की चिट्ठी लिखी थी उस के बारे में जांच पूर्ण की गई है और कोई कार्यवाही की गई है केन्द्र के जो दोषी अधिकारी हैं उन के खिलाफ़ भी कोई कार्यवाही की गई है?

SHRI K. C. PANT: As regards individual cases, if I have notice, I can furnish information.

श्री मधु लिमये : जिनके बारे में उन को पहले से नोटिस है उस के बारे में तो इन को जवाब देना चाहिए।

MR. SPEAKER : He says notice was given by a letter.

THE DEPUTY PRIME MINISTER AND MINISTER OF FINANCE (SHRI MORARJI DESAI) : This is a very strange way of asking questions. Pardon me for saying so. I have great respect for hon. Members, but I cannot have respect for this kind of thing. He had written to me a letter and inquiry is being made. But I cannot just now

reply to that question here. On a general question, I cannot bring in particular questions. I shall certainly tell him what is being done if he gives notice. I have not got it just now; I cannot keep track of every case every day in my head.

श्री मधु लिमये : यह रिस्पैक्ट वगैरह छोड़ दीजिये। सवाल का जवाब दीजिये। मैं माननीय वित्त मंत्री से यह जानना चाहता हूं कि जब से यह वित्त मंत्री बने हैं इन्होंने किन-किन बड़े-बड़े मामलों में जांच की है वह अपने मन से बतलायें, एकाध व्यक्ति के बारे में मैं नहीं पूछ रहा हूं, साधारण सवाल पूछ रहा हूं कि किन बड़े-बड़े मामलों की उन्होंने जांच की है जिसमें 5 लाख से अधिक इनकमटैक्स की चोरी हुई है ?

श्री कृष्ण चन्द्र पंत : 5 लाख से ऊपर वाले इनकमटैक्स के ऐरियर्स का सवाल है चोरी का सवाल नहीं है। उस के लिए जैसा मैंने अभी कहा एक तो कदम यह उठाया गया और कमिश्नर्स के ऊपर इस बात की जिम्मेदारी डाली गई है कि जहां 5 लाख के ऊपर वाले एरियर्स के केसेज हैं उन की जिम्मेदारी वह अपने ऊपर लें। और भी कुछ ऐसे क़दम पहले से उठाये गये जिसमें कि 5 लाख के ऊपर वाले केसेज के लिए इन बड़े केसेज के लिये विशेष कुछ कदम उठाये हैं मसलन यह कि कमिश्नर्स से कहा गया है कि 5 लाख या उस से ज्यादा वाले जो केसेज हैं उन की लिस्ट तैयार की जाय हर क्वार्टर में और डाइरैक्टर आफ़ इंस्पैक्शन को रिपोर्ट दी जाये कि उन में क्या तरक्की हुई है ?

श्री हुकम चन्द कछवाय : इन केसों में कितने केसेज ऐसे हैं जो पिछले तीन सालों से पेंडिंग पड़े हुए हैं ? उन के बारे में कुछ कार्य-वाही नहीं की जा रही है और क्या इन को निबटाने के लिए सरकार कोई कदम स्वयं लेने वाली है ? क्या कोई ऐसी व्यवस्था आप ने की है ?

श्री कृष्ण चन्द्र पंत : जी हां, मंशा यह है कि जल्द से जल्द वह तय हो जायें।

श्री हुकम चन्द कछवाय : मैंने फीगर पूछी है कि कितने केस ऐसे हैं जो तीन साल से अधिक से पेंडिंग पड़े हुए हैं वह आंकड़ा मंत्री जी ने नहीं बतलाया और यह कि वह कितने दिन में निबट जायेंगे ?

श्री कृष्ण चन्द्र पंत : आंकड़े इस समय बतलाना मुश्किल होगा।

SHRI PATODIA : The total amount of arrears also includes such amounts in the arrears against which appeals have been filed. In reply to Question No. 802 the hon. Minister stated that in respect of 65 per cent of the cases the appeals were decided in favour of the assessees. May I, therefore, know out of the amount of arrears how much is such against which appeals have been filed by the assessees, and how much is such against which no appeal has been filed?

SHRI MORARJI DESAI : All these matters were explained at the time of the budget. These figures were given, and if they are asked again by a specific question, they will be given.

SHRI PATODIA : This question arises out of it.

SHRI MORARJI DESAI : It does not arise out of it.

श्री बृज भूषण लाल : क्या मंत्री महोदय यह बतलायेंगे कि 500 करोड़ से ज्यादा का यह जो इनकमटैक्स का ऐरियर है तो यह इतना क्यों हो गया है और क्या आप की मशीनरी जिस के जरिए आप पैसा रिएलाइज़ कराते हैं वह इनएफिशिएंट है या रौंग एसैसमेंट हुआ है जिसकी वजह से यह इनकमटैक्स आप का इतना ऐरियर्स में पड़ा हुआ है ?

श्री कृष्ण चन्द्र पंत : अध्यक्ष महोदय, 66-67 में 541 करोड़ रुपये ऐरियर्स में थे और यह ऐरियर्स के आंकड़े को आप को याद रखना होगा। साल भर में केवल 640 लाख रुपया इनकमटैक्स में इकट्ठा किया जाता है। इस 541 करोड़ में 30 जून को केवल 500 करोड़ रुपया रह गया था तो इस एक साल में 499 करोड़ में से बाकी तो फंसा हुआ है कुछ अपीलों

में कुछ जगह और कुछ रिकवरेबुल है। 205 करोड़ रुपया कुल है जो अडर रिकवरी है।

SHRI HEM BARUA: During Mr. Krishnamachari's time, when he was the Finance Minister of India, certain investigations were made into the income-tax arrears of some of the film stars in Bombay which made certain startling disclosures, and then that investigation was stopped. May I know if our present Finance Minister has tried to mop up the income-tax arrears so far as these film stars are concerned?

SHRI K. C. PANT: Yes, Sir. Film stars get no preferential treatment.

SHRI HEM BARUA: They do not get any preferential treatment, but the investigation was conducted and then it has discontinued, and then the unearned income went underground.

श्री जार्ज फरनेन्डीज: अध्यक्ष महोदय, सरकार का कुछ अजीब सा रुख मुझे मालूम देता है जब इस प्रश्न का उत्तर देते हुए कल यहां पर केवल 95 लाख रुपये पर दिल्ली के 20 हजार शिक्षकों के हड़ताल पर जाने वाली बात आई थी और अब मंत्री महोदय कह रहे हैं कि 500 करोड़ रुपया इनकमटैक्स का बाक़ी है। एक अजीब सा दिमाग है जो मैं समझ नहीं पाता। मेरा प्रश्न यह है कि 1623 नम्बर का प्रश्न इस सत्र में जो श्री एस० एम० जोशी की ओर से पूछा गया था उस का उत्तर देते हुए मंत्री महोदय ने यह कहा कि 63-64, 64-65, 65-66 यह तीन सालों में बताया कि इनकमटैक्स को वसूल करने के वास्ते सिर्फ 28 मुकद्दमें दाखिल करने में आ गये और वह भी 13 लोगों के खिलाफ़। 63-64 में 64-65 में और 65-66 में एक भी मुकद्दमा दाखिल करने में नहीं आया। मंत्री महोदय ने यह भी बता दिया आगे चल कर कि इसमें सिर्फ एक मामला कम्पाउंड करने में आ गया। 20 मामलों में जिनके कि ऊपर मुकद्दमें दाखिल करने में आये थे उन को अदालत ने रिहा कर दिया और 8 मुकद्दमें अभी भी चल रहे हैं तो मंत्री महोदय इस का खुलासा कर सकते हैं कि यह जो केवल 500 करोड़ रुपया आने का है तो यह पैसा वसूल करने के लिए कितने मुकद्दमों को दाखिल करना पड़ेगा और वह क्यों उस को नहीं दाखिल कर रहे हैं और जहां दाखिल करते हैं वहां वह हार क्यों जाते हैं?

श्री कृष्ण चन्द्र पंत: 640 करोड़ रुपया साल में इकट्ठा होता है इस के माने यह है कि 500 किरोड़ जो है वह साल भर से भी कम का इनकमटैक्स है। इसलिये मैंने केवल कहा। जो यह 500 करोड़ है उस में अपील्स में करीब 30 करोड़ फंसा हुआ है, प्रोडक्टिव असेसमेंट में 5 करोड़ है और डबल इनकमटैक्स रिलीफ में 5 करोड़ है। इसलिये इस में कुछ रुपया ऐसा है जो फौरन वापस नहीं लिया जा सकता। बाकी जहां तक केसेज करने का सवाल है, अगर कानून ही में इजाजत देगा तो अवश्य केसेज किये जायेंगे।

SHRI S. R. DAMANI: In the last three years, the number of assesses has increased by 75 per cent against which the number of officers has increased only by 10 to 15 per cent. In order to expedite the recoveries, may I know whether Government is considering to increase the number of officers, so that they can cope up with the work and complete it earlier?

SHRI K. C. PANT: We are approaching it from two angles. We are making the existing officers more effective by decreasing the amount of time they have to devote to smaller cases, so that they can deal with bigger cases better. Where necessary, we can increase the number of officers also.

SHRI H. N. MUKERJEE: We have been told that film stars have no preferential treatment at the hands of the income-tax authorities. May I know how it is that film stars, who had been hauled up for violation of income-tax and allied regulations, figured in certain ceremonies held under the auspices of Mr. Kunte here and his organisation, where the Finance Minister, in spite of puritanic proclivities, is the permanent chief guest and hobnobs with them in a

manner which has given a great deal of undesirable publicity and tends to rehabilitate the image of these income-tax evading film personalities?

SHRI MORARJI DESAI : In my official capacity, I have got to associate myself with many people whom some people consider undesirable. What am I to do about it? My hon. friend has also to put up with me, whom he considers undesirable. We have got to put up with each other. What can we do in these matters? To say that I am a permamanent chief guest only proves the capacity for such exaggeration by the hon. member.

SHRI H. N. MUKERJEE : You did say yourself that you are a permanent chief guest every year.

SHRI MORARJI DESAI : I said I do not want to be a permanent chief guest. Therefore, I did not go there for many years. That he has forgotten.

PACKAGE PROGRAMME

*362. SHRI P. K. DEO : Will the Minister of FINANCE be pleased to state the details of the package programme envisaged and given effect to in order to curb the inflationary tendencies and rising prices in the country?

THE DEPUTY PRIME MINISTER AND MINISTER OF FINANCE (SHRI MORARJI DESAI) : Government's programme to control inflation consists of a number of measures to raise availability through imports as well as higher production, to restrain the level of effective demand through the budget and selective credit control and to regulate prices and/or distribution of essential commodities. This anti-inflationary policy was further elaborated when an Ordinance, called the Taxation Laws (Amendment) Ordinance, 1967, was promulgated on September 14, 1967 so as to make provision in the taxation laws for mobilising additional savings through annuity deposits on current incomes, curbing entertainment expenditure in businesses and professions and for expediting payment of tax dues. Another Ordinance was promulgated on September 16, 1967 to amend the Essential Commodities Act in order to make its penal provisions more stringent and its enforcement more effective. Additional D.A. accruing during the period February 1, 1967 to August 31, 1967, to Central Government employees as a result of the All-India Working Class Consumer Prime Index (1949=100) reaching the twelve-monthly averages of 185 at end-January 1967 and 195 at end-May 1967, was deposited in their provident fund accounts to minimise cash outlays during the current fiscal year.

SHRI P. K. DEO : Sir, in spite of the so-called anti-inflationary measures we find that the economic health of this country is going from bad to worse. The price of rupee is much lower than the par to which we have agreed in any market—Hong Kong or Beirut. The prices are skyrocketing. From all these the conclusion is that the anti-inflationary measures are not effective. In view of our experience, may I know what other steps Government propose to take in this regard?

SHRI MORARJI DESAI : I shall await the concrete suggestions of my hon. friend for improving what I have done and I shall thank him if he gives me any suggestion.

SHRI P. K. DEO : The Government has not yet definitely stated that they have put a stop to deficit financing. May I know whether in the meantime there has been no further deficit financing?

SHRI MORARJI DESAI : I cannot say anything definitely until the year is over. It is not right when the hon. Member says that prices are skyrocketing. Even now the prices are coming down.

SHRI P. K. DEO : It is only a temporary phase.

SHRI MORARJI DESAI : May be a temporary phase (*Interruption*).

श्री महाराज सिंह भारती : आजादी के बाद नोटों की तादाद तीन गुनी बढ़ गई है, हम ने छाप कर बढ़ाई है, लेकिन राष्ट्र का उत्पादन तीन गुना नहीं बढ़ा है। तो क्या सरकार ने कभी इस सुझाव पर भी विचार किया है कि

हम अमरीका से उधार ले कर जो यहां नकद बेचते हैं, और जिस का भुगतान आगे चलकर करना है, उस से हम को जो आमदनी होती है उतने रुपये की करेन्सी हम सर्कुलेशन से विड्रा कर लें ?

श्री मोरारजी देसाई : विचार किया है और इस के बारे में कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, ऐसा फैसला भी किया है।

श्री ओ० प्र० त्यागी : मैं यह जानना चाहता हूं कि पी० एल० 480 और ब्लैक का जो अरबों रुपया छिपा है क्या इन्फ्लेशन में उस का भी कोई हाथ है ? यदि है, तो सरकार ने उस को रोकने के लिये क्या प्रयत्न किया है ?

श्री मोरारजी देसाई : ब्लैक का मामला तो दूसरा है। पी० एल० 480 और ब्लैक में कोई भी साम्य नहीं है। इसलिये इन दोनों को साथ में लाना जरूरी नहीं था। परन्तु ब्लैक के बारे में माननीय सदस्य को कोई जानकारी हो तो वह उस को हमें दे दें। हम उस पर कार्रवाई जरूर करेंगे। जब भी कोई जानकारी हमें मिलती है तब हम उस पर कार्रवाई जरूर करते हैं। पी० एल० 480 के बारे में हाल ही में एक सेमिनार हुआ था, जिसमें दो रायें थीं, लेकिन ज्यादातर राय यह थी कि पी० एल० 480 से इन्फ्लेशन नहीं हुआ।

REORGANISATION OF FINANCIAL INSTITUTIONS

*363. SHRI YASHPAL SINGH: Will the Minister of FINANCE be pleased to state :

(a) whether Government propose to reorganise the entire structure of financial institutions to meet the capital requirements of industries;

(b) if so, the broad details thereof; and

(c) when they would be finalised?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI K. C. PANT) : (a) No, Sir.

(b) and (c). Do not arise.

श्री यशपाल सिंह : क्या मैं जान सकता हूं कि उन के जरिये से कितना रुपया ऐग्रीकल्चर को दिया गया और कितना इंडस्ट्रीज को दिया गया ?

श्री कृष्ण चन्द्र पंत : यह सवाल कैपिटल रिक्वायरमेंट्स आफ इंडस्ट्रीज के सिलसिले में है, इस में ऐग्रीकल्चर के बारे में नहीं पूछा गया है। इंडस्ट्रीज को कुल मिला कर कोई 625 करोड़ रु० मिला है।

श्री यशपाल सिंह : जिन इंडस्ट्रियलिस्ट्स ने एक छोटी सी इंडस्ट्री के नाम से चार-चार जगहों पर रुपया लगाया हुआ है, उन के मुताल्लिक सरकार क्या सोच रही है ?

श्री कृष्ण चन्द्र पंत : माननीय सदस्य हम को जानकारी दें तो हम सोचेंगे।

RAID ON OFFICES OF JUTE SHIPPERS IN CALCUTTA

*364. SHRI MARANDI : Will the Minister of FINANCE be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Customs authorities raided the offices of jute shippers in Calcutta on the 18th August, 1967;

(b) the names of the firms so raided;

(c) whether it is a fact that the Customs authorities have seized revealing documents about foreign exchange and trade agreement violations by these firms; and

(d) if so, the action taken against them?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI K. C. PANT) : (a) to (d). A statement containing the required information partwise is laid on the Table of the Sabha.

Statement

(a) and (b) Between the 18th and 21st August, 1967 the Customs authorities at Calcutta searched the offices of eight exporters of jute goods. The names

of the firms, whose offices were searched are :

1. M/s. Bangur Bros. Ltd.
2. ,, Bird & Co. (P) Ltd.
3. ,, Duncan Bros. & Co. Ltd.
4. ,, Gordhandas Jerambhai.
5. ,, G. Ambalal (Export) P. Ltd.
6. ,, Jardine Henderson Ltd.
7. ,, Thomas Duff & Co. (India) Ltd.
8. ,, Window Glass Ltd. (as also its associate firms M/s Kheruka and Co., M/s Vanaspati Distributors (P) Ltd. and M/s King Bros.)

(c) and (d). A large volume of documents has been seized from these firms and these are being scrutinised. On the basis of the scrutiny made so far of the seized documents, the Customs authorities in Calcutta have found *prima facie* evidence in support of the allegation that the first 5 firms mentioned in the reply to parts (a) and (b) of the question have been exporting goods in contravention of the provisions of the Customs Act, 1962 and the Foreign Exchange Regulation Act, 1947. Show Cause notices for the alleged contraventions, which have come to notice so far, have been issued to these five firms.

As regards the other three firms, investigations are in progress. So far no show cause notice has been issued to them.

The contracting parties to the trade agreements between India and the foreign countries are the governments concerned, and not any individual exporter or importer of the contracting countries. The question of the exporters of jute goods contravening the trade agreements, therefore, does not arise.

श्री मरंडी : क्या यह सच है कि 19 अगस्त को इन फर्मों पर छापा मारा गया परन्तु 3 महीने की अवधि में भी उन पर कोई कार्रवाई नहीं की गई ? क्या सरकार इन फर्मों को ब्लैक लिस्ट में रक्खेगी और इन के लाइसेन्स को रद्द कर देगी ?

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : अभी उन में से पांच फर्मों को शो काज नोटिस जारी किये गये हैं। उस के अनुसार जो भी नतीजे निकलेंगे और जो भी कदम उठाने की आवश्यकता होगी वह उठाये जायेंगे।

श्री मरंडी : क्या यह सच है कि यह फर्में केवल सुलभ मुद्रा वाले क्षेत्रों को निर्यात किये जाने वाले माल को दुर्लभ मुद्रा वाले क्षेत्रों को पुनः भेजने के मामले में अन्तर्ग्रहस्त रही हैं ? यदि हां, तो सरकार ने इस को रोकने के लिये क्या-क्या प्रबन्ध किये ?

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : यह माल साफ्ट करेंसी और हार्ड करेंसी एरियाज़ से सम्बन्ध नहीं रखता है। यह माल नो ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़ और वैस्टर्न कंट्रीज से सम्बन्ध रखता है।

SHRI INDRAJIT GUPTA : I find from the statement that out of these 8 firms at least 5 of them are very big and well-known firms which are connected not only with shipping of jute goods but manufacture of jute goods also. May I know from the hon. Minister whether he is aware of the fact that this continued contravention which is going on for a long time in the matter of jute goods, the contravention of Foreign Exchange Regulations by doing under-invoicing and so on, is being stimulated and encouraged by the fact that the Government has set an example in the case of M/s. Bird & Company, who were caught red-handed in this very crime and offence and they were let off practically scot-free, as the fine imposed on them was reduced very heavily, with the result that the other firms have got the encouragement to go on doing this kind of illegal thing, knowing fully well that there will be no deterrent punishment whatsoever?

SHRI K. C. PANT : This is not a case of under-invoicing. This is a case where goods were ostensibly sent to East European countries but actually sent to West Europe. It is a different kind of case.

DR. RANEN SEN : Some of these firms are definitely old offenders who were indulging in such practices in the past also and there are cases pending against such firms. May I know whether Government have thought it fit to blacklist some of the firms which have become habitual offenders for some time past?

SHRI K. C. PANT : As I said, notices have been issued. Departmental proceedings will then be initiated. After the result of that is obtained, whatever steps are necessary will be taken.

श्री कंवर लाल गुप्त : मंत्री महोदय ने कहा है कि पांच फर्मों के बारे में प्राइमा फेसाई केस बना है। मैं चाहता हूं कि जो इनक्वायरी हुई है और जिस के आधार पर प्राइमा फेसाई केस बना है उसकी कुछ डिटेल्ज आप दें।

मैं यह भी जानना चाहता हूं कि इन पांच फर्मों के बारे में क्या पहले भी कोई शिकायतें आई थीं और क्या यह भी ठीक है कि ये पांच फर्में सरकार से और कई प्रकार की सुविधायें ट्रेड के बारे में लेती हैं ? मैं जानना चाहता हूं कि क्या अब ये सुविधायें आपने इनसे को देना बन्द कर दिया है या नहीं किया है और अगर नहीं किया है तो क्यों नहीं किया है ?

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : ट्रेड की सुविधाओं का जहां तक सवाल है मैं इस के बारे में कुछ नहीं बता सकता हूं। सम्बन्धित मंत्रालय ही बता सकता है। पहले भी इन्होंने इस तरह का जुर्म किया हो, इसकी मुझे खबर नहीं है।

श्री हुकम चन्द कछवाय : इन फर्मों के नाम क्या हैं ?

SHRI KANWAR LAL GUPTA : Sir, I want to know some details about the inquiry, if he can supply them.

THE DEPUTY PRIME MINISTER AND MINISTER OF FINANCE (SHRI MORARJI DESAI) : Details of the inquiry cannot be given until the inquiry is over and final orders are passed. Otherwise, the inquiry will be frustrated.

उर्वरक कारखाने

+

*365. **श्री ओंकारलाल बेरवा :**
श्री इन्द्रजीत गुप्त :
श्री काशीनाथ पाण्डेय :
श्री रघुबीर सिंह शास्त्री :
श्री स० च० बेसरा :

क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नये उर्वरक कारखानों की स्थापना में विलम्ब किया जा रहा है तथा इससे उत्पादन में कमी होने की सम्भावना है, क्योंकि विदेशी कम्पनियों को दी गयी रियायत की अवधि 31 दिसम्बर, 1967 को समाप्त हो रही है ;

(ख) क्या सरकार का विचार रियायत की अवधि को बढ़ाने का है; और

(ग) यदि हां, तो कब और किस तारीख तक उसे बढ़ाने का विचार है ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PETROLEUM AND CHEMICALS AND OF SOCIAL WELFARE (SHRI RAGHURAMAIAH) : (a) No, Sir.

(b) There is no proposal to extend the period.

(c) Does not arise.

श्री ओंकार लाल बेरवा : उर्वरका का बना हुआ सामान हम कितना आयात करते हैं और उस पर कितनी विदेशी मुद्रा खर्च की जाती है ? इस विदेशी मुद्रा को बचाने के लिए हम क्या उपाय कर रहे हैं ?

THE MINISTER OF PETROLEUM AND CHEMICALS AND SOCIAL WELFARE (SHRI ASOKA MEHTA) : My Ministry is not concerned with the import of fertilizers. I do not have that information.

श्री ओंकार लाल बेरवा : उर्वरकों के बारे में प्रश्न है। अगर यह इन से सम्बन्धित नहीं है तो कोई और इसका उत्तर दे। जो रियायतें दी हैं वे 31 दिसम्बर को खत्म हो रही हैं। हम विदेशी मुद्रा बचाने के लिये क्या उपाय कर रहे हैं। कोई जवाब तो आना चाहिये।

MR. SPEAKER: He may ask his second question.

श्री हुकम चन्द कछवाय : पहले प्रश्न का जवाब नहीं आया तो दूसरा प्रश्न कैसे किया जाए ?

श्री ओंकार लाल बेरवा : क्या जवाब देने वाला कोई और नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : अब आप दूसरा प्रश्न करें।

श्री हुकम चन्द कछवाय : एक प्रश्न का जोकि किया गया है उसका उत्तर तो दिलायें।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : शायद बेरवा साहब यह जानना चाहते हैं कि अगर सुविधाओं की तिथि नहीं बढ़ाई जा रही है और नई फैक्ट्रियां नहीं लगेंगी तो हम जो फर्टिलाइजर इम्पोर्ट कर रहे हैं, उस इम्पोर्ट को हम कैसे बन्द कर सकेंगे?

श्री अशोक मेहता : इस तरह से उन्होंने सवाल नहीं पूछा था। इस सवाल का जवाब मैं काफी बार दे चुका हूं। इसके आंकड़े मैंने पहले भी दिये हैं और चाहें तो मैं फिर देने के लिए तैयार हूं। 2.2 मिलियन टन की कैपेसेटी के लिए प्रोपोजल्ज फौर्म हो गई हैं। उसके बारे में या तो काम शुरू हो रहा है या बढ़ेगा। इस साल के आखिर तक 9 लाख टन की हमारी कैपेसेटी हो जाएगी। 1969 में 2.2 मिलियन टन की कैपेसेटी हमारे यहां हो जाएगी। और जो-जो प्रोपोजल्ज हमारे सामने हैं और जिन के बारे में हम फैसला कर रहे हैं, हमें उम्मीद है कि तीन साढ़े तीन मिलियन टन की कैपेसेटी अगले तीन या चार साल में हो जाएगी।

श्री ओंकार लाल बेरवा : हमने विदेशों से किन-किन कम्पनियों से बातचीत की है और हम इसको क्यों खत्म करने जा रहे हैं?

श्री अशोक मेहता : विदेशी कम्पनियों से भी बातचीत होती है। विदेशी कम्पनियों से बातचीत होती है तो उनको भी हिन्दुस्तान पार्टनर्ज खोजने पड़ते हैं। कभी-कभी हिन्दुस्तानी कम्पनियों से बातचीत होती है तो उनको भी विदेशी पार्टनर्ज खोजने पड़ते हैं। दोनों किस्म की कुछ कम्पनियों के नाम मैं आपके सामने रखता हूँ।

They are : Mangalore—Duggal ID & IC Co. Haldia—Phillips Petroleum; Ghaziabad—Modi Spinning and Weaving Co. Ltd. with Rohm and Hass; Mirzapur Pilani Investment Corporation and Kaiser; Vizag Expansion—Coromandel Fertilisers; Kandla—Indian Farmers' Fertiliser Company with the Cooperative League of America. Then, Barium Chemicals have made certain proposals and the details are not before us. I have also received proposals from the Tata and Allied Chemicals. Discussions are going on with Atlantic Richfield and also with Messrs Continental and Inter-ore.

The other part of the question was as to why we are thinking of discontinuing the concession after 31st December. The House knows very well that these concessions were given in order to expedite people filing their applications and we see no reason for continuing the concession.

SHRI INDRAJIT GUPTA : Some time ago we were told that Government has finally turned down the proposal which had been made by, I think Dharamsi Morarji firm for a collaboration project which was going to be based on the import of liquid amonia because that is something which would involve foreign exchange drainage which is not in the interest of the country. I want to know whether it is a fact, as reported recently in the press, that that proposal has been revived and is under the active consideration of Government. What is the exact position? If it is being revived, why is it being revived?

SHRI ASOKA MEHTA: When a letter of intent is given to a company we have to give a notice saying that the letter of intent is being terminated and they have a right to make whatever statement they may want to file. The Dharamsi Morarji company have filed a statement with us saying that they are revising their proposals and they want us to consider them. I cannot stop them from filing the statement. Whether it should be reconsidered or not is a matter which the Government will go into. As to what is the present position, it is known to the House.

SHRI INDRAJIT GUPTA : Is it the same old proposal or is it some new proposal?

SHRI ASOKA MEHTA : I have pointed out that they have modified their proposals. Until some decision is taken, I see no reason why this House should be taken into confidence. As soon as a decision is taken, all the facts will be placed before the House; but while the matter is being processed I cannot say anything.

श्री रघुवीर सिंह शास्त्री : फर्टिलाइजर की इंडस्ट्री जो कि हिन्दुस्तान में बहुत लाभ-पूर्ण और नई है क्या इस बात पर भी विचार किया जा रहा है कि इसके जो नए कारखाने हैं वे पब्लिक सैक्टर में ही बनाये जायें और पूंजी-पतियों को इस क्षेत्र में प्रवेश करने की खुली छूट न दी जाए?

श्री अशोक मेहता : सरकार की नीति यह है कि अपने साधनों, रीसोसिज़, को देखते हुए हम पब्लिक सैक्टर में जितने कारखानें बना सकते हैं, वे बनायें। इस वक्त पांच नये कारखाने पब्लिक सैक्टर में बनाने का काम चल रहा है। इन के अलावा अगले तीन चार महीनों में दो नये कारखाने प्राडक्शन का काम शुरू करेंगे। लेकिन हमारे देश में फ़र्टलाइज़र की मांग इतनी ज्यादा है कि सिर्फ पब्लिक सैक्टर के जरिये से यह सारा काम नहीं हो सकेगा, इसलिए इसमें न सिर्फ प्राईवेट सैक्टर को लाना होगा, बल्कि फ़ारेन इन्वेस्टर्ज को भी लाना होगा। गवर्नमेंट का यह फैसला कई महीनों से हाउस के सामने है और मेम्बर साहबान उस को जानते हैं।

श्री क० ना० तिवारी : बरौनी में भी फ़र्टिलाइज़र का एक कारखाना खड़ा करने की बात है। क्या वजह है कि वहां पर पब्लिक सेक्टर में या प्राईवेट सैक्टरमें कोई फर्टिलाइज़र कारखाना लगाने की कोई बात नहीं कही गई है? मंत्री महोदय ने जो लिस्ट पढ़ी है उस में बरौनी का नाम नहीं है।

श्री अशोक मेहता : मैंने जो लिस्ट पढ़ी है, वह प्राईवेट फर्म्ज की है। बरौनी का कारखाना पब्लिक सैक्टर में है। इस वक्त दो नये कारखाने प्राडक्शन में जा रहे हैं। जो पांच कारखाने पब्लिक सैक्टर में लगाए जायेंगे, उन में बरौनी भी आ जाता है।

श्री मोलहू प्रसाद : सरकार की तरफ से बजट सेशन में बताया गया था कि गोरखपुर की फ़र्टिलाइज़र फैक्टरी में सितम्बर में ट्रायल और प्रोडक्शन शुरू हो जायेगा। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या उस फैक्टरी में ट्रायल हो चुका है और प्राडक्शन शुरू हो गया है, यदि हां, तो प्रति दिन कितने टन वहां पर कितना प्राडक्शन हो रहा है।

श्री अशोक मेहता : वहां पर प्राडक्शन जनवरी में होगा। इस में देर इस लिए लगी है कि मशीनरी के कुछ हिस्से, जो जापान से आये थे, वे ठीक नहीं थे और उन को बदलना जरूरी था। वे पार्टस हासिल करने में कुछ देर लगी। वहां पर दो स्कीम्ज हैं। अभी एक स्कीम के लिए पार्ट आए हैं और दूसरी स्कीम के लिए पार्ट आने में समय लगेगा। इस लिए दो तीन महीने की देरी हो गई है।

SHRI CHENGALRAYA NAIDU : Is it a fact that the American Cooperative Consortium has recommended Kandla and Vizag to start fertiliser factories there and, if so, why have the Government taken interest only in Kandla and why have they not thought of Vizag?

SHRI ASOKA MEHTA : After a very careful study, it was suggested that the first plant should be located at Kandla because in terms of techno-economic benefits, it would be advisable to have at Kandla. It was recommended that the second plant should be at Vizag. At present, the Government is thinking only of setting up one plant, that is, at Kandla. The matter is still under technical, economic and other considerations.

SHRI S. S. KOTHARI : What is the progress of various projects for new fertiliser factories in the public sector?

SHRI ASOKA MEHTA : In the public sector, there are two Corporations, the Fertiliser Corporation of India and the F.A.C.T. As far as the Fertiliser Corporation is concerned, it has got three

plants which are running today. It will have two more plants which will go into production, one at Gorakhpur and another at Namrup in the next few months. As far as the F.A.C.T. is concerned, it has one plant which is under production. The Fertiliser Corporation of India is taking up three more plants, one at Durgapur, one at Barauni and another is Namrup expansion. The F.A.C.T has taken up one more plant at Cochin. Besides this, there is another public sector corporation in which there is foreign collaboration and that is the Madras Refinery. These are the various projects which are under implementation.

SHRI D. C. SHARMA : Each State requires fertiliser and the Minister is doing his level best to make the agriculturists fertiliser conscious. May I know how he is going to distribute these fertiliser factories over the several States of India so that no State is starved of fertiliser in any way?

SHRI ASOKA MEHTA : The location cannot be determined purely on the basis of every State having a fertiliser factory. By and large so long as fertiliser is to be produced from naphtha, the coastal-based plants have a greater advantage than the inland ones. We hope that after sometime we will have inland refinery and when inland refinery comes up, even this difficulty will disappear. At present, every care is taken to locate plants to meet the requirements of every part of the country. Every effort is being made to distribute plants in as many States as possible on techno-economic considerations.

SHRI TENNETI VISWANATHAM : The Minister was pleased to say that the Report recommended plant at Kandla, not at Vizag.

Will he be pleased to place it on the Table of the House?

SHRI ASOKA MEHTA : All these matters are under consideration and until decisions are taken finally, I do not propose to place anything on the Table of the House ?

श्री ओंकार लाल बोहरा : जैसा कि मंत्री महोदय जानते हैं, राजस्थान में जिप्सम का सब से बड़ा भंडार है और वहां पर एक फर्टिलाइज़र प्लांट के लिये प्राईवेट सेक्टर में लाइसेंस दिया जा चुका है। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या वहां पर जिप्सम के इतने बड़े भंडार को देखते हुए सरकार का विचार वहां पर पब्लिक सेक्टर में कोई फैक्टरी खड़ी करने का है।

श्री अशोक मेहता : राजस्थान में कोटा में प्राईवेट सेक्टर का एक फ़र्टिलाइज़र प्लांट बन रहा है। राजस्थान का जिप्सम ऐसा नहीं है कि जिस का फर्टलाइज़र के लिए आगे ज्यादा उपयोग हो सकता है। हम सिन्दरी में राजस्थान का जिप्सम इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन वहां पर इस बारे में काफ़ी दिक्कतें और शिकायतें हैं। हमारी कोशिश यह है कि इह जिप्स की जगह पर सिन्थेटिक जिप्सम बना कर काम किया जाये।

SHRI S. XAVIER : May I know whether there is any proposal to start a fertiliser plant at Tuticorin, Madras State?

SHRI ASOKA MEHTA : The FACT has been working on a Project Report for a fertiliser plant at Tuticorin. As I said, we have already five plants under construction. When we think of further expansion in future development, a plant at Tuticorin will very much be before us.

SHRI G. S. REDDI : May I know whether the Government has drawn up any scheme for the establishment of a public sector fertiliser plant at Kothagudam, where coal is available in plenty and also because Andhra Pradesh consumes a lot of fertilisers.

SHRI ASOKA MEHTA : As far as the requirements of Andhra Pradesh in respect of fertilisers are concerned, adequate care is being taken to set up the necessary production capacity. Whether there should be a coal based plant or not, the Project Report is being prepared, but it appears that on the whole a coal based plant may not be economical.

श्री यशवंत सिंह कुशवाह : क्या मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या

यह सच है कि मध्य प्रदेश सरकार ने केन्द्रीय शासन से यह प्रार्थना की है कि रासायनिक खाद का कारखाना बनाने के सम्बन्ध में मध्य प्रदेश को प्राथमिकता दी जाये ; यदि हां, तो शासन उस पर क्या विचार कर रहा है ?

श्री अशोक मेहता : जी हां, मध्य प्रदेश ने इस बारे में मांग की है। कोरबा के लिये एक कोल-बेस्ड फर्टीलाइज़र के कारखाने का प्राजेक्ट रिपोर्ट एफ० सी० आई० ने तैयार किया है और हमारे यहां उस का टैक्नो-इकानोमिस्ट इवैल्यूएशन हो रहा है।

SHRI NARENDRA SINGH MAHIDA : We have a fertiliser factory at Baroda in Gujarat, and this factory emits chemicals and fumes, which harm the nearby agriculturists. Will the Government therefore, see that in future such factories are not esablished at such places where there are large fields, so that the agriculturists are not harmed?

SHRI ASOKA MEHTA : By and large, the factories are being established near the coast. But I do not know what the Government can do because these matters are carefully gone into by all the departments concerned. I am aware of the difficulties that the hon. Member has referred to, but I do not know what further precautions can be taken. If the hon. Member can point out what further precautions can be taken, I shall be happy.

SHRI HEM BARUA . Since most of our fertiliser plants are naphtha based and since naphtha is likely to be in short supply by 1970-71, may I know whether the Government have taken this aspect of the problem into consideration and have tried to shift their pattern from naphtha to liquid ammonia?

SHRI ASOKA MEHTA : First of all, the hon. Member is not justified in saying that we will have a short supply of naphtha by 1970-71. Secondly, what should be done, whether we should continue to have naphtha based plants or introduce something else, is a matter which is under very careful consideration and I hope to bring before the House. if the House is interested, the projection by 1975-76.

अध्यक्ष महोदय : नेक्स्ट क्वेस्चन—श्री शारदानन्द।

श्री मधु लिमये : अध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न का जवाब आने से पहले मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं।

MR. SPEAKER : During Question Hour?

श्री मधु लिमये : वह क्वेस्चन आवर से ही सम्बन्धित है, वर्ना आप जानते हैं कि मैं उस को न उठाता।

अध्यक्ष महोदय, आज मुझे बहुत दुख हो रहा है कि जब पहले प्रश्न का मंत्री महोदय जवाब दे रहे थे तो मुझे एक लेक्चर उन से सुनना पड़ा। मैं उन की नुक्ताचीनी नहीं कर रहा हूं। उन्होंने कहा कि साधारण प्रश्न पर आप एक निश्चित या व्यक्तिगत सवाल में क्यों पूछते हैं। लेकिन मैं आप की जानकारी में यह बात लाना चाहता हूं कि आज के बैलट में मेरा पहला नम्बर आया था और जैसी कि यहां व्यवस्था है मैंने जिन प्रश्नों को प्रधानता या प्रायरिटी दी थी एक और दो, उन को जानबूझ कर दबाया गया है और जो क्वेस्चन में नहीं चाहता था कि प्रधानता में आये उस को वहां पर रखा गया है। अध्यक्ष महोदय, जिस रामनारायण ऐंड संस के बारे में मैंने सवाल पूछा था उसी को मैं ने प्रधानता दी थी। आप ने स्वीकारा भी था और इसलिए उस को यहां आना चाहिए था। दूसरे सदस्य भी इस बात की शिकायत कर रहे हैं। तो मैं आप का ध्यान इस बात की ओर खींचना चाहता हूं कि बड़ी धांधलियां हो रही हैं। मैं आप को दोष नहीं दे रहा हूं। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप ऐसा इन्तजाम करें हम लोगों से सलाह मशविरा कर के जिस से इस तरह की धाधलियां प्रश्नों के बारे में न हों और मंत्री महोदय का लेक्चर भी हमें सुनना न पड़े।

अशोक होटल के कर्मचारियों के लिये बोनस

+

*366. **श्री शारदानन्द :**

श्री यज्ञदत्त शर्मा :

श्री अटल बिहारी वाजपेयी :

श्री ना० स्व० शर्मा :

श्री मोहन स्वरूप :

क्या **निर्माण, आवास तथा पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नई दिल्ली स्थित अशोक होटल के कर्मचारियों ने बोनस लेने से हाल ही में इन्कार कर दिया है और उनमें बहुत असंतोष फैला हुआ है ; और

(ख) यदि हां, तो उनकी मांगें क्या हैं तथा उनमें असंतोष होने के क्या कारण है?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF WORKS, HOUSING AND SUPPLY (SHRI IQBAL SINGH): (a) The workers refused to accept bonus at the rate of 4% admissible to them under the Payment of Bonus Act, 1965, on the date fixed for its disbursement, *i.e.*, 27th October, 1967.

(b) The workers demanded bonus at the rate of 20%. Non-payment of bonus at this rate was the cause of discontentment amongst them.

(c) and (d). Negotiations were held by the management of the Ashoka Hotel with the representatives of worekrs nominated by the three Unions jointly operating in the Hotel and a settlement was arrived at on 5th November, 1967 in terms of which :

(i) the management of the Ashoka Hotel has given the eligible employees a bonus at the rate of 15% of the wages (basic pay: food allowance and interim relief, where admissible) earned for the year 1966-67 which is 11% higher than what was admissible;

(ii) the three Unions representing the workers have agreed that the existing strength of the workers of the Hotel will take on the additional work of running and maintaining the Annexe to the Hotel, which will start functioning shortly, in the manner which may be prescribed by the management from time to time without any addition in the number of workers; and

(iii) the management can at its discretion, recruit additional staff, if in its opinion it becomes absolutely necessary to do so.

The higher bonus was disbursed on 10th November, 1967.

श्री शारदानन्द : अध्यक्ष महोदय, मैं जानना चाहूंगा कि यह संस्थान सरकार द्वारा चलाया जा रहा है और सरकारी कर्मचारियों और सरकार के बीच उत्पन्न विवाद को निपटाने के लिए सरकार ने क्या कोई स्थायी व्यवस्था की है ?

श्री इकबाल सिंह : यह तो ठीक है कि यह होटल सरकार द्वारा चलाया जा रहा है। जहां तक उन में यूनियन्स का और मैनेजमेंट का ताल्लुक है तीन यूनियन्स हैं, उन के साथ मिलते रहते हैं और कोई बात होती है तो यही करते हैं और इसी के आधार पर यह फैसला हुआ ।

श्री शारदानन्द : क्या मंत्री महोदय बतायेंगे की आज जो उन्होंने जवाब दिया है कि वहां के सरकारी अफसरों ने जो यूनियन्स है उन से मिल कर के यह फैसला किया है कि 15 परसेंट वह बोनस देंगे तो यह फैसला जो उन्होंने बाद में किया क्या वह पहले ही नहीं कर सकते थे ?

श्री इकबाल सिंह : कानून के मुताबिक 4 परसेंट उन को मिलने की सुविधा थी। लेकिन उस के बाद उन्होंने मैनेजमेंट को लिखा और उन्होंने कुछ नोटिस भी दिए। वह दो घंटे की स्ट्राइक पर भी चले गए। उस के बाद यूनियन और मैनेजमेंट का फैसला हो गया कि 15 परसेंट वह बोनस दिया जायगा। लेकिन इस के साथ यह भी फैसला हुआ कि जो एक

ऐनेक्सी है जिस में 300 बेड और भी हैं उन के लिए नया स्टाफ नहीं लिया जायगा। इसलिये यह फैसला मैनेजमेंट के लिए ठीक था और उन्होंने और यूनियन ने दोनों ने इस को माना है।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : अशोक होटल के साथ-साथ जनपथ और रणजीत होटल भी एक ही संस्थान द्वारा चलाये जा रहे हैं। और लोदी होटल भी तो क्या मैं समझूं कि 15 परसेंट बोनस देने का जो फैसला हुआ है वह और होटलों के कर्मचारियों पर भी लागू होगा या उन्हें अलग से हड़ताल करनी होगी?

श्री इकबाल सिंह : जहां तक जनपथ होटल का ताल्लुक है उन के साथ फैसला हो गया है कि वह 10 परसेंट लेंगे और जहां तक रणजीत और लोदी होटल का ताल्लुक है क्योंकि उन में मुनाफा नहीं था इसलिए वहां यह लागू नहीं होगा। जिस होटल में मुनाफा होगा उस के बाद कितने परसेंट देना है यह फैसला तभी किया जा सकेगा।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : यह बात साफ नहीं हुई। अगर रणजीत होटल और लोदी होटल में चार परसेंट दिया जायगा तो क्या जनपथ होटल में भी चार परसेंट दिया जायेगा?

श्री इकबाल सिंह : जो मिनिमम है उस के मुताबिक तो दिया जा सकता है लेकिन इससे ज्यादा नहीं। क्योंकि वह रणजीत और लोदी होटल नये-नये चले हैं और उन में उतना मुनाफा नहीं निकला इसलिए उस में नहीं दिया जा सकता।

श्री ना० स्व० शर्मा : मंत्री महोदय ने बताया कि कानून के मुताबिक तो 4 परसेंट ही बोनस होना चाहिए लेकिन यह बहुत खुशी की बात है कि वह 15 परसेंट देने के लिए राजी हो गए। मैं उन से यह पूछना चाहता हूं कि अगर कानून के मुताबिक 4 परसेंट ही देने का था तो पन्द्रह परसेंट वह हड़ताल वगैरह करने के बाद देने को क्यों राजी हुए? पहले ही अपनी ओर से ही देने के लिए क्यों नहीं तैयार हो गए और दूसरे, इस चार और पन्द्रह परसेंट के कारण कितने रुपये का अंतर पड़ता है दोनों में?

श्री इकबाल सिंह : बोनस ऐक्ट के सेक्शन 8 और 13 के अनुसार 4 परसेंट है लेकिन सेक्शन 33 के मुताबिक इस से ज्यादा भी दिया जा सकता है और दोनों पार्टियां रजामंद हों। और 15 परसेंट इसलिए दिया गया कि जो नई ऐनेक्सी होगी उस में कोई नया आदमी नहीं रखा जायगा। इसी के लिए वह 15 परसेंट माना गया। जहां तक दोनों में अन्तर का ताल्लुक है पहले जब चार परसेंट था तो 80 हजार रुपया देना था, अब 2 लाख 79 हजार देना पड़ेगा।

श्री ना० स्व० शर्मा : जब कि मंत्री महोदय 15 परसेंट बोनस देने के लिए यहां तैयार हो गए हैं तो किस-किस आधार पर और होटलों में 15 परसेंट देने से मना कर सकते हैं।

MR. SPEAKER : No, please. Mr. S. M. Banerjee.

SHRI S. M. BANERJEE : Since the question was put by Shri Vajpayee about the other three hotels, Janpath, Ranjit and Lodi, which are also run by the Central Government, I would like to know whether it is a fact that the workers of the Janpath hotel which is making fabulous profits as compared to the Lodi Hotel and Ranjit Hotel which are not making profits, are being denied a higher bonus and are being given only 4 per cent which is the minimum admissible under the Act because they have to carry the other two hotels which have become liabilities?

MR. SPEAKER : The same question was put a little while ago.

SHRI S. M. BANERJEE : Will the Janpath Hotel workers get the same rate of bonus?

MR. SPEAKER : He said 10 per cent. Evidently the hon. Member was not here then.

COMMITTEE ON THE WORKING OF GOVERNMENT HOSPITALS IN DELHI

+

*367. SHRI S. M. BANERJEE :

SHRIMATI SUSEELA GOPALAN :

SHRI HARDAYAL DEVGUN:

SHRI DHIRESWAR KALITA:

SHRI A. K. GOPALAN :

SHRI MAYAVAN :

SHRI UMANATH :

SHRI BEDABRATA BARUA:

SHRI N. K. SANGHI :

SHRI RAM AVTAR SHARMA :

SHRI SHIV KUMAR SHASTRI :

SHRI RAGHUVIR SINGH SHASTRI :

DR. SURYA PRAKASH PURI:

SHRI Y. S. KUSHWAH :

SHRI RAMJI RAM :

SHRI KANWAR LAL GUPTA:

Will the Minister of HEALTH, FAMILY PLANNING AND URBAN DEVELOPMENT be pleased to state :

(a) whether Government have appointed a committee to enquire into the functioning of the Government hospitals in Delhi;

(b) if so, its terms of reference;

(c) when the first meeting of the committee is likely to be held; and

(d) when the report is likely to be submitted?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF HEALTH, FAMILY PLANNING AND URBAN DEVELOPMENT (SHRI B. S. MURTHY) : (a) Yes, Sir.

(b) The Committee shall review the working of the Central Government Hospitals in New Delhi and make recommendations for improvement in the existing facilities for medical, surgical and specialist care therein.

(c) 4th December, 1967.

(d) The Committee has been asked to submit its report within 6 weeks.

SHRI S. M. BANERJEE: On a previous occasion when we were discussing the death of Dr. Ram Manohar Lohia and the failure of the hospital staff, we were assured by the hon. Prime Minister that some non-officials, eminent members of this House who are doctors, would be associated with this Committee. Have some members of this House also been associated with this Committee?

SHRI B. S. MURTHY : Yes, the name of Dr. D. S. Raju, MP, has been added.

श्री मधु लिमये : कोई गैर-सरकारी आदमी भी नहीं ?

SHRI B. S. MURTHY : From Bombay, we have added the name of Dr. Shantilal J. Mehta, FRCS., Bombay Surgeon.

SHRI S. M. BANERJEE: I am sure that with Shri Satya Narayana Sinha becoming the Health Minister, the health of this country is in the hands of a healthy, wealthy and wise Minister.

MR. SPEAKER : Come to the question now.

SHRI S. M. BANERJEE : My question is this, whether this committee will also collect some other information or evidence from the public, because the grouse is actually on behalf of the public, whether they will invite public evidence also?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HEALTH, FAMILY PLANNING AND URBAN DEVELOPMENT (DR. S. CHANDRASEKHAR): We will invite public men to come forward and give evidence.

SHRI NATH PAI : The Minister accepted that he is wealthy, he did not contradict.

MR. SPEAKER : He accepted the compliment.

श्री हरदयाल देवगुण : क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि दिल्ली के सरकारी अस्पतालों के बारे में समाचार पत्रों में बहुत सी शिकायतें प्रकाशित हुई हैं, तथा इनको स्लाटर-हाउस (बूचड़खाने) तक का नाम दिया गया है—ऐसी अवस्था में इन अस्पतालों के कामों की जांच कराने के लिये इस संसद के सदस्यों या दिल्ली के प्रतिष्ठित प्रतिनिधियों को भी इस जांच समिति के साथ जोड़ा जायगा ताकि इस समिति को दिल्ली की जनता की जो शिकायतें हैं, उनका पूरा ज्ञान हो सके ? क्या सरकार इन प्रतिनिधियों को या दिल्ली के संसद सदस्यों को इस समिति से सम्बन्धित करने का विचार करेगी ?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्री (श्री सत्यनारायण सिन्हा) : माननीय सदस्यों ने देखा होगा कि इस कमेटी में सिर्फ कोठारी साहब को छोड़ कर, हालांकि उन्होंने भी इन्कार कर दिया है, क्योंकि उनके पास वक्त नहीं है, शेष सभी मैडिकल मैन रखे गये हैं। यह कमेटी अस्पतालों की हालत को देखेगी, वहां किस चीज की जरूरत है—एक ले-मैन को इन सब बातों का ज्ञान नहीं होता है। फिर दिल्ली के प्रतिनिधि या संसद सदस्य कमेटी के सामने कोई चीज लाना चाहें, तो ला सकते हैं और उस को देखा जा सकता है।

SHRI BEDABRATA BARUA : The hon. Minister has just stated that only medical men are included in the committee, but the allegations that have been frequently made in the House include such things as negligence and cold reception given to even people who deserve to be treated better. So, will the Minister inform this House whether in view of that, not only medical men, but also other people would be included in the committee, and also evidence from the side of the general public, not just selected public men but people who have experience of going to hospitals and being treated badly, will also be taken?

SHRI SATYA NARAYAN SINHA : We say public evidence will be taken, certainly all people will be included, whatever they have to say by way of grievances. The committee consists of 9 members, we do not want to make it a big committee which will not function.

श्री रघुवीर सिंह शास्त्री : श्रीमन्, दिल्ली के अस्पतालों पर सिर्फ दिल्ली शहर के बीमारों का बोझ नहीं है, बल्कि 100 मील के चारों तरफ के इलाकों के पेशेन्ट भी यहां आते हैं। इस स्थिति को देखते हुये क्या सरकार कोई ऐसी स्थायी समिति बनायेगी जो हमेशा इन अस्पतालों के कामों को, इन के इन्तजाम को, इन में उत्पन्न होने वाली दिक्कतों को दूर करने के लिये काम करती रहे ?

श्री सत्यनारायण सिन्हा : माननीय सदस्य को शायद मालूम न हो, हम ने एक स्टडी-ग्रुप बनाया है, जिसके चेयरमैन ए० पी० जैन साहब हैं, उन की रिपोर्ट फरवरी के पहले या दूसरे सप्ताह में आ जायेगी। वह सब चीजों को देख रहे हैं, उस कमेटी की रिपोर्ट में यदि कोई ऐसी सिफारिश आई कि हम लोग कोई स्थायी कमेटी बनायें, तो उस पर जरूर गौर किया जायगा।

श्री यशवन्त सिंह कुशवाह : क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि दिल्ली के अस्पतालों में गरीब मरीजों और अमीर मरीजों में जो भेद-भाव किया जाता है, उसके बारे में भी यह समिति विचार करेगी ?

श्री सत्यनारायण सिन्हा : सभी बातों की जांच होगी।

श्री कंवरलाल गुप्त : यह अच्छी बात है कि आपने इस कमेटी को बनाया। इस कमेटी के दो काम होंगे—एक तो यह कि डाक्टर्ज के मैडिकल प्वाइन्ट आफ व्यू से यहां पर क्या-क्या दिक्कतें हैं, उनकी जांच की जायगी, दूसरे किन-किन चीजों की कमी है, उस को देखा जायगा। लेकिन दिल्ली के लोगों की जो सब से बड़ी शिकायत है—वह इस बात की है कि आपने पैसा भी खर्च किया हुआ है, वहां पर एपरेटस भी मौजूद हैं, बड़े-बड़े डाक्टरों को

भी वहां बैठा रखा है, लेकिन उन का जो एटी-चुड मरीजों के लिये है, वह बड़ा कैलस है, क्रिमनल नैगलीजेन्स का है, वहां पर करप्शन है और जैसा कि अभी एक माननीय सदस्य ने पूछा कि आपने दिल्ली के किसी भी लोक सभा सदस्य को नहीं लिया, उस के जवाब में आपने यह कहा कि वे भी अपनी बातों को कमेटी के सामने रख दें। ऐसी हालत में जब हम लोग, जो दिल्ली के हैं, अपनी बातों को उनके सामने रखेंगे तो जो डाक्टर अफसर हैं, वे ही हमारी बातों का फैसला करेंगे—यह कोई अच्छी बात नहीं है।

मैं मंत्री महोदय से दो सवाल पूछना चाहता हूं—क्या दिल्ली के लोक सभा के कुछ सदस्यों को उस कमेटी में लिया जायगा, ताकि दिल्ली के लोगों की जो तकलीफें हैं, उन के बारे में निर्णय लेने में उन का भी हिस्सा हो, दूसरे—क्या इस कमेटी का चेयरमैन किसी नान-आफिशियल को बनायेंगे ?

श्री सत्यनारायण सिन्हा : टैक्नीकली हमने उस में चेयरमैन डाइरैक्टर जनरल आफ हैल्थ सर्विसेज को बनाया है, लेकिन वैसे उस में सभी नान-आफिशियल हैं और अच्छे आदमी हैं, वे आपकी इन शिकायतों को जरूर सुनेंगे। यह कमेटी 9 आदमियों की बन गई है, अब इस को और बढ़ायेंगे तो काम नहीं होगा।

श्री कंवरलाल गुप्त : यह ठीक है कि वे हमारी बातों को सुनेंगे, लेकिन उनके बारे में फैसला तो वे अफसर ही करेंगे। आपने दिल्ली के बारे में यह पहली कमेटी बनाई है, लेकिन दिल्ली का आपने इस में किसी को नहीं रखा।

श्री रवि राय : जब डा० लोहिया की चिकित्सा के बारे में बहस हो रही थी, तब हम को इस कमेटी के बारे में बताया गया और कहा गया था कि इस का चेयरमैन डाइरैक्टर आफ हैल्थ सर्विसिज होगा। डाइरैक्टर आफ हैल्थ सर्विसिज तो एक आफिशियल हैं और वह इस मामले में खुद दोषी हैं। मैं माननीय मंत्री से पूछना चाहता हूं कि क्या आप किसी नान-आफिशियल आदमी को, जिस पर जनता को विश्वास है इस कमेटी का चेयरमैन बनायेंगे ? आप डाइरैक्टर आफ हैल्थ सर्विसिज को ही इस का चेयरमैन बनाने की जिद क्यों कर रहे हैं, वे तो खुद इसमें दोषी हैं ?

श्री सत्यनारायण सिन्हा : डाइरैक्टर जैनरल आफ हैल्थ सर्विसिज तो देश के समूचे अस्पतालों का डाइरैक्टर जनरल होता है, इसके अलावा वह दो महीने बाद रिटायर भी हो रहे हैं—इस लिये इसमें ऐसी कोई खास बात नहीं है।

श्री बलराज मधोक : दिल्ली के जितने अस्पताल हैं, इस समय वे एक क्षेत्र में केन्द्रित हैं, जब कि दिल्ली का क्षेत्र बहुत फैल रहा है। दिल्ली की आबादी पुरानी दिल्ली से फैल कर कई मीलों तक पहुंच चुकी है और उन क्षेत्रों में कोई अस्पताल नहीं है। क्या यह कमेटी यह भी विचार करेगी कि दिल्ली की जनता को यूनीफार्म मैडिकल फैसिलिटीज हम किस प्रकार दे सकते हैं ? दूसरे—दिल्ली के अन्दर एक सब से बड़ी दिक्कत यह है कि जब किसी अस्पताल में कोई मरीज जाता है तो उसके साथ ठीक सलूक नहीं होता है और कभी कभी मैडिकल मर्डर भी हो जाता है, लेकिन गरीब आदमियों के पास कोई साधन नहीं है कि शिकायत करें और उनकी सुनवाई हो। क्या आप कोई ऐसी मैशीनरी भी तैयार करेंगे कि जिसमें उन की सुनवाई हो और जो उन का रिड्रेस करे।

श्री सत्यनारायण सिन्हा : जो स्टडी ग्रुप बनाया है, उस में यह बात भी आयेगी। उस के बाद जहां तक अस्पताल खोलने की बात है, उस पर हम और आप बैठ कर विचार कर सकते हैं।

श्री क० कृ० नायर : क्या मंत्री महोदय सदन के सामने उस कमेटी की टर्म्ज आफ-रेफ्रेन्स रखेंगे ? जितने सवाल यहां हुए हैं, उसका कारण यह है कि सदन को कोई जानकारी नहीं है कि उस कमेटी की टर्म्स आफ रेफ्रेन्स क्या हैं ?

MR. SPEAKER: He has already given.

SHRI NATH PAI : May I draw the minister's attention to the fact that it is not his ministry which is principally guilty so far as the present deplorable conditions in Delhi hospitals are concerned ? The two major culprits escapting the attention of the House and the public are the Finance Ministry and the CPWD. It is the stinginess of the Ministry of Finance in providing adequate fund to these hospitals which is resulting in out-dated and obsolete equipments being used. I do not know, Mr. Speaker, if you have had the benefit of being admitted (*Interruption*). I once took the risk and hazard, after a heart attack, because I could not have been flown to Bombay. I must say that all human attention was paid—it would be unfair if I do not say that. But I am telling about the needle. Normally the custom in America and Europe is that after a single injection the needle is discarded. When I began to scream with pain, which I normally do not, I was told that the needle was two years old. This is the kind of equipment that we have in our hospitals. May I know, so far as improving the standard of this hospital is concerned, whether the Finance Minister will have a fresh look at it and the Central P.W.D. will refrain from coming in the way so that the hospital is modernised with modern architects and engineers being allowed to have their say ?

THE DEPUTY PRIME MINISTER AND MINISTER OF FINANCE (SHRI MORARJI DESAI) : May I say that the Finance Ministry has never come in the way of making the hospital properly equipped and it will never come in the way.

THE MINISTER OF WORKS, HOUSING AND SUPPLY (SHRI JAGANATH RAO) : The Central P.W.D. also do not come in the way.

SHORT NOTICE QUESTION

FIRE IN DELHI

6. SHRI KANWAR LAL GUPTA : Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state :

(a) the loss of property and life caused as a result of a fire on the 17th November, 1967 in Chandni Chowk, Delhi;

(b) whether Government propose to make an inquiry about the cause of the fire;

(c) what steps Government propose to take to rehabilitate the sufferers; and

(d) whether Government propose to take steps to prevent such big fires in Delhi ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI VIDYA CHARAN SHUKLA): (a) The fire took place on the 18th November, 1967 and not on 17th November, 1967. There was no loss of life, but the estimated loss of property is about Rs. 43 lacs.

(b) No, Sir. According to the report of the Chief Fire Officer, Delhi Municipal Corporation who enquired into the matter, the probable cause of fire is accidental due to "dropped light".

(c) The Delhi Municipal Corporation is considering the question of temporary rehabilitation of the shopkeepers and the residents who have been affected by the fire. Plans are also being drawn up for reconstruction of the Naya Katra area where the fire broke out.

(d) A survey is being undertaken by the Delhi Municipal Corporation to ensure that suitable fire precautions are being observed in the other Katras of Chandni Chowk in particular and the remaining areas in general. It is also being ensured by the Corporation that the terms of licences of various traders as and where applicable are being strictly observed.

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : अध्यक्ष महोदय, पूर्व इस के गुप्त जी अपना प्रश्न पूछें में कहना चाहता हूं कि मूल प्रश्न अगर हिन्दी में हो तो सम्बन्धित मंत्री द्वारा उसका उत्तर भी हिन्दी में दिया जाय.....

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : मूल प्रश्न अंग्रेजी में ही था।

श्री कंवरलाल गुप्त : यहां पर करीब डेढ़ करोड़ रुपये का नुक्सान हुआ है। मंत्री महोदय ने जो आग से होने वाले नुक्सान का अंदाज लगाया है यह गलत है। करीब 25 लाख रुपये का माल तो ऐसी दुकानों का था जो कि इंश्योर्ड नहीं थीं और उस के अलावा करीब 35 लाख का माल ऐसा था जोकि अंडर इंश्योर्ड था बाकी प्रापरटी का नुक्सान हुआ। 100 दुकानें करीब करीब जली हैं। क्या सरकार इस बात पर विचार करेगी कि जिन लोगों का नुक्सान हुआ है उन को कुछ लोंग टर्म लोन दे रीजनेबुल इंटरैस्ट पर और कुछ सबसिडी दे ताकि वह लोग अपने पैरों पर खड़े हों। मैं प्रधान मंत्री जी और उपप्रधान मंत्री जी का भी धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने जाकर उस को देखो तो मैं जानना चाहता हूं कि उसको देखने के बाद वह क्या कार्यवाही इस सम्बन्ध में कर रहे हैं ?

THE DEPUTY PRIME MINISTER AND MINISTER OF FINANCE (SHRI MORARJI DESAI) : Sir, I have already told my hon. friend, when he asked me, that unless the Delhi Administration sends some proposal it is not possible for this Government to consider it.

SHRI VIDYA CHARAN SHUKLA : As far as the amount of loss is concerned the Delhi Corporation authorities got into touch with the traders who were affected by this fire and according to the estimate given by the traders this figure has been arrived at by the Administration. They have said that the actual loss was Rs. 39 lakhs in terms of material that was destroyed and Rs. 4 lakhs for the buildings, fixtures and furnitures that were destroyed in the fire. As far as relief is concerned, the hon. Deputy Prime Minister has already indicated that if a specific proposal is received then that will be given the fullest consideration.

श्री कंवरलाल गुप्त : यह जो आग लगी उस का एक मुख्य कारण यह था कि एक तो उस कटरे के अन्दर बहुत ज्यादा कंजैशन था और दूसरे एक ही दरवाजा था अंदर जाने के लिए जिसकी कि वजह से दिक्कत हुई आग बुझाने वालों को तो इस तरीके से दिल्ली के अन्दर और भी बहुत सारे मार्केट हैं, बाजार हैं, कटरे हैं जहां पर ठीक से निकलने का भी रास्ता नहीं है, बहुत ही संकरा रास्ता है तो क्या मास्टर प्लान के तहत इस तरीके का कोई एक फेज्ड प्रोग्राम सरकार बनायेगी और उसके लिए कुछ पैसा भी कारपोरेशन को देगी जिससे कि यह मार्केट दूसरी जगह नजदीक ले जाया जाय और एक नये तरीके से वह मार्केट बनाया जाय ताकि फिर इस तरह की कोई दुर्घटना न हो ? क्या सरकार इस तरीके का कोई एक फेज्ड प्रोग्राम बनाने के बारे में सोच रही है ?

श्री विद्याचरण शुक्ल : माननीय सदस्य ने ठीक ही कहा कि यह बहुत ही ज्यादा घनी बस्ती है और वहां आने जाने का रास्ता भी चौड़ा नहीं है वह बहुत ही संकरा व छोटा है जिसके कारण वहां पर आग से लड़ने में बड़ी असुविधा प्रतीत हुई। अभी इसके बारे में दिल्ली नगर निगम के जो चीफ इंजीनियर हैं वह उसका सर्वे कर रहे हैं और इस पर विचार कर रहे हैं कि कैसे उसे बनाया जाय अथवा कैसे उस का इंतजाम किया जाय ताकि आगे कभी ऐसी दुर्घटना न होने पाय।

श्री कंवरलाल गुप्त : उस के लिए आप पैसा देंगे ?

श्री विद्याचरण शुक्ल : सर्वे करने के बाद जब कोई चीज तैयार होगी तब पैसे का सवाल उठेगा।

SHRI UMANATH : Among the sufferers of this fire accident there is a category of about 61 workers who were employed in the shops below which were burnt down. They were residing upstairs. Now their residences and entire belongings have gone and in this winter they are remaining in the open with their children. So, apart from the long-term plan of rehabilitation, may I know whether the Central Government proposes to do anything urgently with regard to such of those families which

are suffering in the streets because they have received no relief from the Delhi Administration ?

SHRI VIDYA CHARAN SHUKLA : After the fire immediate relief was provided to these people. The mid-term or long-term relief is linked up with it.

SHRI UMANATH : What about residence for them ?

SHRI VIDYA CHARAN SHUKLA : It was also provided. First they were provided with tents in Gandhi Maidan. In a few dharmasalas also arrangements were made for putting them up. After that, the shop-keepers under whom they were working, took over the work. I cannot at present say what arrangements were made subsequently but this question of relief in general is being considered.

श्री प्रेमचन्द वर्मा : मैं पूछना चाहता हूं कि क्या उन्हें कोई ऐसी शिकायतें मिली हैं कि पिछले 6 महीने से दिल्ली शहर में गली-गली, कचे-कूचे और बाजार-बाजार में दुकानें खोल दी गई हैं और यह दुकानें ऐसी जगह पर खोली गई हैं जहां पर आबादी है और लोग रह रहे हैं और इस सिलसिले में दिल्ली कारपोरेशन.....

MR. SPEAKER : This is about fire; not about Himachal Pradesh.

Will he kindly sit down ? Probably he is not aware of the fact that it is not absolutely necessary to ask a supplementary. There is nothing compulsory about it.

SHRI BAL RAJ MADHOK : As has been admitted by the hon. Minister the main cause of this fire was the congestion in that area and the fact that almost all the markets are concentrated in a small area where it is very difficult to provide, leave aside the ordinary amenities of life, even tap etc. for preventing fire when it takes place. I would like to know if the government is considering the building up of a new market in an open area where all these small *katras* could be brought so that there will be one big cloth market catering to the needs of the whole of Delhi and surrounding areas.

SHRI VIDYA CHARAN SHUKLA : I have already indicated that the Chief Engineer of the Delhi Corporation is surveying the area which has been affected and other areas also. This is about the first part of the question as to how to prevent this kind of a thing happening again. As far as the question of shifting the entire cloth market to some new area and building a completely new cloth market is concerned, if a proposal of that kind is received we shall definitely give it due consideration.

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : दुकानों में जो छोटे कर्मचारी थे क्या उन को प्रधान मंत्री सहायता कोष से भी कोई सहायता दी गई है ? अगर नहीं दी गई तो क्यों नहीं दी गई ?

श्री विद्याचरण शुक्ल : अभी तक तो इस तरह की सहायता देने की आवश्यकता इस लिये नहीं पड़ी क्योंकि दिल्ली नगर निगम के द्वारा उन्हें तुरन्त सहायता दी गई थी, और उसके बाद, जैसा मैंने कहा, जिन व्यापारियों के साथ वे काम करते थे, उन्होंने उन की देख भाल करनी शुरू कर दी । इस तरह की कोई जरूरत महसूस होती या दिल्ली प्रशासन या नगर निगम के द्वारा इस तरह की किसी सहायता का सुझाव मिलता तो अवश्य उस पर कुछ न कुछ विचार किया जाता ।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : क्या प्रधान मंत्री के सहायता कोष में से धन देने के लिये किसी सुझाव के आने की जरूरत है ? जिन कर्मचारियों के घर जल गये, जो नौकरियों से हट गये, क्या अपनी ओर से प्रधान मंत्री सहायता कोष से उन को धन नहीं दिया जा सकता ?

प्रधान मंत्री, अणु शक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : जब मैं वहां उन को देखने गई थी तो उन्होंने हम से कहा था कि हम आप को बतलायेंगे कि क्या आवश्यकता है और किस हिसाब से सहायता देनी है ?

श्री कंवरलाल गुप्त : क्या आप के पास कुछ लिख कर नहीं आया ?

श्रीमती इन्दिरा गांधी : जहां तक मुझे मालूम है, नहीं आया । जबानी भी मुझे नहीं बतलाया गया ।

SHRI NARENDRA SINGH MAHIDA : Will the Government consider a scheme of having compulsory insurance in such congested areas where such inflammable articles, like nylon and others, are there? Will Government think of having compulsory insurance of these shops?

SHRI VIDYA CHARAN SHUKLA : It is a suggestion for action for the Delhi Corporation.

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

UNIFORM ELECTRICITY RATES FOR RURAL AREAS

*368. SHRI S. M. BANERJEE : Will the Minister of IRRIGATION AND POWER be pleased to state :

(a) the further steps taken for uniform electricity rates for rural areas in the country;

(b) whether this question has been discussed with the State Government; and

(c) if so, with what results?

THE MINISTER OF IRRIGATION AND POWER (DR. K. L. RAO) : (a) to (c). A statement is placed on the Table of the House. [*Placed in Library. See* No. LT-1801/67].

L.I.C. ADVANCES TO BUSINESS HOUSES

*369. SHRI INDRAJIT GUPTA : Will the Minister of FINANCE be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the bulk of the loans advanced by the Life Insurance Corporation to Industries in 1966-67 has gone to the business groups mentioned in the report of the Monopolies Commission;

(b) if so, the reasons therefor;

(c) the amount of loans advanced to these business groups;

(d) whether any principles have been laid down by Government to guide the investment and loan policy of the L.I.C.; and

(e) if so, the details thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI K. C. PANT) : (a) to (c). The loans sanctioned and disbursed during the years 1966-67 to the business houses mentioned in the Monopolies Inquiry commission Report amounted to Rs. 8.50 crores and Rs. 2.01 crores respectively, out of Rs. 12.15 crores and Rs. 4.86 crores of total loans sanctioned and disbursed to all parties during the same year. Loans are given by the L.I.C. on the merits of the applications irrespective of the fact whether these are made by the big industrialists of the smaller ones.

(d) and (e). The investments and loans of the L.I.C. are governed by the provisions of Section 27(A) of the Insurance Act 1938 as applied to the Corporation and further by the criteria mentioned in the statement made by the Finance Minister in Lok Sabha on the 25th August, 1958.

INDRAPRASTHA POWER HOUSE

*370. SHRI JYOTIRMOY BASU :
SHRI A. K. GOPALAN :
SHRI P. RAMAMURTI :
SHRI NAMBIAR :

Will the Minister of IRRIGATION AND POWER be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the first extension unit of the Indraprastha power station inaugurated by the Deputy Minister in November, 1967 went out of commission the same day;

(b) if so, the reasons therefor; and

(c) whether Government propose to enquire into the matter?

THE MINISTER OF IRRIGATION AND POWER (DR. K. L. RAO) : (a) to (c). The first extension unit was inaugurated on the 3rd November, 1967. The machine tripped on the morning of the 4th November, 1967, on account of over-loading of the interconnection with the U.P. Power system. Since then, the inter-connection has been changed to take isolated loads. The machine has again been in service

since the 8th November, 1967. As the unit did not trip under unusual circumstances, no enquiry into the matter is considered necessary.

NATIONAL AND GRINDLAYS BANK

*371. SHRI J. B. SINGH :
SHRI KAMESHWAR SINGH :
SHRI A. SREEDHARAN :

Will the Minister of FINANCE be pleased to refer to the reply given to Starred Question No. 1433 on the 27th July, 1967 and state :

(a) whether the question of allowing the National and Grindlays Bank to act as a special issuing house to underwrite and advise on the issuance of shares has since been examined; and

(b) if so, the result thereof ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE, (SHRI K. C. PANT) : (a) and (b). The National and Grindlays Bank has not yet submitted its final proposals in this regard.

STATE HOUSING MINISTERS CONFERENCE

*372. SHRI MAYAVAN :
SHRI CHENGALRAYA NAIDU :
SHRI BHAGABAN DAS :
SHRI K. RAMANI :
SHRI P. GOPALAN :
SHRI UMANATH :
SHRI DHIRESHWAR KALITA :

Will the Minister of WORKS, HOUSING AND SUPPLY be pleased to state :

(a) whether it is a fact that a State Housing Ministers Conference was held in Madras on the 8th November, 1967;

(b) if so, what were the subjects discussed;

(c) the decisions arrived at; and

(d) the steps being taken to implement them ?

THE MINISTER OF WORKS, HOUSING AND SUPPLY (SHRI JAGANATH RAO) : (a) Yes, Sir; from the 8th to 10th November, 1967.

(b) Housing, Town Planning and Urban Development.

(c) A statement giving a summary of the recommendations made by the Conference is placed on the Table of the Sabha. [*Placed in Library. See* No. LT-1802/67].

(d) The recommendations will be processed in consultation with the concerned Central Ministries and authorities and the Governments of States and Administrations of Union Territories.

PETROLEUM GAS GRID IN GUJARAT

*373. SHRI VIRENDRA KUMAR SHAH : Will the Minister of PETROLEUM AND CHEMICALS be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Government are considering to create a petroleum gas grid in Gujarat;

(b) if so, broad features thereof; and

(c) the steps taken so far to implement them ?

THE MINISTER OF PETROLEUM AND CHEMICALS AND SOCIAL WELFARE (SHRI ASOKA MEHTA): (a) No, Sir.

(b) and (c). Do not arise.

INDANE GAS

*374. SHRI S. C. SAMANTA :
SHRI MADHU LIMAYE :

Will the Minister of PETROLEUM AND CHEMICALS be pleased to state :

(a) the success achieved in marketing Indane gas introduced by the Indian Oil Company and how it compares with the marketing of similar gas by other companies;

(b) whether the Indian Oil Company is in a position to supply all the requirements of this gas in the current Five Year Plan; and

(c) the profit the Indian Oil Company gets on the gas after deducting cost and other charges ?

THE MINISTER OF PETROLEUM AND CHEMICALS AND SOCIAL WELFARE (SHRI ASOKA MEHTA): (a) The Indian Oil Corporation started marketing Liquefied Petroleum Gas (Indane) in October 1965. It is presently being marketed in Calcutta, Patna, Jamshedpur, Ranchi, Allahabad, Varanasi, Lucknow, Delhi and Baroda. As at the end of October, 1967, the Corporation had approximately 29,400 consumers in the above markets. Indane sales achieved by the Indian Oil Corporation after two years of LPG marketing compare favourably with the sales achieved by private sector companies during a similar period of development.

(b) Subject to the availability of LPG cylinders in adequate quantities, the Indian Oil Corporation can adequately meet the requirements of this gas in the areas served by its refineries.

(c) The accounts of the Indian Oil Corporation reflect the overall profitability of their entire operations; product-wise profitability is not determined.

COMPUTERS FOR PUBLIC UNDERTAKINGS

*375. DR. RANEN SEN : Will the Minister of FINANCE be pleased to state :

(a) whether Government have allowed import of electric computers for certain public sector units;

(b) if so, the number of computers to be imported;

(c) the names of public sector undertakings which propose to use them;

(d) whether it is a fact that the Labour Ministry was not consulted on the import of these computers; and

(e) if so, the reasons therefor ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI K. C. PANT) : A statement is laid on the Table of the House. [*Placed in Library. See* No. LT-1803/67].

CHIT FUND SCHEMES

*376. SHRI RAM KISHAN GUPTA : Will the Minister of FINANCE be pleased to refer to the reply given to Starred Question No. 1731 on the 10th August, 1967 and state :

(a) whether Government have considered the suggestions of the Central Bureau of Investigation regarding enactment of a Central law to control and regulate the functioning of the Chit Fund Schemes in the country; and

(b) if so, the result thereof ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI K. C. PANT) : (a) and (b). The suggestions of the Central Bureau of Investigation are still under examination.

SMUGGLING OF INDIAN CURRENCY ABROAD

377. SHRI AMRIT NAHATA : Will the Minister of FINANCE be pleased to state :

(a) whether Government are aware of large-scale smuggling of the Indian currency into the countries of Central Europe and West Asia where it is being bought at a discount by China and Pakistan for use on our borders for subversive activities; and

(b) the steps Government propose to take to check this practice ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI K. C. PANT) : (a) The intelligence available with the Government does not indicate either any large-scale smuggling of Indian currency out of India or of its purchase by any country for use on our borders for subversive activities.

(b) Does not arise.

FOREIGN CAPITAL INVESTMENT IN INDIA

*378. SHRI R. BARUA : Will the Minister of FINANCE be pleased to state :

(a) whether it is a fact that foreign capital investment in India has consi-

derably slowed down in the recent past due to mounting labour unrest in the industrial establishments;

(b) if so, Government's assessment in this regard; and

(c) the steps which have been taken to assure the foreign capitalists about the safety of their investments in India and to attract more foreign capital investment ?

THE DEPUTY PRIME MINISTER AND MINISTER OF FINANCE (SHRI MORARJI DESAI) : (a) and (b). While there is no doubt that the labour unrest has had an adverse effect on industrial production it is difficult to say whether investment of foreign capital has also slowed down in the country as a result of this unrest.

(c) The Government have been in constant touch with the State Governments on measures to eliminate the causes of industrial unrest and to promote the peaceful and orderly settlement of such industrial disputes as they arise from time to time. The subject was also discussed by the Standing Labour Committee at its meeting held in May, 1967. The Committee passed a resolution condemning 'Gherao' as threatening the very basis of orderly labour-management relations as built up in the country through tripartite discussion and consideration.

Government have always kept in view various steps to attract foreign investment in general. They also propose to streamline the procedure by setting up a Foreign Investment Board to deal with more expeditiously with the proposals for foreign investment.

कृषि कार्यों के लिये दी जाने वाली बिजली की दरों में वृद्धि

*380. **श्री देवराव पाटिल** : क्या सिंचाई तथा विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग ने कृषि कार्यों के लिए सप्लाई की जाने वाली बिजली और पानी की दरों में वृद्धि करने का सुझाव दिया है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है?

सिंचाई तथा विद्युत् मंत्री (डा० कु० ल० राव) : (क) और (ख). एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है । [पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल०टी०-1804/67] ।

पट्रोलियम और रसायन उद्योग में विदेशी पूंजीनिवेश

*381. **श्री महाराज सिंह भारती** : क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पैट्रोलियम और रसायन उद्योग में कितनी विदेशी पूंजी लगी हुई है; और

(ख) इसकी शर्तें क्या हैं;

(ग) किस सीमा तक वार्षिक लाभ देश से विदेशों में भेजा जा रहा है; और

(घ) इन उद्योगों में नियुक्त विदेशी कर्मचारियों को दिये जाने वाले वेतन और भत्ते के रूप में कितनी राशि विदेशों में भेजी जाती है और इनकी संख्या कितनी है ?

पैट्रोलियम और रसायन तथा समाज कल्याण मंत्री (श्री अशोक मेहता) : (क) 31 मार्च, 1965 तक पैट्रोलियम और रसायन उद्योग में विदेशी पूंजी निवेश 275.2 करोड़ रुपया था । इस राशि में से 177.8 करोड़ रुपये पैट्रोलियम उद्योग तथा 97.4 करोड़ रुपये रसायन एवं सम्बद्ध उत्पादों के लिए था ।

(ख) हर एक मामले में भारत सरकार की मंजूरी से सम्बन्धित पार्टियों के बीच पूंजी निवेश की शर्तें तय की जाती हैं और इस उत्तर में उनके बारे में साधारण विवरण देना सम्भव नहीं है ।

(ग) तैयार करने वाली और प्रचुर शोधित उत्पादों को बेचने वाली विदेशी तेल कम्पनियों का 1965 में लाभ, सूद तथा टैक्स से पहले, लगभग 18.87 करोड़ रुपये था ।

टैक्स देने के बाद तेल कम्पनियां अपने लाभों में से धन राशि भेजने के हकदार हैं । इसके अतिरिक्त मैसर्स बर्मा आयल कम्पनी ने इंगलिस्तान (U.K.) को 1.26 करोड़ रुपये भेजा था, जो उसके आयल इण्डिया लिमिटेड से सम्बन्धित लाभांश का शेयर था ।

जहाँ तक रसायन उद्योग का सम्बन्ध है इसी प्रकार की सूचना तत्पर उपलब्ध नहीं है ।

(घ) सूचना प्राप्त नहीं है ।

AID INDIA CONSORTIUM MEETING HELD IN PARIS

*382. SHRI D. N. PATODIA :
SHRI MANIBHAI J. PATEL :
SHRI R. BARUA :
SHRI RAGUVIR SINGH SHASTRI :

Will the Minister of FINANCE be pleased to state :

(a) whether it is a fact that a session of the Aid India Consortium was held in Paris on the 13th and 14th November, 1967 to assess India's foreign aid requirements for 1968-69;

(b) if so, the outcome thereof and whether the recommendations made by the Consortium are considered adequate for India's requirement;

(c) the manner in which the Consortium has finally agreed to defer the repayment of loans falling due in the current year; and

(d) whether any suggestions have been made as to the manner and type in which foreign aid received by India might be invested to produce quick results ?

THE DEPUTY PRIME MINISTER AND MINISTER OF FINANCE (SHRI MORARJI DESAI) : (a) and (b). The Aid India Consortium Meeting which was held in Paris on 13th and 14th November, 1967, *inter alia* reviewed, in a preliminary way the probable overall requirements for new non-project and project assistance during the year 1968-69. On the basis of an analysis prepared by the World Bank, members concluded that non-project requirements would continue at a relatively high level and that there would be a need for larger commitments of project aid than in the recent past. In the absence of a concrete idea of the aid that may be available, its adequacy cannot be judged.

(c) While certain member-countries of the Consortium have already agreed to a limited extent of debt relief, the Consortium has not taken a final decision regarding debt relief. A study of this question is being made on behalf of the World Bank and the Consortium is expected to consider the matter again early next year.

(d) A major part of the foreign aid now being received by us is mainly in non-project form and is used, in consultation with the Consortium Members, to import fertilizers and other agricultural inputs and also components, raw materials and spare parts for industrial production and infra-structure activity. Thus the stress is already on use for productive purposes yielding quick results.

DEVELOPMENT OF INDUSTRIAL COMPLEX IN HALDIA

*383. DR. RANEN SEN :
SHRI INDRAJIT GUPTA :

Will the Minister of PETROLEUM AND CHEMICALS be pleased to state :

(a) whether Government have discussed any plan with the West Bengal Minister recently on the development of an Industrial Complex in Haldia; and

(b) if so, the nature of the plan ?

THE MINISTER OF PETROLEUM AND CHEMICALS AND SOCIAL WELFARE (SHRI ASOKA MEHTA) : (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

OLD AGE PENSION SCHEME

384. SHRI S. C. SAMANTA : Will the Minister of SOCIAL WELFARE be pleased to state :

(a) whether old age pension scheme is in existence in any of the States or Union Territories;

(b) if so, the names of the States and Union Territories; and

(c) if the reply to part (a) above be in the negative, the reasons therefor and the action taken to put through such a scheme ?

THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF SOCIAL WELFARE (SHRIMATI PHULRENU GUHA) : (a) Yes, Sir.

(b) Andhra Pradesh, Kerala, Madras, Mysore, Punjab, Rajasthan, Uttar Pradesh and West Bengal and Union Territories of Chandigarh and Himachal Pradesh.

(c) Does not arise.

FOREIGN BALANCES

*385. SHRI YAJNA DATT SHARMA :

SHRI CHINTAMANI PANIGRAHI :

Will the Minister of FINANCE be pleased to state :

(a) whether there has been a sharp decline in the foreign balances held by the Government of India; and

(b) if so, to what extent and the reasons therefor ?

THE DEPUTY PRIME MINISTER AND MINISTER OF FINANCE (SHRI MORARJI DESAI) : (a) and (b). There has been some decline. India's foreign exchange reserves (excluding Gold valued at Rs. 182.52 crores—$243.4 million) which stood at Rs. 271.30 crores ($ 361.7 million) on 18th November, 1966, declined to Rs. 254.99 crores ($340.0 million), on 17th November, 1967. Main reasons for this decline have been heavy debt servicing payments and large outlay on foodgrains imports.

मिट्टी के तेल का उत्पादन

*386. श्री महाराज सिंह भारती : क्या पैट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में मिट्टी के तेल की जितनी उत्पादन-क्षमता है उसका पूर्ण उपयोग नहीं किया जा रहा है तथा मिट्टी के तेल का आयात किया जा रहा है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि आयातित मिट्टी का तेल देसी मिट्टी के तेल की तुलना में बढ़िया है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) विदेशी मुद्रा की बचत करने तथा देश में उपलब्ध उत्पादन-क्षमता का पूर्ण उपयोग करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

पैट्रोलियम और रसायन तथा समाज कल्याण मंत्री (श्री अशोक मेहता) : (क) जी नहीं। क्षमता का पूरी हद तक इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन यह क्षमता इस समय की मांग के मुकाबले के कम है; अतः कमी को पूरा करने के लिए आयात करना पड़ता है।

(ख) जी नहीं।

(ग) और (घ). प्रश्न नहीं उठता।

CONFERENCE OF BANKERS ON SOCIAL CONTROL ON BANKS

*387. SHRI MARANDI :

SHRI D. C. SHARMA :

SHRI PRAKASH VIR SHASTRI :

SHRI RAM AVTAR SHARMA :

SHRI MAHANT DIGVIJAI NATH :

DR. SURYA PRAKASH PURI :

Will the Minister of FINANCE be pleased to state :

(a) whether it is a fact that he called for a Conference of Bankers in Bombay on the 9th November, 1967 to discuss Government scheme of social control on banks; and

(b) if so, the outcome of the discussion held ?

THE DEPUTY PRIME MINISTER AND MINISTER OF FINANCE (SHRI MORARJI DESAI) : (a) The Deputy Prime Minister had informal meetings with some Indian and foreign bankers when some of the questions arising out of social control over banks were discussed.

(b) The bankers assured full cooperation with Government in the implementation of social control measures.

COMMERCIAL TRADE OPPORTUNITIES FOR U.S. BUSINESSMEN

*388. SHRI YASHPAL SINGH : Will the Minister of FINANCE be pleased to state :

(a) whether shortage of foreign exchange had limited commercial trade opportunities for U.S. businessmen; and

(b) if so, whether any measures are contemplated to off-set this drawback ?

THE DEPUTY PRIME MINISTER AND MINISTER OF FINANCE (SHRI MORARJI DESAI) : (a) Since the reference is to shortage of foreign exchange for commercial trade opportunities, it is presumed that the Honourable Member has in mind our imports under free foreign exchange. If so, there is no particular reason why any shortage limits opportunities for U.S. businessmen to export to India any more than for businessmen from other friendly foreign countries.

(b) Does not arise.

LEAKAGE OF GOVERNMENT'S DECISION RE. WAGE-PRICE DIVIDEND FREEZE

*389. SHRI MADHU LIMAYE : Will the Minister of FINANCE be pleased to state :

(a) whether Government are aware that certain news has been leaked in August, 1967 about Government's decision in regard to wage-price dividend freeze;

(b) whether this leakage had any effect on the share market;

(c) whether some people close to Government took undue advantage of this to reap some quick profit;

(d) whether any inquiry has been ordered into this leakage; and

(e) if so, the results thereof ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI K. C. PANT) : (a) Government had seen news items that appeared in certain newspapers which seemed to be no different in character from any of the several speculative reports that had appeared about the possible measures that Government might undertake to contain prices.

(b) Such reports had some effect on the share market.

(c) No, Sir.

(d) and (e). Since there has been no leakage of any Government decision it is not considered necessary to order any enquiry.

कृषिजन्य आय पर कर

*390. श्री देवराव पाटिल : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग ने समूचे देश में कृषिजन्य आय पर कर लगाने तथा कृषिजन्य आय और अन्य आयों पर समान रूप से कर लगाने का सुझाव दिया है ;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) इस सुझाव को किन-किन राज्य सरकारों ने मान लिया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) जी, हां ।

(ख) सुझाव अभी विचार की प्रारम्भिक अवस्था में है ।

(ग) सुझाव अभी तक राज्य सरकारों को उनकी राय जानने के लिए नहीं भेजा गया है ।

ASSISTANCE TO STATES BY RESERVE BANK OF INDIA

2410. SHRI VIRENDRA KUMAR SHAH : Will the Minister of FINANCE be pleased to state :

(a) the various types of financial assistance given by the Reserve Bank of India to all the States *e.g.* overdraft, loans, advances etc.; and

(b) the limits of overdrafts fixed by the Reserve Bank of India in the case of each State ?

THE DEPUTY PRIME MINISTER AND THE MINISTER OF FINANCE (SHRI MORARJI DESAI) : (a) The Reserve Bank provides financial assistance to State Governments in the form of ways and means advances repayable within three months from the date of advance. These advances are both unsecured and secured against pledge of Government of India securities held by the State Governments. In addition, loans are also advanced by the Bank to State Governments, repayable over a period not exceeding twenty years, for subscribing to share capital of co-operative societies.

(b) The present authorised limits of ways and means advances available to State Governments from the Bank are :—

(In lakhs of rupees)

State	Limits for unsecured advances	*Limits for special ways and means advances against cover of Government of India securities.
(1)	(2)	(3)
Andhra Pradesh	1,50	5,00
Assam	60	2,60
Bihar	1,05	3,50
Gujarat	1,05	2,10
Haryana	45	90
Kerala	90	3,75
Madhya Pradesh	1,20	2,80
Madras	1,65	3,30
Maharashtra	2,25	4,50
Mysore	1,20	2,75
Nagaland	15	30
Orissa	90	1,80
Punjab	90	4,80
Rajasthan	90	1,80
Uttar Pradesh	2,55	10,00
West Bengal	1,50	3,00

DEVELOPMENT WORKS IN CHANDA DISTRICT FOR TRIBAL WELFARE

2411. SHRI K. M. KOUSHIK : Will the Minister of SOCIAL WELFARE be pleased to state :

(a) the development works undertaken by the Central Government in the Chanda District which has a considerable tribal population during the period from 1962—67;

(b) the amount spent during the above period, year-wise; and

(c) if the reply to part (a) above be in the negative, the reasons therefor ?

THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF SOCIAL WELFARE (SHRIMATI PHULRENU GUHA) : (a) to (c). The requisite information has been called for from the State Government and it will be laid on the Table of the House when received.

अनुसूचित जातियों के लिए शिक्षा तथा वित्त संबंधी सुविधाएं

2412. श्री देवराव पाटिल :
श्री ओ० प्र० त्यागी :

क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अनुसूचित जातियों के लोगों और आदिवासियों को मिलने वाली शिक्षा तथा वित्त सम्बन्धी सुविधायें उन लोगों को देने का भी निर्णय किया है, जिन्होंने अपना धर्म बदल लिया है ; और

(ख) यदि हां; तो कब से और किन किन राज्यों में ये सुविधायें दी जायेंगी ?

*These are normally twice the limits indicated in column (2). However, the Reserve Bank allows higher limits, where necessary, so long as Government of India securities are available with States for being pledged with the Bank.

समाज कल्याण विभाग में राज्य मंत्री (श्रीमती फूलरेणु गुह) : (क) और (ख). अनुसूचित जातियों का उल्लेख करने वाले विभिन्न आदेशों के अन्तर्गत किसी ऐसे व्यक्ति, जिस का धर्म हिन्दू या सिख धर्म से भिन्न हो, को अनुसूचित जाति का सदस्य नहीं माना जायगा। अनुसूचित आदिम जातियों के सम्बन्ध में ऐसी कोई पाबन्दी नहीं है।

NEW PUBLIC UNDERTAKINGS IN GUJARAT

2413. SHRI NARENDRA SINGH MAHIDA : Will the Minister of FINANCE be pleased to state :

(a) whether any major public sector undertaking is proposed to be set up in Gujarat during the Fourth Five Year Plan; and

(b) if so, the nature of the industry and the venue thereof ?

THE DEPUTY PRIME MINISTER AND MINISTER OF FINANCE (SHRI MORARJI DESAI) : (a) and (b). Provision has been made in the Draft Fourth Five Year Plan for the following public sector projects to be located in the State of Gujarat :—

Name of the Project	Outlay proposed (Rs. crores)
1. Petro-chemical Complex, Koyali	47.00
2. Machine Tool Plant, Bhavnagar	14.60
3. Kharagoda Salt Works, Kharagoda.	0.50

In view of the changed economic situation and the decline in the demand for machine tools, the implementation of the machine tool project at Bhavnagar is likely to be deferred.

मसर्स ओरियन्टल टिम्बर ट्रेडिंग कारपोरेशन (प्राइवेट) लिमिटेड

2414. श्री निहाल सिंह : क्या **वित्त** मंत्री 10 अगस्त, 1967 के अतारांकित प्रश्न संख्या 8702 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) या मैसर्स ओरियंटल टिम्बर ट्रेडिंग कारपोरेशन (प्राइवेट) लिमिटेड के बारे में जांच इस बीच पूरी हो गई है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

बम्बई की फर्म मैसर्स झुनझुनवाला एण्ड ब्रदर्स द्वारा लिया गया ऋण

2415. श्री निहाल सिंह : क्या **वित्त** मंत्री 3 अगस्त, 1967 के अतारांकित प्रश्न संख्या 7820 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बम्बई की फर्म मैसर्स झुनझुनवाला एण्ड ब्रदर्स द्वारा लिये गये ऋण के सम्बन्ध में की जा रही जांच इस बीच पूरी हो चुकी है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

मैसर्स जे० पी० एण्ड सन्स, ओरियन्टल टिम्बर ट्रेडिंग कारपोरेशन और मेकेंजीज लिमिटेड बम्बई

2416. श्री निहाल सिंह : क्या **वित्त** मंत्री 3 अगस्त, 1967 के अतारांकित प्रश्न संख्या 7828 के उत्तर के सम्बध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसर्स जे० पी० एन्ड सन्स, ओरियन्टल ट्रेडिंग कारपोरेशन (प्राइवेट) लिमिटेड और मेकेंजीज लिमिटेड, बम्बई द्वारा किये गये सौदों से सम्बद्ध व्यक्तियों के सम्बन्ध में की जा रही जांच इस बीच पूरी हो चुकी है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसमें और कितना समय लगने की संभावना है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) जी, नहीं ।

(ख) सवाल ही नहीं उठता ।

(ग) मैसर्स जे० पी० एण्ड सन्स के मामले में जांच चालू वित्तीय वर्ष के अन्त तक पूरी हो जाने की सम्भावना है । कई लेन-देनों की जांच होनी है इसलिये अन्य दो मामलों के सम्बन्ध में यह कहना सम्भव नहीं है कि जांच-पड़ताल कब तक पूरी हो जायगी । जांच-पड़ताल को यथा सम्भव शीघ्र पूरी करने के लिये सभी उपाय किये जा रहे हैं ।

मैसर्स ओरियन्टल टिम्बर ट्रेडिंग कारपोरेशन (प्राइवेट) लिमिटेड

2417. **श्री निहाल सिंह** : क्या वित्त मंत्री 3 अगस्त, 1967 के अतारांकित प्रश्न संख्या 7819 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या मैसर्स ओरियन्टल टिम्बर ट्रेडिंग कारपोरेशन (प्राइवेट) लिमिटेड द्वारा किये गये आय कर अभिदान के बारे में जांच इस बीच पूरी हो गई है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) जी, नहीं ।

(ख) सवाल ही नहीं उठता ।

PRICE OF CRUDE OIL

2418. SHRI VIRENDRAKUMAR SHAH : Will the Minister of PETROLEUM AND CHEMICALS be pleased to state :

(a) whether Government are aware of the dispute between the Oil and Natural Gas Commission and other companies, namely Burmah-Shell, Esso and Indian Oil Corporation, regarding fixation of price of crude oil supplied by Gujarat to these companies;

(b) if so, the details thereof;

(c) whether it is a fact that this dispute has been referred to his Ministry; and

(d) if so, the final recommendations thereof ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PETROLEUM AND CHEMICALS AND OF SOCIAL WELFARE (SHRI RAGHU RAMAIAH) : (a) and (b). The Agreement with the Bombay Refineries provides for the fixation of the price of crude oil based on the arithmetical average of the price of two types of crudes imported by the Refineries from Middle East in the year 1961. After the stoppage of the import of Aramco crude, a difference of opinion has arisen on the interpretation of the Price Clause in the Contract between ONGC and the two Refineries namely Burmah-Shell and Esso. The dispute with the Indian Oil Corporation is in respect of the various elements in the price build-up claimed by the ONGC and disputed by the I.O.C.

(c) No, Sir. No dispute has been referred to the Ministry for a decision.

(d) Does not arise.

MAJOR IRRIGATION SCHEME IN GUJARAT

2419. SHRI VIRENDRAKUMAR SHAH : Will the Minister of IRRIGATION AND POWER be pleased to state :

(a) whether it is a fact that per head irrigated land available in Gujarat State is lower than the related all India figure; and

(b) the reasons for not providing any major irrigation scheme by the Central Government for Gujarat in view of the above disparity ?

THE MINISTER OF IRRIGATION AND POWER (DR. K. L. RAO) : (a) Yes.

(b) There are a number of major irrigation schemes in Gujarat in progress at various stages. They are :

Mahi Stage I;
Kakrapar;
Banas (Dantiwada);
Shetrunji (Palitana);
Ukai;

Narmada;

Kadana; and

Hathmati.

On completion of these schemes the *per capita* irrigation would go up appreciably.

SLUM CLEARANCE—AMOUNT SPENT BY DELHI MUNICIPAL CORPORATION

2420. SHRI KANWAR LAL GUPTA : Will the Minister of WORKS, HOUSING AND SUPPLY be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Government have not paid the amount so far to the Delhi Municipal Corporation which the Corporation spent on the slum improvement in the Capital;

(b) if so, reasons for the delay;

(c) whether it is also a fact that Corporation has not provided even basic amenities in all katras which were transferred by the Ministry of Rehabilitation to the Corporation during the last few years on account of paucity of funds; and

(d) if so, whether Government propose to provide more funds for this purpose to the Corporation ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF WORKS, HOUSING AND SUPPLY (SHRI IQBAL SINGH) : (a) and (b). In accordance with the instructions issued by the Ministry of Works, Housing and Supply in September, 1962, the Municipal Corporation of Delhi are required to formulate specific projects for carrying out improvement works under the Slum Clearance and Improvement Scheme and obtain the administrative approval and expenditure sanction therefor from the Delhi Administration. The Corporation did not do so and are stated to have spent a sum of Rs. 50.3 lakhs for the purpose up to 31st March, 1967. Although normally no payment is to be made against slum improvement works which are not administratively approved by the Delhi Administration an 'on-account' payment of Rs. 37.10 lakhs has been made to the Corporation. The Delhi Administration have been advised to examine the extent to which the expenditure of Rs. 50.30 lakhs stated to have been incurred by the Corporation, would be covered by the provisions of the Scheme and regularise that expenditure.

(c) The Corporation has taken over 2,433 properties from the Ministry of Rehabilitation and the Delhi Development Authority. After the transfer of the property, the Corporation has carried out substantial work of repairs to these properties to ensure their structural stability. Basic amenities have also been provided in these katras as far as possible.

(d) A sum of Rs. 69 lakhs has already been provided by the Central Government under the Slum Clearance Scheme (including improvement to slum areas) for Delhi for the year 1967-68.

ADVERTISEMENT GIVEN BY STATE BANK OF INDIA

2421. SHRI BABURAO PATEL : Will the Minister of FINANCE be pleased to state :

(a) the amount spent by the State Bank of India in 1966-67 in advertising in newspapers and periodicals;

(b) the names of papers and periodicals in several languages and the amount of advertising space and value in rupees of advertising given to each in 1966-67;

(c) the criteria by which the newspapers and periodicals are selected and whether the State Bank of India maintains the circulation records of all the papers and periodicals used by it for the purposes of advertising;

(d) the name of the advertising agency or agencies through which the advertising was done and the amount of commission or remuneration or service charges paid to them in 1966-67;

(e) the principal details of the agreement between the advertising agent or agents and the State Bank of India and the period of this agreement;

(f) whether any other media of advertising besides newspapers and periodicals were used; and

(g) if so, the details thereof and the amount spent on them during 1966-67

and the name or names of agent or agents through whom such media were used and the amount of commission earned by them during 1966-67?

THE DEPUTY PRIME MINISTER AND MINISTER OF FINANCE (SHRI MORARJI DESAI) : (a) to (g). The information is being collected and will be laid on the Table of the House in due course.

INDUSTRIAL FINANCE CORPORATION

2422. SHRI BABURAO PATEL : Will the Minister of FINANCE be pleased to state :

(a) the number and amounts of loans sanctioned by the Industrial Finance Corporation of India during the year 1966-67 with the names of parties to whom the loans were given;

(b) the number and nature of industrial units to whom these loans were sanctioned and the criteria adopted in sanctioning them;

(c) the number, their names and the amount due from defaulters in the payment of interest and principal; and

(d) the steps taken by Government to recover the dues and the amount likely to be recovered?

THE DEPUTY PRIME MINISTER AND MINISTER OF FINANCE (SHRI MORARJI DESAI): (a) The required information for the accounting year July 1966 to June, 1967 of the Industrial Finance Corporation of India is contained in Appendix 'B' of its Nineteenth Annual Report for the year ended the 30th June, 1967, which was laid on the Table of the Lok Sabha on the 23rd November, 1967.

(b) The number and nature of industrial units to whom financial assistance, including loans, was sanctioned during the year 1966-67 is given in paragraphs 12 to 14 of the said Report. The criteria adopted by the Corporation in sanctioning financial assistance is also given in paras 26—30 of the Report.

L88LSS/67—3

(c) The number of concerns who have defaulted in payment of interest and principal to the Corporation as also the amount due from them as at 30th June, 1967, is given in Table 14 of para 39 of the Report. The defaults have occured because of adverse business conditions in most cases and not due to any deliberate intention to avoid payment of dues of the Corporation. It would not, therefore, be proper to divulge the names of the industrial concerns in question.

(d) Government do not interfere in the day to day working of the Corporation consistent with its autonomous character although Government directors nominated on the Board of the Corporation keep a watch on its activities.

STATE BANKS LOANS TO INDUSTRIES IN MADRAS

2423. SHRI BABURAO PATEL : Will the Minister of FINANCE be pleased to state

(a) the amount advanced by the State Bank of India between 1962 and 1966 to small industries in Madras and the names of firms and industries with amounts advanced to each during the period with the rate of interest charged;

(b) the details of the security taken from each to safeguard the loan;

(c) the number and amount of these loans which have now become bad debts and the names of the parties concerned;

(d) the steps taken by the State Bank of India to recover the loans and the amount of irrecoverable loans with the names of the debtors and the amount of loss sustained so far or expected to occur; and

(e) the details of the security criteria used for advancing these loans and the names of six top officials who sanctioned these loans?

THE DEPUTY PRIME MINISTER AND MINISTER OF FINANCE (SHRI MORARJI DESAI): (a) Under section 44(1) of its statute, the State Bank is precluded from disclosing information relating to the transactions of its individual constituents. The consolidated position in regard to the Bank's loans to small scale industries in Madras is as follows :—

At the end of	Units assisted	Limits	
		sanctioned (Rs.	outstanding lakhs)
1961	151	42.50	28·54
1962	132	52·88	35·31
1963	216	131·10	60·02
1964	358	268·01	177·65
1965	440	324·65	269·90
1966	468	391·91	372·81

The rates of interest applicable to advances to small scale industries are based on the State Bank advance rate which changes from time to time. At present, the interest rate ranges between seven and three fourth per cent and nine and half per cent.

(b) The security for working capital advances comprises of raw materials, stocks in process, finished products, receivables and movable machinery. For term loans, land and buildings and plant and machinery are taken as security. Clean loans are also occasionally granted without any security.

(c) Nil.

(d) Where necessary, loans have been called up and legal proceedings instituted. No loss has been sustained so far and none is apprehended at this stage.

(e) Loans are sanctioned on the basis of the borrowers' capacity and ability to conduct the manufacturing operations on a profitable basis. The extent of the security to be taken depends upon the protection available. Advances to small scale industries are sanctioned by branch agents upto certain specified limits which in certain cases extend upto Rs. 2 lakhs.

State Bank of India

2424. SHRI BABURAO PATEL: Will the Minister of FINANCE be pleased to state :

(a) whether Government propose to appoint a Parliamentary Committee to investigate into the entire working of the State Bank of India which is not being run satisfactorily for some years now; and

(b) if not, the reasons therefor ?

THE DEPUTY PRIME MINISTER AND MINISTER OF FINANCE (SHRI MORARJI DESAI): (a) and (b). With a steady growth in its deposits and advances, with the large support it gives to the small scale industries and with the successful implementation of its programme to open branches in hitherto unbanked areas, the Government do not think that the State Bank can be said, by and large, to be functioning unsatisfactorily so as to warrant the appointment of a Parliamentary Committee to review its working.

Promotion Rules for Section Officers in C.P.W.D.

2425. SHRI S. D. SOMASUNDARAM : Will the Minister of WORKS, HOUSING AND SUPPLY be pleased to state :

(a) whether it is a fact that in C.P.W.D., recruitment to the grade of Assistant Engineer (Civil) C.E.S. Class-II is made from three sources (i) by promotion of Section Officers, (ii) by selection from Section Officers, and (iii) by direct recruitment through U.P.S.C.;

(b) if so, the percentage prescribed for each category; and

(c) how the *inter-se* seniority of all of them is determined ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF WORKS, HOUSING AND SUPPLY (SHRI IQBAL SINGH): (a) Appointment to the grade of Assistant Engineer in C.E.S. Class II in the C.P.W.D. is made (i) by promotion of Section Officers in the Department on the basis of selection, and (ii) by direct recruitment through Union Public Service Commission.

(b) *For permanent posts* :

(i) 50% by direct recruitment.

(ii) 25% by confirmation of temporary direct recruits.

(iii) 25% by confirmation of departmental promotees.

For temporary posts.

(i) 50% by direct recruitment.

(ii) 50% by promotion from the grade of S.Os. in the ratio of 50 : 50 for graduates and non-graduates.

(c) Principles for determining relative seniority of direct recruits and departmental promotees are—

(i) Direct Recruits against permanent vacancies in a particular year will *en bloc* rank senior to departmental promotees confirmed in the same year.

(ii) Direct Recruits against temporary vacancies and confirmed later against permanent vacancies will rank below the direct recruits against permanent vacancies who join in the same year but above the departmental promotees confirmed in that year.

(iii) Direct Recruits against temporary vacancies will *en bloc* rank above departmental promotees of the same year.

COMPENSATORY (CITY) ALLOWANCE TO CENTRAL GOVERNMENT EMPLOYEES STATIONED AT FARIDABAD

2426. SHRI S. D. SOMASUNDARAM : Will the Minister of FINANCE be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 3236 on the 22nd June, 1967 and state :

(a) whether it is a fact that certain Government employees working in Central Government Offices stationed in Faridabad on the 1st September, 1966 are deprived of the city compensatory allowance on the ground that they were not themselves stationed at Faridabad on that date; and

(b) if so, why this discrimination is made between the same category of Government employees in the matter of grant of city compensatory allowance ?

THE DEPUTY PRIME MINISTER AND MINISTER OF FINANCE (SHRI MORARJI DESAI) : (a) and (b). As Faridabad is a 'C' class city, compensatory (city) allowance is not admissible to Government servants stationed there. However, Central Government employees who were transferred to Faridabad on account of shift of offices from Delhi on or after 1-1-1966 are allowed to continue drawing compensatory (city) allowance at Delhi rates for one year and, thereafter, the rates to be reduced to nil over the next eighteen months. This concession has also been extended to employees of offices already stationed in Faridabad as on 1-9-1966, in order to avoid difference in emoluments between the staff stationed there on that date and those shifted from Delhi along with their offices. In a matter like this, a line has to be drawn somewhere and it was decided that the concession should be restricted to those who were already posted in Faridabad at the beginning of the month when the decision was taken.

INDUSTRIAL HOUSE-BUILDING SCHEME IN GUJARAT

2427. SHRI NARENDRA SINGH MAHIDA : Will the Minister of WORKS, HOUSING AND SUPPLY be pleased to state :

(a) the number of houses constructed so far in Gujarat under the subsidised Industrial House-building scheme;

(b) the total amount so far allocated to Gujarat for the purpose;

(c) whether there is any proposal of constructing more houses in Gujarat under the Scheme during 1967-68; and

(d) if so, the details thereof ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF WORKS, HOUSING AND SUPPLY (SHRI IQBAL SINGH) : (a) and (b). 20,843 houses were built under the Scheme in Gujarat

since its inception in September, 1952 upto the 31st March, 1967. The amount of Central assistance released to the Government of Gujarat under the Scheme upto the 31st March, 1967, is Rs. 699.99 lakhs.

(c) and (d). The Subsidised Industrial Housing Scheme is a continuing scheme and the State Governments have been authorised to sanction projects for construction of houses for industrial workers under this scheme. A sum of Rs. 17.00 lakhs has been provided by the State Government in their budget for 1967-68 for this scheme. According to the information received from the State Government, the following projects have been sanctioned by them during 1967-68 so far :—

Name of the construction Agency	No. of houses	Location	Approved Cost (Rupees in lakhs)
1. Gujarat State Road Transport Corporation	74	Mehsana	2·44
2. Varsha Industrial Co-operative Housing Society Ltd., Baroda	50	Baroda	2·68
3. Nure Ahwadi Co-operative Housing Society Ltd., Ahmedabad	25	Ahmedabad	1·22

खाद्य पदार्थों की शुद्धता

2428. **श्री ज्ञा० सुन्दर लाल** : क्या **स्वास्थ्य, परिवार नियोजन एवं नगर विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली में तेल, शहद तथा मसालों जैसे खाद्य पदार्थों की शुद्धता की जांच के लिए साधन या सुविधायें उपलब्ध नहीं हैं; और

(ख) यदि हां, तो उसके कारण क्या हैं ?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ब० सु० मूर्ति) : (क) जी, नहीं । दिल्ली नगर निगम के स्वास्थ्य विभाग के अन्तर्गत चल रही खाद्य प्रयोगशाला में तेल, शहद और मसाले जैसे खाद्य पदार्थों की शुद्धता को जांचने की सुविधायें मौजूद हैं ।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता ।

महाराष्ट्र में बड़ी सिंचाई परियोजनायें

2429. **श्री देवराव पाटिल** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि महाराष्ट्र में बड़ी सिंचाई परियोजनाओं की प्रगति निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार नहीं हुई है;

(ख) अब तक कौन-कौन सी परियोजनायें पूरी हो चुकी हैं;

(ग) अगले वित्तीय वर्ष में कौन कौन सी परियोजनायें आरम्भ की जायेंगी, और

(घ) विभिन्न सिंचाई परियोजनाओं की प्राथमिकता सूची में वित्तीय व्यवस्था की दृष्टि से महाराष्ट्र की स्थिति क्या है ?

सिंचाई तथा विद्युत मंत्री (डा० कु० ल० राव) : (क) संशोधन की कमी के कारण साधारणतः सारे देश की सिंचाई परियोजनाओं के निर्माण पर प्रभाव पड़ा है । यह किसी हद तक महाराष्ट्र के बारे में भी सच है ।

(ख) निम्नलिखित दो बड़ी परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं :

(1) वीर

(2) घोड

निम्नलिखित तीन बड़ी परियोजानाएं पूर्ण होने वाली हैं :

(1) खड़कवासला —चरण-1

(2) गिर्ना

(3) पुर्ना

(ग) ऊपरी गोदावरी परियोजना नामक एक और बड़ी परियोजना को 1968-69 में शुरू करने का विचार है ।

(घ) केन्द्रीय सहायता समेत प्रत्येक राज्य की अपनी योजना के लिये उपलब्ध कुल संसाधनों के आधार पर ही सिंचाई परियोजनाओं के लिये धन का आवन्टन किया जाता है। वित्तीय आवन्टन के लिये सिंचाई परियोजनाओं की कोई प्राथमिकता सम्बन्धी सूची नहीं है ।

अनुसूचित जातियां

2430. **श्री देवराव पाटिल** : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र राज्य की 'कोकी', बुरुद, पारमी और ढांगर जातियों को अनुसूचित जातियों की सूची में शामिल किये जाने के सम्बन्ध में सरकार को कोई ज्ञापन प्राप्त हुए हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

समाज कल्याण विभाग में राज्य मंत्री (श्रीमती फूलरेणु गुह) : (क) हां ।

(ख) सरकार के निर्णय अनुसूचित जातियां तथा अनुसूचित आदिम जातियां आदेश (संशोधन) विधेयक, 1967 में शामिल कर लिए गए हैं ।

Small Pox Vaccination

2451. **SHRI BABURAO PATEL** : Will the Minister of HEALTH, FAMILY PLANNING AND URBAN DEVELOPMENT be pleased to state :

(a) whether Government are contemplating a Central Act for giving powers to the Health Officers in the States to enforce vaccination at any stage as suggested by the two-day conference held in New Delhi on the 27th and 28th September, 1967;

(b) if so, the reasons therefor;

(c) whether Government are aware that frequent vaccinations lead to undesirable after-effects in the affected individuals; and

(d) if so, whether Government propose to dispense homoeopathic preventive doses of variolinum 200 which is equally effective in checking small-pox instead of resorting to vaccination ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF HEALTH, FAMILY PLANNING AND URBAN DEVELOPMENT (SHRI B. S. MURTHY) : (a) and (b). A recommendation in this behalf has been made by the All India Small-pox Workers' Conference which is under consideration.

(c) Some after-effects of frequent re-vaccinations have been noticed by Homoeopaths, but there are no definite studies to warrant this conclusion.

(d) Variolinum 200 has been in use by individual Homoeopaths who are said to have found it as a preventive for small-pox. Authentic data regarding the utility of this drug in checking small-pox is not available. The question of undertaking scientific experiments with this medicine is being considered.

Nizam of Hyderabad

2432. **SHRI KANWAR LAL GUPTA** : Will the Minister of FINANCE be pleased to state :

(a) the income on which the Nizam of Hyderabad has been re-assessed by the Income-tax Department in the assessment years for which his cases were reopened;

(b) whether Government have made inquiry as to why the Nizam was under-assessed by the Income Tax Department; and

(c) if so, the result thereof?

THE DEPUTY PRIME MINISTER AND MINISTER OF FINANCE (SHRI MORARJI DESAI) : (a) The same incomes on which he was originally assessed for the assessment years 1954-55, 1955-56 and 1956-57, as mentioned below :—

1954-55	Rs. 44,04,261
1955-56	Rs. 20,37,981
1956-57	Rs. 19,69,449

(a) and (c). The assessments were re-opened for withdrawing a rebate which had been given. The rebate was withdrawn in the re-assessments made. Subsequently, following a decision of the Supreme Court, the Appellate Assistant Commissioner held that that the rebate had been correctly allowed in the original assessment. The question of inquiry into under-assessment does not, therefore, arise.

FLOOD CONTROL MEASURES IN MIDNAPUR (WEST BENGAL)

2433. SHRI SAMAR GUHA : Will the Minister of IRRIGATION AND POWER be pleased to state :

(a) whether Government propose to undertake a scheme for ensuring permanent flood control measures in Contai sub-division of Midnapur District of West Bengal to ensure safety of food production and also to increase paddy yield in that area;

(b) if so, the details thereof; and

(c) if not, the reasons therefor ?

THE MINISTER OF IRRIGATION AND POWER (DR. K. L. RAO) : (a) to (c). The responsibility for initiation and execution of flood control scheme is that of the State Government concerned. The Government of West Bengal have already taken up a scheme known as Contai Basin Drainage Scheme-Phase I, which is under execution. The scheme, which is estimated to cost Rs. 36.24 lakhs, consist of the construction of drainage channels in a length of 11 miles for providing protection to an area of 19,000 acres in the Contai sub-division of Midnapur District.

In the light of experience of floods during 1967, the Consultants of the Ministry of Irrigation and power have also been asked to undertake a study of the flood problem of the area lying between the Subarnarekha and Contai areas of West Bengal, which are subject to innudation and suggest the additional flood control works which may be required in this area.

STRIKE BY EMPLOYEES OF ALL INDIA INSTITUTE OF MEDICAL SCIENCES

2434. SHRI K. M. ABRAHAM :
SHRI VISWANATHA MENON :
SHRI A. K. GOPALAN :
SHRI RAM CHARAN :
SHRIMATI SUSEELA GOPALAN :
SHRI K. RAMANI :

Will the Minister of HEALTH, FAMILY PLANNING AND URBAN DEVELOPMENT be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the employees of the All India Institute of Medical Sciences, New Delhi, are on hunger strike;

(b) if so, what are their demands;

(c) whether the management of All India Institute of Medical Sciences have negotiated with the employees to settle the dispute;

(d) if not, the reasons therefor; and

(e) the steps taken by Government to settle the dispute ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF HEALTH, FAMILY PLANNING AND URBAN DEVELOPMENT (SHRI B. S. MURTHY) : (a) No employees of the All India Institute of Medical Sciences is on hunger strike at present.

Some members of an unrecognised Union of the Institute aided by some others had started a hunger strike on 25th September, 1967. The strike was unconditionally called off subsequently.

(b) The following were the demands made by the strikers :—

(1) Each employee of the Institute should be promoted by seniority and there should be no favouritism.

(2) Vacancies reserved for scheduled castes/tribes candidates should be filled from candidates belonging to these communities by making special relaxation. In the administration, there should be one Class I Officer belonging to the scheduled castes and he should compulsorily be the member of each selection committee.

(3) Sweepers should be recruited to the posts of Laboratory attendants and peons by making special relaxation.

(4) The sweepresses should be promoted to the posts of Nursing Ayas.

(5) The employees who have not been made permanent and have rendered more than three years service should be made permanent.

(6) The Khalasis should be supplied with liveries and the washing allowance should be raised from Rs. 1 to Rs. 3. The liveries should be issued in full in March/November and not piecemeal.

(7) The pay scale of the Head Jamadar should be revised to Rs. 95—155. The pay scale of fitter, pump driver, carpenter, wiremen mason should be revised.

(8) Those members of the staff who are entrusted with field duty in the campus of the Institute may be granted cycle allowance.

(9) One Security Jamadar should be from Scheduled Castes.

(10) Good medicines and beds should be arranged in the Employees Health Scheme.

(11) Allowance should be granted to those who work in the Operation Theatre.

(12) The employees whose duty falls from 2-00 P.M. to 10-00 P.M. and who cannot get the bus for going to their homes which are very far off, should be provided with a rest-room.

(13) There should be a separate arrangement for the test of blood, urine and X-ray of staff members.

(14) Interview may be granted to 5 members of the Sangh.

(15) The Sangh may be granted recognition.

(c) and (d). Since there are five Unions/Associations functioning in the Institute at present and none of them has been recognised, the authorities of the Institute did not find it possible to negotiate with them separately. The demands of various categories of staff have, however, been discussed by them with the representatives of the employees in the Staff Committee meetings for necessary relief and redress. This procedure has been working smoothly for a number of years in the past.

(e) The authorities of the Institute have already considered the demands mentioned in (b) above and conceded those which were found reasonable. *Inter alia* they have agreed to—

(i) Lower the minimum educational qualification required for the posts of Laboratory Attendants so that sweepers and other Class IV employees may become eligible for these posts.

(ii) Permit the sweepers and Scheduled Caste employees of similar status to apply for the posts of peons and Animal Attendants.

(iii) Consider the sweepers working in the hospital for appointment as Nursing Orderlies and sweepresses as Nursing Ayas.

(iv) Confirm the employees working against permanent posts after verifying their suitability.

(v) Supply liveries to the Khalasis working in the Gas plant and further consider the question of supplying liveries to othe categories of Khalasis.

(vi) Ensure timely supply of liveries to the Class IV employees.

(vii) Raise the rate of washing allowance from Rs. 1 to Rs. 2 per month.

(viii) Consider the grant of cycle allowance to the maintenance staff who are required to undertake extensive tours in the campus.

(ix) Improve the supply of medicines for the beneficiaries of the Employees Health Scheme.

(x) Provide rest rooms to the employees who are not able to return to their homes after duty on account of long distances.

(xi) Consider the question of recognising the Unions functioning in the Institute at peresent.

तालकटोरा रोड, नई दिल्ली में पानी का बन्द हो जाना

2435. **श्री विभूति मिश्र** : क्या **स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 27 अगस्त, 1967 को तालकटोरा रोड, नई दिल्ली और इसके आसपास के क्षेत्रों में लगे पानी के नलों में पानी बन्द रहा था;

(ख) यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि नई दिल्ली नगर पालिका के कर्मचारियों की लापरवाही के कारण पानी बन्द हुआ था; और

(क) यदि हां, तो इस स्थिति को सुधारने के लिए सरकार का क्या उपाय करने का विचार है ?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) नई दिल्ली के कुछ भागों में, जिन में तालकटोरा रोड और उसके आसपास का क्षेत्र भी सम्मिलित है, पीने के पानी का दिया जाना 27 अगस्त, 1967 के पूर्वाह्न को बन्द रहा। तालकटोरा जलाशय की मेन-लाइन में परिवर्तन करने के लिए इसे 26 अगस्त, 1967 को रात को दस बजे बन्द कर दिया गया था । काम कुछ जटिल था और रात्रि के समय इसके संचालन में कुछ अप्रत्याशित कठिनाइयों के कारण इसके पूरा होने में विलम्ब हो गया ।

(ख) पानी कर्मचारियों की लापरवाही के कारण बन्द नहीं हुआ ।

(ग) इस क्षेत्र में अब राजधानी के अन्य क्षेत्रों की भांति पानी नियमित रूप से मिल रहा है ।

PRICES OF ESSENTIAL GOODS

2436. **SHRI RABI RAY** : Will the Minister of **FINANCE** be pleased to state :

(a) whether the Planning Commission have considered as to how to bring down the prices of essential commodities after the reorganisation of the Planning Commission; and

(b) if so, the nature of their recommendations ?

THE DEPUTY PRIME MINISTER AND MINISTER OF FINANCE (SHRI MORARJI DESAI) : (a) and (b). According to the Planning Commission, additional resource mobilisation through all possible measures by the Centre and the States will in any case be necessary. Taxation in particular would enable exercising restraint on consumption and generate additional savings and exportable surpluses. All this will help to keep the upward pressure on prices under restraint. If adequate buffer stock of foodgrains is built up during the current season and the distribution of foodgrains as well as other essential consumer goods is satisfactorily arranged through the net-work of fair-price shops, consumer co-operatives etc. it should be possible to stabilise prices of essential articles and promote growth under conditions of stability.

SOCIAL BOYCOTT OF HARIJANS IN A DELHI VILLAGE

2437. **SHRI DHIRESWAR KALITA** : Will the Minister of **SOCIAL WELFARE** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the residents of Wazidpur Thakuran village of Delhi territory organised a social-boy-

cott of the Harijan residents of their village; and

(b) if so, whether Government have arrested any person in this connection?

THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF SOCIAL WELFARE (SHRIMATI PHULRENU GUHA) : (a) There has been social tension in this village.

(b) Eleven persons are being tried in a court of law under the Untouchability (Offences) Act, 1955.

BEAUTIFICATION OF CHANDIGARH

2438. SHRI SHRI CHAND GOEL : Will the Minister of WORKS, HOUSING AND SUPPLY be pleased to state :

(a) the details of the various schemes which the Administration of the Union Territory of Chandigarh has undertaken or propose to undertake for beautifying Chandigarh, with details of the amounts spent so far or proposed to be spent on each such scheme; and

(b) the measures taken to ensure that the expenditure incurred is essential and useful?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF WORKS, HOUSING AND SUPPLY (SHRI IQBAL SINGH) : (a) On landscape works, which include development of parks, planting of trees, shrubs and other ornamental plants, which were in progress, an expenditure of Rs. 5.5 lakhs was incurred during the financial year 1966-67. During the current financial year, the under mentioned schemes are priposed to be taken up :

(i) Landscaping of open spaces in various sectors. Rs. 1.00 lakh
(ii) Setting up of rose garden. Rs. 0.50 lakh
(iii) Development of Leisure Valley. Rs. 0.20 lakh
(iv) Planting of ornamental trees and bushes along roads, etc. Rs. 5.50 lakh.

(b) The proposals of the Administration are examined by the Government of India before inclusion in budget estimates and presented to Parliament. In this way the essentiality of the expenditure is ensured.

PROHIBITION POLICY AT TOURIST CENTRES

2439. SHRI K. LAKKAPPA : Will the Minister of SOCIAL WELFARE be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Government of India have instructed the States to relax prohibition at tourist centres in order to attract foreign tourists;

(b) if not, whether it is also a fact that the Government of Mysore has decided to do so; and

(c) if so, the details of the decision taken by the Government of Mysore?

THE MINISTER OF PETROLEUM AND CHEMICALS AND SOCIAL WELFARE (SHRI ASOKA MEHTA) : (a) A copy of the letter No. 5/17/66-Proh. Cell dated 21st January, 1967 is laid on the Table of the House. [Placed in Library. *See* No. LT-1805/67].

(b) and (c). Provisions of Mysore Prohibition Act except Sections 1, 2 and 15 are withdrawn and provisions of Excise Act are extended recently in some areas of States where free consumption of liquor is permissible.

केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के मुख्य इंजीनियर को विवाह के लिए बंगलों का दिया जाना

2440. श्री अटल बिहारी वाजपेयी :
श्री ना० स्व० शर्मा :

क्या निर्माण, आवास तथा पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के मुख्य इंजीनियर को अपनी पुत्री का विवाह करने के लिए बंगला संख्या 14-सी फिरोजशाह रोड तथा बगला संख्या 9 कर्जन रोड अलाट किये गये थे।

(ख) मुख्य इजीनियर को अलाट किये जाने से पहले ये बंगले अथवा इनमें से कोई एक बंगला कितने समय तक खाली रखा गया और उसके क्या कारण थे;

(ग) जितने समय तक ये खाली रखे गये उतने समय के किराये की कुल राशि कितनी है;

(घ) सरकार को हुई किराये की इस हानि के लिए जिम्मेदार व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की जा रही है;

(ङ) क्या उन्होंने किसी संसद सदस्य को उन दिनों, जबकि ये बंगले खाली थे, यह पत्र लिखा था कि कोई बंगला खाली नहीं है; और

(च) यदि हां, तो इसके क्या कारण थे ?

निर्माण, आवास तथा पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (श्री इकबाल सिंह): (क) जी नहीं। बंगला नं० 14–सी, फिरोजशाह रोड संसद् सदस्यों के पूल में है तथा उसे राज्य सभा की आवास समिति की सिफारिश पर विवाह के प्रयोजन के लिए संसद् सदस्य श्री जे० के० पी० एन० सिंह को आवंटित किया गया। बंगला नं० 9, कर्जन रोड, संपदा निदेशालय के नियन्त्रण में नहीं है तथा सम्भवतः यह गैर-सरकारी संपत्ति है।

(ख), (ग) और (घ) : प्रश्न ही नहीं उठता।

(ङ) और (च). विवाह के प्रयोजन के लिए कर्जन लेन, केनिंग लेन तथा फिरोजशाह रोड क्षेत्र में, मकान के आवंटन के लिए एक संसद् सदस्य का अनुरोध प्राप्त हुआ था। क्योंकि इस क्षेत्र में सामान्य पूल में कोई बंगला उपलब्ध नहीं था, अतएव कोई आवंटन करना सम्भव नहीं हो सका। बंगला नं० 14–सी, फिरोजशाह रोड संसद् पूल में है तथा इसके आवंटन का नियन्त्रण संसद् की आवास समिति करती है। बंगला नं० 9, कर्जन लेन, जो कि खाली है, रक्षा मंत्रालय के पूल में है।

भूतपूर्व पैट्रोलियम मंत्री की ओर बकाया राशि

2441. श्री अटल बिहारी वाजपेयी :
श्री ना० स्व० शर्मा :
श्री शारदानन्द :
श्री श्रीचन्द गोयल :

क्या **निर्माण, आवास तथा पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भूतपूर्व पैट्रोलियम मंत्री श्री के० डी० मालवीय की ओर सफदरजंग लेन पर स्थित बंगला नम्बर 2 के किराये आदि के रूप में सितम्बर, 1967 तक साढ़े तीन हजार रुपये की राशि बकाया है और सरकार ने इस राशि को वसूल करने के लिए तब तक कोई कानूनी कार्यवाही नहीं की थी;

(ख) क्या यह भी सच है कि उनके पुत्र को मोती बाग में फलैट नम्बर सी–2/25 बिना प्राथमिकता के दे दिया गया है; और

(ग) यदि हां, तो इन अनियमितताओं को दूर करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

निर्माण, आवास तथा पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (श्री इकबाल सिंह) : (क) श्री के० डी० मालवीय से बंगला नं० 2, सफदर जंग लेन के सम्बन्ध में 3,817.98 रुपये किराये की शेष राशि देय है। उन्होंने कुछ आपत्तियां उठाई थीं जिनकी परीक्षा की जा रही है तथा पत्राचार के अधीन है।

(ख) जी हां। सेवानिवृत्त अथवा हारे हुए संसद् सदस्यों के पुत्र/पुत्रियों को, यदि वे वास के पात्र हैं, तो, सामान्य पूल से वैकल्पिक वास उसी आधार पर दिया जाता है जिस पर कि सेवानिवृत्त/मृत्यु को प्राप्त सरकारी कर्मचारियों के पुत्र/पुत्रियों को सरकारी वास दिया जाता है।

(ग) अभी प्रश्न ही नहीं उठता।

MASTER PLAN FOR IRRIGATION OF AGRICULTURAL LAND

2442. SHRI RANDHIR SINGH : Will the Minister of IRRIGATION AND POWER be pleased to state :

(a) whether Government have any master plan under consideration to cover every inch of agricultural land by irrigation within the span of ten years;

(b) if so, the broad details thereof; and

(c) if not, the reasons therefor ?

THE MINISTER OF IRRIGATION AND POWER (DR. K. L. RAO) : (a) to (c). Preliminary studies indicate that about 50% of our agricultural land could be provided with irrigation facilities. Surface water resources would irrigate about 150 million acres and Ground Water another 50 million acres. Subject to availability of resources, attempts will be made to develop this irrigation potential within the next 20-25 years.

ACCOMMODATION FOR TEACHERS IN DELHI

2443. SHRI M. L. SONDHI : Will the Minister of WORKS, HOUSING AND SUPPLY be pleased to state :

(a) whether teachers working under the Delhi Administration when transferred to certain areas of New Delhi or South Delhi have to vacate the Government accommodation allotted to them or have to pay commercial rent; and

(b) if so, the reasons therefor ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF WORKS, HOUSING AND SUPPLY (SHRI IQBAL SINGH) : (a) and (b). The employees whose place of duty falls beyond the limits of Delhi, fixed by the Government, are not eligible for allotment/ retention of general pool accommodation irrespective of the fact whether they are working under Delhi Administration or in an eligible office under the Central Government. Such employees cannot retain general pool accommodation in their occupation beyond the concessional period provided in the Allotment Rules.

INCOME-TAX EVASION BY BIRLA FIRMS

2444. SHRI BHOGENDRA JHA : Will the Minister of FINANCE be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Income-tax Department reported after investigation from Calcutta that there has not been any tax evasion by the Birla firms;

(b) whether it has now been detected that Birlas had evaded payment of tax by diverting part of their profit to M/s Keshoram Cotton Mills Ltd. by way of special salaries to the wives of four senior executives; and

(c) if so, the action which Government have taken or propose to take in the matter ?

THE DEPUTY PRIME MINISTER AND MINISTER OF FINANCE (SHRI MORARJI DESAI) : (a) No, Sir.

(b) In the case of M/s. Keshoram Industries and Cotton Mills Ltd., Calcutta, complaints of tax evasion have been investigated and salaries paid to the wives of three senior executives have been disallowed in the hands of that company for several assessment years on the ground that the salaries were not paid wholly and exclusively for the purpose of the business. The disallowances are, however, being disputed by the company in appeal, which is pending.

(c) Does not arise as the amounts have been assessed in the hands of the company.

HANDING OVER OF 7, RAKABGANJ ROAD, NEW DELHI TO S.S.P.

2445. SHRI ONKAR LAL BERWA : Will the Minister of WORKS, HOUSING AND SUPPLY be pleased to state :

(a) whether the Samyukta Socialist Party has approached Government for the transfer of the building at No. 7, Rakabganj Road to that Party, so that a suitable memorial could be made in

the memory of the late Dr. Lohia in that bungalow; and

(b) if so, the decision taken in the matter ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF WORKS, HOUSING AND SUPPLY (SHRI IQBAL SINGH) : (a) Yes.

(b) It has not been found possible to accept the request of the Samyukta Socialist Party.

राज्यों में प्रति व्यक्ति आय

2446. **श्री विभूति मिश्र** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विभिन्न राज्यों में प्रति व्यक्ति आय में बहुत बड़ी असमानता है;

(ख) क्या यह भी सच है कि पहली, दूसरी, तीसरी आयोजना और चौथी आयोजना की वार्षिक आयोजनाओं के लिए रकम का निर्धारण जन संख्या के आधार पर नहीं किया गया; और

(ग) क्या यह भी सच है कि इन सभी आयोजनाओं में अन्य राज्यों की तुलना में बिहार के लिए अपेक्षाकृत कम रकम का निर्धारण किया गया है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) सब से हाल के जो अनुमान उपलब्ध हैं उनसे पता चलता है कि विभिन्न राज्यों की प्रति व्यक्ति आय में काफी असमानता है।

(ख) राज्यों को केन्द्रीय सहायता, उनकी आबादी और अन्य सम्बद्ध बातों का विचार करके, दी गयी थी।

(ग) जी, नहीं।

Profit of Indian Oil Corporation Refineries

2447. **SHRI PREM CHAND VERMA** : Will the Minister of PETROLEUM AND CHEMICALS be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the profit of the Refineries Division of the Indian Oil Corporation which stood at Rs. 77.97 lakhs in 1964-65 fell to Rs. 27,000 in 1965-66;

(b) if so, the reasons therefor; and

(c) the estimated profits in 1967-68 ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PETROLEUM AND CHEMICALS AND OF SOCIAL WELFARE (SHRI RAGHU RAMAIAH) : (a) Yes, Sir.

(b) During 1964-65, only the Gauhati refinery was in operation and the Refineries Division made a profit of Rs. 77.97 lakhs. Although the Gauhati refinery made a profit of Rs. 108 lakhs, the shortfall during 1965-66 was due to operational loss on the Barauni and Gujarat refineries, which came on stream during this period.

(c) Rs. 135 lakhs.

Purchase of Stores and Equipment by Public Undertakings

2448. SHRI N. K. P. SALVE : Will the Minister of FINANCE be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Public Sector Undertakings procure their stores, equipment and material from private sector even though such material or stores are available with other public sector undertakings; and

(b) if so, whether Government propose to issue instructions to the public sector undertakings to discontinue this practice ?

THE DEPUTY PRIME MINISTER AND MINISTER OF FINANCE (SHRI MORARJI DESAI): (a) and (b). The enterprises normally make their purchases of stores, equipment and matetrials on the basis of competitive offers keeping in view the suitability of offers, delivery position etc., and it is not proposed to change this practice except when there are any special circumstances warranting a change.

Exports to Indonesia

2449. SHRI ARJUN SINGH BHADORIA : Will the Minister of FINANCE be pleased to state :

(a) whether Indonesia has utilised Rs. 10 crores credit given to it by India this year; and

(b) if so, which products have been purchased from India from this credit?

THE DEPUTY PRIME MINISTER AND MINISTER OF FINANCE (SHRI MORARJI DESAI) : (a) Yes, Sir. As on the 20th November, 1967, an amount of Rs. 3.88 crores approximately has been utilised by the Government of Indonesia out of the credit.

(b) The products purchased are Jute products, Cambrics, cotton textiles, Bicycle Spare parts and bicycles in c.k.d. condition, Writing papers, Components and Spare parts for Buses and trucks, Chemicals Dye-stuffs, Spare parts for Oil Mill and Iron & Steel products.

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के सम्बन्ध में प्रशासनिकसुधार आयोग का प्रतिवेदन

2450. **श्री रघुवीर सिंह शास्त्री :**
श्री कृष्ण मूर्ति :
श्री मोहन स्वरूप :

क्या वित्त मंत्री 13 जुलाई, 1967 के अतारांकित प्रश्न संख्या 5557 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के बारे में प्रशासनिक सुधार आयोग का प्रतिवेदन सरकार को इस बीच प्राप्त हो चुका है ;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य मुख्य सिफारिशें क्या हैं; और

(ग) उन पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) जी, हां।

(ख) आयोग की मुख्य सिफारिशें इन पहलुओं से सम्बन्धित हैं :

(1) संगठनात्मक ढांचा।

(2) सरकारी उद्यम, संसद और सरकार।

(3) प्रायोजनाओं का आयोजन और निर्माण।

(4) साधन-बाह्य और आन्तरिक।

(5) वित्तीय और सामग्री-सम्बन्धी व्यवस्था।

(6) कर्मचारी।

(7) लेखापरीक्षा और मूल्यांकन।

(ग) सिफारिशें सरकार के विचाराधीन हैं।

कानपुर स्थित लूप कारखानों में गोलमाल

2451. **श्री ओंकार लाल बेरवा :** क्या स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कानपुर स्थित लूप कारखाने में गोलमाल के अनेक मामले हुए हैं तथा वहां पर लाखों रुपये की लागत के लूप बिना बिके पड़े हैं ;

(ख) क्या यह भी सच है कि केन्द्रीय सरकार कोई सहायता नहीं दे रही है तथा कारखाना बन्द होने वाला है; और

(ग) यदि हां, तो इनके क्या कारण हैं तथा कारखाने के बन्द हो जाने की हालत में श्रमिकों को अन्य रोजगार देने के लिए क्या प्रबन्ध किये गये हैं ?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नागरीय विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० श्रीपति चन्द्रशेखर): (क) कानपुर-स्थित लूप कारखाना उत्तर प्रदेश सरकार के प्रशासकीय नियन्त्रण में है। भारत सरकार को कारखाने में हुए गोलमाल के किसी मामले का पता नहीं है। भारत सरकार उत्तर प्रदेश सरकार से परस्पर तय की गई दरों पर, आवश्यकता के अनुसार, सभी लूप और इन्सरटर्स खरीद लेती है। ताजा सूचना के अनुसार कारखाने में एक लाख रुपये से कम का पास किया हुआ माल पड़ा है। वस्त्र और कपड़ा मुख्य निरीक्षणालय कानपुर द्वारा निरीक्षणाधीन/निलंबित माल का मूल्य 1.5 लाख रुपये से कम है।

(ख) और (ग). कारखाना उत्तर प्रदेश सरकार का है और वही उसका प्रबन्ध करते हैं। समय समय पर, परस्पर निश्चित की गई

दरों पर, आवश्यकता के अनुसार, भारत सरकार लूप और इन्सरटर्स खरीदती रहती है।

INDUSTRIAL FINANCE CORPORATION AND INDUSTRIAL DEVELOPMENT BANK

2452. SHRI BHOGENDRA JHA : Will the Minister of FINANCE be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Industrial Finance Corporation and the Industrial Development Bank together advanced assistance amounting to Rs. 169 crores in 1965-66 and Rs. 127 crores in 1966-67, the latter including foreign exchange component at devalued rate;

(b) whether it is also a fact that 116 unfinished projects assisted by the Industrial Finance Corporation showed an increase of expenditure of Rs. 75 crores over the estimated expenditure of Rs. 386 crores and of the 217 projects in production 133 projects incurred losses and only 43 declared dividend; and

(c) if so, the reasons therefor ?

THE DEPUTY PRIME MINISTER AND MINISTER OF FINANCE (SHRI MORARJI DESAI) : (a) No, Sir. The Industrial Finance Corporation and the Industrial Development Bank together sanctioned during the financial years 1965-66 and 1966-67 financial assistance amounting to Rs. 112.7 crores and Rs. 85.0 crores respectively. These include foreign currency loans sanctioned by the Industrial Finance Corporation expressed in rupees on the post-devaluation basis. The figures mentioned by the Hon'ble Member are those of assistance sanctioned by all the long-term financial institutions in the country including State Financial Corporations.

(b) and (c). A study made by the Industrial Finance Corporation for assessing the impact of devaluation on the cost of 116 projects assisted by it which had not gone into production showed that their costs had increased from Rs. 386.37 crores to Rs. 460.95 crores *i.e.*, by Rs. 74.58 crores due to devaluation.

The dividend paying capacity of the industrial concerns financed by the Corporation was affected by the difficult economic conditions that prevailed during the year ended 30th June, 1967. Of the 217 concerns in production, 133 incurred losses during the period or could make only marginal profits. During this period the number of concerns who were able to declare equity dividend was 84 of whom 43 declared dividend at a rate of 10% or above.

NEW PUBLIC UNDERTAKING IN MADHYA PRADESH

2453. SHRI MANIBHAI J. PATEL : Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether any major public sector undertaking is proposed to be located in Madhya Pradesh during the Fourth Five Year Plan;

(b) if so, the details thereof; and

(c) if not, the reasons therefor ?

THE DEPUTY PRIME MINISTER AND MINISTER OF FINANCE (SHRI MORARJI DESAI) : (a) and (b). The Central public sector projects proposed to be set up, or schemes of expansion proposed to be taken up, in Madhya Pradesh during the Fourth Five Year Plan period along with their location are mentioned below :—

Name of the Project	*Location*
1. Expansion of Bhilai Steel Plant	Bhilai
2. Expansion of Heavy Electrical Project	Bhopal
3. Expansion of Nepa Mills	Nepanagar
4. Security Paper Mills	Hoshangabad
5. Korba Aluminium Project	Korba
6. New Alkaloid Factory	Neemuch
7. Cement Factory	Mandhar

In addition, the possibility of establishing a paper/pulp factory in the Dandakaranya area is under consideration.

(c) Does not arise.

POONAKSHI DAM

2454. SHRI BENI SHANKER SHARMA : Will the Minister of IRRIGATION AND POWER be pleased to state :

(a) whether Government have received any proposal regarding the construction of Poonakshi Dam on the Ajoy River in the District of Santhal Parganas in the State of Bihar;

(b) whether the Scheme has been approved; and

(c) whether it will be taken up during the Fourth Five Year Plan ?

THE MINISTER OF IRRIGATION AND POWER (DR. K. L. RAO) : (a) Project report on "Punasi Reservoir Project" on the Ajoy river in the district of Santhal Parganas has been received in Central Water and Power Commission for technical examination.

(b) No.

(c) The scheme has not been included by the Government of Bihar in their Draft Fourth Plan proposals.

EMPLOYEES SUGGESTION SYSTEM IN PUBLIC UNDERTAKINGS

2455. SHRI S. R. DAMANI : Will the Minister of FINANCE be pleased to state :

(a) whether employee suggestion system designed to encourage active cooperation of the employee in cost reduction or cost prevention or increasing productivity or efficiency has been working in the public sector undertakings; and

(b) if so, the extent to which it has proved successful ?

THE DEPUTY PRIME MINISTER AND MINISTER OF FINANCE (SHRI MORARJI DESAI) : (a) and (b). The suggestion System is in operation in various enterprises and, by and large, it has has been found useful in giving a sense of participation to the employees in the working of the enterprises, quite apart from introducing some valuable suggestions for increasing productivity.

राष्ट्रीय बचत योजना

2456. श्री रघुबीर सिंह शास्त्री :
श्री कं० हाल्दर :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कई राज्यों ने यह प्रार्थना की है कि विभिन्न राष्ट्रीय बचत योजनाओं के अन्तर्गत दिये जाने वाले ब्याज की दर में वृद्धि की जाये;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) राष्ट्रीय बचत सम्बन्धी केन्द्रीय सलाहकार बोर्ड ने हाल में हुई अपनी बैठक में इस बारे में क्या सिफारिशें की हैं; और

(घ) सरकार की इस बारे में क्या प्रतिक्रिया है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) जी हां।

(ख) केन्द्रीय सरकार को ब्याज की दर बढ़ाने की प्रार्थना स्वीकार करना सम्भव नहीं मालूम हुआ।

(ग) राष्ट्रीय बचत केन्द्रीय सलाहकार बोर्ड ने 18 नवम्बर 1967 को हुई अपनी बैठक में विभिन्न बचत योजनाओं पर ब्याज की दरें बढ़ाने की कोई सिफारिश नहीं की।

(घ) यह सवाल पैदा ही नहीं होता।

AGRICULTURAL REFINANCE CORPORATION

2457. SHRI VASUDEVAN NAIR : Will the Minister of FINANCE be pleased to state :

(a) the number of land development schemes so far helped by the Agricultural Refinance Corporation;

(b) the total amount so far advanced by the Corporation for the purpose;

(c) the progress so far made in the execution of these schemes;

(d) whether the Corporation has taken any steps to help the formulation of land development schemes in different States; and

(e) if so, the steps taken so far ?

THE DEPUTY PRIME MINISTER AND MINISTER OF FINANCE (SHRI MORARJI DESAI) : (a) to (c). The Corporation has so far approved 25 land development schemes, involving a total financial outlay of Rs. 3,780 lakhs, covering an area of 24.13 lakh acres. The Corporation's commitment in respect of these schemes amounts to Rs. 3,054 lakhs, against which a sum of Rs. 762 lakhs has so far been disbursed. The land mortgage banks concerned have paid a total sum of Rs. 963 lakhs as loans for developing 4.49 lakh acres of land and, according to information available, 2.65 lakh acres of land have been developed till the 30th October, 1967.

(d) and (e). Yes, apart from laying down the guide lines for the formulation of such schemes, the Corporation has also posted its officers at Bangalore, Calcutta, Coimbatore and Hyderabad to help the State Governments in the actual formulation of the schemes.

EVICTION OF TRIBES FROM TRIBAL LAND IN TRIPURA

2458. SHRI VISWANATHA MENON : Will the Minister of SOCIAL WELFARE be pleased to state :

(a) the number of tribes evicted from 1960 to 1967 in Tripura;

(b) the steps taken by Government to stop eviction of Tribes from tribal land;

(c) whether Government propose to amend Tripura Land Revenue and Land Reforms Act, 1960 to give more protection to tribes; and

(d) if not, the reasons therefor ?

THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF SOCIAL WELFARE (SHRIMATI PHULRENU GUHA) : (a) to (d). Information is being collected from the Government of Tripura and will be placed on the Table of the House.

ARREST OF FOREIGN NATIONALS

2459. SHRI M. L. SONDHI :
DR. RANEN SEN :

Will the Minister of FINANCE be pleased to state :

(a) the total number of foreign nationals who have been apprehended in the Capital in the last six months for possessing *charas, opium* or such other contraband articles;

(b) the countries from which these national entered into India and the quantity of charas, opium or other contraband articles found from them;

(c) if so, whether there is any evidence of link between them and dope smugglers in India;

(d) the action taken in each of these cases and whether their Governments have been intimated of their unlawful activities; and

(e) whether proper verification was carried out before granting them visas ?

THE DEPUTY PRIME MINISTER AND MINISTER OF FINANCE (SHRI MORARJI DESAI) : (a) 17.

(b) The information is given below :—

Country from which the foreign nationals entered into India	Number
(1)	(2)
Pakistan	9
Nepal	5
Ceylon	1
Kabul	2

(*ii*) Quantity of contraband articles seized.

19·265 kgs. Charas

(c) No such evidence is available.

(d) The action taken in these cases is indicated below :—

Arrested	Challaned	Convicted	Discharged
17	17	16	1

(ii) Information as to whether the governments concerned have been intimated in these cases is being ascertained and will be laid on the Table of the Sabha.

(e) There is no reason to believe that the Indian Missions concerned have not observed the normal procedure of verification before granting visas to the persons concerned.

SMUGGLING OF ROCKSALT

2460. SHRI YAJNA DATT SHARMA : Will the Minister of FINANCE be pleased to state :

(a) whether it is a fact that a large quantity of rocksalt from Pakistan is being smuggled into Kashmir Valley;

(b) if so, whether Government have investigated how and from which route these smugglers operate; and

(c) the action taken by Government to check it ?

THE DEPUTY PRIME MINISTER AND MINISTER OF FINANCE (SHRI MORARJI DESAI) : (a) The enquiries made so far do not indicate that a large quantity of rock-salt is being smuggled from Pakistan into Kashmir Valley.

(b) and (c). Do not arise.

SCHEDULED CASTES IN GOA

2461. SHRI MARANDI :
SHRI MOHAN SWARUP :

Will the Minister of SOCIAL WELFARE be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Government have decided to compile a list of Scheduled Castes in Goa, Daman and Diu;

(b) if so, how many Scheduled Castes have been counted in Goa, Daman and Diu so far; and

(c) the facilities provided by the State and Central Governments to them ?

THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF SOCIAL WELFARE (SHRIMATI PHULRENU GUHA) : (a) to (c). The specification of Scheduled Castes and Scheduled Tribes in Goa, Daman and Diu is under consideration; and Presidential orders are expected to be issued shortly.

INDIAN AUDIT AND ACCOUNTS SERVICE

*2462. SHRI S. R. DAMANI : Will the Minister of FINANCE be pleased to state the present strength of the Indian Audit and Accounts Service and whether all are working with the Central Government ?

THE DEPUTY PRIME MINISTER AND MINISTER OF FINANCE (SHRI MORARJI DESAI) : The strength of the Indian Audit and Accounts Service as on 15th November, 1967 was 520. Of these 463 officers were working with the Central Government (including the Indian Audit and Accounts Department) and in the Public Sector Undertakings/Statutory bodies set up by the Central Government.

RESTRICTIONS ON REMITTANCES OF MONEY INTO INDIA

2463. SHRI S. R. DAMANI : Will the Minister of FINANCE be pleased to state :

(a) whether it is a fact that persons with income in foreign countries because of restrictions by foreign Governments on remittances have not been allowed benefits under Section 220(7) of the Income Tax Act;

(b) if so, the names of foreign countries which have put restrictions on remittances of money into India; and

(c) whether necessary instructions have been issued to the assessing authorities to make available the relief claimed ?

THE DEPUTY PRIME MINISTER AND MINISTER OF FINANCE (SHRI MORARJI DESAI) : (a) and (b). The information is being collected and will be laid on the Table of the House as early as possible.

(c) No general instructions have been issued as the provisions in the Income Tax Act for granting such relief are quite clear.

MEDICAL COLLEGE AT COIMBATORE

2464. SHRIMATI SUSEELA GOPALAN :
SHRI P. RAMAMURTI :
SHRI K. RAMANI :
SHRI E. K. NAYANAR :

Will the Minister of HEALTH, FAMILY PLANNING AND URBAN DEVELOPMENT be pleased to state :

(a) whether there is any proposal to set up a Medical College at Coimbatore;

(b) if so, when it is likely to start functioning; and

(c) the extent of Central financial assistance proposed to be sanctioned to the said college ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF HEALTH, FAMILY PLANNING AND URBAN DEVELOPMENT (SHRI B. S. MURTHY): (a) and (b). The Government of Madras have started Medical College at Coimbatore in July, 1966.

(c) Central assistance for new Medical Colleges opened during the Fourth Plan is rendered at the rate of 50% of the recurring as well as non-recurring expenditure.

The request of the Government of Madras for Central assistance for the Medical College at Coimbatore is under consideration.

M. Ps. ADMITTED TO HOSPITALS IN DELHI

2465. SHRI R. S. VIDYARTHI : Will the Minister of HEALTH, FAMILY PLANNING AND URBAN DEVELOPMENT be pleased to state :

(a) the number of Members of Parliament who were admitted in Willingdon Hospital and All India Institute of Medical Sciences, New Delhi during the last 10 years; and

(b) the names of the Members of Parliament who died in each hospital, separately, the nature of their disease and the period of their stay in the hospital ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF HEALTH, FAMILY PLANNING AND URBAN DEVELOPMENT (SHRI B. S. MURTHY) : (a) During the last ten years ending September, 1967, 477 Members of Parliament were admitted in the Willingdon Hospital. The All India Institute of Medical Sciences Hospital was started in December, 1958 and so far 12 Members of Parliament have been admitted in that Hospital.

(b) Out of the admissions made in the above Hospitals, no death took place in the All India Institute of Medical Sciences Hospital while a statement in respect of those Members of Parliament who died in the Willingdon Hospital is laid on the Table of the House. [*Placed in Library. See* No. LT-1806/67.]

सीमा शुल्क विभाग द्वारा पकड़ा गया सामान

2466. **श्री रा० स्व० विद्यार्थी :**
श्री मोलहू प्रसाद :
श्री प्रकाशवीर शास्त्री :
श्री रामावतार शर्मा :
श्री शिवकुमार शास्त्री :
श्री महन्त दिग्विजय नाथ :
श्री यशवन्त सिंह कुशवाह :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जुलाई से अक्तूबर, 1967 तक की अवधि में सीमा शुल्क अधिकारियों ने कितने मूल्य की वस्तुयें पकड़ीं ;

(ख) इन वस्तुओं में सोने और चांदी की कितनी मात्रा थी और ये किन किन स्थानों से पकड़े गये थे तथा अन्तर्राष्ट्रीय दरों एवं भारत की वर्तमान दरों के हिसाब से क्रमशः इनका मूल्य कितना था ;

(ग) कितनी विदेशी मुद्रा पकड़ी गई थी और वह किस देश की थी ; और

(घ) इस सम्बन्ध में कितने व्यक्ति गिरफ्तार किये गये ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) से (घ). इस सम्बन्ध में सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा की मेज पर रख दी जायगी ।

नई दिल्ली स्थित वायुसेना मुख्यालय भवन की छत में पानी का टपकना

2467. **श्री रा० स्व० विद्यार्थी** : क्या **निर्माण, आवास तथा पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नई दिल्ली में रामकृष्णपुरम् स्थित वायुसेना मुख्यालय का भवन वर्षा ऋतु में टपकता है ;

(ख) यदि हां, तो घटिया किस्म की सामग्री का इस्तेमाल करने के लिए जिम्मेदार अधिकारियों के विरुद्ध सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ;

(ग) यदि उपरोक्त भाग (ख) का उत्तर नकारात्मक हो, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(घ) रामकृष्णपुरम् स्थित उन भवनों की संख्या कितनी है, जिनके बारे में ऐसी शिकायतें प्राप्त हुई हैं ?

निर्माण, आवास तथा पूर्ति मंत्रालय में उप मंत्री (श्री इकबाल सिंह) : (क) से (ग). खंड VI, रामकृष्णपुरम् में पानी टपकने की शिकायत वायु सेना मुख्यालय से जुलाई, 1967 में प्राप्त हुई थी, तथा भवन के ठेकेदारों, हिन्दुस्तान हाउसिंग फैक्ट्री ने उसे सुधार दिया था । यह टपकना किसी घटिया सामग्री के उपयोग के कारण नहीं था, किन्तु यह इस वर्ष में अत्याधिक वर्षा होने के कारण था । अतएव केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के किसी अधिकारी के विरुद्ध कोई अनुशासनिक कार्यवाही करने का प्रश्न ही नहीं है ।

(घ) रामकृष्णपुरम् के अन्य भवनों के सम्बन्ध में ऐसी कोई बड़ी शिकायत नहीं प्राप्त हुई थी । कुछ छोटी मोटी शिकायतें प्राप्त हुई थीं जिन्हें तुरन्त ठीक कर दिया गया ।

ASSETS OF NIZAM OF HYDERABAD

2468. SHRI SHIVA CHANDRA JHA : Will the Minister of FINANCE be pleased to state :

(a) the total financial assets of the Nizam of Hyderabad;

(b) the amount of taxes he pays annually; and

(c) the industries or banks in which the Nizam has made investments, sector-wise ?

THE DEPUTY PRIME MINISTER AND MINISTER OF FINANCE (SHRI MORARJI DESAI) : (a) The latest Wealth-tax assessment completed is for the assessment year 1960-61 according to which the net wealth of the Late H. E. H. The Nizam of Hyderabad as on 31-3-1960 amounted to Rs. 8,22,73,646/-.

(b) The various taxes paid by the Late H. E. H. The Nizam under various Direct Taxes Acts in the previous 5 financial years are given below :—

Financial Year	*Income-tax*	*Wealth-tax*	*Gift-tax*	*Expenditure-tax*	*Total*
1962-63 . . .	—	11,80,000	—	—	11,80,000
1963-64 . . .	19,74,998	1,50,000	96,000	—	22,20,998
1964-65 . . .	15,46,104	—	5,03,819	4,87,173	25,37,096
1965-66 . . .	6,27,532	15,19,270	4,00,000	4,02,565	29,49,367
1966-67 . . .	7,35,593	17,32,776	23,61,003	—	48,29,372
	48,84,227	45,82,046	33,60,822	8,89,738	1,37,16,833

(c) The information is not readily available. It will be collected and placed on the Table of the House.

FOREIGN BANKS

2469. SHRI SHIVA CHANDRA JHA : Will the Minister of FINANCE be pleased to state :

(a) the total paid-up capital and bank deposits of foreign banks in India and their ratios;

(b) the number of Indian shareholders in the foreign banks and the percentage of shares they hold; and

(c) the number of Indians in the Directorship of these foreign banks and the amount of loans standing in their names ?

THE DEPUTY PRIME MINISTER AND MINISTER OF FINANCE (SHRI MORARJI DESAI) : (a) and (b). The information is being collected and will be laid on the Table of the House in due course.

(c) Nil.

U.S.S.R. INSTRUMENT FOR ABORTION

2470. SHRI SHIVA CHANDRA JHA :
SHRI RAM AVTAR SHARMA :
SHRI SHIV KUMAR SHASTRI :
DR. SURYA PRAKASH PURI :
SHRI Y. S. KUSHWAH :

Will the Minister of HEALTH AND FAMILY PLANNING be pleased to state :

(a) whether it is a fact that U.S.S.R. has presented some instrument to India by which abortion would be made easier and quicker;

(b) if so, the name of that instrument and their number so far presented to India;

(c) whether Government propose to manufacture that instrument in India; and

(d) if not, the reasons therefor ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HEALTH, FAMILY PLANNING AND URBAN DEVELOPMENT (DR. S. CHANDRASEKHAR) : (a) and (b). The Health Minister of U.S.S.R. recently presented through the Russian Ambassador in India one unit of an apparatus known as Vacuum Aspirator.

(c) and (d). This apparatus has still to be tried in India and its utility evaluated. The question of its manufacture in India will then be considered.

BEGGARY

2471. SHRI SHIVA CHANDRA JHA : Will the Minister of SOCIAL WELFARE be pleased to state :

(a) whether it is a fact that beggary has increased in India; and

(b) if so, the total number of beggars in India during the last three Plans, plan-wise ?

THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF SOCIAL WELFARE (SHRIMATI PHULRENU GUHA) : (a) Yes, Sir.

(b) The information is not available.

LAND FOR RAJ GHAT AND SHANTIVAN

2472. SHRI SHIVA CHANDRA JHA : Will the Minister of WORKS, HOUSING AND SUPPLY be pleased to state :

(a) how many acres of land have been taken for making Rajghat, Shantivan and Vijayghat;

(b) the estimated amount to be spent for completing those ghats; and

(c) the estimated annual expenditure incurred on their maintenance ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF WORKS, HOUSING AND SUPPLY (SHRI IQBAL SINGH) : (a) to (c). So far as Rajghat is concerned, complete development plans stand sanctioned. Development of Shantivana and Vijay Ghat is being taken up in phases. The figures of estimated expenditure in respect of the latter two samadhis, therefore, represent the proposals sanctioned so far.

The required information is as given below :—

	Acreage of land	Approximate amount to be spent on development	Approximate annual expenditure on maintenance of works [completed
		(Rs. in lakhs)	(Rs. in lakhs)
Rajghat	175	94·44	1·31
Shanti Vana	81	34·23	0·17
Vijay Ghat	75	2·29	0·10

FOREIGNERS ARRESTED IN VARANASI

2473. SHRI SATYA NARAIN SINGH :
SHRI GANESH GHOSH :
SHRI P. RAMAMURTHI :
SHRI NAMBIAR :

Will the Minister of FINANCE be pleased to state :

(a) whether it is a fact that three foreigners were arrested on the 30th September, 1967 at Varanasi under the Excise Act for possession of opium and Ganja;

(b) if so, the names and nationalities of the foreigners;

(c) the number of foreigners arrested for various smuggling crimes during the last six months in the country; and

(d) the steps taken by Government to check smuggling by foreigners ?

THE DEPUTY PRIME MINISTER AND MINISTER OF FINANCE (SHRI MORARJI DESAI) : (a) on the 30th September, 1967 three foreigners were arrested at Varanasi under the Opium Act and the Excise Act for possession of opium and ganja.

(b) The information is given below :—

Name of the arrested person.	*Nationality.*
Mr. John Kofod.	Danish.
Mr. Duchi Jean Baptiste Mr. Dofour Gerard.	French.

(c) The information is being collected and will be placed on the Table of the Sabha.

(d) All the enforcement agencies, both of Central and State Governments concerned with the suppression of illicit traffic such as the Customs, the Excise, the Police and the staff of the Narcotics Department are on the alert and keep a watch on suspicious persons including foreigners.

SUBSIDISED INDUSTRIAL HOUSING SCHEME

2474. SHRI S. M. BANERJEE : Will the Minister of WORKS, HOUSING AND SUPPLY be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Central Government have stopped giving subsidy to the State Governments specially to the Uttar Pradesh Governmtnt for building housss under Subsidised Industrial Housing Scheme;

b) if so, the reasons therefor; and

(c) whether it is a fact that the Central Government have not paid any subsidy to Uttar Pradesh Givernment in 1965 and 1966 ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF WORKS, HOUSING AND SUPPLY (SHRI IQBAL SINGH) : (a) No.

(b) Does not arise.

(c) The Central Government released the following amounts of loan and subsidy to the Government of Uttar Pradesh during the years 1964-65 and 1965-66 for building houses under the Subsidised Industrial Housing Scheme :

	Loan	Subsidy
1964-65	Rs. 39·66 lakhs	Rs. 17·02 lakhs
1965-66	Rs. 17·5 lakhs	Rs. 17·14 lakhs

HOUSES FOR HARIJANS

2475. SHRI S. M. BANERJEE : Will the Minister of SOCIAL WELFARE be pleased to state :

(a) the steps taken to construct houses for Harijans in the country; and

(b) whether any special financial aid has been given or is being given to the various State Governments for this purpose ?

THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF SOCIAL WELFARE (SHRIMATI PHULRENU GUHA) : (a) and (b). There are two Schemes in operation :—

(i) Subsidies given for construction of houses by Harijans

under the State Plan schemes with central assistance; and

(ii) Grants-in-aid given to the State Governments for housing of sweepers and scavengers under the Centrally Sponsored scheme; this supplements the Slum Clearance Scheme and the Low Income Group Housing Scheme of the Ministry of Works and Housing.

TAX ARREARS DUE FROM M/S. B. R. SONS LTD., BOMBAY

2476. SHRI S. M. BANERJEE : Will the Minister of FINANCE be pleased to state :

(a) the action taken for the realisation of the huge tax arrears from M/s. B. R. Sons Ltd.;

(b) the action taken against the officers responsible for the huge accumulation of tax arrears and allowing the Company to dissipate its assets and earnings; and

(c) the action taken or proposed to be taken to bring to book persons responsible for the disappearance of the Company's assets and accumulation of tax arrears ?

THE DEPUTY PRIME MINISTER AND MINISTER OF FINANCE (SHRI MORARJI DESAI) : (a) (i) Notices u/s 226(3) of the Income-tax Act, 1961 have been issued to all debtors.

(ii) The shares held by M/s. B. R. Sons Ltd., have been attached.

(iii) Petition has been moved in the Bombay High Court for sending M/s. B. R. Sons Ltd. into compulsory liquidation u/s. 439(b) read with section 433(e) of the Companies Act, 1956, to enable the Income-tax Officer to proceed against the Directors under section 542 and 543 of the Companies Act, 1956.

(b) No action has been taken so far as enquiries are being made.

(c) As stated in reply to part (a) of the Question above, petition has been moved in the Bombay High Court for sending the company into compulsory liquidation with a view to enable the Income-tax Officer to proceed against the Directors of the Company u/s. 542 and 543 of the Companies Act, 1956.

INTERNAL AUDIT OF PUBLIC UNDERTAKINGS

2477. SHRI YAJNA DATT SHARMA : Will the Minister of FINANCE be pleased to state :

(a) whether it is a fact that in a number of public sector undertakings there is no system of internal audit in vogue nor there is any manual laying down the detailed procedure for compilation and maintenance of accounts;

(b) if so, the reasons therefor; and

(c) whether Government propose to issue any instructions to such undertakings in this regard ?

THE DEPUTY PRIME MINISTER AND MINISTER OF FINANCE (SHRI MORARJI DESAI) : (a) to (c). The importance of proper system of internal audit in Public Enterprises and the compilation of Accounting Manuals by them has always been recognised and the Enterprises have been advised to take necessary steps in these directions. Out of 45 Companies in respect of which information is available in the Central Government Audit Report (Commercial) 1967, 35 had introduced internal audit and 32 had compiled Accounting Manuals by the end of 1965-66. While improvements in these matters are being continuously sought to make these comprehensive and effective, instructions have also been issued to the enterprises, who have not already done so, to adopt similar measures.

"TOURS BY OFFICIALS FOR INCOME-TAX ASSESSMENTS"

2478. SHRI YAJNA DATT SHARMA : Will the Minister of FINANCE be pleased to state :

(a) whether the Commissioner of Income-tax Punjab, Haryana, Himachal Pradesh and Jammu and Kashmir has issued instructions to Income-tax Officers within his jurisdiction for curtailing mofussil tours for finalising Income-tax assessments;

(b) if so, whether these instructions cause great hardship to assessees who have to be summoned to headquarters for assessment purposes; and

(c) if so, the steps taken by Government in the matter?

THE DEPUTY PRIME MINISTER AND MINISTER OF FINANCE (SHRI MORARJI DESAI) : (a) No, Sir. Only the Income-tax Officer, B-Ward, Hissar, was asked, on 30th October, 1967, to fix hearing of cases of Hansi at his headquarters.

(b) No, Sir. Hansi is situated at a distance of hardly 16 miles from Hissar and is connected with Hissar by regular bus services operating at intervals of less than half an hour.

(c) Does not arise.

हरिजन सेवक समाज

2479. **श्री मोलहू प्रसाद** : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार 'हिन्द स्वीपर सेवक समाज', 'अखिल भारतीय हरिजन सेवक समाज' तथा 'हरिजन सेवक संघ' को अनुदान देती रही है;

(ख) क्या सरकार ने कभी उनके लेखों की लेखापरीक्षा की है ; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

समाज कल्याण विभाग में राज्य मंत्री (श्रीमती फूलरेणु गुहा) : (क) 1966-67 में नीचे बताए गये अनुदान उन्मोचित हुए :—

हिन्द स्वीपर सेवक समाज ।	47,392 रुपये
हरिजन सेवक संघ	4,45,870 रुपये

(ख) केन्द्रीय राजस्व के महालेखाकार, नई दिल्ली, ने हरिजन सेवक संघ के लेखों की लेखा-परीक्षा की है ।

(ग) सहायक अनुदान नियमों के अन्तर्गत महालेखाकार एक लाख से अधिक वार्षिक अनुदान पाने वाले संस्थानों के लेखों की लेखा-परीक्षा करता है ।

अन्य संस्थानों के लेखों की लेखा परीक्षा शासप्राप्त लेखापालों (चारटर्ड अकाऊंटेन्ट्स) द्वारा किये जाने की अनुमति है ।

Bharat Sewak Samaj

2480. SHRI MOLAHU PRASAD : SHRI RAM CHARAN :

Will the Minister of WORKS-HOUSING AND SUPPLY be pleased to state :

(a) whether it is a fact that about 12 rooms of the Theatre Communication Building, Connaught Place, New Delhi, allotted to the Bharat Sewak Samaj are still in its possession;

(b) whether it is also a fact that Bharat Sewak Samaj had wounded up mostly its work from the above building;

(c) whether it is also a fact that the Bharat Sewak Samaj has been sub-letting six rooms of the above building with various agencies for the sake of earning money by unfair means; and

(d) if so, the steps taken against the Bharat Sewak Samaj for getting the premises vacated and preventing it from unauthorised sub-letting without permission of Government?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF WORKS, HOUSING AND SUPPLY (SHRI IQBAL SINGH): (a) The Bharat Sewak Samaj Central Office as well as the Delhi Pradesh Wing are at present occupying 5,902 square feet of accommodation comprising of 20 rooms in the Theatre Communication Building.

(b) We have no precise information as to whether the activities of those sections of the Bharat Sewak Samaj which are located in the Theatre Communication Building have been wound up.

(c) and (d). So far five cases where the Bharat Sewak Samaj had placed rooms or part of rooms allotted to them

in the Theatre Communication Building at the disposal of some other organisations have come to our notice. The allotment of two of such rooms has been cancelled and the Bharat Sewak Samaj have been asked to surrender vacant possession of the same by the 31st December, 1967. In case the Samaj are unable to hand over the complete vacant possession by the above mentioned date, eviction proceedings will be initiated against them under the Public Premises (Eviction of unauthorised Occupants) Act, 1958. In one case, the party concerned has since vacated the accommodation. The other cases are under consideration for regularisation of the allotment/allotment of alternative accommodation in the names of the occupying parties as the parties have made requests on that account.

SEIZURE OF GOLD IN BOMBAY

2481. SHRI P. VISWAMBHARAN :
SHRI S. M. JOSHI :
SHRI J. B. SINGH :
SHRI SHRI CHAND GOEL :
SHRI KAMESWAR SINGH :
SHRI A. SREEDHARAN :

Will the Minister of FINANCE be pleased to state :

(a) whether contraband gold worth Rs. 90 lakhs was seized in Bombay on the 11th October, 1967;

(b) if so, whether some foreigners are involved in this case; and

(c) if so, the details thereof ?

THE DEPUTY PRIME MINISTER AND MINISTER OF FINANCE (SHRI MORARJI DESAI) : (a) On 11th October, 1967 45,000 tolas of gold bearing foreign markings valued at Rs. 44,28,900/- at the international rate was recovered from a spot near the Belapur-Panvel creek near Bombay.

(b) No indication of foreigners being involved has come to light.

(c) Does not arise.

कृषि तथा ग्राम्य अर्थ-व्यवस्था समिति

2482. **श्री महाराज सिंह भारती** क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चौथी योजना के लिए कृषि और ग्राम्य अर्थ व्यवस्था के बारे में श्री हरिश्चन्द्र माथुर की अध्यक्षता में नियुक्त की गई समिति द्वारा इस आशय की जो सिफारिश की गई थी, कि योजना का आकार चाहे कैसा भी हो, योजना के प्रथम तीन वर्षों में 1,000 एकड़ अतिरिक्त भूमि की सिंचाई की जानी चाहिए, उस पर क्या कार्यवाही की गई है; और

(ख) उस समिति द्वारा की गई इस सिफारिश को, कि जिन क्षेत्रों को सिंचाई नदियों अथवा नहरों से नहीं की जा सकती उनका भी सर्वेक्षण किया जाय, कहां तक क्रियान्वित किया गया है ?

सिंचाई तथा विद्युत मंत्री (डा० कु० ल० राव) : (क) चौथी पंचवर्षीय योजना को अन्तिम रूप देते समय इन सुझावों पर योजना आयोग विचार करेगा ।

(ख) विस्तृत सर्वेक्षण कार्य को हाथ में लेने से पूर्व असिंचित क्षेत्रों को निर्धारित करने के लिए आवश्यक आंकड़े इकट्ठे किये जा रहे हैं ।

BARAK DAM PROJECT

2483. SHRIMATI JYOTSNA CHANDA : Will the Minister of IRRIGATION AND POWER be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 7889 on the 3rd August, 1967 and state :

(a) whether the report on the Barak Dam Project has since been submitted;

(b) if so, the recommendations thereof; and

(c) when Government propose to start the work ?

THE MINISTER OF IRRIGATION AND POWER (DR. K. L. RAO) : (a) to (c). The report of the Barak Dam Project has been prepared by the Central Water and Power Commission.

The following alternatives have been recommended in the project report :

(i) A purely Flood control project costing Rs. 25.2 crores and,

(ii) A Multipurpose project for Flood Control and hydropower costing Rs. 39.6 crores.

The report prepared by the Central Water and Power Commission has been referred to two Consultants of the Ministry of Irrigation and Power for their opinion on the project proposals framed by the Commission.

Copies of the project report have also been sent to the State Government for their consideration work on the Project can start only after the project is mooted by the State, approved by the Planning Commission and included in the Plan.

NEW C.G.H.S. DISPENSARIES IN OLD DELHI AREAS

2484. SHRI HARDAYAL DEVGUN : Will the Minister of HEALTH, FAMILY PLANNING AND URBAN DEVELOPMENT be pleased to state :

(a) whether Government are considering any proposal to open new C.G.H.S. Dispensaries in the Old Delhi area as the Government employees residing in those areas are experiencing a lot of difficulty;

(b) if so, when these will be opened and where, locality-wise; and

(c) if not, the reasons therefor ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF HEALTH, FAMILY PLANNING AND URBAN DEVELOPMENT (SHRI B. S. MURTHY) : (a) Yes.

(b) Subject to availability of funds and suitable accommodation for housing the dispensaries, it is proposed to open three new dispensaries in the Corporation area during 1968-69. The location will be decided when the budgetary position is clear.

(c) Does not arise.

GOLD AND JEWELLERY WITH TEMPLES

2485. SHRI BHOGENDRA JHA : Will the Minister of FINANCE be pleased to state :

(a) whether Government have explored the possibility of putting the gold and jewellery in possession of temples into some productive purposes; and

(b) if so, the steps taken in this direction?

THE DEPUTY PRIME MINISTER AND MINISTER OF FINANCE (SHRI MORARJI DESAI) : (a) No Sir. Government have no such proposal under consideration. Temples and public religious institutions have, however, in the past, on their own volition, invested some of their gold and jewellery in National Defence Gold Bonds and other schemes.

(b) Does not arise.

VISHARJAN ASHRAM

2486. SHRI BHOGENDRA JHA : Will the Minister of HEALTH, FAMILY PLANNING AND URBAN DEVELOPMENT be pleased to refer to the reply given to Unstarred Queston No. 4043 on the 29th June, 1967 and state:

(a) whether Government have since taken any decision regarding the demarcation of the respective areas of operation of the American Mission and the Visharjan Ashram;

(b) whether Government are aware that the American Missionaries indulge in activities other than anti-leprosy work; and

(c) if so, whether any investigations have been made in this regard and the result thereof?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF HEALTH, FAMILY PLANNING AND URBAN DEVELOPMENT (SHRI B. S. MURTHY) :

(a) Yes.

(b) Nothing adverse has so far been brought to the notice of Government.

(c) Does not arise.

TAKING OVER OF WESTERN KOSI CANAL

2487. SHRI BHOGENDRA JHA : Will the Minister of IRRIGATION AND POWER be pleased to state :

(a) whether Government have taken any decision regarding the taking over of the Western Kosi canal;

(b) if so, the details thereof; and

(c) if not, the reasons therefor?

THE MINISTER OF IRRIGATION AND POWER (DR. K. L. RAO): (a) No proposal for taking over of the Western Kosi Canal has been under consideration of Government.

(b) and (c). Do not arise.

EXPLORATION IN RAJASTHAN BORDER

2488. SHRIMATI TARKESHWARI SINHA : Will the Minister of PETROLEUM & CHEMICALS be pleased to state :

(a) the country which has been given the contract for oil exploration along the Rajasthan border;

(b) the period for which the contract has been given;

(c) the estimated amount to be spent on the preliminary surveys; and

(d) the amount already spent towards discovering oil in Rajasthan and success achieved so far?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PETROLEUM AND CHEMICALS AND OF SOCIAL WELFARE (SHRI RAGHU RAMAIAH) :

(a) and (b). The following companies conducted surveys and drilling on behalf of O.N.G.C. in the Jaisalmer area of Rajasthan :—

Name of Company	*Name of work*	*Total period of Contract*
1. Institut Franoaise du Petrole	Planning, direction and supervision of exploration work and interpretation and synthesis of field data.	5 years, 8 months and 28 days.
2. Compagnie Generale de Geophysique.	Seismic survey.	3 years and 11 months.
3. -do-	Drilling of tube wells.	1 year and 8 days.
4. Forasol	Structural drilling	2 years, 2 months and 26 days.
5. Societe de Prospection Electrique Schlumberger.	Electrologging and other	2 years, 3 months and 27 days.

(c) The expenditure on the seismic survey had been originally estimated at Rs. 117.32 lakhs.

(d) The total expenditure incurred upto the end of October, 1967 on the exploration work was Rs. 419.21 lakhs approximately. This does not include the investment on fixed assets, stores inventory and other miscellaneous accounts and the element of depreciation on fixed assets.

It is too early to come to any conclusion about the possibility of finding oil/natural gas in commercial quantities.

CONSUMPTION OF ELECTRICITY AND WATER FOR MINISTERS

2489. SHRI N. S. SHARMA :
SHRI SHARDA NAND :
SHRI A. B. VAJPAYEE :
SHRI JAGANNATH RAO JOSHI :

Will the Minister of WORKS, HOUSING AND SUPPLY be pleased to state :

(a) the monthly amount spent on the consumption of water and electricity on each Minister under the Heads 'For Residential Purposes' and 'For Office Pur-

poses' separately both being in the same compound since 1st April, 1967; and

(b) the procedure according to which it is determined whether the water and electricity consumed is for 'Residential purposes' or for 'Office purposes' ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF WORKS, HOUSING AND SUPPLY (SHRI IQBAL SINGH): (a) A statement is laid on the Table of the House. [*Placed in library. See* No. LT—1807/67]

(b) According to the Ministers' Salaries and Allowances Act, 1952, the Ministers/Deputy Ministers are entitled to free supply of electricity and water without any limit. However, the Ministers/Deputy Ministers have agreed to a voluntary ceiling of Rs. 2,400/- per annum for free supply of electricity and water in their residences and to reimburse to Government any expenditure in excess of this ceiling. This ceiling applies to the portion of the residence for private use of the Ministers concerned and not to the portion for official use. The apportionment of the expenditure on electricity and water in the Ministers residences is done as under :—

"Private" use	"Official use
(1)	(2)
(*i*) Consumption in "Private" portion of the residence.	(*i*) Consumption in "office" portion of the residence.
(*ii*) Consumption in servants quarters.	(*ii*) Consumption of electricity for security lights or gate lights.
(*iii*) Consumption of water at dhobi ghats.	(*iii*) Consumption of electricity in the Guard room.

All the Ministers have been requested to have the meters in their residences separated or readjusted suitably, if necessary for apportioning the expenditure as mentioned above.

LIMIT FOR FREE FURNITURE AND ELECTRICAL APPLIANCES FOR MINISTERS

2490. SHRI N. S. SHARMA :
SHRI A. B. VAJPAYEE :
SHRI JAGANNATH RAO JOSHI :

Will the Minister of WORKS, HOUSING AND SUPPLY be pleased to state :

(a) the ceilings upto which a Cabinet Minister, a Minister of State or a Deputy Minister is at present allowed free furniture, electrical goods, water and electricity;

(b) the names of Ministers to whom furniture and electrical appliances worth more than the prescribed limits have been supplied; and

(c) how much amount of rent etc. for the excess furniture and electrical appliances is due in each case?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF WORKS, HOUSING AND SUPPLY (SHRI IQBAL SINGH):

(a) The value of furniture and electrical appliances etc., to be provided free of rent in the residential portion of the Cabinet Ministers/Ministers of State/Deputy Ministers has been fixed as under :—

(i) Cabinet Ministers and Ministers of State.—Rs. 38,500/-.

(ii) Deputy Ministers.—Rs. 22,500.

Under the Salaries and Allowances of Ministers Act, 1952, the Ministers are entitled to free supply of water and electricity in their residences without any limit. However, the Ministers have voluntarily agreed to a monetary ceiling of Rs. 2,400/- per annum on the consumption of water and electricity in the residential portion of their bungalows and to reimburse to Government charges on this account in excess of this ceiling.

(b) if so, when it started functioning; in respect of the present Cabinet for

the period from 1st April, 1967 to 31st October, 1967, is given below :—

Name of the Cabinet Minister/Minister of State/Deputy Minister	Amount of Rent Payable
	Rs.
Shri Fakhruddin Ali Ahmed	563·12
Shri Jagjivan Ram . .	173·54
Shri P. Govinda Menon .	1·19
Shri K. Raghu Ramaiah .	58·19
Shri K. L. Rao . . .	5·23
Shri V. C. Shukla . .	0·64
Shri J. B. Muthyal Rao .	175·38
Shri Bhanu Prakash Singh .	105·38
Shri B. S. Murthy . .	62·53
Shri D. Ering . . .	58·14
Shri Mohd. Shafi Quarashi .	20·19

The bills are being sent to the Ministers concerned for payment.

ANTIBIOTICS PROJECT AT RISHIKESH

2491. SHRI JYOTIRMOY BASU :
SHRI A. K. GOPALAN :
SHRI P. RAMAMURTI :
SHRI NAMBIAR :

Will the Minister of PETROLEUM AND CHEMICALS be pleased to state:

(a) whether the pilot plant of the Antibiotics Project at Rishikesh has started functioning;

(b) if so, when it started functioning;

(c) the total monthly expenditure incurred on the project plant so far; and

(d) the total quantity of material produced in 1967?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PETROLEUM AND CHEMICALS AND OF SOCIAL WELFARE (SHRI RAGHURAMAIAH) :

(a) Yes.

(b) From the 30th October, 1965.

(c) The total expenditure including salaries and services incurred so far on the Pilot Plant is approximately Rs. 10.86 lakhs. The monthly expenditure depends on the number of batches run. For instance, in the month of July, 1967, Rs. 25,000 was spent, while in March, 1967 lbs. 76,000 was spent.

(d) The Pilot plant is not a production unit, it is meant to conduct experiments with improved and new processes and for substitution with indigenous materials in production, as well as to improve the Russian processes to suit Indian conditions. The Pilot Plant has been of considerable help in this regard.

CANADIAN AID

2492. SHRI MARANDI : Will the Minister of FINANCE be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Government of Canada are considering to give bigger loan and more effective assistance to India for agricultural and industrial development;

(b) if so, whether any assessment has been made and to what extent Canada is agreeable to assist India; and

(c) whether any expert from Canada visited India in this regard?

THE DEPUTY PRIME MINISTER AND MINISTER OF FINANCE (SHRI MORARJI DESAI): (a) and (b). The level of assistance to be extended by the Government of Canada to the Government of India for each year is indicated in the Aid India Consortium meetings for considering aid to India from members of the Consortium. For 1967-68, the loan assistance from Canada was C.$ 50.5 million. Indications about the quantum of such assistance for 1968-69 will only be available when the Aid India Consortium meets to consider aid to India for that year.

(c) An Agricultural Task Force from Canada is presently in India reviewing the possibilities of Canada rendering assistance in the field of agriculture.

BUREAU OF VOLUNTEERS FOR CENTRAL SOCIAL WELFARE BOARD

2493. SHRI MARANDI :
SHRI MAYAVAN :

Will the Minister of SOCIAL WELFARE be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Central Social Welfare Board has decided to set up a Bureau of Volunteers;

(b) if so, the main purposes thereof; and

(c) the reasons for setting up the same.

THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF SOCIAL WELFARE (SHRIMATI PHULRENU GUHA): (a) Yes, Sir.

(b) and (c). The Bureau seeks to mobilise effectively the services of Voluntary Workers and to make the same available to Voluntary Social Welfare Organisations. The Voluntary Agencies will be in a better position to serve the people by making available to them the willing services of a band of dedicated workers.

ENGINEERS INDIA LTD.

2494. SHRI VALMIKI CHOUDHARY : Will the Minister of PETROLEUM AND CHEMICALS be pleased to state :

(a) whether Bechtels, the American concern wants to pull out of the Engineers India Ltd.; and

(b) if so, the reasons therefor ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PETROLEUM AND CHEMICALS AND OF SOCIAL WELFARE (SHRI RAGHU RAMAIAH) : (a) The Government of India and Bechtel have by mutual agreement terminated their partnership in Engineers India Ltd. The agreement transferring Bechtel's interests in the company to Government was executed on 14-6-1967.

(b) This was done because the two sides found that the company was not adequately serving their respective aims.

L.I.C. FUNDS

2495. SHRI RANDHIR SINGH : Will the Minister of FINANCE be pleased to state :

(a) whether there is any proposal under consideration to divert Life Insurance Corporation funds for development of minor irrigation works, for agricultural production, slum clearance, cottage industries and house-building for poorer sections of society keeping in view over-all national development;

(b) if so, the salient features thereof; and

(c) if not, the reasons therefor?

THE DEPUTY PRIME MINISTER AND MINISTER OF FINANCE (SHRI MORARJI DESAI) : (a) to (c). LIC's investments are governed by section 27A of the Insurance Act, 1938, as applied to it. There is no proposal under consideration to change these provisions as these are wide enough to cover all avenues of investment from which benefits to the activities enumerated in the question accrue directly or indirectly.

SLUM CLEARANCE AND HOUSE-BUILDING SCHEMES FOR RURAL AREAS

2496. SHRI RANDHIR SINGH : Will the Minister of WORKS, HOUSING AND SUPPLY be pleased to state:

(a) whether Government have any scheme in hand for slum clearance and house-building for poorer sections in the rural areas of our country;

(b) whether any such scheme has been sent to State Governments for implementation;

(c) if so, the details thereof and the reaction of State Governments thereto; and

(d) if not, the reasons therefor?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF WORKS, HOUSING AND SUPPLY (SHRI IQBAL SINGH): (a) to (d). A Scheme called the Village Housing Projects Scheme, introduced in August, 1957, is being implemented in most of the States and Union Territories. It aims at improving the housing conditions and environmental hygiene in rural areas and provides for :

(i) loans to villagers for construction of new houses or improvement of existing ones to the extent of 80% of the cost subject to a maximum of Rs. 3,000 per house—the loan being recoverable in 20 annual equated instalments;

(ii) grants for laying of streets and drains for improvement of

environmental hygiene in the selected villages;

(iii) allotment of house-sites free of cost (or at nominal cost) to landless agricultural workers who are also eligible for loan assistance under the Scheme for construction of their houses;

(iv) establishment of Rural Housing Cells at the State level. The main function of these Cells is to prepare layout plans for the replanning of selected villages and model designs of rural houses besides providing technical advice to villagers in the construction of their houses.

The entire expenditure on the first three programmes and 50% of the expenditure on the pay and allowances of the staff of the Rural Housing Cells is met from Central assistance to State Governments/Union Territories.

The progress reported so far by the various States/Union Territories under the Scheme is as follows :

1. *Houses completed*—35,220.

2. *Streets and Drains*—About 163 Kms. of streets and 44 Kms. drains have been completed in Kerala, Madras, Maharashtra, Mysore and Tripura; 4,800 Kms. of streets have been sanctioned in Bihar. Besides, the work of providing streets and drains has been completed in 99 villages and is in progress in 21 villages in Madhya Pradesh and Himachal Pradesh.

3. *Provision of House-Sites to landless agricultural workers*—10 acres of land have been acquired in Bihar. 228 house-sites have been allotted in Gujarat, Kerala and Mysore.

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के लिए सुविधायें

2497. **श्री बलराज मधोक :** क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अनुसूचित जातियों को दी गई सुविधायें अनुसूचित आदिम जातियों को नहीं दी जाती हैं;

(ख) क्या यह भी सच है कि अनुसूचित जातियों को दी जाने वाली सुविधायें उनके ईसाई अथवा इस्लाम धर्म कबूल कर लेने पर वापिस ले ली जाती हैं परन्तु अनुसूचित आदिम जातियों के लिए धर्म परिवर्तन के बाद भी ये सुविधायें बनी रहती हैं;

(ग) क्या यह भी सच है कि इस लाभ के कारण ईसाई लोग आदिम जातियों के लोगों का धर्म परिवर्तन करने में बहुत सक्रिय हैं; और

(घ) यदि हां, तो स्थिति में सुधार करने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

समाज कल्याण विभाग में राज्य मंत्री (श्रीमती फूलरेणु गुह) : (क) कुछ विकास कार्यक्रम समान हैं, अन्य विभिन्न जातियों की स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार आयोजित किए गए हैं ।

(ख) जी, हां ।

(ग) धर्म परिवर्तन के कारणों के बारे म सरकार के पास कोई सूचना नहीं है ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

दिल्ली में विकसित भूमि की बिक्री

2498. **श्री बलराज मधोक :** क्या निर्माण, आवास तथा पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 15 अगस्त, 1967 से लेकर 15 नवम्बर, 1967 तक की अवधि में दिल्ली विकास प्राधिकरण ने कुल कितनी भूमि का विकास किया तथा कितने प्लाट बेचे ;

(ख) प्लाटों की बिक्री से कितनी राशि वसूल हुई; और

(ग) क्या इससे दिल्ली में जमीन की कीमतें कम हो गई हैं ?

निर्माण, आवास तथा पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (श्री इकबाल सिंह) : (क) भूमि का विकास एक लम्बी प्रक्रिया है तथा इसमें केवल भूमि को समतल करना, सड़कें बनाना,

सीवरेज डालना, बरसाती पानी के लिए नालियां बनाना जैसे कार्य ही शामिल नहीं हैं, अपितु पानी तथा बिजली की व्यवस्था करना आदि भी है। 15 अगस्त, 1967 से 15 नवम्बर, 1967 तक की अवधि में विकासित किये गये क्षेत्र को विशिष्ट रूप से बताना संभव नहीं।

दिल्ली विकास प्राधिकरण ने 15 अगस्त, 1967 से 15 नवम्बर, 1967 तक की अवधि में 501 प्लाट बेचे।

(ख) इन प्लाटों को बेचने से 79,10,839 रुपये प्राप्त हुए थे।

(ग) जी हां। जमीन की कीमतें कम हो रही हैं।

इण्डियन आयल कारपोरेशन

2499. **श्री बलराज मधोक** : क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इंडियन आयल कारपोरेशन के पास भारत में उत्पन्न तेल के वितरण के लिए पर्याप्त संख्या में पैट्रोल पम्प तथा अन्य संसाधन नहीं हैं,

(ख) क्या यह भी सच है कि इन कारणों से ऐसे तेल की बहुत बड़ी मात्रा लागत मूल्य पर भारत में कार्य कर रही विदेशी तेल कम्पनियों को बेची जाती है ;

(ग) क्या यह भी सच है कि यह तेल बेच कर उक्त समवाय भारी लाभ कमा रहे हैं;

(घ) क्या सरकार को भी इन समवायों द्वारा अर्जित लाभ का कुछ अंश मिलता है ; और

(ङ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

पैट्रोलियम और रसायन तथा समाज कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रघुरमैया) : (क) और (ख). देश में उत्पादित तेल के वितरण के लिए काफी फुटकर पैट्रोल पम्प हैं। तो भी, इण्डियन आयल कारपोरेशन के फुटकर पम्पों की संख्या उसके उपलब्ध उत्पाद के मुकाबले में पर्याप्त नहीं हैं। यह एक कारण है कि इण्डियन आयल कारपोरेशन अपने मोटर स्पिरिट के उत्पादन के कुछ अंश को दूसरी तेल कम्पनियों को बेचता है। हाई स्पीड डीजल आयल, जो फुटकर पम्पों द्वारा बेचा गया केवल दूसरा पदार्थ है, इण्डियन आयल कारपोरेशन अपने पम्पों द्वारा बेचता है। इण्डियन आयल कारपोरेशन दूसरी तेल कम्पनियों के फुटकर पैट्रोल पम्पों द्वारा बेच गये अपने मोटर स्पिरिट का शोधनशाला पर लगाये गये मूल्य को वसूल करता है।

(ग) दूसरी तेल कम्पनियां ऐसे विक्रयों पर, जिनकी भारत सरकार के मूल्य सूत्र में व्यवस्था की गई है, सामान्य बिक्री लाभ प्राप्त करती हैं।

(घ) नहीं, सिवाये टैक्सों द्वारा।

(ङ) उस कार्य को करने वाली तेल कम्पनी का फुटकर विक्रय का लाभ मिलता है।

ASSISTANCES TO MADHYA PRADESH

2500. **SHRI MANIBHAI J. PATEL**: Will the Minister of FINANCE be pleased to state :

(a) whether any request has been received from the Madhya Pradesh Government for additional funds for the tribal development blocks during the current year;

(b) if so, the details thereof; and

(c) whether the decision taken in the matter has since been communicated to the Madhya Pradesh Government?

THE DEPUTY PRIME MINISTER AND MINISTER OF FINANCE (SHRI MORARJI DESAI) : (a) Yes, Sir.

(b) The State Government requested for additional funds of the order of Rs. 15 crores spread over a period of 12 years, for a special development programme of the Bhil and Central Gond regions and of Baster district.

(c) The State Government were advised to accommodate as much as possible of the special programme within the

allocations for State Plan and Centrally sponsored schemes, as it is not possible for the Centre to provide any additional amounts outside the Central assistance which is made available for the Plan.

ALL-INDIA AYURVEDIC COUNCIL

2501. SHRI MANIBHAI J. PATEL: Will the Minister of HEALTH, FAMILY PLANNING AND URBAN DEVELOPMENT be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 426 on the 25th May, 1967 and state :

(a) whether the proposed Committee for the establishment of All India Ayurvedic Council has since been set up;

(b) if so, its composition and functions; and

(c) the progress made by the Committee so far?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF HEALTH, FAMILY PLANNING AND URBAN DEVELOPMENT (SHRI B. S. MURTHY) : (a) Yes.

(b) The Committee consists of the following members :—

Chairman

1. Pt. Shiv Sharma M.P.

Members

2. Shri H. G. Vartak.
3. Shri Mohan Lal P. Vyas.
4. Smt. Purabi Mukopadhyaya.

Member (Convenor)

5. Shri R. N. Madhok.

The Committee will examine the details of legislation for setting up a Central Council of Indian Systems of Medicine including Homoeopathy.

(c) The Committee has been asked to submit its report to Government within three months from the date of its first meeting which is proposed to be held on the 4th January, 1968.

LIBERAL OVERDRAFTS BY COMMERCIAL BANKS

2502. SHRI MANIBHAI J. PATEL : Will the Minister of FINANCE be pleased to state :

(a) whether the question of grant of liberal overdrafts by the commercial banks has been examined; and

(b) if so, the decision regarding utilising the banking credits and managements of the banking institutions?

THE DEPUTY PRIME MINISTER AND MINISTER OF FINANCE (SHRI MORARJI DESAI) : (a) Overdrafts are granted by the commercial banks in their discretion depending generally on the credit-worthiness of the borrower. If, however, the question relates to grant of liberal advances, the package of measures announced by the Reserve Bank since July 1967 designed to stimulate the flow of credit into the priority sectors, have been indicated in the answer to Unstarred Question No. 1486 on the 23rd November, 1967.

(b) It is presumed that this refers to the decision regarding social control over banks. Final proposals in this regard will be placed before Parliament soon.

दिल्ली में बस्तियों को मंजूर करना

2503. श्री शशि भूषण वाजपेयी : क्या **निर्माण, आवास तथा पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली विकास प्राधिकार द्वारा दिल्ली में मंजूर की गई बस्तियों को फिर से नामंजूर कर दिया गया है और क्या इस परिवर्तन के फलस्वरूप लोगों को हुई हानि की ओर सरकार का ध्यान दिलाया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

निर्माण, आवास तथा पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (श्री इकबाल सिंह) : (क) और (ख). प्रश्न को कृपया और अधिक स्पष्ट करें क्योंकि इसके वर्तमान रूप से यह स्पष्ट नहीं है कि वास्तव में किसी सूचना की आवश्यकता है ।

नर्मदा बांध

2504. **श्री शशि भूषण वाजपेयी** : क्या सिंचाई और विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन देशों के नाम क्या हैं, जिन्होंने नर्मदा बांध परियोजना के लिये मशीनें तथा वित्तीय और तकनीकी सहायता देने का आश्वासन दिया है; और

(ख) इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

सिंचाई तथा विद्युत मंत्री (डा० कु० ल० राव) : (क) और (ख). सूचना मिली है कि रूस की एक संस्था ने मध्य प्रदेश सरकार को नर्मदा सागर परियोजना के लिए मशीनरी और उपस्कर देने के लिए अपनी सेवायें प्रस्तुत की हैं। किसी भी परियोजना के लिए विदेशी सहायता तभी ली जाती है जब परियोजना तकनीकी रूप से स्वीकार कर ली जाती है और इसके कार्यान्वन के लिए आवश्यक धन-राशि का प्रबन्ध योजना में कर लिया जाता है। मध्य प्रदेश सरकार से नर्मदा सागर परियोजना की पुनरीक्षित रिपोर्ट की प्रतीक्षा की जा रही है।

Drilling at Jwalamukhi

2505. SHRI HEM RAJ : Will the Minister of PETROLEUM & CHEMICALS be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the drilling operations at Jawalamukhi have been given up and there are several buildings both at Sapri (Jawalamukhi) and Jawalamukhi proper belonging to the department; and

(b) if so, the use to which these buildings are being put to?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PETROLEUM AND CHEMICALS AND OF SOCIAL WELFARE (SHRI RAGHU RAMAIAH) : (a) Yes, Sir. The buildings in question belong to the Oil and Natural Gas Commission.

(b) The residential quarters at Jawalamukhi are unoccupied. At Sapri, the sheds are being utilised for storage etc. of the equipment and the residential quarters are occupied by the Staff of the Oil & Natural Gas Commission engaged in the storage and maintenance of the Rig and Equipment and its despatch to other areas.

Tea Standards

2506. SHRI HEM RAJ : Will the Minister of HEALTH, FAMILY PLANNING AND URBAN DEVELOPMENT be pleased to state :

(a) whether it is a fact that samples of green and black tea of Kangra and Dehra Dun were taken for the fixation of tea standards under the Prevention of the Food Adulteration Act; and

(b) if so, the results thereof?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF HEALTH, FAMILY PLANNING AND URBAN DEVELOPMENT (SHRI B. S. MURTHY) : (a) The Indian Standards Institution who are undertaking work of formulating standards for black and green tea for inclusion under the Prevention of Food Adulteration Rules 1955 had considered available data regarding Kangra and Dehra Dun Teas.

(b) On the basis of the analytical results of the Indian Standards Institution, the Central Committee for Food Standards have recommended amendment of the existing standards for tea so as to cover both varieties of tea, namely, green as well as black. The recommendation is being examined by Government.

Admission of Patents in Willingdon Hospital, New Delhi

2507. SHRI SHARDA NAND :
SHRI JAGANNATH RAO JOSHI :

Will the Minister of HEALTH, FAMILY PLANNING AND URBAN DEVELOPMENT be pleased to state :

(a) whether it is a fact that in the Willingdon Hospital, New Delhi, admission is granted to patients only if they have a certain minimum income;

(b) if so, the details of rules governing admissions of patients;

(c) whether Government have received any complaints in this regard; and

(d) if so, the action taken thereon?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF HEALTH, FAMILY PLANNING AND URBAN DEVELOPMENT (SHRI B. S. MURTHY) : (a) Admission to General Wards is free irrespective of any income. Only in case of admission to Paying Wards and Nursing Home the minimum income is Rs. 251 and 501 respectively.

(b) Extracts of rules 3, 4 and 5 governing admission of patients in the Willingdon Hospital is laid on the Table of the House. [*Placed in library See* No. LT—1808/67.]

(c) No. There are 56 beds in the Nursing Home and 24 in the Special Wards. Admission is made in the order in which applications are received from the patients. Emergent cases are admitted without reference to applications.

(d) Does not arise.

नई दिल्ली में मोतीबाग में दुकानों का अलाटमेंट

2508. **श्री शारदानन्द :** क्या **निर्माण, आवास तथा पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मोती बाग, नई दिल्ली में सरकारी दुकानों का अलाटमेंट झुग्गी झोंपड़ी योजना के अन्तर्गत किया गया है;

(ख) रामकृष्णपुरम में सरकारी दुकानों का अलाटमेंट किन नियमों के अनुसार किया गया है ;

(ग) क्या यह भी सच है कि रामकृष्णपुरम के बहुत-से अलाटियों ने पगड़ी के रूप में बहुत अधिक राशि लेकर सरकारी दुकानों का कब्जा दूसरे लोगों को दे दिया है; और

(घ) यदि हां, तो ऐसे कदाचारों को रोकने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

निर्माण, आवास तथा पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (श्री इकबाल सिंह) : (क) जी नहीं ।

(ख) रामकृष्णपुरम में दुकानों का आरंभिक नियतन विभिन्न व्यवसायों में प्रतिनिधित्व के संतुलन को तथा सम्बन्धित आबंटी की क्षमता को ध्यान में रखते हुए किया गया था । बाद में दुकानों का आवंटन टेंडर के आधार पर किया गया ।

(ग) और (घ). दुकानों को सबलैट करने के मामले सरकार के नोटिस में समय-समय पर आये हैं । इन मामलों में निम्नांकित कार्यवाई की गयी :—

(i) जब दुकान तीसरी पार्टी को सबलैट कर दी जाती है तथा सबलैटी नियमतीकरण के लिए सरकार के पास आता है तो बाजार के प्रशासन के लिए वर्तमान निदेशों के अनुसार दुकान का नियमतीकरण उसके पक्ष में कर दिया जाता है, बशर्ते कि वह यह स्थापित कर दे कि वह दुकान उसके दखल में है, कोई बकाया किराया शेष नहीं है, तथा दुकान के लिए निर्धारित बाजार किराये के साथ उसका 50 प्रतिशत और के बराबर लाइसेंस फ़ीस देने को तैयार है ।

(ii) उन मामलों में जिनमें कि सरकार इस निर्णय पर पहुंचती है कि वास्तव में दुकान तीसरी पार्टी को सबलैट कर दी गयी है तथा सबलैटी दुकान के नियमतीकरण के लिए नहीं आता तो आवंटन रद्द कर दिया जाता है तथा पब्लिक प्रेमिसेज (एविक्शन आफ़ अनआथराइज्ड आक्यूपैन्ट्स) एक्ट, 1958 के अन्तर्गत बेदखली की कार्यवाही की जाती है ।

(iii) दुकानों का उसके दखलकारों के द्वारा तीसरी पार्टी को हस्तान्तरित करना व्यापार की एक सामान्य प्रथा है तथा बाजार के प्रशासन के लिए निर्देशों में इसकी समुचित व्यवस्था है ।

Assistance to West Bengal

2509. **SHRI K. HALDAR :** Will the Minister of FINANCE be pleased to state :

(a) whether the West Bengal Government have made a representation to

the Centre seeking financial assistance to meet the deficit caused largely by its commitment in respect of enhanced dearness allowance to its employees and relief work;

(b) if so, whether the Centre would provide the help; and

(c) if not, the reasons therefor?

THE DEPUTY PRIME MINISTER AND MINISTER OF FINANCE (SHRI MORARJI DESAI) : (a) Yes, sir.

(b) and (c). Since the cost of the State administration ought to be met by the State Government themselves, the Centre has not agreed to provide any assistance to the State Government towards the expenditure on account of enhanced dearness allowance to their employees. So far as relief works are concerned, the Centre will provide the necessary assistance, to the extent the expenditure conforms to the conditions laid down in the existing system of sharing of the expenditure by the Centre.

सिन्धु नदी पर बांध

2510. **श्री यशवन्त सिंह कुशवाह** : क्या सिंचाई तथा विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मगरौनी के निकट सिन्धु नदी पर बान्ध बनाने और मध्य प्रदेश में ग्वालियर कमिश्नरी क्षेत्र में हरसी बांध को पानी पहुंचाने के लिये सरकार द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन का सरकार ने वित्तीय सहायता देने की दृष्टि से अध्ययन कर लिया है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

सिंचाई तथा विद्युत् मंत्री (डा० कु० ल० राव) : (क) मध्य प्रदेश सरकार ने अक्तूबर, 1966 में सिन्ध नदी पर एक व्यपवर्तन वियर के द्वारा ग्वालियर के हरसी बांध जलाशय में पानी की कमी को दूर करने के लिये एक स्कीम प्रस्तुत की थी । इस स्कीम की जांच केन्द्रीय जल तथा विद्युत् आयोग में की गई और फरवरी, 1967 में राज्य सरकार के पास टिप्पणियां भेज दी गईं थीं । इन टिप्पणियों के उत्तर अभी तक प्राप्त नहीं हुए हैं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

Accommodation Rules

2511. SHRI M. L. SONDHI :
SHRI VISHWANATHA MENON :
SHRI NAMBIAR :
SHRI SATYA NARAIN SINGH :
SHRI P. RAMAMURTI :

Will the Minister of WORKS, HOUSING AND SUPPLY be pleased to state :

(a) whether Government propose to lay on the Table a copy of the rules defining the local limits of areas for eligibility of Government accommodation from General Pool Accommodation in Delhi;

(b) the date when the rules were first made and the date when these were last amended;

(c) whether it is a fact that the Central Government employees working in offices/installations in Delhi Cantonment are not considered eligible for allotment of General Pool residence under the control, of the Directorate of Estates, New Delhi under the above rules; and

(d) if so, the name of the authority who will make arrangements for Government accommodation for Central Government employees working in offices/installations in Delhi Cantonment Area?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF WORKS, HOUSING AND SUPPLY (SHRI IQBAL SINGH) : (a) and (b). The provision contained in clause (e) under SR-317-B-2 of the Allotment of Government Residences (General Pool in Delhi) Rules, 1963 is reproduced below :—

> "*S.R.*-317-*B*-2(e)—'eligible office' means a Central Government Office the staff of which has been declared by the Central

Government as eligible for accommodation under these rules".

In accordance with the powers conferred on the Government under this rule, the Government of India laid down the criteria for declaring Central Government offices as 'eligible offices' for purposes of allotment of general pool accommodation in Delhi/New Delhi vide letter No. 3/39/63-Acc.I, dated 31st January, 1964, a copy of which is laid on the Table of the House. [*Placed in library see* No. LT—1809/67.]

Prior to coming into being of Delhi Municipal Corporation the allotment from the general pool was made to employees of such offices which were located within the jurisdiction of New Delhi Municipal Committee/Delhi Municipal Committee. Consequent on the formation of Delhi Municipal Corporation the Government reviewed the position and fixed the limits for Delhi/New Delhi for purposes of allotment of residential accommodation from the general pool in March, 1962. These limits have not been revised thereafter.

The employees working in offices located in Delhi Cantonment were neither eligible for general pool accommodation according to the provisions contained in the Allotment Rules, 1950 nor they have been declared eligible under the new rules which came into force from 15th May, 1963.

(c) Yes.

(d) The Ministry of Defence provides accommodation for civilian Government employees paid out of the Defence Services Estimates to the extent of 15% of the sanctioned strength of civilians in Key Location Plan and non-key location plan units at Delhi Cantonment. The Ministry of Defence have drawn up a scheme for a provision of 449 residential units for such civilian staff. Air Headquarters also propose to provide married accommodation for Civilian staff numbering 144 belonging to Air Force Central Accounts Office and Air Force Record Office which have been shifted to the Cantonment area.

ACCOMMODATION FOR GOVERNMENT EMPLOYEES IN DELHI CANTONMENT

2512. SHRI M. L. SONDHI : Will the Minister of WORKS, HOUSING AND SUPPLY be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Central Government employees serving in Delhi Cantonment area are not being allotted quarters as there is acute shortage of accommodation there;

(b) if so, the reasons for not sharing shortage by all the Central Government employees;

(c) whether Government propose to make the Central Government employees of Delhi Cantonment area eligible for allotment during the current year; and

(d) if not, the reasons therefor ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF WORKS, HOUSING AND SUPPLY (SHRI IQBAL SINGH) : (a) to (d). For purposes of allotment of the general pool accommodation in Delhi/New Delhi, the Government have fixed certain limits and Central Government offices located beyond these limits have not been declared as 'eligible offices'. The Government servants working in ineligible offices are not eligible for allotment of accommodation from the general pool. As the offices located in Delhi Cantt. and other areas are beyond the limits of Delhi/New Delhi fixed for purposes of allotment of residential accommodation, the question of treating those Government employees working in such offices, as eligible for allotment of general pool accommodation, does not arise at present on account of existing acute shortage of residential accommodation.

ALLOTMENT OF QUARTERS IN RAMAKRISHNA PURAM AREA

2513. SHRI M. L. SONDHI : Will the Minister of WORKS, HOUSING AND SUPPLY be pleased to state :

(a) whether 2,500 Quarters in Rama Krishna Puram area are due to be allotted to the Government employees;

(b) if so, now many quarters have been allotted from the 18th October, 1967 so far; and

(c) if not, the reasons therefor?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF WORKS, HOUSING AND SUPPLY (SHRI IQBAL SINGH): (a) to (c). 1784 quarters in types II-IV were ready but could not be allotted as water supply and electricity were not made avaliable by the Corporation and Delhi Electric Supply Undertaking respectively. The Corporation have since laid the pipe line and it has been decided to make these quarters ready for allotment without electricity, A phased programme has been drawn up for making these quarters ready for allotment and in the month of November, 488 quarters have been handed over to the Directorate of Estates and have been allotted to eligible Government servants. Another 376 quarters will be allotted in December, 1967. The remaining 920 quarters are expected to be ready for allotment shortly thereafter.

साउथ एवेन्यू, नई दिल्ली में झुग्गियां

2514. **श्री राम सिंह अयरवाल:** क्या **निर्माण, आवास तथा पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि साउथ एवेन्यू, नई दिल्ली में धोबियों की झुग्गियों को गिरा दिया गया है परन्तु उनको कोई वैकल्पिक स्थान नहीं दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार का विचार उनको वैकल्पिक स्थान कब देने का है ?

निर्माण, आवास तथा पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (श्री इकबाल सिंह): (क) से (ग). साउथ एवेन्यू में अधिकांशत: धोबियों द्वारा दखल की गयी 46 अनधिकृत झुग्गियां 26 अक्तूबर, 1967 को गिराई गयीं। झुग्गी झोंपड़ी हटाने की योजना के अन्तर्गत 15 परिवारों को मदनगिरि में वैकल्पिक वास दे दिया गया था। शेष परिवार योजना के अन्तर्गत वैकल्पिक वास के पात्र नहीं थे।

SILVER TRADE

2515. SHRI J. B. SINBH :
SHRI KAMESHWAR SINGH :
SHRI A. SREEDHARAN :

Will th Minister of FINANCE be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Reserve Bank of India is going to take over the silver trade; and

(b) if not, the reasons therefor ?

THE DEPUTY PRIME MINISTER AND MINISTER OF FINANCE (SHRI MORARJI DESAI) : (a) No, Sir.

(b) Trading in silver is not one of the legitimate statutory functions of a central banking institution like the Reserve Bank of India.

अस्पृश्यता मानने के मामले

2516. **श्री ओ० प्र० त्यागी:** क्या **समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि ग्रामों में अभी हरिजनों के साथ अछूतों जैसा व्यवहार किया जा रहा है;

(ख) 1 अप्रैल, 1965 से 31 मार्च, 1967 के बीच पुलिस के पास अस्पृश्यता सम्बन्धी कितनी शिकायतें आईं और कितने मामलों में लोग दोषी पाये गये तथा उनको दण्ड दिया गया ?

समाज कल्याण विभाग में राज्य मंत्री (श्रीमती फूलरेणु गुह): (क) और (ख). सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

Mosquito Menace in New Delhi Areas

2517. SHRI VASUDEVAN NAIR : Will the Minister of HEALTH, FAMILY PLANNING AND URBAN DEVELOPMENT be pleased to state :

(a) whether the mosquito menace is on the increase in New Delhi areas; and

(b) if so, the steps taken to fight the menace ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF HEALTH, FAMILY PLANNNG AND URBAN DEVELOPMENT (SHRI B. S. MURTHY) : (a) and (b). There is no increase in the mosquito menace in the New Delhi area. However, there is always seasonal increase in mosquito breeding especially during monsoon and spring season due to increased domestic breeding. Mosquito breeding is being kept under control by intensive anti-larval and anti-adult measures. All the slum areas and most of the houses are sprayed with D.D.T., etc., to control the nuisance.

Anti-Begging Legislation

2518. SHRI SHRI CHAND GOEL : Will the Minister of SOCIAL WELFARE be pleased to state :

(a) the latest position prevalent in each State/Union Territory in the country in respect of the enforcement of anti-beggary Legislation;

(b) the steps taken or proposed to be taken to bring uniformity in whole of the country;

(c) the main difficulties which have to be surmounted in the matter of complete and proper enforcement of anti-beggary laws in different States/Union territories;

(d) the steps taken or proposed to be taken to overcome them; and

(e) the target date fixed by which complete enforcement of such laws is scheduled to be achieved ?

THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF SOCIAL WELFARE (SHRIMATI PHULRENU GUHA) : (a) A statement is laid on the Table of the House. [*Placed in Library. See* No. LT—1810/67]

(b) No steps have been taken and none are under immediate contemplation.

(c) and (d). Lack of resources have presented the main difficulty.

(e) It is not possible to fix any target date.

Reorganisation of Income-tax Depatrment

2519. SHRI D. C. SHARMA : Will the Minister of FINANCE be pleased to state :

(a) the steps taken to reorganise the Income-tax Department with the phased introduction of the system of functional distribution under which assessment is being separated from collection; and

(b) the progress made in this regard ?

THE DEPUTY PRIME MINISTER AND MINISTER OF FINANCE (SHRI MORARJI DESAI): (a) and (b). The functions of an Income-tax Officer can be classified broadly as falling under Administration, assessment and collection. All these functions were being performed by one Income-tax Officer in respect of one assessee. The purpose of the reorganisation is to separate these functions and entrust them to different officers. As a result of the reorganisation these functions were separated and are performed by different Officers. The Income-tax Officer-Administration performs all administrative functions; one or two Income-tax Officers (depending on the volume of work) attend to collection and the other Income-tax Officers deal exclusively with assessments.

The functional distribution was introduced in 64 ranges of Assistant Commissioners with effect from 1st July, 1967 and covers roughly ranges which collect 50% of the tax. This scheme has been extended to ranges which consist of atleast 8 officers.

PRIVATE RESOURCES FOR CONSTRUCTION OF HOUSES

2520. SHRI D. C. SHARMA : Will the Minister of WORKS, HOUSING AND SUPPLY be pleased to state :

(a) whether the question of attracting private resources for the construction of houses in the country has been considered;

(b) if so, with what results;

(c) whether it is proposed to set up a national council for regional and urban development; and

(d) if so, the details thereof ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF WORKS, HOUSING AND SUPPLY (SHRI IQBAL SINGH) : (a) and (b). Yes. The matter was considered at the Conference of the Ministers of Housing, Town Planning and Urban Development held at Madras recently. A statement giving extracts of the recommendations, on the subject, made by the Conference is laid on the Table of the House. [*Placed in Library See* No. LT-1811/67.]

These recommendations will be processed in consultation with the concerned Central Ministries and authorities and the Governments of the States and the Administrations of Union Territories.

(c) No.

(d) Does not arise.

DEGENERATION DISEASES IN INDIA

2521. SHRI D. C. SHARMA : Will the Minister for HEALTH, FAMILY PLANNING AND URBAN DEVELOPMENT be pleased to state :

(a) whether it is a fact that degeneration diseases are spreading rapidly in India;

(b) if so, whether Government have looked into the causes of these diseases;

(c) whether it is also a fact that these diseases are on the increase due to lack of milk, butter and ghee; and

(d) if so, whether Government propose to encourage the increased use of these articles ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF HEALTH, FAMILY PLANNING AND URBAN DEVELOPMENT (SHRI B. S. MURTHY) : (a) There is no study or other evidence to indicate a rapid spread of degeneration diseases in India;

(b) Adverse effects of malnutrition tend to produce degeneration diseases.

(c) Of the various types of nutritional deficiencies, protein-calorie malnutrition has been found to be mainly responsible for causing such diseases.

(d) A coordinated approach towards the problem of malnutrition is being undertaken by the various Departments of the Government with the help of international agencies. This comprises supplementary feeding programmes amongst the vulnerable sections, production of nutritious processed food and is distribution, increased production of food in every possible manner, nutrition, education and extension, applied nutrition programmes and treatment and screening of early cases of malnutrition. The following measures are adopted to improve the level of nutrition among children :

(1) Supplementary feeding is provided through the following programmes which are run with the aid of various agencies :—

(i) Feeding under the Applied Nutrition Programme;

(ii) Feeding through Balwadis;

(iii) CARE feeding programme; and

(iv) UNICEF milk feeding programme.

(2) Imparting nutrition education to the mothers to enable them to utilise commonly available cheap foods for providing nutritious diet to their children.

(3) Treatment of early cases of malnutrition through M.C.H. Centres.

(4) The Department of Food have taken steps to combat protein malnutrition among children and other

vulnerable groups by starting projects for the manufacture of high-protein foods such as : 'BALAHAR',

MULTIPURPOSE FOOD AND WEANING FOOD.

INCREASE IN BANK RATE BY BANK OF ENGLAND

2522. SHRI D. C. SHARMA : Will the Minister of FINANCE be pleased to state :

(a) whether the Bank of England has raised its interest rate to six per cent from 19th October, 1967; and

(b) what will be its impact on the Indian economy ?

THE DEPUTY PRIME MINISTER AND MINISTER OF FINANCE (SHRI MORARJI DESAI) : (a) The Bank of England raised the bank rate from 5½ per cent to 6 per cent on 19, October 1967 and subsequently to 6½ per cent on 9th November and further to 8 per cent on 18th November.

(b) Changes in U.K. Bank rate mainly affect the Indian economy in respect of interest payable on official loans, movement of banking funds and India's exports to the U.K. Interest payable on future, withdrawals of loans out of the unutilised portions of the authorisation prior to October 1965 would increase. Authorisations after October 1965 are completely free of interest. The inflow of banking capital may be lower. The rise in the cost of credit in the U.K. consequent to the rise in the Bank rate may lead to slight fall in the demand for India's exports for stock holding purposes. The rise in the U.K. Bank rate will not affect India's outstanding payment obligations and flow of official loans from the U.K.

AMERICAN BANKING AND INDUSTRIAL EXECUTIVE VISIT TO INDIA

2523. SHRI MAYAVAN : Will the Minister of FINANCE be pleased to state :

(a) whether it is a fact that a team of American banking and industrial executives visited India during November, 1967;

(b) if so, the main purpose of their visit; and

(c) the subjects discussed by them with the Indian Government; and

(d) whether any report has been submitted by them ?

THE DEPUTY PRIME MINISTER AND MINISTER OF FINANCE (SHRI MORARJI DESAI) : (a) No. Sir.

(b) to (d). Do not arise.

SMALL POX

2524. SHRI MAYAVAN :

SHRI CHENGALRAYA NAIDU :

Will the Minister of HEALTH FAMILY PLANNING AND URBAN DEVELOPMENT be pleased to state :

(a) whether it is a fact that experts have declared that small pox will break out in the epidemic form in the country in 1968; and

(b) if so, the reaction for Government thereto; and

(c) the steps proposed to be taken to meet this threat ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF HEALTH, FAMILY PLANNING AND URBAN DEVELOPMENT (SHRI B. S. MURTHY) :

(a) Yes, according to the epidemiology of small pox, the year 1968 is likely to be a cyclic period for the next epidemic.

(b) and (c). The National Smallpox Eradication Programme is already in operation throughout the country. An All-India Smallpox Workers Conference was held in September, 1967 for considering the various preventive measures which should be taken to meet the situation arising out of the threatened outbreak of smallpox epidemic in 1968. The important recommendations for the said Conference are given below :—

(i) The vaccination drive against smallpox should be intensified by raising the strength of vaccinators.

(ii) High priority should be given for covering slum areas, migratory and labour population.

(iii) Necessary legislation and model bye-laws be framed for adoption by the States and local bodies to make primary and re-vaccination compulsory.

(iv) For the proper implementation of the National Smallpox Eradication Programme, the vaccinators and other health staff engaged in the programme should be under the administrative and technical control of the health departments.

The recommendations of the Conference which were endorsed by the Central Council of Health at its meeting held on 3rd to 5th October, 1967, have been forwarded to the State Governments for taking necessary action thereon.

Apart from supplying to-date about 700 million doses of smallpox freeze-dried vaccine, free of cost to the States, Central assistance to the extent of Rs. 887.75 lakhs has been given to the States for implementation of the National Smallpox Eradication Programme, upto 1966-67. An smallpox Cell in the Directorate General of Health Services gives technical advice and guidance to the States for the Programme.

GRANT FOR ORISSA

2525. SHRI RABI RAY : Will the Minister of WORKS, HOUSING AND SUPPLY be pleased to state :

(a) whether Orissa Government have asked him for financial assistance for building houses for those whose houses have been completely damaged by the recent cyclone in the State;

(b) if so, the amount demanded; and

(c) the action taken by Government thereon ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF WORKS, HOUSING AND SUPPLY (SHRI IQBAL SINGH) : (a) Yes.

(b) Rs. 6 crores.

(c) My Ministry has no specific scheme for housing in cyclone affected areas. But the allocations made under the social housing schemes can be utilised for any area at the discretion of the State Governments. For the year 1967-68, the Government of Orissa have provided a sum of Rs. 24.4 lakhs in their Annual Plan for the implementation of the various social housing schemes. Further, in consideration of the extensive damages caused by the recent cyclone in Orissa, an amount of Rs. 100 lakhs has been allocated as loan to the State Government out of L.I.C. funds for construction of houses under approved schemes during 1967-68 as against Rs. 60 lakhs of L.I.C. funds advanced during 1966-67.

GOVERNMENT HOTELS

2526. SHRI RABI RAY : Will the Minister of WORKS, HOUSING AND SUPPLY be pleased to state :

(a) the number of hotels being run by this Ministry and the amount which has so far been invested in these hotels; and

(b) the amount of profit earned by these hotels during the last three years ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF WORKS, HOUSING AND SUPPLY (SHRI IQBAL SINGH) :

(a) and (b) : Four

These are :

(i) The Ashoka Hotel, New Delhi, run by the Ashoka Hotels Limited.

(ii) Hotel Janpath
(iii) Ranjit Hotel, and
(iv) Lodhi Hotel

} run by the Janpath Hotels Limited.

The amounts invested in these companies are :

	Investment in share capital		Total	Loans		Total
	Upto 31-3-67	From 1-4-67 to-date		Upto 31-3-67	From 1-4-67 to-date	
	(In lakhs of Rupees)					
Ashoka Hotels Ltd.	134·15	60·00	194·15	27·00	60·00	87·00
Janpath Hotels Ltd.	18·50	1·50	20·00	15·27	1·50	16·77

	1964-65	1965-66	1966-67
	(In lakhs of Rupees)		
Ashoka Hotel	(+)41·47	(+)25·05	(+)27·49
Hotel Janpath	(+) 4·39	(+) 2·35	(+) 2·43
Ranjit Hotel	Started functioning on 7-11-1965	(—) 1·37	(—) 3·56
Lodhi Hotel	Started functioning on 15-9-1965	(—) 1·34	(—) 2·46

(+) = profit
(—) = loss

DRINKING WATER SUPPLY IN HIMACHAL PRADESH

2527. SHRI PREM CHAND VERMA : Will the Minister of HEALTH, FAMILY PLANNING AND URBAN DEVELOPMENT be pleased to state :

(a) whether any schemes for making adequate provision for drinking water supply in Himachal Pradesh for the next year has been submitted by Himachal Pradesh Government for Centre's approval;

(b) if so, details thereof; and

(c) the amount which will be provided by the Central Government and how much will be made available by the Government of Himachal Pradesh?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF HEALTH, FAMILY PLANNING AND URBAN DEVELOPMENT (SHRI B. S. MURTHY) : (a) to (c). The Information is being collected and will be laid on the Table of the Sabha.

HYDEL PROJECT IN HIMACHAL PRADESH

2528. SHRI PREM CHAND VERMA : Will the Minister of IRRIGATION AND POWER be pleased to state :

(a) whether there is a scheme for a Hydel project in Himachal Pradesh between Kulu and Manali which has been sanctioned by the Central Government;

(b) if so, when the work on this project is likely to start and how long it would take to complete the scheme;

(c) the estimated cost on the scheme and whether the total amount will be spent by the Centre or the Himachal Pradesh Government will have to share it; and

(d) the extent of power to be generated and irrigation potential?

THE MINISTER OF IRRIGATION AND POWER (DR. K. L. RAO) : (a) to (d). The Government of Himachal Pradesh have been requested to investigate in detail the potential hydro power sites available between Kulu & Manali in the Uppar Beas Valley. The ques-

tion of sanctioning the project will be considered after the investigations are complete and the project is finalised.

PHYSICAL VERIFICATION OF GODOWNS

2529. SHRI PREM CHAND VERMA : Will the Minister of WORKS, HOUSING AND SUPPLY be pleased to state :

(a) whether the physical verification of godowns belonging to his Ministry has been undertaken during the last four months;

(b) if so, whether shortages were discovered and the quantity of each material which was found short; and

(c) the action taken against the staff responsibile for the custody and whether any persons were arrested and prosecuted or departmental action taken against them?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF WORKS, HOUSING AND SUPPLY (SHRI IQBAL SINGH) : (a) Yes.

(b) Only minor discrepencies were noticed. These are under reconciliation/investigation in the respective units.

(c) The discrepancies are being looked into and the question of taking suitable action will be considered wherever necessary.

SEIZURE OF SMUGGLED GOODS NEAR BOMBAY HARBOUR

2530. SHRI PREM CHAND VERMA :
SHRI BIBHUTI MISHRA :
SHRI MADHU LIMAYE :

Will the Minister of FINANCE be pleased to state :

(a) whether it is a fact that on the 24th August, 1967 three foreign boats carrying goods silver bars, nylon, blades, foreign currency and travellers cheques were apprehended by the Customs Officials near Bombay harbour;

(b) whether it is also a fact that the smugglers offered considerable resistance before surrender;

(c) the value of goods seized and the countries from which the smuggling was indulged and whether any foreigners were arrested; and

(d) the action taken in the matter?

THE DEPUTY PRIME MINISTER AND MINISTER OF FINANCE (SHRI MORARJI DESAI) : (a) Yes, Sir. The boats were apprehended on the 25th August, 1967.

(b) Smugglers in one of the boats offered some resistance.

(c) Foreign exchange worth £20,350 and U.S.A. $5,656 was seized from one boat. Silver ingots valued at Rs. 6,68,109 were seized from the second boat. Foreign cigarettes, blades and nylon yarn totally valued at Rs. 3,51,500 were seized from the third boat. The foreign exchange and silver ingots were intended for export to Persian Gulf areas and the other goods were smuggled from Dubai. Twenty-four foreigners were arrested.

(d) As stated in reply to part (c), the goods have been seized. Besides, the three foreign mechanised sailing vessels have also been seized. Adjudication proceedings are being initiated.

The crew members, 33 in all (24 foreigners and 9 Indians) and 2 local Indian fishermen found in one of the vessels were arrested and were released on bail. All these persons are being prosecuted in a court of law.

COST OF PRODUCTION OF GOLD IN KOLAR GOLD MINES

2531. SHRI VIRENDRA KUMAR SHAH : Will the Minister of FINANCE be pleased to state :

(a) the reasons for the increase in the cost of production of gold produced per ounce at the Kolar Gold Mines from Rs. 367 in 1961 to Rs. 450 in 1966-67;

(b) the reasons for the decline in output of gold at the Kolar Gold Mines from 1,36,498 ounces to 91,500 ounces during the above period;

(c) the difference between the international price for gold and the cost of production of gold in India;

(d) whether the Government have implemented the recommendations of the Cost Reduction Committee appointed in 1963 at the Kolar Gold Mines; and

(e) the achievement in concrete terms in the field of cost reduction as a result of implementation of those recommendations?

THE DEPUTY PRIME MINISTER AND MINISTER OF FINANCE (SHRI MORARJI DESAI): (a) and (b). The fall in the output of gold and the rise in the cost of production at Kolar Gold Mines during 1966-67 as compared to 1961-62 have been caused by the following factors :

Production of gold :

(1) There was a fall in the average grade of ore milled (from 7.64 grammes per metric tonne in 1961-62 to about 7 grammes per metric tonne in 1966-67).

(2) There was a shortage in the tonnage of ore milled, which was due to adverse mining conditions caused by natural calamities etc., the more important of which are enumerated below :—

(i) Major rockbursts took place on 26-11-1962 in the Champion Reef Mine, affecting the whole of Glen Ore Shoot and the Southern Ore body of the mine —these Sections were contributing about 40 to 50 per cent of the gold produced in this mine. An outbreak of a major fire occurred in the Northern Folds Section of the Champion Reef Mine resulting in sealing of the area from July, 1965 to February, 1966. There were 3 short fires again in 1966-67 in this mine. Further, due to unprecedented rain during September—November, 1966, the mines were flooded. In December, 1966 due to ground movement, the sub auxiliary shaft and the associated levels were damaged by a series of rockbursts. The effect of all these natural calamities in the Champion Reef Mine has been to cause a fall in the production of ore.

(ii) The Mysore Mine is a very old mine with limited reserves and mining of ore in this has had to be restricted on account of various technical considerations.

(iii) The Nundydroog Mine, which has large deposits of ore but of comparatively low grade, suffered a set-back in production of ore as during 1965-66 there was an accident to No. 2 Auxiliary Shaft in the mine, and during 1966-67 the unprecedented rains resulted in flooding of parts of the mine.

Costs :

(i) Increase in the wages and dearness allowances of the employees.

(ii) Rise in the costs of materials *e.g.* costs of Cyanide & granite have gone up by over 50% since 1962.

(iii) Distribution of the fixed overhead charges over a smaller output of gold, in arriving at the costs.

(c) The cost of production of gold at Kolar Gold Mines during 1966-67 was Rs. 241.38 per ounce more than the present international price of gold (Rs. 262.50 per ounce).

(d) Yes, Sir. Out of the 7 recommendations made by the Cost Reduction Committee, 5 have already been implemented and one (relating to the setting up of the Central Workshops) is in the process of implementation. Regarding the recommendation for revision of the basis of accident pay and sick benefits, the dearness allowance paid in addition to the Accident Pay computed under Workmen's Compensation Act has been frozen at the rate that was admissible on the 31st March, 1965.

(e) The implementation of the cost reduction measures referred to meant a saving of Rs. 70.90 lakhs in revenue expenditure during 1965-66, as compared to 1963-64. Of this, approximately Rs. 60 lakhs was due to the reduction in the staff expenditure.

Eye Bank Movement

2532. SHRI YASHPAL SINGH : Will the Minister of HEALTH, FAMILY PLANNING AND URBAN DEVELOPMENT be pleased to state :

(a) whether it is a fact that eye-bank movement has made very slow progress;

(b) if so, whether any assessment has been made to find out the causes for the same; and

(c) the measures contemplated to popularise the donation of eyes?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF HEALTH, FAMILY PLANNING AND URBAN DEVELOPMENT (SHRI B. S. MURTHY) : (a) Yes.

(b) The main difficulty is about getting donors.

(c) The measures in practice and contemplated are :

(i) publicity of the working of eye banks;

(ii) appeals for donation of eyes; and

(iii) introduction of legislation, where such legislation does not exist, for facilitating the donation of eyes by an individual through a will.

As a result of the recommendation of the Central Council of Health, commended to State Governments, for taking up legislation and educational activity in the interest of corneal grafting, legislation on corneal grafting now exists in 12 States and two Union Territories *viz.*, Andhra Pradesh, Bihar, Gujarat, Haryana, Kerala, Madhya Pradesh, Madras Maharashtra, Orissa, Punjab, Uttar Pradesh, West Bengal, Delhi and Himachal Pradesh. Other States are expected to follow suit.

ALLOTMENT OF GOVERNMENT ACCOMMODATION 'OUT OF TURN' BASIS

2533. SHRI YASHPAL SINGH: Will the Minister of WORKS, HOUSING AND SUPPLY be pleased to state :

(a) whether Government has again started the allotment of residential accommodation to its employees on the 'out-of-turn' basis; and

(b) if so, the reasons therefor?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF WORKS, HOUSING AND SUPPLY (SHRI IQBAL SINGH): (a) and (b). Out-of-turn allotment to eligible Central Government employees is governed by the Allotment of Government Residences (General Pool in Delhi) Rules, 1963. The allotments on out-of-turn basis are being made to eligible employees on very compassionate grounds in deserving cases.

CONSTRUCTION OF BIG BUILDING IN PUBLIC SECTOR

2534. SHRI YASHPAL SINGH: Will the Minister of WORKS, HOUSING AND SUPPLY be pleased to state :

(a) whether Government have decided to stop the construction of big buildings in the public sector; and

(b) if so, the reasons therefor?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF WORKS, HOUSING AND SUPPLY (SHRI IQBAL SINGH) : (a) No.

(b) Does not arise.

DEVELOPMENT OF INDIGENOUS SYSTEM OF MEDICINE DURING FOURTH PLAN

2535. SHRI CHANDRA SHEKHAR SINGH : Will the Minister of HEALTH, FAMILY PLANNING AND URBAN DEVELOPMENT be pleased to state :

(a) the steps which are being taken by Government to encourage and develop the indigenous system of medicine during the Fourth Plan period;

(b) the total allocation provided for its development in the first two years of the Fourth Plan; and

(c) the amount spent so far?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF HEALTH, FAMILY PLANNING AND URBAN DEVELOPMENT (SHRI B. S. MURTHY) : (a) Promotion of the Indigenous system of Medicine is a continuing process and development is taking place on the lines already set.

(b) and (c). The total allocation and the expenditure incurred on the development of Indigenous Systems of Medicine including Nature Cure and Homoeo-

pathy during 1966-67 and 1967-68 so far, are given below :—

	1966-67		1967-68	
	Allocation	Expenditure	Allocation	Expenditure
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.
(*i*) Purely Central Schemes	33,59,300	21,72,548·65	34,50,000	9,36·360 (Upto 25-11-67)
(*ii*) Centrally Sponsored Schemes	5,00,000	1,75,000·00	7,00,000	(Figures not yet available)

As regards the Centrally Aided Schemes in these systems, the Central assistance is released through Ways and Means Advances for a group of schemes, and separate figures of expenditure are not available.

FOREIGN TOURS BY OFFICIALS

2536. SHRI SAMAR GUHA : Will the Minister of FINANCE be pleased to state :

(a) the expenditure incurred, in terms of foreign exchange and Indian currency, for covering the visits of officials of the Central Government abroad during the period from 1962 to 1967 up-to-date and the amount separately spent by officials of different Ministries;

(b) the purpose for which these officials went on tour to foreign countries;

(c) who are the officials who visited the foreign countries several times a year and which countries they visited; and

(d) whether in view of huge expenditure incurred on official tours abroad, Government propose to set up an expert committee to investigate into questions of justifiability of these foreign tours and formulate a fresh regulation to restrict and control foreign tours by the officials of the Central Government?

THE DEPUTY PRIME MINISTER AND MINISTER OF FINANCE (SHRI MORARJI DESAI) : (a) The information regarding foreign exchange expenditure is given in the statement laid on the Table of the House. [*Placed in Library*. See No. LT-1812/67.]

The information regarding expenditure in Indian currency is being collected and will be laid on the Table of the House as soon as it is available.

(b) The information is given in the statement laid on the Table of the House. [*Placed in Library*. *See* No. LT-1812/67.]

(c) The information is being collected and will be laid on the Table of the House as soon as it is available.

(d) All proposals for deputation of Government officials abroad are strictly scrutinised by a Committee of senior Secretaries and ordinarily only such deputations are permitted as are unavoidable or are likely to lead to substantial saving in foreign exchange or relate to the Defence effort or to training requirements. In the circumstances it is not proposed to set up another expert Committee to go into the question.

दिल्ली रेलवे स्टेशन पर ब्लेडों और फाउन्टेन पैनों का पकड़ा जाना

2537. श्री प्र० न० सोलंगी : क्या वित्त मंत्री 6 जुलाई 1967 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4713 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अप्रैल, 1967 के अन्तिम सप्ताह में दिल्ली स्टेशन पर पकड़े गये स्टेनलैस स्टील के बने विदेशी ब्लेडों तथा फाउन्टेन पैनों के बारे में सरकार ने इस बीच जांच पूरी कर ली है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो यह जांच कब तक पूरी हो जायेगी ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) जी, हां ।

(ख) इस मामले में की गई जांच-पड़ताल से यह पता नहीं चला कि यह माल भारत में किस देश से चोरी-छिपे लाया गया था । लेकिन ब्राण्ड से पता चलता है कि पकड़े गये ब्लेड ब्रिटेन के बने हैं और फाउन्टेन पेन चीन के बने हैं । माल पूरी तरह से जब्त कर लिया गया है ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता है ।

मद्रास में पकड़ा गया सोना

2538. **श्री प्र० न० सोलंकी** : क्या **वित्त** मंत्री 6 जुलाई, 1967 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4834 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मद्रास में पकड़े गये सोने के मामले में छानबीन इस बीच पूरी हो गई है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इस काम में और कितना समय लगने की संभावना है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) जी, हां ।

(ख) जांच पड़ताल से पता चला है कि इस मामले में पकड़ा गया सोना, सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 के उपबन्धों का उल्लंघन करके विदेशों से चोरी छिपे भारत में लाया गया था । मामले का अभी विभागीय न्याय-निर्णय हो रहा है ।

(ग) यह प्रश्न ही नहीं उठता ।

जबलपुर में पकड़ा गया सोना

2539. **श्री हुकमचन्द कछवाय** : क्या **वित्त** मंत्री 27 जुलाई, 1967 के अतारांकित प्रश्न संख्या 6911 के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जबलपुर में सोना पकड़े जाने के मामले में कार्यवाही इस बीच पूरी हो चुकी है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि हां, तो इसमें और कितना समय लगने की संभावना है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) अदालत ने अभी इस मामले का फैसला नहीं दिया है ।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) अदालती मामला पूरा होने के बाद ही विभागीय न्यायनिर्णय की कार्यवाही की जायेगी ।

गोहाटी के निकट पकड़ी गई अफीम

2540. **श्री हुकमचन्द कछवाय** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अगस्त, 1967 के पूर्वार्द्ध में आयकर अधिकारियों ने गोहाटी के निकट जागी रोड से 81 किलो अफीम पकड़ी है;

(ख) यदि हां, तो यह अफीम किस स्थान से लाई गई थी; और

(ग) इस बारे में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) असम आबकारी विभाग के अधिकारियों ने 4 अगस्त 1967 को गोहाटी से करीब 32 मील दूर जागी रोड में एक मोटरकार को रोका और उसमें से 81 किलोग्राम अफीम बरामद की ।

(ख) यह सन्देह किया जाता है कि पकड़ी गयी अफीम उत्तर प्रदेश में बरेली से ले जायी गयी थी ।

(ग) अफीम तथा मोटर कार को पकड़ लिया गया और चार व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया । मामले की जांच-पड़ताल अभी भी चल रही है ।

कलकत्ता में सोना पकड़ा जाना

2541. **श्री हुकमचन्द कछवाय** : क्या वित्त मंत्री 27 जुलाई, 1967 के अतारांकित प्रश्न संख्या 6913 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कलकत्ता में सीमाशुल्क अधिकारियों ने जिस पार्टी से सोना पकड़ा था उसको दिये गये कारण-बताओ नोटिस पर इस बीच क्या कार्यवाही की गई है; और

(ख) यदि कोई कार्यवाही नहीं की गई है तो इसमें और कितना समय लगने की संभावना है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) और (ख): इस मामले में तीन पार्टियों को, अर्थात् (1) इन पोस्ट पार्सलों को भेजने वाली बम्बई की फर्म को, (2) कलकत्ते की जिस फर्म से सोना पकड़ा गया उसको, तथा (3) कलकत्ते की फर्म के एक साझीदार को कारण-बताओ नोटिस जारी किये गये थे जिनका उत्तर कलकत्ते की फर्म से तथा बम्बई की फर्म से तो प्राप्त हो गया है परन्तु कलकत्ते की फर्म के साझीदार ने कारण-बताओ नोटिस का जवाब पेश करने की मियाद को 6 दिसम्बर 1967 तक लाने की प्रार्थना की है । उसके उत्तर की प्रतीक्षा की जा रही है । उसका उत्तर प्राप्त होते ही मामले को न्याय-निर्णय के लिये हाथ में ले लिया जायगा ।

RESEARCH ON YOGA

2542. SHRI P. K. DEO : Will the Minister of HEALTH, FAMILY PLANNING AND URBAN DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) whether the All India Institute of Medical Sciences has been making research on Yoga and its effects on human body and mind; and

(b) if so, the result thereof?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF HEALTH, FAMILY PLANNING AND URBAN DEVELOPMENT (SHRI B. S. MURTHY) : (a) Yes.

(b) While a very large number of practising *Yogis* have been investigated only a very few have shown interesting results like capacity to control involuntary activities, cut down metabolic activity and be to some extent independent of peripheral stimulation.

More studies have to be done before any definite conclusions can be drawn. But this is difficult since response from well practised *Yogis* to offer themselves for laboratory tests is poor.

MEDICAL LIBRARY IN DELHI

2543. SHRI CHENGALRAYA NAIDU : Will the Minister of HEALTH, FAMILY PLANNING AND URBAN DEVELOPMENT be pleased to state :

(a) the total expenditure involved in setting up a National Medical Library at the All India Institute of Medical Sciences, New Delhi;

(b) whether Government have any proposal under consideration to the effect that regional medical libraries should be attached to the regional post-graduate medical education and Research Centres;

(c) if so, the estimated expenditure involved in the scheme; and

(d) when they are likely to be set up?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF HEALTH, FAMILY PLANNING AND URBAN DEVELOPMENT (SHRI B. S. MURTHY) : (a) The estimated cost of the project is about Rs. 50.00 lakhs.

(b) to (d). No scheme for the establishment of Regional Medical Libraries has yet been made out.

PROGRESS OF FAMILY PLANNING IN RAJASTHAN

2544. SHRI D. N. PATODIA : Will the Minister of HEALTH AND FAMILY PLANNING be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the progress of family planning programme has not been satisfactory in Rajasthan;

(b) if so, the reasons therefor;

(c) the amount of assistance given to the State Government for the implementation of this programme during the last two years; and

(d) whether it is a fact that the funds allocated to the State for 1965-66 and 1966-67 could not be utilised fully?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HEALTH, FAMILY PLANNING AND URBAN DEVELOPMENT (DR. S. CHANDRASEKHAR) : (a) The progress of Family Planning Programme in Rajasthan was not satisfactory during 1966-67, but the State is now making steady progress.

(b) Shortage of trained doctors and other technical staff, high percentage of illiteracy etc. were amongst the reasons for the slow progress.

(c) The central assistance for the years 1965-66 and 1966-67 to Rajasthan was Rs. 23.32 and Rs. 43 lakhs respectively.

(d) While the central assistance could not be fully utilised during the year 1965-66, it was fully utilised during the year 1966-67.

EXPLORATION IN RAJASTHAN

2545. SHRI D. N. PATODIA : Will the Minister of PETROLEUM AND CHEMICALS be pleased to state :

(a) the number of drilling operations which have been undertaken by M/s FORASOL of Assam in Rajasthan for locating oil so far;

(b) the number of cases in which the drilling operations have yielded positive results;

(c) the number of drilling operations that are likely to be made during 1967-68;

(d) whether a seismic survey has been made of the entire State; and

(e) if so, the likely prospects of oil in the State of Rajasthan with their locations?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PETROLEUM AND CHEMICALS AND OF SOCIAL WELFARE (SHRI RAGHU RAMAIAH) : (a) This is "restricted information" under Defence of India Rules, 1962.

(b) In one of the wells drilled, indications of the presence of Natural gas were obtained.

(c) This is "restricted information" under Defence of India Rules, 1962.

(d) No, Sir, only of parts of the State.

(e) It is too early to give any definite conclusion on this point.

MANUFACTURE OF ORAL CONTRACEPTIVE PILLS IN INDIA

2546. SHRI D. N. PATODIA : Will the Minister of HEALTH AND FAMILY PLANNING be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Government propose to manufacture oral contraceptive pills in India;

(b) if so, whether any plans have been drawn up in this regard;

(c) whether any aptitude survey has been conducted to find out the acceptibility of the pills; and

(d) if so, the findings thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HEALTH, FAMILY PLANNING AND URBAN DEVELOPMENT (DR. S. CHANDRASEKHAR) : (a) Not for the present.

(b) Does not arise.

(c) and (d). The Indian Council of Medical Research has carried out a few studies on oral contraceptives. The report thereof is laid on the Table of the House. [*Placed in Library. See* No. LT-1813/67.]

RESERVE BANK'S PLAN FOR ASSISTANCE TO FARMERS

2547. SHRI D. N. PATODIA :
SHRI RANDHIR SINGH :

Will the Minister of FINANCE be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Reserve Bank of India has formulated a plan for giving necessary assistance to farmers to mechanise their agricultural operations;

(b) if so, the broad details thereof; and

(c) when it is likely to be implemented?

THE DEPUTY PRIME MINISTER AND MINISTER OF FINANCE (SHRI MORARJI DESAI) : (a) to (c). The Reserve Bank has not formulated any scheme of direct assistance to farmers for the purpose. However, the Reserve Bank, as also the Agricultural Refinance Corporation, supports the debenture programme of land mortgage banks, which advance long term loans for the purchase of agricultural machinery such as tractors, power tillers, pump sets and other costly farm equipment. The Industrial Development Bank a subsidiary of the Reserve Bank, also provides refinance facilities to commercial banks financing sales of agricultural implements on deferred payment terms. Under the latter scheme, there is no minimum amount for a transaction, the maximum being Rs. 50 lakhs in respect of a single purchaser over a year. The maximum period of deferred payment is 7 years.

VENEREAL DISEASES CONTROL IN INDIA

2548. SHRI V. NARASIMHA RAO: Will the Minister of HEALTH, FAMILY PLANNING AND URBAN DEVELOPMENT be pleased to state :

(a) the plan from which the Venereal Diseases Control Programme started and total expenditure incurred during each Plan up to 1967-68;

(b) the number of States which have undertaken venereal diseases control measures in India; and

(c) the number of Venereal Diseases Clinics receiving 'P.A.M.' medicine from the Director General of Health Services to meet their requirements?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF HEALTH, FAMILY PLANNING AND URBAN DEVELOPMENT (SHRI B. S. MURTHY) : (a) The Venereal Diseases Control Programme was started from the First Five Year Plan.

During the First Five Year Plan a provision of Rs. 3.26 lakhs was made for the establishment of an Antigen Production Unit. The provision was fully utilised. During subsequent Plans, the following provision was made :—

Second Plan	..	Rs. 95.71 lakhs
Third Plan	..	Rs. 58.24 lakhs

The following Central assistance has been released to the States for this programme during the years 1966-67 and 1967-68 :

1966-67	..	Rs. 11.00 lakhs
1967-68	..	Rs. 10.50 lakhs

As the Programme was classified as Centrally-aided from the Second Five Year Plan onwards, the actual expenditure incurred by the States in connection with the implementation of the Programme is not known.

(b) 16 States/Union Territories undertook V.D. Control Programme in India during the Second Plan. During the Third Plan 9 States/Union Territories implemented the Programme.

(c) The number of V.D. Clinics receiving 'PAM' from the Government of India is as under :—

Second Plan	..	100 Clinics
Third Plan	..	142 lakhs

(continuing)

PARAFFIN WAX

2549. SHRI J. N. HAZARIKA : Will the Minister of PETROLEUM AND CHEMICALS be pleased to state :

(a) the total quantity of paraffin wax produced in the country, refinery-wise;

(b) the total requirement at present;

(c) the quantity exported annually;

(d) the foreign exchange earned by its export during the years from 1963-64 to 1966-67; and

(e) whether any import has also been allowed in lieu of export earnings?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PETROLEUM AND CHEMICALS AND OF SOCIAL WELFARE (SHRI RAGHU RAMAIAH) : (a) Only one refinery (*viz.*, the Assam Oil Company's Refinery at Digboi) produces Paraffin Wax. The production in 1967 is estimated at 36,000 tonnes approx.

(b) Annual Demand is of the order of 41,000 tonnes.

(c) 5,000 tonnes approx. in 1967.

(d)

Years	Rs./lakhs
1963	68·03
1964	63·38
1965	59·18
1966	65·27
1967 (upto Oct.) . . .	37·19

(e) No, Sir.

सरकारी क्वार्टरों की मरम्मत

2550. **श्री रामावतार शर्मा** : क्या **निर्माण, आवास तथा पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के क्वाटरों में कितने समय बाद मरम्मत तथा सफेदी की जाती है;

(ख) पिछली बार इन क्वाटरों की मरम्मत तथा सफेदी किस तारीख को की गई थी;

(ग) क्या यह सच है कि गत पांच वर्षों से इन क्वाटरों की न तो मरम्मत की गई है और न ही सफेदी और बहुत से क्वाटरों की हालत खराब होने के कारण उनमें ताले लगे हुए हैं; और

(घ) यदि हां, तो इस मामले में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

निर्माण, आवास तथा पूर्ति मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री इकबाल सिंह) : (क) से (घ) : जब कभी आवश्यकता होती है सरकारी क्वार्टरों की मरम्मत की जाती है । सफेदी सामान्यत: प्रति वर्ष की जाती है किन्तु 1962 तथा 1965 के दौरान चीनी तथा पाकिस्तानी आक्रमण के परिणामस्वरूप सरकार के द्वारा लगाई गई रोक के कारण एक वर्ष से अधिक समय तक यह नहीं कराई गई । तथापि, अधिकांश क्वार्टरों में अन्तिम बार सफ़ेदी आदि अप्रैल 1966 से मार्च 1967 के दौरान की गयी थी । केवल उन क्वार्टरों को खाली कराया गया है जिनकी आयु पूरी हो चुकी है तथा जिन्हें ख़तरनाक घोषित किया जा चुका है । इनमें से अधिकांश को गिरा दिया गया है तथा शेष में गिराये जाने तक ताला लगा दिया गया है ।

INDIRECT TAXES

2551. SHRI S. R. DAMANI : Will the Minister of FINANCE be pleased to state :

(a) whether there is any proposal to appoint an enquiry committee to go into the question of existing pattern of indirect taxes and to suggest suitable modification within the overall policy of Government; and

(b) if so, the details thereof?

THE DEPUTY PRIME MINISTER AND MINISTER OF FINANCE (SHRI MORARJI DESAI) : (a) and (b). Some time back the Government have appointed Shri S. Boothalingam, formerly Secretary, Ministry of Finance, as One-Man Committee for recommending measures for simplifying and rationalising the existing structure of Direct and Indirect Taxes. Its report regarding Indirect Taxes is still awaited.

APPELLATE TRIBUNAL FOR CUSTOMS AND CENTRAL EXCISE APPEALS

2552. SHRI S. R. DAMANI : Will the Minister of FINANCE be pleased to state :

(a) whether a proposal to set up an appellate tribunal for hearing customs and central excise appeals is under consideration of Government; and

(b) if so, the decision taken thereon?

THE DEPUTY PRIME MINISTER AND MINISTER OF FINANCE (SHRI MORARJI DESAI) : (a) and (b). In so far as the Customs appeals are concerned, certain proposals in this behalf have been made by the Customs Study Team appointed by the Government and the same are under consideration at present.

As regards Central Excise appeals, at present no proposal to this effect is under consideration.

बिहार में जीवन बीमा निगम का कार्यालय

2553. **श्री रामावतार शर्मा** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जीवन बीमा निगम ने बीमे को काम-काज बढ़ाने की दृष्टि से पटना नगर में 1961 में एक शाखा कार्यालय स्थापित किया था;

(ख) क्या पटना नगर शाखा कार्यालय ने प्रथम वर्ष में ही 70 लाख रुपये का काम किया जो कि बाद में 1965-66 में बढ़ कर 1.30 करोड़ रुपये हो गया;

(ग) क्या पश्चिमी पटना में एक पृथक कार्यालय कार्य कर रहा था; और

(घ) यदि हां, तो पटना नगर शाखा कार्यालय को 1966 में पश्चिमी पटना में स्थानान्तरित करने का क्या औचित्य था और क्या सरकार का विचार पटना नगर शाखा कार्यालय पुनः खोलने का है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) से (ग). जी हां।

(घ) कार्यालय को वर्तमान जगह पर इसलिए स्थानान्तरित किया गया है कि यह जगह व्यवसाय की उन्नति के लिये अधिक उपयुक्त समझी जाती है तथा (कार्यालयी) कर्मचारियों और क्षेत्रीय (कार्यकारी) कर्मचारियों के लिये सुविधाजनक भी। पटना नगर के क्षेत्र में रहने वाले पालिसीधारियों को कोई असुविधा न होने देने की दृष्टि से उनको शहरी क्षेत्र के सभी अनुसूचित बैंको के जरिये अपनी किस्तें जमा कराने की सुविधा दी गयी है।

TAXES DUE FROM SHRI RAM RATTAN GUPTA

2554. SHRI RABI RAY : Will the Minister of FINANCE be pleased to state :

(a) the total amount of taxes to be paid to the Central Government by Shri Ram Rattan Gupta of Kanpur on different counts; and

(b) the details thereof?

THE DEPUTY PRIME MINISTER AND MINISTER OF FINANCE (SHRI MORARJI DESAI) : (a) The total amount of taxes outstanding for payment against Shri Ram Rattan Gupta in his personal assessments is Rs. 36,678.

	Rs.
(b) Income-tax . . .	36,428·00
Penalty for Non-payment of Tax	250·00
TOTAL .	36,678·00

PUBLICITY INDUSTRY

2555. SHRI RAM KISHAN GUPTA : Will the Minister of FINANCE be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 7761 on the 3rd August, 1967 and state :

(a) whether Government have since considered the request of the National Book Development Board regarding adding books as an item under the Fifth Schedule of the Income-tax Act to afford necessary facilities for the growth of publicity industry; and

(b) if so, the result thereof ?

THE DEPUTY PRIME MINISTER AND MINISTER OF FINANCE (SHRI MORARJI DESAI) : (a) The request of the National Book Development Board is still being considered by the Government.

(b) Does not arise.

PALANA LIGNITE POWER PROJECT

2556. SHRI AMRIT NAHATA : Will the Minister of IRRIGATION AND POWER pleased to state :

(a) whether Government have received the scheme report for the installation of Palana Lignite Power Project from the Rajasthan Government;

(b) if so, whether Government have agreed to include the Palana Lignite Power project in the Fourth Five Year Plan; and

(c) if not, the reasons thereof ?

THE MINISTER OF IRRIGATION AND POWER (DR. K. L. RAO) : (a) Pending detailed exploration of the lignite reserves at Palana, the Government of Rajasthan were requested to prepare and submit scheme report for the installation of one 50 MW Unit or alternatively two units of 30 MW each. The scheme report is still awaited.

(b) and (c). Do not arise.

PETRO-CHEMICAL CORPORATION

2557. SHRI K. LAKKAPPA : Will the Minister of PETROLEUM AND CHEMICALS be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 4489 on the 27th April, 1966 and state :

(a) whether the decision to set up the Petro-Chemical Corporation has since been taken; and

(b) if so, the broad features thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PETROLEUM AND CHEMICALS AND SOCIAL WELFARE (SHRI RAGHU RAMAIAH) : (a) and (b). No Sir. The matter is still under consideration.

पिछड़े वर्गों सम्बन्धी आयोग

2558. **श्री राम सेवक यादव** : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार पिछड़े वर्ग के लोगों की आर्थिक और सामाजिक स्थिति की जांच करने के लिए एक आयोग नियुक्त करने का है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या उनके मंत्रालय ने प्रथम आयोग के प्रतिवेदन के बाद से ऐसे लोगों की स्थिति के बारे में कोई सर्वेक्षण कराया है; और

(घ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम और रसायन तथा समाज कल्याण मंत्री (श्री अशोक मेहता) : (क) नहीं ।

(ख) सरकार ने पिछड़ापन निश्चित करने के लिये आर्थिक-कसौटी को स्वीकार कर लिया है । देश के समस्त विकास-प्रयत्न का लक्ष्य है कि जन-गण का जीवन-स्तर ऊपर उठाया जाये; खास तौर पर जन समूह के कमजोर अंगों का ।

(ग) नहीं ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

IMPLEMENTATION OF IRRIGATION PROJECTS IN MYSORE STATE

2560. SHRI K. LAKKAPPA : Will the Minister of IRRIGATION AND POWER be pleased to state :

(a) whether any financial aid is proposed to be provided in the Fourth Five Year Plan to implement any major and medium irrigation projects in Mysore State;

(b) if so, the name of the projects that are under contemplation in the plan; and

(c) when the work is likely to start ?

THE MINISTER OF IRRIGATION AND POWER (DR. K. L. RAO) : (a)

The Fourth Five Year Plan has not yet been finalised.

(b) and (c). Do not arise.

दिल्ली में क्वार्टरों का अलाटमेंट

2561. **श्री क० प्र० सिंह देव :**
श्री कृ० मा० कौशिक :

क्या **निर्माण, आवास तथा पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय दिल्ली में कितने कर्मचारियों को सरकारी क्वार्टर दिये गये हैं और कितने कर्मचारियों को अभी तक क्वार्टर नहीं मिले है ;

(ख) उन कर्मचारियों की संख्या कितनी है जिनके पास राजधानी में अपने निजी मकान हैं और जिन्होंने सरकारी क्वार्टर भी ले लिये हैं;

(ग) क्या यह सच है कि जिन कर्मचारियों के पास राजधानी में अपने मकान हैं, वे सरकारी क्वार्टरों को दुगुने अथवा चौगुने किराये पर लगा देते हैं; और

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार ऐसे कर्मचारियों को क्वाटरों का अलाटमेंट बन्द करने का है, ताकि जिन कर्मचारियों को अभी तक क्वार्टर नहीं मिले हैं, उनको क्वार्टर दिये जा सकें ?

निर्माण, आवास तथा पूर्ति मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री इकबाल सिंह) : (क) दिल्ली में सामान्य पूल में उपलब्ध वास में से दिल्ली/नयी दिल्ली में 39,357 पात्र सरकारी कर्मचारियों को निवास स्थान आवंटित किया जा चुका है तथा 6०,788 आवंटन की प्रतीक्षा में हैं ।

(ख) सरकारी निवास स्थानों (दिल्ली में सामान्य पूल) के आवंटन के वर्तमान 1963 के नियमों में उपबन्धों के अनुसार वे सरकारी कर्मचारी जिनके पास अपने मकान हैं सामान्य पूल से उसी सामान्य किराये को देने पर, जो कि उन सरकारी कर्मचारियों पर लागू है जिनके पास अपने मकान नहीं हैं, निवास-स्थान के पात्र हैं । जिन सरकारी कर्मचारियों के पास अपने मकान हैं तथा जिन्होंने सरकारी निवास स्थान का आवंटन स्वीकार कर लिया है, उनके सम्बन्ध में संपदा निदेशालय कोई आंकड़े नहीं रखता ।

(ग) और (घ). संपदा निदेशालय में प्राप्त क्वार्टरों की सबलेटिंग के सम्बन्ध में शिकायतों में यह उल्लिखित नहीं होता कि आवंटी के पास राजधानी में अपना मकान है । किन्तु कुछ मामलों में जांच के दौरान यह पता चला कि आवंटी या तो गाजियाबाद अथवा गुडगांव के निकट और कुछ मामलों में झुग्गियों में रह रहे थे । इस समय, उन सरकारी कर्मचारियों को जिनके पास अपने मकान हैं, सामान्य पूल में से आवंटन रोक देने का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

NEW MEDICAL COLLEGES IN FOURTH PLAN

2562. SHRI CHINTAMANI PANIGRAHI : Will the Minister of HEALTH, FAMILY PLANNING AND URBAN DEVELOPMENT be pleased to state :

(a) whether the proposal to open 25 new Medical Colleges during the Fourth Plan has materialised;

(b) if so, to what extent; and

(c) whether there is any request from Orissa Government to start any new medical college in the State during the Fourth Plan ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF HEALTH, FAMILY PLANNING AND URBAN DEVELOPMENT (SHRI B. S. MURTHY) : (a) and (b). Out of 25 new Medical Colleges proposed in the draft Fourth Five Year Plan, five Medical Colleges have already been opened.

(c) The Government of Orissa do not propose to start any new Medical College during the Fourth Plan.

MYSORE FINANCE MINISTER'S TOUR ABROAD

2563. SHRI J. H. PATEL: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the Finance Minister of Mysore State went on a tour abroad with the Chairman, Mysore State Industrial Investment and Development Corporation; and

(b) if so, what was the purpose of that tour and the foreign exchange allowed to him?

THE DEPUTY PRIME MINISTER AND MINISTER OF FINANCE (SHRI MORARJI DESAI): (a) Yes, Sir.

(b) It was a business-*cum*-study trip related to certain projects in which the State Government was either directly participating or was keenly interested. The total period of stay abroad was 6 weeks. For maintenance, foreign exchange equivalent to Rs. 150/- per day was sanctioned. In addition, foreign exchange equivalent to Rs. 750/- was given as entertainment expenses.

मध्य प्रदेश में बिजली की खपत

2564. **श्री ग० च० दीक्षित** : क्या सिंचाई और विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि समूचे भारत में बिजली की जितनी औसत खपत है इसकी तुलना में मध्य प्रदेश में बिजली की की औसत खपत बहुत ही कम है;

(ख) यदि हां, तो इस के क्या कारण हैं; और

(ग) इस खपत को अखिल भारतीय औसत के बराबर लाने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

सिंचाई तथा विद्युत् मंत्री (डा० कु० ल० राव) : (क) जी, हां ।

(ख) मध्य प्रदेश समेत कुछ राज्यों में बिजली की प्रति व्यक्ति खपत के कम होने का मुख्य कारण यह है कि वे आर्थिक दृष्टि से कम विकसित हैं ।

(ग) देश के उन क्षेत्रों के आर्थिक विकास में तेजी लाने के लिये चौथी योजना के दौरान विशेष प्रयत्न किये जाने हैं जो बहुत कम विकसित हैं ।

मध्य प्रदेश में गन्दी बस्तियां

2565. **श्री ग० च० दीक्षित** : क्या **निर्माण, आवास तथा पूर्ति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश सरकार ने गन्दी बस्तियों के हटाने के सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार को कोई योजना भेजी है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

निर्माण, आवास तथा पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (श्री इकबाल सिंह) : (क) और (ख) . राज्य सरकारों को यह आवश्यक नहीं कि गंदी बस्तियों की सफ़ाई तथा सुधार की परियोजनाओं को स्वीकृति के लिए भारत सरकार को प्रस्तुत करें । स्वयं राज्यों के द्वारा अथवा उनकी निर्माण एजेंसियों के द्वारा बनाई गयी ऐसी परियोजनाओं को स्वीकृत करने के लिए वे सक्षम हैं । योजना के अन्तर्गत उनके द्वारा किये गये खर्चे के आधार पर उन्हें प्रतिवर्ष केन्द्रीय सहायता दी जाती है ।

BOARD OF CONCILIATION FOR TROMBAY FERTILIZER FACTORY

2566. SHRI GEORGE FERNANDES: Will the Minister of PETROLEUM AND CHEMICALS be pleased to state:

(a) whether a Board of Conciliation has been appointed by the Government of Maharashtra to make recommendations on certain demands of the employees of the Trombay Unit of the Fertilizer Corporation of India;

(a) Yes.

(b) if so, its terms of reference;

(c) who represents the Fertilizer Corporation of India on the Board;

(d) the stage at which the proceedings are before the Board; and

(e) whether there has been any protest against the nomination of an official from New Delhi to serve on the Board of conciliation in Bombay ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PETROLEUM AND CHEMICALS AND OF SOCIAL WELFARE (SHRI RAGHU RAMAIAH) : (a) Yes, Sir.

(b) The Board of Conciliation has been constituted for promoting a settlement of the industrial dispute connected with the following matters :

(i) Dearness allowance on the following basis shall be paid with retrospective effect from 1st January 1966 :—

	D.A. as C.P.I. 531—540	Variatkion for every 10 points of the C.P.I
Basic pay :		
1st 100 . .	185%	5%
2nd 100 . .	97%	2½%
3rd 100 . .	47%	1¼%

The minimum dearness allowance payable shall be 100% of the revised textile scale, Bombay, for all the days of the month.

(ii) What interim relief, if any, should be given to the workmen ?

(c) The Industrial Relations Adviser.

(d) The Board held several meetings but no agreement could be arrived at. Later, the management negotiated further with the representatives of the Union and agreed to pay to each workman Rs. 125 upto 30-11-67 and Rs. 16 per month with effect from 1-12-67, both as advance to be adjusted against the amount to be finally determined as payable in accordance with constitutional methods. The workers have agreed not to resort to strike, go-slow tactics, etc. etc. in order to obtain such a decision.

(e) Yes, Sir. A communication to this effect was received by the Management of the Corporation to which a suitable reply was sent by the Management.

HINDUSTAN INSECTICIDES

2567. SHRI GEORGE FERNANDES : Will the Minister of PETROLEUM AND CHEMICALS be pleased to refer to the reply given to Starred Question No. 1729 on 10th August, 1967 and state :

(a) whether the inquiry into the allegations made against the management of Hindustan Insecticides Ltd., New Delhi has since been completed;

(b) if so, the result thereof; and

(c) action taken against the delinquents ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PETROLEUM AND CHEMICALS AND OF SOCIAL WELFARE (SHRI RAGHU RAMAIAH) : (a) to (c). Government have carefully examined the seven points raised in the memorandum. In respect of two of them—purchase of raw materials from D.C.M. and the sale price of DDT—Government are awaiting the recommendations of the Board of Directors of the Company, who have appointed Sub-Committee for the purpose of a thorough examination of the problems. In regard to the remaining five points, no further action has been considered necessary.

FAMILY PLANNING PROGRAMME AT A.I.R.

2568. SHRI SRADHAKAR SUPAKER : Will the Minister of HEALTH AND FAMILY PLANNING be pleased to state :

(a) whether the time allotted to family planning programmes in the different stations of A.I.R. is proposed to be increased; and

(b) if so, to what extent and at which stations ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HEALTH, FAMILY PLANING AND URBAN DEVELOPMENT (DR. S. CHANDRASEKHAR) : (a) and (b). Family Planning Units have been set up at 22 stations of A.I.R. These units are broadcasting family planning programmes varying from 5 to 45 minutes depending on the nature and the type of the programmes. The question of increasing the number as well as the duration of the programmes on family planning is under consideration but the details have still to be finalized.

Family Planning in Public Sector Undertakings

2569. SHRI M. SUDARSANAM : Will the Minister of HEALTH AND FAMILY PLANNING be pleased to state :

(a) whether the attention of Government has been drawn to a Press Report which appeared in *Patriot* of the 15th September, 1967 to the effect that an agreement has been arrived at between the employees and employers in a factory in Dandeli in North Canara that an employee who gets a fourth child would not be entitled to his normal annual increment; and

(b) whether Government propose to extend this to the public sector undertakings also ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HEALTH, FAMILY PLANNING AND URBAN DEVELOPMENT (DR. S. CHANDRASEKHAR) : (a) I have seen a press report to this effect.

(b) The proposal has not yet been considered.

Ram Ganga Dam

2570. SHRI ACHAL SINGH : Will the Minister of IRRIGATION AND POWER be pleased to state :

(a) whether the construction of Ram Ganga Dam is in progress; and

(b) if so, when it will be completed?

THE MINISTER OF IRRIGATION AND POWER (DR. K. L. RAO) :

(a) Yes.

(b) By March, 1972.

Assistance to Orissa for utilising Electricity for Agricultural Purposes

2571. SHRI K. P. SINGH DEO : Will the Minister of IRRIGATION AND POWER be pleased to state :

(a) whether Government propose to give financial assistance to Orissa State in 1967-68 to increase the quantum of power in the State for utilising cheap electricity for agricultural purposes;

(b) if so, the details thereof; and

(c) if not, the reasons therefor ?

THE MINISTER OF IRRIGATION AND POWER (DR. K. L. RAO) : (a) to (c) : Earmarked Central assistance to the extent of Rs. 88 lakhs has been allocated to the State of Orissa in 1967-68 for rural electrification with particular emphasis on energisation of irrigation pumps for increasing agricultural production.

Assistance to Orissa for New Irrigation Projects

2572. SHRI K. P. SINGH DEO : SHRI P. K. DEO :

Will the Minister of IRRIGATION AND POWER be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 8763 on the 10th August, 1967 and state :

(a) whether the request made by the Government of Orissa for additional allocation of central assistance to the extent of Rs. 11 crores for the new irrigation projects to be taken up in the Fourth Plan has since been considered by Government;

(b) if so, whether Government have agreed to give the financial assistance sought by the Orissa Government; and

(c) if so, the break-up for the various irrigation projects ?

THE MINISTER OF IRRIGATION AND POWER (DR. K. L. RAO) : (a) to (c). The proposal is still under consideration.

ASSISTANCE TO ORISSA FOR FLOOD CONTROL MEASURE

2573. SHRI K. P. SINGH DEO : Will the Minister of IRRIGATION AND POWER be pleased to state:

(a) whether Government propose to give additional assistance to Orissa for flood control measures to be taken up along the Brahmani and Mahanadi rivers; and

(b) if so, the details thereof ?

THE MINISTER OF IRRIGATION AND POWER (DR. K. L. RAO) : (a) and (b). Flood control works from part of the State Plans and provision for new works have also to be made within the State's Annual Plans. Further no request for additional assistance for flood control works in the Mahanadi and Brahmani river basins has been received from the Government of Orissa.

INCOME-TAX EVATION ON SALE OF FILMS

2574. SHRI ARJUN SINGH BHADORIA : Will the Minister of FINANCE be pleased to state :

(a) whether Government are aware that the sale deeds in respect of films in Bombay, Delhi, Calcutta and Madras are being registered at lesser value in order to evade income-tax;

(b) if so, the number of such registrations that have come to the notice of Government so far; and

(c) the action which Government have taken in this regard?

THE DEPUTY PRIME MINISTER AND MINISTER OF FINANCE (SHRI MORARJI DESAI) : (a) Sale deeds or distribution/lease deeds are not registered with any authority. They are executed on stamped paper.

(b) Six cases of execution of deeds at lesser value have come to the notice of the Government.

(c) Necessary action to tax the escaped income is being taken.

INCOME-TAX EVATION BY FILMS PEOPLE

2575. SHRI ARJUN SINGH BHADORIA : Will the Minister of FINANCE be pleased to state :

(a) whether it is a fact that certain film music directors and playback singers have evaded Income-tax;

(b) if so, the names of the music directors and playback singers who have income more than fifty thousands rupees during the last five years; and

(c) the steps taken to enforce recovery of Income-tax from them?

THE DEPUTY PRIME MINISTER AND MINISTER OF FINANCE (SHRI MORARJI DESAI) : (a) Yes, Sir.

(b) and (c). This information is being collected and will be laid on the Table of the House. All steps provided in law for recovery are taken, wherever necessary.

PRICE OF QUININE

2576. SHRI BHOLA RAUT : Will the Minister of PETROLEUM AND CHEMICALS be pleased to state :

(a) whether the prices of Quinine and Quinine have been increased by State Governments;

(b) the action taken on the applications received from the Government Quinine Factories at Madras and West Bengal regarding increase of their price; and

(c) whether approval to the price increase to these Government factories has been given and if so, from which date and to what extent?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PETROLEUM AND CHEMICALS AND OF SOCIAL WELFARE (SHRI RAGHU RAMAIAH) : (a) Yes.

(b) and (c). The applications are still under consideration.

LIFT CHANNEL ON RAJASTHAN CANAL

2577. DR. KARNI SINGH : Will the Minister of IRRIGATION AND POWER be pleased to state :

(a) whether the proposal to construct a lift channel from Birdwal at mile 48 on the Rajasthan Canal has been sanctioned; and

(b) if not, the reasons therefor?

THE MINISTER OF IRRIGATION AND POWER (DR. K. L. RAO) : (a) and (b). The State Government has approved lift irrigation on Rajasthan Canal Project. Various alternative schemes prepared for the Lift Channel from Mile 48 are under active consideration with the Rajasthan Government.

FIRE IN GAUHATI OIL REFINERY

2578. SHRI HEM BARUA : Will the Minister of PETROLEUM AND CHEMICALS be pleased to state :

(a) whether it is a fact that fire broke out near the Gauhati oil refinery recently;

(b) whether the causes of the fire have been ascertained; and

(c) if so, the causes thereof and the action taken in the matter ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PETROLEUM AND CHEMICALS AND OF SOCIAL WELFARE (SHRI RAGHU RAMAIAH) : (a) Yes, Sir. It broke out outside the premises of the refinery.

(b) No; the matter is under investigation.

(c) Results of investigations will be awaited before any action is taken.

NEW IRRIGATION PROJECTS IN STATES

2580. SHRI K. LAKKAPPA : Will the Minister of IRRIGATION AND POWER be pleased to state :

(a) whether Government have given any direction to the States to improve irrigation facilities at an early date taking up new projects as envisaged in Centre and State Plans to build self-sufficiency in food front; and

(b) if so, which are those States that have taken new projects assisted by Centre?

THE MINISTER OF IRRIGATION AND POWER (DR. K. L. RAO) : (a) and (b). The Centre is constantly urging States to improve irrigation facilities. However due to constraint of resources, no new major or medium irrigation scheme has been taken up by any State with special earmarked Central Loan assistance.

मध्य प्रदेश को सहायता

2581. **श्री गं० च० दीक्षित** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार ने मध्य प्रदेश सरकार की सहायता-कार्यों के लिए अनुदान देने से इन्कार कर दिया है;

(ख) क्या यह सच है कि मध्य प्रदेश सरकार सहायता-कार्यों पर 15 करोड़ रुपया पहले ही खर्च कर चुकी है और केन्द्रीय सरकार ने इस में से केवल 5.5 करोड़ रुपया देना ही स्वीकर किया है; और

(ग) यदि हां, तो क्या मध्य प्रदेश सरकार को और सहायता देने का सरकार का विचार है ।

उप प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) जी, नहीं ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) यह सवाल पैदा ही नहीं होता ।

नई दिल्ली में राजौरी गार्डन क्षेत्र में श्मशान भूमि

2582. **श्री प० ला० बारूपाल** : क्या **निर्माण, आवास तथा पूर्ति** मंत्री यह बताने की करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ब्लाक नम्बर जे-11, राजौरी गार्डन, नजफगढ़ रोड, नई दिल्ली की श्मशान भूमि इस बीच बन्द कर दी गई है;

(ख) क्या दिल्ली विकास प्राधिकार ने इस भूमि का अर्जन कर लिया है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इस भूमि के कब तक अर्जित कर लिये जाने की सम्भावना है ?

निर्माण, आवास तथा पूर्ति मंत्रालय में उप मंत्री (श्री इकबाल सिंह): (क) से (ग). सूचना एकत्रित की जा रही है तथा यथासमय सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

INCOME-TAX REALISED FROM ASSAM

2583. SHRI B. N. SHASTRI : Will the Minister of FINANCE be pleased to state :

(a) the total amount of income-tax realised and received from Assam during the last financial year; and

(b) how it compares with the previous financial year?

THE DEPUTY PRIME MINISTER AND MINISTER OF FINANCE (SHRI MORARJI DESAI) : (a) The total income-tax collections in the charge of Commissioner of Income-tax Assam during 1966-67 were Rs. 5.12 crores.

(b) The collections during 1965-66 amounted to Rs. 4.33 crores. The collections in 1966-67 have therefore gone up by Rs. 79 lakhs as compared to the collections in 1965-66.

'P' FORM FOR VISITS ABROAD

2584. SHRI B. N. SHASTRI : Will the Minister of FINANCE be pleased to state :

(a) whether it is a fact that due to inordinate delays is issuing 'P' forms, persons going abroad on invitation of foreign agencies and in whose cases no foreign exchange is required are often put to great inconvenience; and

(b) if so, the reason therefor and the remedial steps proposed to be taken in the matter?

THE DEPUTY PRIME MINISTER AND MINISTER OF FINANCE (SHRI MORARJI DESAI) : (a) and (b). There is no delay or inconvenience in granting approvals for passages in cases where individuals are proceeding abroad on invitation from foreign agencies if the application is given in time with all requisite documentation in support. In some cases the applicants do not supply complete information and the Reserve Bank has perforce to obtain the required details before they could consider the application and this may take time.

DIESEL OIL

2585. SHRI K. M. KOUSHIK : Will the Minister of PETROLEUM AND CHEMICALS be pleased to state :

(a) whether the oil fields in the country are producing diesel oil which is necessary for the running of our locomotives;

(b) whether there is a plentiful supply as to suffice for both the locomotives and the motor vehicles;

(c) if not, whether diesel is being imported; and

(d) if so, the reasons for increasing the number of diesel locomotives in view of the plentiful supply of steam coal available in the country?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PETROLEUM AND CHEMICALS AND OF SOCIAL WELFARE (SHRI RAGHU RAMAIAH): (a) and (b). Diesel Oil, both high speed and low speed, are petroleum products obtained by refining the crude oil produced in the oilfields. The present production of these products in the indigenous refineries is sufficient to meet all of the demands, including those for locomotives and the motor vehicles.

(c) and (d). Do not arise.

SCHEDULED TRIBES

2586. SHRI K. M. KOUSHIK : Will the Minister of SOCIAL WELFARE be pleased to state the *criteria* laid down by Government for inclusion of any caste among the Scheduled Tribes?

THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF SOCIAL WELFARE (SHRIMATI PHULRENU GUHA) : The criteria laid down for scheduling tribes are indications of primitive traits, distinctive culture, geographical isolation, shyness of contact with the community at large, and backwardness.

TAX EVASION BY FILM ACTOR

2587. SHRI ARJUN SINGH BHADORIA : Will the Minister of FINANCE be pleased to state :

(a) whether any complaint was received by the Assistant Director of Inspetetion (Intelligence) Bombay, about tax evasion by Shri Devanand, a famous film star of Bombay;

(b) whether a raid was carried out at his home or his studio 'Navketan';

(c) if so, the results thereof; and

(d) the action taken against him?

THE DEPUTY PRIME MINISTER AND MINISTER OF FINANCE, (SHRI MORARJI DESAI) : (a) and (b). No, Sir.

(c) and (d) Do not arise.

FLOUR MILLS IN PAHARAGANJ, DELHI

2588. SHRI RAM SWARUP : Will the Minister of WORKS, HOUSING AND SUPPLY be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the existing flour mills in Paharganj, Delhi, which are not in conformity with the Master Plan, are being considered for allotment of alternative industrial plots by the Delhi Development Authority on the recommendations of the Director of Industries, Delhi; and

(b) if so, the number of such applications received and the action taken thereon?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF WORKS, HOUSING AND SUPPLY (SHRI IQBAL SINGH):

(a) Yes. Units which are working on more than 7½ H.P. or are employing more than 4 workers, will be asked to shift to the industrial areas developed by the Delhi Development Authority.

(b) The information is being collected and will be laid on the table of the House in due course.

CENTRAL ASSISTANCE TO ORISSA

2589. SHRI K. P. SINGH DEO : Will the Minister of FINANCE be pleased to state :

(a) whether it is a fact that according to the procedure laid down for the Central assistance for relief works in the States, the Centre has to share 75 per cent of the expenditure on this account;

(b) if so, the Central assistance that became due to Orissa for relief work during the current year;

(c) the actual amount of assistance given by Government; and

(d) the reasons for the non-payment of dues in full?

THE DEPUTY PRIME MINISTER AND MINISTER OF FINANCE (SHRI MORARJI DESAI): (a) Where the expenditure on relief measures exceeds in any year the amount taken into account by the Finance Commission in its recommendations relating to financial devolution from the Centre, 75% of the excess in respect of the total approved expenditure is met by the Centre by way of reimbursement to the State concerned (50% as grants and 25% as loans).

(b) Since the Central assistance is by way of reimbursement on the basis of audited figures of expenditure during the year no payment has become due to Orissa for relief work during the current year.

(c) In view of their ways and means position advance *ad hoc* payment of Rs. 1 crore has been made to the State Government.

(d) Does not arise.

PAYMENT OF INCOME-TAX BY REPRESENTATIVES OF POLITICAL PARTIES

2590. SHRI BENI SHANKAR SHARMA : Will the Minister of FINANCE be pleased to state :

(a) whether the political parties having their representatives in the State Legislative Assemblies and Centre, are assessed to income-tax on the moneys they receive from persons other than the members of their parties;

(b) if not, the steps Government propose to take to get them on the G.I.R. of the Income-tax Department and assessed or exempted according to law; and

(c) whether Government propose to make it obligatory on the part of the representatives to report to the income-tax authorities of their area all receipts

above a certain amount just to have the source where from the money was coming examined?

THE DEPUTY PRIME MINISTER AND MINISTER OF FINANCE (SHRI MORARJI DESAI) : (a) No, Sir. Such receipts do not constitute income under the Income-tax Act and hence, are not taxable under the law.

(b) Does not arise in view of reply to part (a).

(c) Political Parties are liable to tax on income from investments. In the course of the assessment, the Income-tax Officer can enquire into the source of any sum included in the accounts of an assessee for the purposes of section 68 of the Income-tax Act. Government do not consider it necessary to make any other provision for the purpose.

INCOME-TAX OFFICES IN CALCUTTA

2591. SHRI BENI SHANKER SHARMA : Will the Minister of FINANCE be pleased to state :

(a) the number of places where Income-tax Offices have been accommodated in Calcutta alongwith their location and the annual rent paid for the rented buildings with rates thereof separately;

(b) whether it is a fact that the rent paid for rented buildings is so high that in four or five years the total amount of rent paid would exceed the cost of the building itself;

(c) whether it is also a fact that the location of Income-tax Offices in different places of the town, some of which are situated in very congested areas and are difficult to approach, are causing great inconvenience both to the assessees and the authorities; and

(d) if so, the steps proposed to be taken to bring all the offices in one building or at least in the same area ?

THE DEPUTY PRIME MINISTER AND MINISTER OF FINANCE (SHRI MORARJI DESAI) : (a) to (d). The information is being collected.

12.10. Hrs.

RE SENAPATI BAPAT

SHRI NATH PAI (Rajapur) : Mr. Speaker, the matter is such that I would not like to enter into an argument with you but I have not got a reply to my letter in which I requested you that the House should be given an opportunity to pay its respects to the late Senapati Bapat one of our revolutionary leaders. I was informed by the Minister of Parliament Affairs that they would not have any objection to it.

MR. SPEAKER : I do not know and I do not mind but we will have to consider when some leader in some State..... (*Interruption*)

SHRI NATH PAI : There was not the like of him.

MR. SPEAKER : There are respected leaders in the States. I do not want to discuss names.

SHRI NATH PAI : May I only make a little protest; normally, I do not. It was not a State leader that I was interested in paying a compliment or tribute. He was the fighter of the freedom movement of the nation.

SHRI HEM BARUA : (Mangaldai) : Rightly obituary reference was made in this House to Master Tara Singh. When we make an obituary reference to Master Tara Singh .....(*Interruption*)

MR. SPEAKER : If you make it, well and good. But you make it a controversy. You should not do it on the floor of the House. I do not think you are doing any justice to the departed person. But, unfortunately, you raise these things here.

SHRI NATH PAI : All right; we shall discuss it with you.

12.12. Hrs.

CALLING ATTENTION TO MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

RE. NEW POLICY OF IMPORT AND DISTRIBUTION OF WOOL

श्री मधु लिमये (मुंगेर) : अध्यक्ष महोदय, मैं अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्नलिखित विषय की ओर व्यापार मंत्री का ध्यान

दिलाता हूं और प्रार्थना करता हूं कि वह इस बारे में एक वक्तव्य दें :

"ऊन के आयात और वितरण के बारे में सरकार की नई नीति"

THE MINISTER OF COMMERCE (SHRI DINESH SINGH) : Sir, this is a somewhat detailed statement.

MR. SPEAKER : You may place it on the Table of the House.

SHRI DINESH SINGH : Sir, I place it on the Table of the House.[*Placed in Library. See* No. LT-1856/67.]

MR. SPEAKER : Questions on it may be asked tomorrow.

श्री मधु लिमये : मैं मांग करता हूं कि यह पढ़ा जाये । सदन को कम से कम कुछ पता तो लगे ।

MR. SPEAKER : That is exactly what I thought. It is an eight-page statement and it will be difficult for others to follow.

श्री मधु लिमये : यह इम्पोर्ट आफ वूल के बारे में है । कल लें तो ठीक होगा ।

AN HON. MEMBER : It can be circulated.

MR. SPEAKER : Yes.

12.13. Hrs.

PAPERS LAID ON THE TABLE

ANNUAL REPORT OF THE LIFE INSURANCE CORPORATION OF INDIA ALONG WITH THE AUDITED ACCOUNTS FOR THE YEAR 1966-67

THE DEPUTY PRIME MINISTER AND MINISTER OF FINANCE (SHRI MORARJI DESAI) : Sir, I beg to lay on the Table a copy of the Annual Report of the Life Insurance Corporation of India for the year ended the 31st March, 1967 along with the Audited Accounts, under section 29 of the Life Insurance Corporation Act, 1956 [*Placed in Library. See* No. LT-1792/67.]

NOTIFICATIONS UNDER DRUGS AND COSMETICS ACT, 1940 AND STATEMENT SHOWING REASONS FOR DELAY IN LAYING THE SAME

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF HEALTH, FAMILY PLANNING AND URBAN DEVELOPMENT (SHRI B. S. MURTHY) : On behalf of Dr. S. Chandrasekhar, I beg to lay on the Table :—

(1) A copy each of the following Notifications under sub-section (3) of section 33 of the Drugs and Cosmetics Act, 1940 :—

(a) The Drugs and Cosmetics (First Amendment) Rules, 1967, published in Notification No. S.O. 2369 in Gazette of India dated the 15th July, 1967;

(b) The Drugs and Cosmetics (Second Amendment) Rules, 1967, published in Notification No. S.O. 2405 in Gazette of India dated the 22nd July, 1967.

(2) A statement showing reasons for delay in laying the Notifications mentioned at (1) above.

[*Placed in Library. See* No. LT-1793/67]

श्री जार्ज फरनेन्डीज (बम्बई दक्षिण) : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने जो कागज टेबल पर रक्खा है उस के बारे में मेरा व्यवस्था सम्बन्धी प्रश्न है ।

आज का जो आर्डर पेपर दिया गया है उस में यह लिखा गया है कि :

"A statement showing reasons for delay in laying the Notifications mentioned at (1) above."

टेबल पर नोटिफिकेशन रखने में देरी का क्या कारण मंत्री महोदय बतला रहे हैं, मुझे नहीं मालूम, मगर जिस ड्रग्स और कास्मेटिक्स ऐक्ट, 1940 के क्लाज 33(3) के आधार पर वे इस को रखने जा रहे हैं, मैं उस को आप को पढ़ कर सुनाना चाहता हूं । 33(3) इस प्रकार है :

"Every rule made under this Section shall be laid as soon as may be, after it is made, before each House of Parliament while it is in session for a total period of 30 days which may be comprised in one session or in two successive sessions and if, before the expiry of the session in which it is so laid or the

[Shri George Fernandes]

session immediately following, both Houses agree in making any modification in the rule or both Houses agree that the rule should not be made, the rule shall, thereafter, have effect only in such modified form or be of no effect as the case may be. So, however, with any such modification or annulment shall be without prejudice to the validity of anything previously done under that rule."

अब जो सदन के नियम हैं उन नियमों के 234 (ए) के मातहत सरकार की ओर से यहां कागज आदि रखने का काम होता है। 234 (ए) में कहा गया है कि :

"Where a regulation, rule, sub-rule, by-law etc. framed in pursuance of the Constitution or of the legislative functions delegated by Parliament to a subordinate authority is laid before the House, the period specified in the Constitution or the relevant Act for which it is required to be laid shall be completed before the House is adjourned *sine die* and later prorogued, unless otherwise provided in the Constitution or the relevant Act."

मेरा आप से निवेदन है कि इस ड्रग्स ऐंड कास्मेटिक्स ऐक्ट में सरकार को कहीं भी यह छूट नहीं दी गई है कि जब इस सदन का सेशन चल रहा हो, उस वक्त इस को पेश न कर के बाद में माफी मांग कर के इस को पेश कर सकते हैं। एक बड़ा अहम सवाल इस से यहां खड़ा हो जायेगा। जिन दोनों नियमों को सरकार यहां पेश करने जा रही है उन में से एक तो 15 जुलाई, 1967 को और दूसरा 22 जुलाई, 1967 को गजट में निकला। उस वक्त सदन का काम चल रहा था और 12 अगस्त तक यह सदन चला था। उसी सत्र में इन दोनों नियमों को सदन के सामने पेश करना चाहिये था। इस कानून के अन्तर्गत लेकिन उन को पेश नहीं किया गया और अब मंत्री महोदय स्टेटमेंट शोइंग रीजन्स फार डिले दे कर के पेश करने जा रहे हैं मेरी अर्ज यह है कि यह डिले क्यों हुई यह बतलाने के लिये न तो कानून में कोई छूट है न नियमों के अन्दर कोई छूट है। अब अड़चन हम लोगों के सामने यह आ जायेगी कि जुलाई महीने में जिस नियम को उन को यहां पेश करना चाहिये था, वह उन्होंने नहीं पेश किया। इन नियमों के अन्दर कोई अधिकार नहीं दिया गया यह बतलाने का कि यहां पर उस को समय से पेश करने का काम क्यों नहीं किया गया।

इसलिये मेरी अर्ज है कि इस व्यवस्था के प्रश्न को लिया जाये और मंत्री महोदय से कहा जाय कि वह इन नियमों को वापस लें और फिर उन को सदन के सामने पेश करने का काम करें।

SHRI B. S. MURTHY : Sir, the delay was because the rules were not finalised. As soon as.....

श्री जार्ज फरनन्डीज : गजट हो गये। कैसे कहते हैं कि फाइनलाइज नहीं हुए ?

SHRI B. S. MURTHY : The hon. Member may please see (a) which says :

"The Drugs and Cosmetics (First Amendment) Rules, published in Notification No. S.O. 2369 in Gazette of India dated the 15th July, 1967;"

The same thing has again been revised and amended on 22nd July, 1967. Therefore, as we had to give consideration to both first and second Amendments, we had not been able to come before the House and lay these papers.

MR. SPEAKER : The point is that they were gazetted in July and the Parliament was in session till August 11th or 12th. Anyway, I am glad that they have expressed their regret for not having placed it on the Table of the House in July.

श्री जार्ज फरनेंडीज: ये नियम गैर कानूनी हो जायेंगे चूंकि कानून को तोड़ा जा रहा है। मैं कानूनी प्रश्न उठा रहा हूं। कोई भी अदालत में जा सकता है और कह सकता है कि ये नियम गैर कानूनी हैं चूंकि सदन के सामने इनको समय पर नहीं रखा गया है। माफी मांगने

की कोई भी छूट कानून के अन्दर नहीं है । इसलिये मैं चाहता हूं कि इन नियमों को वापिस लिया जाए ।

MR. SPEAKER : That is correct. Mr. Jaganath Rao.

STATEMENT OF CASES IN WHICH LOWEST TENDERS HAVE NOT BEEN ACCEPTED BY THE INDIA SUPPLY MISSIONS, LONDON AND WASHINGTON

THE MINISTER OF WORKS, HOUSING AND SUPPLY (SHRI JAGANATH RAO) : I beg to lay on the Table a statement of cases in which lowest tenders have not been accepted by the India Supply Mission, London, and India Supply Mission, Washington, for the half year ending the 30th June, 1967. [Placed in Library, *See* No. LT—1794/67.]

श्री जार्ज फरनेंडीज : यह कानून और नियमों का सवाल है, अध्यक्ष महोदय । माफी मांगने से काम नहीं बनता है । उनको आप कहिये कि नए सिरे से वे इसको करें ।

MR. SPEAKER : What the hon. Member says is correct. The delay was there. It is accepted; it is not as though anybody has not accepted that.

श्री जार्ज फरनेंडीज : मैं नियम 294 के आधार पर आप के सामने खड़ा नहीं हूं ।

MR. SPEAKER : We shall discuss. He may give proper notice. Let us then see.

श्री जार्ज फरनेंडीज : कोई छूट नहीं है । इसमें यह है कि रूल्ज शैल बी लेड । दे हैव नाट बीन लेड । फिर नियमों का क्या होगा इस कानून के अन्तर्गत?

MR. SPEAKER : It has already been placed on the Table. They do agree that it ought to have been laid in July and they have delayed it. They have expressed regret for it. If there is anything wrong in that, he may certainly give notice. Let us examine that also.

श्री मधु लिमये : (मुंगेर) अभी इनको टेबल पर रखने की आप इजाजत न दें । गैर कानूनी नियम हैं । अब नहीं रख सकते हैं ।

ANNUAL REPORT OF THE AGRICULTURAL REFINANCE CORPORATION AND NOTIFICATIONS UNDER CUSTOMS ACT AND CENTRAL EXCISE AND SALT ACT

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI K. C. PANT): I beg to lay on the Table :—

(1) A copy of the Annual Report of the Agricultural Refinance Corporation, Bombay, for the year ended the 30th June, 1967, along with the Audited Accounts, under sub-section (2) of section 32 of the Agricultural Refinance Corporation Act, 1963. [Placed in Library, *see* No. LT—1796/67.]

(2) A copy each of the following Notifications under section 159 of the Customs Act, 1962 :—

(i) S.O. 4053 published in Gazette of India dated the 10th November, 1967.

(ii) G.S.R. 1725 published in Gazette of India dated the 18th November, 1967. [Placed in Library, *see* No. LT—1796/67.]

(3) A copy each of the following Notifications under section 159 of the Customs Act, 1962 and section 38 of the Central Excises and Salt Act, 1944 :—

(i) The Customs and Central Excise Duties Export Draw-back (General) Fifty-eighth Amendment Rules, 1967, published in Notification No. G.S.R. 1727 in Gazette of India dated the 18th November, 1967.

(ii) The Customs and Central Excise Duties Export Draw-back (General) Fifty-ninth Amendment Rules, 1967, published in Notification No. G.S.R. 1728 in Gazette of India dated the 18th November, 1967.

(iii) The Customs and Central Excise Duties Export Draw-back (General) Sixtieth Amendment Rules, 1967, published in Notification No. G.S.R. 1729 in

[Shri K. C. Pant]

Gazette of India dated the 18th November, 1967. [Placed in Library, *see* No. LT—1797/67.]

12.22 HRS.

STATEMENT *RE*: INDEPENDENCE OF THE PEOPLE'S REPUBLIC OF SOUTH YEMEN

THE PRIME MINISTER, MINISTER OF ATOMIC ENERGY, MINISTER OF PLANNING AND MINISTER OF EXTERNAL AFFAIRS (SHRIMATI INDIRA GANDHI) : After more than one century and a quarter of colonial domination, South Arabia today emerges as a free and independent nation—The People's Republic of South Yemen. On this auspicious occasion, we extend our greetings and offer our good wishes to the Government and the people of the new State. We also pay our tribute to the valiant freedom fighters who have laid down their lives during the struggle for their independence.

There have been close and intimate relations for centuries between India and South Arabia. It shall be the earnest endeavour of the Government of India to further strengthen our relations with the independent State and also to extend such economic and technical assistance as we can and which they may need.

As the House is aware, India has consistently supported the right to independence and sovereignty for the people of South Arabia, and for many years now we have made earnest efforts for the achievement of this aim through the United Nations and otherwise. Therefore, it is a matter of great satisfaction and pleasure to us that South Arabia is now an independent nation.

The independence of South Arabia is yet another step towards decolonisation in the world. It is earnestly hoped that the day is not far off when the remaining colonised peoples and countries will also become independent.

The Government of India has extended recognition to the People's Republic of South Yemen and it is our intention to convert our Commission in Aden into an Embassy with a resident Ambassador. The necessary steps in this regard have already been initiated.

I am sure that all Members of this House, as also the people of India, join me in extending a warm welcome to the new State of the People's Republic of South Yemen in the comity of nations and in wishing it a bright future.

12.25 HRS.

STATEMENT *RE* : SITUATION IN WEST BENGAL

THE MINISTER OF HOME AFFAIRS (SHRI Y. B. CHAVAN) : Mr. Speaker, Sir, the House is aware of the action taken by the Speaker of the West Bengal Legislative Assembly yesterday, and the observations which he made while adjourning the Assembly *sine die* have been published in the press to-day. While concluding his observations, the Speaker said :

> "The matters in issue are of the highest constitutional importance..... It is obvious, therefore, that if I am to find out how exactly I should act so as to preserve and protect the privileges of this House, I should need more time and then only gave a considered ruling on the grave issues at stake. This is why in exercise of my powers under Rule 15 I have adjourned this House *sine die*."

While reserving final judgment, the Speaker has nevertheless expressed his views on a number of issues. I do not wish to comment on the conduct of the Hon'ble Speaker of the West Bengal Legislative Assembly. But there are certain matters on which I should like to make the stand of the Central Government clear.

According to the best legal advice available to us it was within the constitutional competence of the Governer to dissolve the Council of Ministers headed by Shri Ajoy Mukherji in the circumstances in which the Governor did so . . .. (*Interruptions*)

SOME HON. MEMBERS : No, No.

SHRI Y. B. CHAVAN : We are further advised that the Council of Ministers headed by Dr. P. C. Ghosh is lawfully constituted..... (*Interruptions*)

श्री मधु लिमये (मुंगेर) : बिल्कुल नहीं ।

SHRI Y. B. CHAVAN : We are convinced that this is a correct view and that, notwithstanding the observations..... (*Interruptions*)

MR. SPEAKER : Order, Order, please.

SHRI Y. B. CHAVAN : We are convinced that this is a correct view and that, notwithstanding the observations made by the Speaker of the West Bengal Legislative Assembly, Dr. P. C. Ghosh and his colleagues continue to function..... (*Interruptions*)

श्री राम सेवक यादव (बाराबंकी) : कैसे ?

श्री मधु लिमये : आप को आपकी ही भाषा में उन्होंने जवाब दिया है ।

MR. SPEAKER : Let him complete.

SHRI Y. B. CHAVAN : ..... as the lawful Council of Ministers of West Bengal.

The Governor's action in dissolving the Council of Ministers headed by Shri Ajoy Mukherji and installing the one headed by Dr. P. C. Ghosh was based on his judgment that Shri Ajoy Mukherji had ceased to have the support of a majority of Members in the Assembly. .....(*Interruptions*) and that Dr. Ghosh had such support. By adjourning the sitting of the Assembly *sine die* the Speaker did not allow it to be tested by a vote of the Assembly..... (*Interruptions*) whether Shri Ajoy Mukherji or Dr. P. C. Ghosh had the support of the majority. But the events yesterday have made it clear that Dr. P. C. Ghosh has the majority.

MANY HON. MEMBERS FROM THE OPPOSITION *rose*—

MR. SPEAKER : Will you kindly resume your seats? Some hon'ble Members have given me this morning—that is natural—a substantive motion in connection with this. I discussed with the hon'ble Members of the Opposition—Mr. Mukherjee, Mr. Banerjee, Dr. Ranen Sen, Mr. Indrajit Gupta and Mr. S. N. Dwivedy and yourself also—the substantive motion that :

> "This House recommends to the President that he be pleased to dismiss the present Governor of West Bengal for his unconstitutional act of dismissing the ULF Ministry in West Bengal."

That was the motion given in the name of five hon'ble Members.

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (बलरामपुर) : आज गृह मंत्री जी ने एक महत्वपूर्ण वक्तव्य दिया है । उस वकतव्य पर सदन को विचार करने का अवसर मिलना चाहिये । एक तरीका विचार करने का अवसर देने का यह है कि आप एक ऐसा संकल्प स्वीकार करें जिस में गृह मंत्री के वकतव्य पर चर्चा उठाई जा सके और उस प्रस्ताव के वैकल्पिक संकल्प के रूप में ये प्रस्ताव आ सकते हैं । गृह मंत्री के वक्तव्य पर विचार करने के बाद सदन राष्ट्रपति को जो भी सिफारिश करना चाहे कर सकता है ।

MR. SPEAKER : Does the hon'ble Member want a separate discussion? I think we can club both.

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : चर्चा एक ही हो ।

श्री मधु लिमये : अध्यक्ष महोदय, इस प्रस्ताव का और श्री वाजेपेयी ने जो सुझाव दिया है, उस का मैं विरोधी भी नहीं हूं । लेकिन मैंने आप को एक काम-रोको प्रस्ताव दिया है । उस का और इस प्रस्ताव का कोई सम्बन्ध नहीं है । अगर आप कृपया मेरे काम-रोको प्रस्ताव को पढ़ेंगे, तो आप देखेंगे कि मैंने उस में कहा है .....

MR. SPEAKER : Whatever it is, I have not accepted it. There is no point in discussing it.

श्री मधु लिमये : मैं चाहता हूं कि इस काम-रोको प्रस्ताव पर भी बहस हो, क्योंकि इस सरकार ने पहले अनुमान नहीं लगाया कि

[श्री मधु लिमये]

संविधान के अनुच्छेद 164 और पश्चिम बंगाल विधान सभा के नियम 15 के जो परस्पर-विरोधी भाष्य किये जा रहे हैं, उस से संवैधानिक आपत्ति उत्पन्न होगी, संविधान पर अमल नहीं होगा और एक संकट पैदा होगा। इस लिए हम इस सरकार की असफलता के लिए उस की आलोचना करना चाहते हैं। आप इन के प्रस्ताव को भी ले लीजिए और काम-रोको प्रस्ताव को भी ले लीजिए, क्योंकि सरकार की संवैधानिक असफलता, कांस्टीट्यूशनल फेल्युर हुआ है।

SHRI SURENDRANATH DWIVEDY (Kendrapara) : You had read out some motion, but the motion which I had given notice of was slightly different from it. I did not mention the word 'dismissal' etc. in my motion, but I had only suggested 'recommend to the President to remove . . .

MR. SPEAKER : It is a difference of only one word, but substantially it is the same.

SHRI SURENDRANATH DWIVEDY : I have not suggested outright dismissal etc. I had referred to the present situation. I do not know whether this has been referred to in the motion which you have been pleased to accept.

MR. SPEAKER : Let me explain the position. A number of distinct motions had come. It is not as though the same wording was there in all of them; the wording may have been a little different in each one of them, but the substance is the same, namely removal of the Governor. My point was this. The statement of the Home Minister will have to be discussed, as Shri A. B. Vajpayee has said.

SHRI A. K. SEN (Calcutta—North—West) : We support it.

MR. SPEAKER : Apart from that, suppose on an adjournment motion we begin discussing whatever has happened in an Assembly, then I do not know where it will lead to, tomorrow it may be Madhya Pradesh and day after tomorrow it may be some other State where the Speaker may adjourn the House or something else may happen. We are not competent to discuss what happens in the Assembly.

श्री हुकम चन्द कछवाय (उजैन) : अध्यक्ष महोदय, ...

MR. SPEAKER : After I go home, Shri Hukam Chand Kachwai can teach me; and I would like to take some lessons from him also, but here unfortunately I am in the Chair and he should listen to me. If we begin discussing what has happened in an Assembly, on an adjournment motion, then it will be a dangerous thing, because so many Assemblies are there. But I do admit that the Home Minister's statement will have to be discussed, and opportunity must be given for that; there is no doubt about it. The Home Minister has just now made a statement, and it is the property of the House today, and it must be discussed. I am fixing up some time for it tomorrow. I did consult the Opposition leaders and I suggested that we could discuss it for about a couple of hours tomorrow. I have fixed up the time for this tomorrow. . . . . .

SHRI S. M. BANERJEE (Kanpur): Please make it 3½ hours.

MR. SPEAKER : For this evening I have already allowed a discussion on the situation in Kashmir. Between this evening and tomorrow morning, there is not going to be much of a material change either in the Governor or in the Government there. Therefore, I have admitted this discussion for tomorrow, and we can certainly discuss it tomorrow.

SHRI TRIDIB KUMAR CHAUDHURI (Berhampore): In your wisdom you have allowed a discussion on the statement made by the Home Minister and also on the substantive motion of Shri Surendranath Dwivedy and others. But I think you have not perhaps given consideration to this fact namely that a situation has arisen in West Bengal where there is some kind of a constitutional impasse. The Central Government here have taken one view that the Government headed by Dr. P. C. Ghosh there is perfectly legal and constitutional.

MR. SPEAKER : The hon. Member can discuss all this tomorrow.

SHRI TRIDIB KUMAR CHAUDHURI : It is true that we can discuss all that tomorrow. But at the same time it has been our experience that in these matters we cannot always go by the opinion of the Law Ministry and the Home Ministry which has referred it to the Law Ministry. I would only refer you to the celebrated Berubari case. The Government here had taken the view and the former Attorney-General also had said the same thing that the Government had the right to cede any area to other countries.....

MR. SPEAKER : He can discuss it tomorrow. Now he is going into the merits. What is his suggestion?

SHRI S. M. BANERJEE : The Governor there should be dismissed.

SHRI TRIDIB KUMAR CHAUDHURI : My suggestion is that this aspect of the matter namely whether there is a constitutionally and properly constituted government functioning in West Bengal.....

AN. HON. MEMBER : It has already been decided.

SHRI TRIDIB KUMAR CHAUDHURI : Who has decided it?

Article 355 lays upon the Government here the responsibility for seeing that the government of every State is carried on in accordance with the provisions of the Constitution.

MR. SPEAKER : That is exactly what he will discuss tomorrow on the statement of the Home Minister.

SHRI TRIDIB KUMAR CHAUDHURI : That cannot come under the substantive motion that you have read out, calling upon the Government.....

MR. SPEAKER : The Home Minister's statement also will be before the House.

श्री मधु लिमये : काम-रोको प्रस्ताव को भी लिया जाये ।

MR. SPEAKER : Why does he want to complicate it further? I have already allowed the discussion.

श्री राम सेवक यादव : अध्यक्ष महोदय, भारत सरकार एक एक कर के ऐसी कारगुजारियां दिखा रही है , ...

MR. SPEAKER : He is going into the merits.

श्री रामसेवक यादव : . . . . . जिनसे सारे देश का वातावरण क्षुब्ध हो रहा है अंग्रेजी लादने और भारतीय भाषाओं की उपेक्षा को ले कर आज उत्तर प्रदेश में आग लग रही है ।

MR. SPEAKER : Order, order. The language issue in UP cannot be raised here.

श्री रामसेवक यादव : उस को ले कर मैं ने एक काम-रोको प्रस्ताव दिया है । अंग्रेजी लादी जा रही है और भारतीय भाषाओं की उपेक्षा हो रही है ।

MR. SPEAKER : The language Bill is coming here. If he wants to condemn English or Hindi or whatever he wants, he could do it then.

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : उस बिल की वजह से तो उत्तर प्रदेश में आन्दोलन हो रहा है । आप कह रहे हैं कि बिल आ रहा है । उस से आन्दोलन और बढ़ेगा । उस बिल को रोकना चाहिये ।

MR. SPEAKER : I know. I cannot help it. The State Government is there. (*Interruptions*) It is a bad principle that so many hon. Members should get up and begin speaking. I have not permitted any of them to talk about Hindi or the agitation in Banaras.

If the agitation in Banaras is permitted to be referred to here, lathi charge somewhere else will be raised. No please. If we allow that, there will be no end (*Interruptions*).

श्री मधु लिमये: बनारस विश्वविद्यालय का मामला केन्द्रीय मामला है । माननीय सदस्य लखनऊ और इलाहाबाद का मामला नहीं उठा रहे हैं । वह बनारस का मामला उठा रहे हैं ।

श्री रामसेवक यादव: मेरी बात एक मिनट में खत्म हो जायेगी। अध्यक्ष महोदय, . . .**

MR. SPEAKER : Nothing that is being said will be recorded. Shri Khadilkar.

12.36½ HRS.

CONSTITUTION AMENDMENT BILL

EXTENSION OF TIME FOR PRESENTATION OF REPORT OF JOINT COMMITTEE

SHRI KHADILKAR (Khed) : I beg to move :

"That the time appointed for the presentation of the Report of the Joint Committee on the Bill further to amend the Constitution of India, be further extended upto the first day of the next session".

MR. SPEAKER : The question is :

"That the time appointed for the presentation of the Report of the Joint Committee on the Bill further to amend the Constitution of India, be further extended upto the first day of the next session".

The motion was adopted.

12.37 HRS.

MOTION *RE* : FOOD SITUATION IN THE COUNTRY—*Contd.*

MR. SPEAKER : Further consideration of the following motion moved by Shri Annasahib Shinde on the 29th November 1967, namely :—

"That the food situation in the country be taken into consideration",

along with the amendments moved.

Shri P. K. Deo may continue.

SHRI P. K. DEO (Kalahandi): Yesterday I was saying that the mess in our food and agriculture sector is the culmination of the persistent pursuit of wrong policies by Government all these years since independence. A faulty order of priorities in planning, neglect of agriculture and irrigation, excessive taxation and suffocating controls with attendant corruption and waste and lastly, the expropriatory land reforms—all these together have been responsible for bringing about disaster on the food and agriculture front. This has resulted in our overdependence on foreign food aid.

In the beginning of every Plan, we have been told parrot-like that we shall attain self-sufficiency at the end of the Plan. But it has turned out to be a complete moonshine. Our dependence on foreign food aid is bad, but this is inevitable under the present circumstances. Foreign food aid is increasing from Plan to Plan. From an annual average of 2.4 million tonnes in the First Plan, it had gone up to 13 million tonnes last year, and this year we estimate that we shall be importing 7.5 million tonnes.

12.40 HRS.

[MR. DEPUTY-SPEAKER *in the Chair*]

In this regard, I would like to pay our grateful thanks to the foreign countries, especially Australia, Canada and USSR, and particularly USA, which gave aid in the shape of P.L. 480, for their timely aid to help us turn this tight corner.

Our achievement in the field of food production is far from satisfactory. Our food production has not kept pace with the growth of our population. Every day we add 24,000 people to our population, and 12 million people, the total population of Australia, is added every year. It is like climbing a greasy pole. For every foot of height gained in climbing, we lose three feet.

In crop yield also, we are one of the lowest in the world. In wheat we produce 898 kg. per hectare, whereas the UK produces 3,930 kg. and Netherlands 4,230 kg. Similarly, in the case of rice, our production figure is also very low. It is 1,530 kg. per hectare, whereas in Netherlands it is 4,230 kg. and in Spain 6,360 kg. There have been some startling revelations in the ECAFE report so far as our economic growth is concerned. It has stated that if we proceed at this rate; it will take 139 years for us to reach the Japanese level of today, and it will take 205 years to reach the stage of New Zealand.

It is because of these wrong priorities that there has been a complete neglect of our basic industry, that is agriculture. We are glad that our campaign to

---

**Not recorded.

eradicate illiteracy from the Congress benches has made some effect, that the effort from these benches in educating the Government has borne some fruit. There has been a new awareness, a new rethinking on the subject; unlike the second and third plans, now more stress is going to be laid on agriculture, a definite shift towards realities.

Secondly, this is evident from the AICC resolution passed in Jabalpur which is conspicuous by the absence of any reference to the expropriatory land-reforms which rob the tenant of his freehold rights and reduces him to a serf.

I take this opportunity to congratulate Shri K. Subba Rao, the former Chief Justice, and his distinguished colleagues, for their very bold pronouncement in the latest Supreme Court Judgment in upholding the fundamental rights of the Kisan, in exploding the myth of the so-called reform, which has set at rest all speculations of political demagogues and opportunists. In this victory, I also congratulate my leader Shri Ranga who has championed the cause of the kisan throughout his life.

After two successive droughts we expect a record crop of 95 million tonnes this year. India's agriculture depends on the vagaries of the monsoon. Our former Food Minister had been chanting the mantra

काले वर्षतु पर्जन्य: ।

Up till now there has been no awareness of the necessity of irrigation. Floods, drought and cyclone are the regular features of this country. In spite of this year's good rain, if there had been one rain in October in my State, Orissa, there would have been a bumper crop, but the lack of timely rain has reduced our expectations by 50 per cent.

The Indian agriculturist is taking advantage of modern technological advance. With his enthusiasm for the latest techniques, with assured water supply, with the use of fertilisers and hybrid seed, self-sufficiency can be attained, there is no doubt about it.

So, top priority has to be given to irrigation. Dr. K. L. Rao has given a very learned discourse sometime back. He stated that for an additional population of 12 million every year, we need 1 million tons of food, for which 2 million acres of land have to be brought under irrigation, that is, we have to make a provision of Rs. 100 per child born in this country. I pay my compliments to him for his timely advice, but I am sorry this reality is not appreciated by the Government. Every year we spend crores in foreign exchange on food imports. Last year it reached the figure of Rs. 500 crores. In previous years also, we have been importing large quantities of food, depleting our much-needed foreign exchange. If these amounts had been utilised to improve our irrigation, things would have been quite different.

I am very sorry to state that in the first plan only a provision of Rs. 300 crores was made for irrigation. In the second plan it was Rs. 380 crores and in the third plan it was Rs. 600 crores. This shows how our irrigation sector is completely neglected. In the third plan period, as against a target of 12.2 million acres to be brought under irrigation through medium and major irrigation projects, only 6 million acres have been so brought, of which an irrigation potential of 2 million acres has remained unutilised. Because of the high water rate, the cultivators are not utilising the wonderful potential that has been created. I pay my compliments to the Orissa Government who have lately reduced the water tax by 50 per cent. I hope this lead will be followed by the other States.

Our experience during droughts has been that minor irrigation has been a complete failure because with the limited catchment area, if there is no rain, there is no irrigation to the fields. Therefore, in future Government should not run after minor irrigation, but concentrate on major and medium irrigation. I am sorry to state that even though the Orissa State, which is one of the few surplus States, asked for an assistance of Rs. 10 crores from the Centre to complete the old projects and take up new projects, there has been hesitancy on the part of the Centre and I deplore that no action has been taken so far. Tube-

[Shri P. K. Deo]

wells have to be dug in millions to tap the underground water. Pumps have to be energised for which electricity has to be supplied at concessional rates. Transmission lines have to be subsidised. I am sorry that *Jai Kisan* is only a slogan and there is absolutely no awareness on the part of the Government to the needs of the cultivator. Whereas an industrialist has to pay only 3 paise per unit of electricity for his aluminium plant the kisan has to pay in some States even 19 paise. In some States there has been some reduction, but it has not been uniform and consistent with the realities.

The latest craze for fertilisers and adaptability to modern techniques are welcome signs. But in respect of nitrogenous fertilisers, as against a target of 12.2 million tons, by the end of the third plan we have achieved only 6 million tons. Of course, new plants are coming up in Namrup, Gorakhpur, Visakhapatnam, etc.

The installed capacity will then come to 21 million tons. Naphtha from our refineries is the main raw material for our nitrogenous fertiliser plants now. There may be shortage with a 21 million installed capacity. So I beg to submit that ammonia from the surplus natural gas in the middle-east should be tapped. There should be no diplomatic dogma in this regard. We should try to get the latest technical know-how in agriculture. Taiwan and Israel have made tremendous progress. But, I am sorry to say, diplomatic dogma stands in the way. We have not even recognised their existence. We should try to exchange technical know-how in the field of agriculture. We should try to send progressive agricultural farmers to these areas and there should be an exchange of ideas in this regard.

Regarding food zones, we are against food zones and controls because these breed corruption. We are for an all-India market but in special cases where the purchasing power of the people is very poor, especially in States like Orissa surrounded by an industrial belt, as soon as the barrier will be removed the surplus State will be reduced to a deficit one.

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FOOD, AGRICULTURE, COMMUNITY DEVELOPMENT AND COOPERATION (SHRI ANNASAHIB SHINDE): Would you like to have State zones for Orissa or not?

SHRI P. K. DEO : I am explaining that in special cases where the purchasing power of the people is very poor then we will have to have these zones.

Sir, in this House and in the Rajya Sabha we have been hearing several allegations that food is being used as a lever to topple down non-Congress Governments. I do not know how far it is true. Orissa is a surplus State. We have no experience of this political move or this elbow twisting so far. But if it is true, it is a sad day for this country (*Interruptions*).

Procurement should be maximised. But this procurement should be made in the open market. I do not mind the Food Corporation of India working in competition with the traders. Even though there has been some improvement in the procurement price—I welcome it—I say that it should be the minimum support price and anything above that will be welcome. The traders should be given freedom to trade in foodgrains inside the State and if there is any surplus, of course, it can be exported.

SHRI RANGA (Srikakulam): Exported through the Food Corporation.

SHRI P. K. DEO : Coming to prices, the prices have been sky-rocketting. Even though there has been a slight decrease in the prices in August-September-October this year, it is much more than the prices prevailing in the corresponding period of last year. Taking the base of 100 in 1952-53 the wholesale price index of cereals and foodgrains has gone up to 220 in October which is a decrease from 232 prevailing before August, but last year at this time it was only 170.

Sir, the essential food needs of a common man have to be assured. The weaker and vulnerable sections of our society have to be supplied these articles at subsidised rates. I take my hat off

at the achievement of the DMK Government in Madras for supplying one measure of rice per rupee to the people in the statutory rationing area.

High prices and inflation are the creation of the Central Government. For this subsidy the Central government should bear the full burden. Even in other States if the weaker and vulnerable sections of the society have to be supplied food at subsidised rates, it is the Centre which has to pay it to the State Government.

In the last two years of drought there has been a shortfall of 30 million tons and complete depletion of the buffer stock and this year 7 million tons have to be procured from the kharif.

Coming to credit, I would like to submit that adequate credit had to be made available, at best at 10 per cent interest. Now, while the Reserve Bank has been giving loans at 3 per cent interest, the cooperative societies are charging much more.

Lastly, in regard to debts given to agriculturists during natural calamities like floods and cyclone there should be a moratorium and they should even be written off. Similarly, the assistance given by the Centre to the States to fight natural calamities should be written off and the States should not be asked to pay them back.

Then I would say that there should be complete abolition of land revenue. A directive should go from the Centre to the States to implement the decision about abolition of land revenue. A lead has already been given by the Orissa Government in this matter.

Then, we have not yet explored the vast resources of the sea which we have in the matter of marine food. It is high time that we made some effort to tap these resources to relieve our food problem. Also, efforts should be made to reclaim the Rann of Kutch, the great Thar desert, the Chambal Valley and the Dandakaranya area. It should be done in right earnest and the land should be distributed to the landless.

Finally, Sir, there is a great awakening among the farmers and all sections of our people and, if properly harnessed, the release of this tremendous energy could help us to tide over our food problems for all times to come.

SHRI D. N. PATODIA (Jalore) : Sir, I have given notice of a substitute motion which I want to move.

श्री देवराव पाटिल (यवतमाल) : उपाध्यक्ष महोदय, इस के सम्बन्ध में मेरा भी एक संकल्प था . . . . .

SHRI ANNASAHIB SHINDE : All the substitute motions have been moved already.

MR. DEPUTY-SPEAKER : Not all. Those members who were present and those who requested the Chair were allowed to move their motions.

श्री देवराव पाटिल : मैं मीटिंग में चला गया था, मेरे पीछे से इस को यहां ले लिया गया । जब मैं आया और मैंने रिक्वेस्ट की तो मुझे कहा गया कि कल पूछना । मैं अपने संकल्प को प्रस्तुत करना चाहता हूं ।

MR. DEPUTY-SPEAKER : I will now allow them to move their substitute motions.

SHRI D. N. PATODIA : I beg to move :

"That for the original motion, the following be *substituted*, namely :—

'This House, having considered the food situation in the country, is of the opinion that the zonal restrictions regarding movement of foodgrains from State to State and district to district should be expeditiously abolished and as and when the State Governments take the initiative in this regard they should be encouraged by the Centre and not hindered in their initiatives.'"(13)

SHRI DEORAO PATIL : I beg to move :

"That for the original motion, the following be *substituted*, namely :—

'This House, having considered the food situation in the

[Shri Deorao Patil]

country, appreciates the attempts made by the Government to ease the food situation in the country and recommends to the Government that (a) minimum procurement prices of agricultural commodities, especially of foodgrains, should be remunerative to farmers, being based on actual cost of production and (b) immediate steps be taken to subsidise the price of foodgrains for weaker sections of the society.'" (37)

श्री क० ना० तिवारी (बेतिया) : उपाध्यक्ष महोदय, ...

MR. DEPUTY-SPEAKER : The hon. Member may resume his speech after the lunch recess.

13 HRS.

The Lok Sabha adjourned for Lunch till Fourteen of the Clock.

The Lok Sabha re-assembled after Lunch at four minutes past Fourteen of the Clock.

[MR. DEPUTY-SPEAKER *in the Chair*]

MOTION *RE* : FOOD SITUATION IN THE COUNTRY—*Contd.*

MR. DEPUTY-SPEAKER : Before Shri K. N. Tiwary resumes his speech I would like to point out that since it is an important debate and I have already received chits from many hon. Members from various regions, to accommodate as far as possible all regions and all sections of the House I would request hon. Members to be very brief.

श्री क० ना० तिवारी (बेतिया) : उपाध्यक्ष महोदय, यह एक रिचुएल जैसा हो गया है कि जब भी पार्लियामेंट बैठती है तब हम फूड पर डिबेट करते हैं लेकिन मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि उस के दौरान जो सुझाव दिये जाते हैं उस पर सरकार ने कितना अमल किया है और किया जा सकता है इस के उपर सरकार ध्यान नहीं देती है । इससे हम लोगों का असन्तोष बढ़ता है और साथ ही कृषि उत्पादन में वृद्धि करने, पैदावार को बढ़ाने में ज्यादा प्रगति नहीं होती है । मैं उन प्वाइंट्स को दुहराना नहीं चाहता जिनका कि जिक्र आज से पहले कई मौकों पर किया जा चुका है । इस अवसर पर मैं कुछ सुझाव सदन के सामने देना चाहता हूं और कुछ बातों की ओर इस हाउस और मंत्री महोदय का ध्यान दिलाना चाहता हूं जो कि किसानों के लिए बहुत ही आवश्यक हैं ।

फूड ऐंड एग्रीकलचरल डिपार्टमेंट ने एक कमेटी सैट अप की थी जिसका कि नाम एग्रीकलचरल प्राइसैज कमिशन हुआ । उस ने एक रिपोर्ट की है । बार-बार इस बात के लिये अन्य लोगों ने और हमारे विभूति मिश्र जी ने सरकार से मांग की है कि इस कमेटी में किसानों के रिप्रजेंटेटिव्स रहने चाहिए लेकिन सरकार ने इस के ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया । उस कमेटी में बैठने वाले प्रोफेसरों ने एयरकंडिशंड कमरों में बैठ कर एक रिपोर्ट तैयार कर ली और उसे सबमिट कर दिया बाकी मुझे यह कहने के लिए माफ़ किया जाय कि वह लोग धान, मकई आदि के पौधों में कोई फर्क नहीं समझते । उनको पहचान भी नहीं सकते । ऐसे लोगों की उस कमेटी में नियुक्ति की गई है । यह रिपोर्ट जो मेरे हाथ में है उस को देखने से यह पता चलता है कि जिस काम के लिए उनको मुकर्रर किया गया उन्होंने एक शब्द भी उस के बारे में नहीं कहा । फूड कमोडिटीज की प्राइस क्या होनी चाहिए वह नहीं बतलाई गई है । धान की क्या प्राइस होनी चाहिये, मकई की क्या प्राइस होनी चाहिए, कोर्स ग्रेन की, गेहूं की क्या प्राइस होनी चाहिए उस के बारे में इस रिपोर्ट में एक शब्द नहीं लिखा गया है । मालूम ऐसा होता है कि यह किसानों के विरुद्ध कोई कमेटी बैठाई गई हो और चुनांचे जितनी भी किसानों के हित की बातें हैं उन के विरोध में जितना भी वह लिख सकते हैं वह उस कमेटी ने लिखा है और उसने अपनी वह रिपोर्ट गवर्नमेंट को सबमिट की है ।

इस समय उन सारी बातों में और उन सारे डिटेल्स में मैं नहीं जाना चाहता क्योंकि समय नहीं है लेकिन यह चीज कि कितना मिलियन अनाज बाहर से आयेगा, कितना मिलियन यहां देश में पैदा होगा और कितने मिलियन का बफर स्टाक है इन सब की चर्चा इस किताब में की गई है। लेकिन जैसा कि मैंने पहले कहा इस में किसी जगह पर यह नहीं बतलाया गया और आज तक इस बात की खोज इस कमिशन ने नहीं की कि क्या लागत खाद्यान्न के उत्पादन में आती है चाहे वह धान हो, ईख हो या और कोई कोर्स ग्रेन हो। आज तक कमिशन का जो मुख्य काम था जिस के कि अधार पर प्राइस फिक्सेशन होता और किसानों को रैम्यु-निरेटिव और एक इंटेग्रेटैड प्राइस मिल सकती जिस के लिए कि आन्दोलन किया जा रहा है, मांग की जा रही है गवर्नमेंट आज तक उसे नहीं दे सकी है। इसलिये मेरा सुझाव है कि यह जो रिपोर्ट दी गई है उस रिपोर्ट को अमल में न लाया जाय। यह रिपोर्ट ऐंटी किसान है। इसमें साफ़ कहा गया है कि उन्हें अन्न का भाव कम दिया जाय। जो मार्केट प्राइस हो उस मार्केट प्राइस से कम दाम किसानों को दिया जाय। अब आप यह समझें कि हर एक चीज जो कि किसानों को अपनी जरूरत के लिए खरीदनी पड़ती है चाहे वह फर्टिलाइजर्स हो, चाहे वह बैल हों, साग-सब्जी हो, कपड़ा हो या खेती के अन्य आवश्यक औजार आदि हों, उस की जीवनापयोगी सभी आवश्यक चीजों के दाम जोकि उसे बाजार से खरीदनी पड़ती हैं आज किसान को उनकी कीमत दुगनी, चौगुनी, दस गुनी और किसी किसी हालत में तो 100, 100 गुनी तक अदा करनी पड़ती है। ऐसी हालत जब हो रही है तो अगर इस कमेटी की सिफारिशों को अमल में लाया गया तो जो पैदावार में वृद्धि की अपेक्षा सरकार रखती है वह पैदा-वार उपलब्ध नहीं होगी क्योंकि यथेष्ट प्रोत्साहन के अभाव में किसान उतना ही उत्पादन करेंगे जितने कि उन को अपने लिये आवश्यकता है। परिणाम आखिर में इस का यह होगा कि सरकार अनाज का जो बफर स्टाक बनाना चाहती है या सरकार जो उन से प्रोक्योरमेंट करना चाहती है वह प्रोक्योरमैन्ट नहीं हो सकेगा।

इस रिपोर्ट में यह बात कही गई है कि एक सुझाव इस कमेटी के सामने यह आया था कि एक गांव से दूसरे गांव में अन्न न जाने दिया जाय क्योंकि उस का हमें प्रोक्योरमेंट करना है। लेकिन अब जब कि सारा देश इस बात की डिमांड कर रहा है, मांग कर रहा है कि जोनल सिस्टम हटना चाहिए और इस बात के लिए यहां जो हमारे विरोधी सदस्य हैं वह भी इस की मांग करते हैं लेकिन जहां उनके द्वारा सरकारें बनाई गई हैं वहां पर उन की सरकारें बनने के बाद भी इस को अमल में नहीं लाते।

लेकिन अगर पूछा जाय तो 100 में से 99 आदमी ऐसे होंगे जो जोनल सिस्टम के खिलाफ हैं, सिवा उन सरकारी नौकरों के और बनियों के जो इस से फायदा उठाते हैं।

श्री हुकम चन्द कछवाय : सब बनिये कांग्रेस के अन्दर हैं।

श्री क० ना० तिवारी : वह जन संघ में ज्यादा हैं।

इस लिये मेरा खयाल है कि जोनल सिस्टम को हटाना, जिस की मांग देश के लोग कर रहे हैं, आवश्यक है। इस को ले कर यू० पी० में एक गांव से दूसरे गांव को अन्न जाने पर भी रोक लगाने की कोशिश की जा रही है, एक ब्लाक से दूसरे ब्लाक में अन्न नहीं जाने पाता। उस पर रोक लगाई जा रही है। इस का नतीजा क्या होगा, इस से किसानों के अन्दर किस प्रकार की भावना पैदा होगी, इस पर सरकार को विचार करना चाहिये।

दूसरी बात जिस की ओर मैं सरकार का ध्यान खींचना चाहूंगा यह है कि जो प्रत्येक राज्य सरकारें हैं, उन की परिस्थितियां

[श्री क० न० तिवारी]

अलग अलग हैं । वह अपने प्रान्त में अन्न का क्या भाव दें इस की उन को छूट होनी चाहिये । केन्द्रीय सरकार को रास्ते में नहीं आना चाहिये इस के दो कारण हैं । अगर केन्द्रीय सरकार कहेगी कि यह भाव दिया जाये तो जितने राज्यों में अपोजीशन की सरकारें हैं, वह सब कहेंगी कि सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं देना चाहती है, इस लिये हम नहीं दे रहे हैं । दूसरा नतीजा यह होगा कि किसानों को उचित प्राइस नहीं मिलेगी । परिणामस्वरूप उत्पादन में कमी होगी । क्योंकि किसानों की दूसरी चीजों की परचेजिंग पावर नहीं रहेगी । उनको रैम्युनरेटिव प्राइस नहीं मिलेगी । वह फर्टिलाइजर लेना चाहेंगे पैदावार बढ़ाने के लिये तो वह भी नहीं मिल पायेगी ।

इसके अलावा एक सब से खतरनाक चीज प्लैनिंग कमिशन करने जा रहा है, जिस की खबरें अखबारों और दूसरे सोर्सिज से सुनने में आ रही है । अगर यह बात हुई तो कांग्रेस सरकार याद रक्खे कि वह ट्रेजरी बेंचेज पर नहीं बैठ सकते हैं । इस लिये नहीं बैठ सकते कि किसानों के वोट्स से लोग यहां आते हैं और यहां सब लोग छोटी-छोटी सी बातों से फायदा उठाते हैं और हमारे खिलाफ प्रचार करते हैं । यही सरकारी नौकर, जिन को आप सर पर चढ़ाये हुए हैं, जिन को बिठला कर आप प्लानिंग कमीशन का काम लेते हैं, वह आप की जड़ खोद रहे हैं । उन्होंने मुसलमानी बादशाह को हटाया, अंग्रेजों को हटाया और अब आप को भी हटा कर रहेंगे । इस का कारण यह है कि जो प्लानिंग कमिशन के चेअरमैन हैं वह गांव से नहीं आते, वह शहर के रहने वाले हैं, श्री अशोक मेहता देहात के रहने वाले नहीं हैं । उन का कृषि से कोई सम्बन्ध नहीं है । इस लिये वह कहते हैं कि ऐग्रिकल्चर पर टैक्स लगना चाहिये । इनकम टैक्स लगाना चाहिये, ऐग्रिकल्चर टैक्स लगाना चाहिये । आप को पता है कि एक साल बाढ़ आ जाती है तो दूसरे साल सूखा हो जाता है । लेकिन इस के लिये गवर्नमेंट कोई कम्पेन्सेशन तो नहीं देती । कोई तरीका नहीं है जिससे वह इस के लिये कम्पेन्सेशन दे सकें । चूंकि एक साल बाढ़ आ जाती है और दूसरे साल सूखा पड़ जाता है इस लिये सरकार बफर स्टाक बना कर रखना चाहती है क्योंकि लोग शोर मचाते हैं कि उन को खाना दिया जाये । लेकिन यह किसान के लिये तो नहीं है । अगर एक साल सूखा पड़ गया और दूसरे साल बाढ़ आ गई तो वह यह तो नहीं सोच पाता है कि अगर वह बफर स्टाक नहीं रक्खेगा तो बाल बच्चों को खिलायेगा क्या । उन का क्या होगा ।

इस के अलावा बिहार सरकार प्रति एकड़ किसानों से 8 मन अनाज लेने जा रही है, जो कि खिचड़ी सरकार है । उस के बाद जो भी पैदावार होती है उस की प्राइस वह मार्केट प्राइस से 10 या 15 रु० कम देती है । नतीजा यह है कि जितने भी किसान हैं वह सब के सब घबराये हुए हैं कि अगर वह 8 मन दे दें तो फिर उन के पास बचेगा ही क्या रिपोर्ट में कहा गया है कि कोई कहता है कि 100 मिलियन टन होगा, कोई कहता है कि 95 मिलियन टन होगा और कोई कहता है कि 90 मिलियन टन होगा । हमारे यहां एक कहावत है कि लेखा जोखा था ही, लड़का बूड़ने का ही । एक लालाजी थे । उन्होंने हिसाब लगाया कि यहां पानी एक हाथ है; यहां तीन हाथ है और यहां पांच हाथ है इसलिए औसत इतना हुआ । उसने यह सोचकर के लड़के को पार कराया । लेकिन जहां ज्यादा गहरा था उस का हिसाब नहीं लगाया । नतीजा यह हुआ कि लड़का डूब गया हमारा जिला जो एक तरह से सर्पलस जिला है, आज डेफिसिट हो गया है । आज एक तिहाई जगहें ऐसी हैं जहां पर बिल्कुल फसल काट कर जानवरों को लोग खिला रहे हैं । आरा जिले में भी यही हालत है । हर जिले में कोई न कोई भाग ऐसा है जहां इस प्रकार की हालत है । फिर भी आप कहते हैं कि किसान 8 मन प्रति एकड़ दे दे । कहां से दे ? आज कोई भी गृहस्थ अपनी रोपनी, सोहनी नहीं

करा सकता, अगर वह वनिहारी अनाज में न पे करे अगर कोई मजदूरों को अनाज न दे, क्योंकि अनाज का भाव बहुत ज्यादा है, और रुपया पैसा देना चाहे तो उस को मजदूर नहीं मिलेंगे। इसलिये मजदूर काइन्ड में लेना चाहता है। किसी भी गृहस्थ को अपने खाने के लिये, अपने हलवाहे के खाने के लिये, रोपनी का खर्च, जो कुछ भी है सब के लिये आनाज रखना पड़ता है, और गवर्नमेंट कहती है कि सिर्फ 10 क्विंटल रक्खो। अगर उस के पास अनाज घट गया तो आप के पास कोई सकीम नहीं है, जिससे उस को अनाज मिल सके। इस लिये मेरा अपना खयाल है कि गवर्नमेंट को इन सब बातों की तरफ ध्यान देना चाहिये, यही नहीं होना चाहिये कि वह ऐग्रिकल्चर टैक्स, इरिगेशन टैक्स या दूसरे टैक्स बढ़ावे। प्लैनिंग कमिशन रिकमेन्ड करता है कि इरिगेशन टैक्स बढ़ाया जाये, एलेक्ट्रिसिटी टैक्स बढ़ाया जाये। इस तरह की बात वह सब कहता है लेकिन यह नहीं कहता कि किसान को रेम्यूनरेटिव प्राइस मिलनी चाहिये। जब उस को वह रेम्यूनरेटिव प्राइस देने के लिये तैयार नहीं है तो फिर किसान कैसे क्या करेगा ?

एक बात मैं सरकार से ट्रैक्टरों के बारे में कहना चाहता हूं। वह लोगों को सस्ता दिया जाये। साथ ही हम देखते हैं कि आज फियट और अम्बैसेडर कार का कोटा होता है। मैं समझता हूं कि अगर हम ट्रैक्टर लेना चाहते हैं तो हम को वह भी मिलना चाहिये। यहां बहुत से ऐग्रिकल्चरिस्ट्स बैठे हुए हैं, जो कि ट्रैक्टर इस्तेमाल करते हैं। हमारी मांग यह है कि ट्रैक्टरों का भी कोटा रख दिया जाये, जिस में कि हमें वह जल्दी से मिल जायें और हम समय पर उस को खरीद सकें। जो लेजिस्लेटर्स होते हैं उन के लिये आप ने कारों का कोटा रक्खा हुआ है। अगर आप जरूरत समझें तो कार का कोटा उड़ा दीजिये, लेकिन ट्रैक्टर का कोटा उन को जरूर दिया जाये।

हमारे यहां गंडक प्रोजेक्ट है। बिहार में 13 लाख टन को डेफिसिट है। यह प्रोजेक्ट शरू हो चुकी है, काम हो रहा है, लेकिन रुपये की कमी है। जिस बिहार में 12 या 13 लाख टन का डेफिसिट है वहां अगर यह प्रोजेक्ट पूरी हो जाये तो बिहार की पैदावार 26 से ले कर 30 लाख टन तक बढ़ सकती है। इस तरह से न सिर्फ हम सेल्फ सफिशिएंट हो जायेंगे बल्कि हिन्दुस्तान के दूसरे भागों को भी दे सकेंगे। इसलिये इस प्रोजेक्ट के लिये कहीं से भी हो, बेग, बारो आर स्टील, रुपया मिलना चाहिये।

प्रोक्योरमेंट के बारे में मेरा यह कहना है कि कांग्रेस सरकार जब थी तब वह प्रति एकड़ 65 के० जी० लेवी लगाती थी लेकिन आज की जो सरकार है वह 8 मन प्रति एकड़ ले रही है। यह क्वांटिटी जो बढ़ाई गई है उसको नहीं बढ़ाना चाहिये।

अब मैं इम्प्रूवड सीड्स के बारे में कह कर बैठ जाऊंगा। इस के सम्बन्ध में रिपोर्ट में बहुत सी बातें कही गई हैं। यू० पी० की रिपोर्ट को मैंने पढ़ा। एस 227 की जो इम्प्रूव्ड वेराइटी है वह वहां पर 150 रु० के० जी० तक बिका। जो भी किसान उस को खरीदना चाहे उस को 150 रु० के० जी० में मिलता है। लेकिन दिल्ली के पास एक फार्म है उस के लिये विभाग कंट्रोल रेट पर सीड देता है, हालांकि वह फार्म अपने यहां से 150 रु० के० जी० ही बेचता है। इस तरह की गड़बड़ियां इम्प्रूव्ड सीड्स के बारे में हो रही हैं। यह नहीं होना चाहिये। नई रिसर्च से जो सीड आ रहे हैं, उनकी तरफ गवर्नमेंट का ध्यान जाना चाहिये और हर एक प्रान्त को उस का फायदा मिलना चाहिये। जो भी किसान उन को मांगते हैं, उन्हें मिलना चाहिये। मैंने खुद मांगा था लेकिन आपके डिपार्टमेंट ने नहीं दिया। 308 है, 227 है, सलोन है, शरबती है, इन सब की तरफ सरकार का ध्यान जाना चाहिये।

अन्त में बहुत न कह कर मैं यही कहना चाहता हूं कि जो सुझाव मैं ने दिये हैं उन को काम में लाना चाहिये। साथ ही जो आप के

[श्री क० न० तिवारी]
अफसरों की कथनी और करनी में अन्तर है उस को भी आप समाप्त करें।

श्री याज्ञिक (अहमदाबाद) : उपाध्यक्ष महोदय आज सारे देश में अन्न का अभाव है। बीस साल हमें आजाद हुए हो गए हैं। आजादी के बाद से नहरों इरिगेशन, बिजली आदि पर काफी रुपया खर्च किया गया है। हमेशा हकूमत की तरफ से कहा गया है कि यह कैनाल होगी, यह पावर हाउस होगा तो हम पूरी तरह से अन्न के मामले में स्वाश्रयी हो जायेंगे। आज भी हम को कहा जाता है कि 1971 के बाद हम को बाहर से अनाज मंगाने की जरूरत नहीं होगी। इस तरह की बातों को हम आज तक हमेशा सरकार से सुनते आ रहे हैं। लेकिन ऐसा आज तक हुआ नहीं। आज मैं समझता हूं कि कैनाल की कुछ बात करना, बिजली की कोई बात करना व्यर्थ है। हम अगर बीस साल में कुछ नहीं कर सके हैं तो 1971 तक जो तीन चार साल बाकी हैं उसमें हम क्या कर सकेंगे। तीन चार साल में अन्न के मामले में स्वावलम्बी हम हो जायेंगे इसमें मुझे संदेह है। हम दो तीन साल में कुछ नहीं कर पायेंगे।

आज हमारे देश का ध्यान खाद, फर्टिलाइजर पर एकाग्र हुआ है। यह बात सच है कि कुछ पानी, कुछ बिजली, कुछ डीजल पम्प और कुछ सीड्ज और कुछ लोन भी किसान को मिलता है। लेकिन आधार सचमुच जमीन की उत्पादन शक्ति पर रहता है। और उत्पादन शक्ति का आधार खाद पर रहता है। इसमें कोई शंका नहीं है। बड़े से बड़ा सवाल आज देश के सामने यह है कि खाद की न्यूनता की कैसे भरपाई की जाए? इसके बारे में क्या किया जाए, किस तरह से देश के लिए जो खाद की जरूरत है, उसको पूरा किया जाए। आज केन्द्रीय सरकार हो या राज्य सरकार हो, जिला परिषद् हो, या ताल्लुका पंचायत हो या ग्राम पंचायत हो या कृषक संघ हो, सब लोगों ने रासायनिक खाद के लिए, जिस को इनआर्गेनिक खाद कहते हैं, उसके पीछे दौड़ धूप शुरू की है। जहां जहां किसानों की, कृषक संघ की, जिला पंचायत की मीटिंगें होती हैं वहां वहां रासायनिक खाद के दलाल पहुंच जाते हैं और शोर मचाते हैं किसानों के बीच में कि हमारा खाद ले लो तो आप पूर्ण रूप से स्वाश्रयी हो जाओगे। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि बीस साल पहले महात्मा गांधी ने जो बात कही थी और जिस को वह इससे पहले भी बराबर कहते रहे हैं उस बात को सब भूल गए हैं। विरोधी पक्ष वाले भूल गए हैं यह कहना. ठीक नहीं है। लेकिन हकूमत तो जरूर भूल गई है इस में कोई शुबाह नहीं है।

अभी कुछ महीने पहले मैंने 28-12-1947 का हरिजन पढ़ा। उस में गांधी जी लिखते हैं कि मीरा बहन देहरादून में थीं। वह वहां खेती का प्रयोग करती थीं। उन्होंने दिल्ली में कम्पोस्ट खाद के लिए एक सम्मेलन बुलाया। राजेन्द्र बाबू उस के प्रमुख थे। उस कान्फ्रेंस में एक प्रस्ताव पास किया गया कि देश में कम्पोस्ट खाद बनाने के लिए काफी प्रयास किसान और जनता और हकूमत की तरफ से होना चाहिये। उस कान्फ्रेंस में मनुष्य, पशु, वनस्पति आदि सब का मल, मूत्र, कचरा, भूसा आदि जो कुछ भी होता है उस सब को मिला कर सुनहरी खाद पैदा करने का एक प्रस्ताव के द्वारा निश्चय व्यक्त किया गया था। इसके बारे में गांधीजी ने जो कुछ लिखा है, मैं उसको आप के सामने रखना चाहता हूं। वह लिखते हैं।

"Given the willing co-operation of the masses of India, the country can not only drive out the shortage of food"

यह वह बीस साल पहले लिखते हैं।

"but can provide India with more than enough. This organic manure ever enriches, never impoverishes, the soil. The daily waste judiciously composted returns to the soil in the form of golden manure causing a

saving of millions of rupees and increasing manifold the total yield of grains and pulses. In addition, the judicious use of waste keeps the surroundings clean, and cleanliness is not only next to godliness; it promotes health".

उस पर लिखते हुए गांधी ने आगे कहा है : कि इस प्रस्ताव पर अमल करना है तो एक मीरा बहन से काम नहीं चलेगा, हजारों और लाखों मीरा बहनों की जरूरत होगी। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि इस के बारे में पिछले बीस साल में हकूमत की तरफ से क्या किया गया है, किसान संगठनों की तरफ से क्या हुआ है, जनता ने क्या किया है, लैंड आर्मी की बात हम सुनते रहते हैं, उस लैंड आर्मी ने क्या किया है, कुछ पता नहीं। अवश्य ही शहरों की जो म्यूनिसिपल कमेटीज़ होती हैं उनको कम्पोस्ट बनाने के लिए हकूमत की तरफ से कुछ सहायता मिलती है। लेकिन उसके लिए कोई यश हमारी हकूमत नहीं ले सकती है। ..... अंग्रेजी हकूमत ने इस म्यूनिसिपल कम्पोस्ट को आरम्भ किया था। आज तक शहरों में इस कम्पोस्ट खाद की प्रक्रिया चलती है, उसका उत्पादन होता है और किसान लोग बहुत खुशी से ज्यादा पैदा दे कर भी इस खाद को ले जाते हैं और अपनी जमीन को अच्छा बनाते हैं।

लेकिन सब से बड़ा सवाल तो देहातों का है। हिन्दुस्तान देहातों का देश है। ज्यादा जनता देहातों में रहती है। कल एक गांधीवादी नेता से मैं मिला था। उन्होंने एक सच बात मुझे बताई। उन्होंने कहा कि किसान और जनता के सामने हम चर्खे की बात करें तो कर तो सकते हैं लेकिन चर्खे से हर एक आदमी का कोई, सच पूछा जाए तो, ताल्लुक नहीं रहता है। लेकिन हर आदमी, हर इंसान पुरुष, स्त्री, बच्चा कोई भी हो खाना तो खाता है और कुछ मल का भी त्याग करता है। जैसे पशु करता है वैसे हर आदमी करता है, हर इंसान करता है। इस वास्ते हर इंसान का फर्ज होता है, उसकी ड्यूटी होती है उसका जो मल है वह देश में खेती के लिए उपयोग में आ जाए। गांधीजी ने कहा था कि यह बहुत मूल्यवान खाद बनती है और उन्होंने एक प्रार्थना सभा में इसके बारे में बोलते हुए कहा था....

"The excreta of animals and human beings mixed with refuse could be turned into golden manure, itself a valuable commodity. It increases the productivity of the soil which receives it. Preparation of this manure was itself a village industry, but this, like all village industries, could not give tangible results unless the crores of India co-operated in reviving it and thus making India prosperous."

अगर कोई यह कहे कि गांधीजी तो पुराने ज़माने के आदमी थे, आज का विज्ञान तो और तरीके से आगे बढ़ रहा है, तो मैं इस सदन को एक किताब में से पढ़ कर सुनाना चाहता हूं, जिस का नाम है, "फ़ार्मिन्ग एंड गार्डनिंग फ़ार हैल्थ आर डिज़ीज़" और उस को लिखने वाले हैं सर अलबर्ट हावर्ड। उन्होंने सारे हिन्दुस्तान में इस बारे में अनुसन्धान किया और खेती का प्रयोग देखा। बरसों के तजुर्बे के बाद उन्होंने 1945 में इंगलैण्ड में एक लैक्चर दिया। उन्होंने एक बड़ी किताब लिखी है, जिस में उन्होंने रासायनिक खाद के अनर्थ का काफ़ी विवरण दिया है।

लेकिन इस नेगेटिव, नकारात्मक, बात पर मैं ज्यादा जोर नहीं देना चाहता हूं, बल्कि मैं इस के पाज़िटिव, रचनात्मक, पहलू पर ज्यादा जोर देना चाहता हूं। मैं रासायनिक खाद के बारे में किसी विवाद में नहीं पड़ना चाहता हूं। सर अलबर्ट हावर्ड सारे हिन्दुस्तान में घूमने के बाद इन्दौर आये। जो कुछ तजुर्बा उन को सारे देश में हुआ था, अपनी सारी जिन्दगी में उन्होंने विज्ञान का जो अनुसन्धान और खेती का अभ्यास किया था, उसके परिणाम स्वरूप उन्होंने इन्दौर में जा कर कम्पोस्ट मैन्युर बनाने की एक योजना बनाई इस किताब में इन्दौर योजना

[श्री याज्ञिक]

का काफ़ी विवरण दिया गया है । हिन्दुस्तान के साथ उन के बड़े अच्छे ताल्लुकात रहे थे । बरसों तक अनुसन्धान और अभ्यास करने के बाद आखिर में इन्दौर में उन्होंने अपनी योजना पक्की बनाई थी ।

सर अलबर्ट हावर्ड अपनी किताब में लिखते ह ....

"We can restore and maintain the fertility of our soil by copying the operations of nature as seen in our roadside hedges and in any place of wood land. To do this, we must convert all our vegetable and animal waste into humus. Nature in the wood or hedgerow does this on the surface of the ground. The vegetable and animal refuse make an ideal mixture which is then broken down by moulds and microbes with the ultimate formation of sweet-smelling leaf mould as humus. Two things have to amalgamate to form this humus, the undecayed portion of the mixed wastes and the remains of the moulds and microbes which ferment these residues.

इस बारे में गांधीजी ने जो विचार प्रकट किये हैं, उसकी ओर भी में सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं । उन्होंने गुजराती में लिखा है, लेकिन मैं गुजराती नहीं पढ़ूंगा, उसका सारांश हिन्दी में दूंगा ।

श्री अ० सि० सहगल (बिलासपुर) : गुजराती में ही पढ़िये ।

श्री याज्ञिक : अच्छा । गांधीजी ने कहा है :

"आवा खातर ने हूं सोना जेटलूं किमती खातर गणु छूं । ए खातर थी जमीन हमेशा ताजी रहे छे । जुसई ने परी नथी जती क्यारे एम कहवाय छे के रासायनी खातर थी जमीननो कस चुसई जाए छे । तेपार्थी जीव उड़ी जाए छे । ने अमुक वपराश पछी तेने खाली राखवी पड़े छे । वली जीवतु खातर हानिकर जीवपैदा नथी थवा देतु ।"

यह जो रासायनिक खाद है, उस से क्या होता है ? कीट और जन्तु काफ़ी पैदा होते हैं और उन को मारने के लिए इन्सैक्ट साइड और पेस्टी साइड का बड़ा प्रवाह भारत में भी शुरू हो गया है ।

अब मैं रचनात्मक दृष्टि से हुकूमत को एक सुझाव देना चाहता हूं । गांधीजी की जन्म-शताब्दी दो साल में आने वाली है । मैं तो पुराना गांधीवादी हूं । मैं सोचता हूं कि जब जन्म शताब्दी का उत्सव मनाया जायेगा, तो हमारी हुकूमत क्या करेगी, हमारी जनता क्या करेगी ? सिर्फ सम्मेलन और नाटक किये जायेंगे । फोटो लगाये जायेंगे और कुछ मूर्ति-पूजन होगा । मैं सोचता हूं कि यह एक ऐसा मौका है, जब हुकूमत को इस बारे में कोई ठोस कदम उठाना चाहिये । अंग्रेज सरकार ने म्यूनिसिपल कम्पोस्ट के बारे में जो कुछ किया था, वह तो आज भी चलता है, लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि हमारी हुकूमत ने देहात में किसानों द्वारा कम्पोस्ट के उत्पादन को उत्तेजन देने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया है ।

एक माननीय सदस्य : क्या ठोस कदम उठाना चाहिए ?

श्री याज्ञिक : म्यूनिसिपेलिटी की तरफ से कम्पोस्ट खाद बनाई जाये, इस के लिए सबसिडी, लोन और मदद दी जाती है, मगर देहात में जो ज्यादा कम्पोस्ट होती है, उसके लिए कुछ नहीं किया जाता है । चाहे रासायनिक खाद का कितना भी उत्पादन हो, हमारे देश के कोटि-कोटि किसानों तक वह पहुंचने वाला नहीं है, क्योंकि वह बहुत महंगा है । हमारे मंत्री नये नये कारखाने मगाने के लिए बहुत दौड़-धूप कर रहे हैं । लेकिन चाहे कितने भी कारखाने लग जायें, हिन्दुस्तान के कोटि-कोटि किसानों के लिए पूरा प्राविजन नहीं होगा । यह खाद देहात के क्षेत्र में बहुत है । वह किसान के घर के नजदीक है । वह सोना है । गुजराती में उस को

धूल कहते हैं। धूल से अनाज पकने वाला है, पक सकता है। गांधीजी ने जो रास्ता दिखाया है, अगर किसान, सब पार्टियों के हमारे दोस्त और हुकूमत, सब परस्पर सहयोग करते हुए, कन्धे के साथ कन्धा मिला कर उस पर चलें, तो मैं समझता हूं कि हम अन्न के सम्बन्ध में कुछ बरसों में ही स्वाश्रयी हो सकते हैं।

गांधीजी ने इस बारे में एक चेतावनी दी थी। उस चेतावनी की तरफ ध्यान न देने से क्या परिणाम होगा, वह आज हम देखते हैं। उन्होंने कहा है :

> "Unless India concentrated her whole energy on this vast constructive effort, if her children occupied themselves in unseemly communal strifes, her fate would be like that of the Yadavs of old, who wasted their time in drinking, debauchery and gambling and ended by cutting each other's throat."

यह एक चेतावनी है जनता को भी और हुकूमत को भी। मैं हाथ जोड़ कर यह विनती करना चाहता हूं कि सब इस बारे में सोचें। हमारे देहाती क्षेत्र में खाद की बहुत सामग्री पड़ी है। वह मुफ्त में पड़ी है। उस को हम आसानी से इकट्ठा कर सकते हैं। वह किसान को बहुत सस्ते में मिल सकती है। सब उसका उपयोग करने की कोशिश करें।

SHRIMATI SUCHETA KRIPALANI (Gonda) : Mr. Deputy-Speaker, Sir, as most of the hon. Members will confine their remarks mainly to the problem of cereals or food as such, in the limited time at my disposal I am going to confine my remarks only to the difficulties created in one important item of food—sugar.

There is a crisis in production. There is a crisis in distribution and there is a crisis in prices or availability. Throughout there is a crisis in the sugar industry and sugar production. The unfortunate part of it is, this crisis has been with us for the last twenty years. If I am not wrong, in the very first Parliament and the beginning of the First Plan, respected Member Acharya Kripalani had very strong things to say about sugar industry.

AN HON. MEMBER : And very bitter things too.

SHRIMATI SUCHETA KRIPALANI : I find that every year is a year of crisis for the sugar industry and sugar production itself. That goes to show that we have not succeeded in evolving a long-range policy. I can understand if we have a long-range policy and from time to time as emergencies occur we adjust it and follow certain short-range policies within that long-range policy. But, unfortunately, we have not succeeded at all in evolving any policy which is reasonable. At one time we gave certain incentives in the price of sugarcane; as a result vast acres of land went under sugarcane cultivation. Then we, that is States, were given instructions to reduce the land under sugarcane cultivation and increase production of cereals. The State Governments then tried to give some disincentives and the acreage under sugarcane was brought down. The moment that was done, again there was difficulty and they were asked to increase the acreage under sugarcane. So, there have been ups and downs all the time. I can understand this kind of ups and downs in a very vital item like sugar if we have a totally free economy and there is no planning. Then such a chaotic condition can prevail.

But we have been under a planned economy for the last 16 or 17 years. What is the meaning of Plan? The Plan takes into consideration what is the domestic requirement of sugar, how much we need for export, how many factories are there and what is the productive potential in the country, and taking everything into consideration the planners lay out a policy which we follow gradually, increase our production and satisfy the requirements of the people and meet export needs.

Somehow or the other this problem has baffled the ingenuity of Government. In spite of all the clever people in the Planning Commission the result we see

[Shrimati Sucheta Kripalani]

is that prices are continuously rising and there are fluctuations in production. Continuously this situation is obtaining for the last twenty years. So I am constrained to conclude that we have really no policy, we have only a hand-to-mouth policy. If there is more production we adopt one measure and if there is less production we adopt another measure. Somehow or the other we are not able to meet this problem.

The chaotic condition that now prevails in the sugar industry is due to two factors. One is, more and more acreage is going away from sugarcane cultivation and the other is, the keen competition in price between khandsari, gur and sugar. In India we have adopted a mixed economy. We say we will have both large-scale and small-scale industries. We do not want to kill either of them. If we do not wish to kill either of them, we have to demarcate the spheres, demarcate the areas and give protection to both in a balanced manner so that gur and khandsari can survive and at the same time sugar industry does not suffer. But here we see that sugar is controlled by the Central Government, the factories are also under the control and regulation of the Central Government whereas gur and khandsari are under the control of the State Governments. Balance and harmony that should exist in the policy to protect the three is not there and as a result sugar industry is suffering very greatly. Formerly, as I said, there was a certain incentive given in the price of sugarcane and therefore sugar production increased. Then the production of cereals was at a disadvantage. Now sugar is not the only cash crop. Cereals, paddy, wheat or whatever it is—are also virtually cash crops. Therefore, the element of incentive in cane price is no longer there. On the other hand, *khandsari* and *gur* are able to pay an extra-ordinarily high price for the sugarcane as a result of which there is large-scale diversion of cane.

We may not have sympathy for the capitalists or for the factory owners, but we have to have sympathy for the industry itself. I come from a State, Uttar Pradesh, where there is no worthwhile industry, except the sugar industry, with 71 mills and an organised labour of something like one lakh workers. If this labour is thrown out and if the factories are closed, you can very well imagine what the situation would be. I do not wish to expand on another point, namely, Bihar and U.P. are the two land-locked States which suffer from great disadvantages compared to other States in the matter of the sugar industry. We have legitimately a grievance against the Central Government but this is not the forum for raising that issue. I only want to reiterate that there is that problem, the problem of having proper adjustment between the different States to ensure industrial progress. We now have only rivalry and not adjustment between States. For these reasons, sugar industry in both the States is languishing.

Even in the matter of distribution, even though distribution is controlled by the Government, what is the situation? Where is sugar distributed? It is distributed only in the urban areas. The rural areas do not get sugar. Therefore, in the matter of production, distribution and cane prices, everywhere we notice difficulties and imbalance.

SHRI ANNASAHIB SHINDE: If the State Governments want to distribute sugar in the entire rural areas, I have no objection.

SHRIMATI SUCHETA KRIPALANI: I quite appreciate that the quantity at our disposal is not adequate enough to distribute it to the rural areas all over India. I am only placing the facts of the case before the House. The facts of the case are that what we give to the rural areas is only *nam matra*, only a symbol. We do not give anything to the rural areas. Therefore, we have this problem and we have to admit it. This industry has entered a vicious circle and we have not been able to bring it out of it through lack of a proper long-range policy.

The production had gone up, because of various encouragements, in 1965-66 to 35.37 lakhs tons. It has now come

down to 22 lakh tons, may be even less. Whereas the target for this year was 37 lakhs tons, there is, therefore, a fall in production of 38 per cent and there is a fall in acreage of sugarcane by 14 per cent. Here I would quote from the statement issued by the government themselves. In the statement on Sugar Policy, government stated :

> "On the basis of information so far received it is estimated that the area under sugarcane crop in this country during the next season" that is 1967-68 "may see a further decline of about 17 per cent over the current year. *Gur* and *khandsari* prices continue to rule very high. On the basis of the existing pattern of controls the production of sugar in the coming year is estimated to vary from 15 to 17 lakhs tons, as against 22 lakhs tons."

This is government's own statement. That means that there is a very serious crisis in the industry. How to meet it is the problem.

Two years back, the Central Government raised the excise duty from Rs. 28.35 to Rs. 37. This increase in excise duty added to the complication of the sugar industry. As a result, there is acute shortage, high prices and diversion of cane from the factories to *gur* and *khandsari*.

I shall just give you a brief idea about the prices. We, many of us, have been demanding that the sugarcane price should be given a rise, it should be revised upwards. The Government have fixed the price at Rs. 2.75 per maund whereas the actual price in East UP, where we have very little competition from *gur and khandsari* except in some pockets, is Rs. 10.72. In West UP it varies from Rs. 12 to 15 and in the Kumaun division, where the cane unions had recently met, have demanded Rs. 20 per quintal plus one kilo of sugar per cart of sugar delivery. In Haryana the government and the sugarcane growers came to some kind of understanding and they fixed a price of Rs. 12 per quintal. The same thing has happened by mutual adjustment in Punjab—Rs. 12 per quintal. In Maharashtra, where the price is linked with recovery, the prices range from Rs. 12 to Rs. 14, even up to Rs. 17 per quintal. In Rajasthan it is Rs. 12 per quintal. In Bengal, in Plassey Mills, it is Rs. 10.38 per quintal.

Nowhere it is less than Rs. 10; it is in fact more. It is Rs. 12 and anything higher than that. Why is such high price range obtaining? It is because the prices of gur and khandsari have gone beyond any calculation. In Hapur market gur, is Rs. 180 a quintal this year whereas it was Rs. 74 a quintal last year. It has become more than double. Khandsari is Rs. 350 to Rs. 380 a quintal and more. I am sure, the Minister knows that they are bonding the cane for the next season at a very fantastic price. Therefore, in the next season, as he has rightly envisaged, we will produce even less sugar.

Against this background the millowners demanded that a certain quantum of sugar production should be allowed to them for free sale. The Government has accepted that suggestion and have allowed 35 per cent for free sale. We have to wait and watch. I am not one to say that you make the entire sugar free; I would certainly like you to watch. But the representation that the millowners have made to us is that the Government levy will be 65 per cent of production taking the export quantum and the quantum that the Government will distribute under control. So, for free sale they will have 35 per cent only. If, instead of paying Rs. 2.75, they are paying Rs. 15 or Rs. 20 a quintal, the entire burden of the increased sugarcane price will fall on this 35 per cent. Therefore, the price of sugar in the free market will not come down. I agree that we should watch the market but I feel that the price of sugarcane needs to be revised taking into consideration the prevailing market price which is Rs. 12, Rs. 15, Rs. 16 or Rs. 17. If the prevailing market price is so much, how do you expect the factories to get the cane at that absurd price of Rs. 2.75? Many States have been recommending that there should be an upward revision of the sugarcane price. I appre-

[Shrimati Sucheta Kripalani]

ciate the difficulties before the Government but then there should be some kind of a balance between the actual price and the price fixed by Government.

If the sugar factories close, what is the condition in UP with which I am more familiar, I will tell you.

एक माननीय सदस्य : बिहार की क्या स्थिति है ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी: बिहार की भी वही कन्डीशन है।

Bihar and UP more or less are on the same lines but the UP people were careful enough to give me the facts and figures; you did not.

In West UP, the factories started crushing almost three weeks later than the normal season and after four or five days of starting some factories stopped. Again, after fixing the price at Rs. 15 some of them have started functioning but I am told that they do not expect to run beyond the end of December or at the most the first week of January. Then, what happens to labour? Those of us who are familiar with the condition of labour know that if the factories do not run for 90 days there will be compulsory leave granted even to permanent labour. We have in UP one lakh of labour in the factories. If they are thrown out and are unable to earn or if they have to go on compulsory leave, with the present condition of recession in industry the situation there will be further aggravated.

Then, as a result of the loss in sugar production there will be other losses to the Government. The Government is going to lose about Rs. 40 crores in excise duty and in foreign exchange. The Government have had to cut down their export quantity. The State Governments are going to lose heavily on purchases tax. Besides, other industries that are dependent on the sugar industry, like alcohol, and paper, because bagasse and molasses will be in short supply, these industries will suffer. Therefore, all round there is a grave crisis facing the sugar industry and other connected industries.

How is this to be saved? I do not say that it is an easy problem; it is a very difficult problem. But even this difficult problem can be solved if all of us put our heads together and try to find a way out.

SHRI J. B. KRIPALANI (Guna) : Do we have heads?

SHRIMATI SUCHETA KRIPALANI : The Government, first of all, have to take a decision on the policy.

SHRI UMANATH (Pudukkottai) : He asks, "Do we have heads?"

SHRIMATI SUCHETA KRIPALANI : That is for you to decide because today we were given a compliment for wisdom and what not.

SHRI UMANATH : I am not asking; he is asking.

SHRIMATI SUCHETA KRIPALANI : We have to see that the consumer gets the goods at a reasonable price. With the price ranging at Rs. 6, Rs. 7 or Rs. 8—some people say, Rs. 15; I do not know whether it is correct or not—it is much beyond the Indian consumer's capacity. Therefore it has got to come down.

If gur has to survive, if khandsari has to survive and if sugar has to survive—if all the three have to survive, we have somehow or other to exercise some kind of control on the other two items also so that there is some rationalization price at which they should sell.

Then, there is also the regional rivalry between State and State and some States suffer from grave disadvantages.

SHRI J. B. KRIPALANI : Gur is being used for making liquor.

SHRIMATI SUCHETA KRIPALANI : Yes; the price of gur is ranging so very high because gur is being used for illicit distillation. I am glad, Acharya Kripalani has reminded me of that. The reason why gur is selling at this fantastic price is not only because people are taking more and more to gur—they are taking gur—but because

a good quantity of it is being diverted for illicit distillation for which any price (the sky is the limit) can be demanded.

AN HON. MEMBER : What about sugarcane price ?

SHRIMATI SUCHETA KRIPALANI : I have said that the time has come for a rational upward revision of sugarcane price. There should be a balance between the market price that is prevailing and the reasonable price that the Government should fix. If there is no touch between these two margins, then the industry is thrown into a very chaotic condition. I would, therefore, state that, after twenty years (it does not make me happy to say that) the plan, so far as the sugar industry is concerned, has totally failed, the consumers are suffering and the industry is facing a crisis. The Government should take early steps to remedy the situation.

श्री जि० ब० सिंह (शाहबाद) : उपाध्यक्ष महोदय, आज भी हमारे देश के सामने खाद्य की समस्या उतनी ही जटिल है, जितनी कुछ समय पहले थी। आज भी हमें दूसरे देशों की दया पर निर्भर रहना पड़ रहा है। खाद्य समस्या का हल मुख्यतया चार बातों पर निर्भर रहता है—

1. खाद
2. बीज
3. पानी
4. वितरण व्यवस्था

खाद के सम्बन्ध में मुझे यह कहना है कि आज हमारे खेतों को जो खाद चाहिये, उतनी मात्रा में खाद उपलब्ध कराने में यह सरकार असफल रही है। साथ ही बीज भी हम किसानों को समय पर वह अच्छा नहीं दे पाते हैं। पानी के लिये तो यहां का किसान सदैव इन्द्र देव की कृपा पर निर्भर रहता आया है। आज भले ही हमारे खाद्य मंत्री मन में यह संतोष कर के बैठ रहें कि बरसात अच्छी होने के कारण फसलें अच्छी हो रही हैं, पर मैं कहना चाहूंगा कि यह उनकी भूल होगी। यदि समय रहते प्रबन्ध न किया गया तो इससे भी भीषण कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है। पिछले सालों में जब वर्षा कम हुई और कई राज्यों में सूखे की स्थिति उत्पन्न हो गई तो उसका मुकाबला करने के लिये जो उत्साह आया था, आज वह ठंडा पड़ता जा रहा है। साथ ही हमारे वे सभी प्रयत्न भी ठंडे पड़ते जा रहे हैं। जरूरत इस बात की है कि पानी के विषय में किसान को आत्म निर्भर बनाना होगा, चाहे वह कूंआ खोद कर या ट्यूब-वेल लगा कर या नहरों द्वारा इस मूल समस्या को हल करना होगा। इसके लिये किसानों को सभी प्रकार की सुविधायें प्रदान करनी होंगी। सस्ती सिंचाई की व्यवस्था ही इस समस्या का समाधानकारक हल है।

14.58 HRS.

[SHRI BALRAJ MADHOK *in the Chair*]

मैं एक बात और कहना चाहता हूं और वह यह है कि सरकार को असिंचित जमीन का सर्वे कराना चाहिये। साथ ही उन कारणों की खोज भी होनी चाहिये कि इस जमीन को पानी क्यों नहीं मिल पा रहा है। यदि किसान समर्थ है तो उसे सुविधायें दे कर प्रोत्साहित किया जाय और यदि किसान के बूते से बाहर की बात है तो सरकार को ऐसे स्थानों पर स्वयं सरकारी व्यवस्था करनी चाहिये ताकि पानी की कमी को पूरा किया जा सके। मेरी तो यह भी धारणा है कि यदि पानी की पर्याप्त व्यवस्था न की गई और इन नई खादों का अधिक मात्रा में उपयोग हुआ तो हमारी जमीन की उर्वरा शक्ति क्षीण हो जायगी जिससे लाभ के बजाय अधिक हानि की सम्भावना है।

वितरण भी आज सही न होने के कारण भी इस समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा है। आज देश के अधिकांश लोग जोनल सिस्टम को हटाने की मांग कर रहे हैं। पर खाद्य मंत्री महोदय बड़े गर्व के साथ जवाब देते हैं कि मैं इसे समाप्त नहीं करूंगा। मैं यह कहूंगा कि उन्हें यह करना पड़ेगा, आज नहीं तो कल उन्हें यह पाबन्दी उठानी ही पड़ेगी। कितनी खराब बात है कि एक जगह अन्न सड़ता रहे और

[श्री० जि० ब० सिंह]

दूसरी जगह के लोग तरसते रहें। इससे इस भावना को ठेस लगती है कि भारत के किसी कोने में रहनेवाले हम सब एक हैं। एक की कठिनाई दूसरे की कठिनाई है। मैं तो यहां तक कहूंगा कि यह खाद्यान्न की कमी मानव निर्मित समस्या है और वह मानव यह सरकार और सरकार को चलाने वाले वह व्यक्ति हैं जिन्होंने इस देश के किसानों का अनादर किया। योजनाओं में खेती की तरफ़ दुर्लक्ष किया गया। आज अपने को बचाने के लिए तरह-तरह के बहाने किये जाते हैं। कहीं कहा जाता है कि आबादी बढ़ने से यह समस्या उत्पन्न हुई है तो कहीं चीन व पाकिस्तान के हमले की बात कही जाती है। मैं इसे नहीं मानता कि आज देश में अन्न की कमी है। पहले सन् 1951-52 में जितनी ज़मीन पर खेती होती थी आज उससे दुगनी जमीन पर खेती हो रही है पर इस बीच में आबादी दुगनी नहीं हुई है। साथ ही हमारे देश का अधिक अन्न चोरी छिपे नेपाल द्वारा चीन को और पाकिस्तान को चला जाता है। इसे हम रोक नहीं पाते और मैं पुनः कहूंगा कि अब समय आ गया है कि सरकार को ज़ोनल सिस्टम समाप्त कर देना चाहिए।

15 Hrs.

आज दूसरी समस्या चीनी की देश के सामने है। इसको भी उत्पन्न करने का श्रेय इसी सरकार को है। इस सरकार ने सदैव मिल-मालिकों के दबाव में आकर कार्य किया। चीनी की क़ीमत को तो बढ़ाते गये पर गन्ने की क़ीमत की तरफ़ ध्यान नहीं दिया और किसान पिसता रहा। आज से 5 वर्ष पहले हमारे देश में इतनी शकर पैदा हुई कि हम आत्मनिर्भर हो गये और हमने कुछ विदेशी मुद्रा भी कमाई पर धीरे-धीरे किसान को उसकी मेहनत की कमाई जब सरकार द्वारा न दिलाई गई तो उसने निराश होकर गन्ने की बोआई कम कर दी। आज भी मिलमालिकों को 40 प्रतिशत छूट देकर और गन्ने का भाव 2 रुपये 75 पैसे मन कर के सरकार ने मिलमालिकों की तरफ़दारी की है। आज देश के किसानोंकी मांग है कि गन्ने की क़ीमत 6 रुपये मन की जाय। आज किसान सरकार से यह मांग कर रहा है न कि वह चाहता है कि मिलमालिकों की दया पर उसे छोड़ा जाय जैसा कि आज सरकार ने किया है। यदि इस समस्या को सरकार हल करना चाहती है तो उसे किसान की इस मांग को मान लेना चाहिए।

सभापति महोदय, जब तक इन सभी बातों पर सरकार ध्यान नहीं देगी तब तक इस समस्या का हल हो पाना असम्भव है।

श्री अ० सिं० सहगल : माननीय सदस्य ने अभी कहा कि गन्ने की क़ीमत 6 रुपये मन होना चाहिए तो यह खाड व शक्कर की क़ीमत क्या होगी इसे भी क्या वह ज़रा बतलायेंगे ?

श्री जि० ब० सिंह : अभी बरेली में फ़ैक्ट-रोज गन्ने का दाम किसानों को 5 रुपये मन दे रही हैं।

SHRI CHANGALRAYA NAIDU (Chittoor) : The hon. Ministers, Shri Jagjiwan Ram and Shri Annasahib Shinde, after becoming Ministers in the Ministry of Food and Agriculture, have worked hard to improve the food production and also to improve the conditions of farmers, and the farmers of this country are grateful to them for what they have done so far. But for what they are contemplating to do from now on, for what they are going to do, the farmers cannot excuse the Agriculture Ministers. I was told that the economists and the others in the Planning Commission, who sit in air-conditioned rooms, do not know anything about what is happening outside. They think that they know everything, but actually they do not know anything about agriculture; they might be knowing some other thing, but they do not know anything about agriculture.

For the last twenty years, after getting Independence, the Government wanted to increase the food production and the Government have taken so many steps to improve the food production and also to improve the conditions of agriculturists, but even then, we are not able to reach the target of self-sufficiency in foodgrains. Now our

Ministers have announced on the floor of the House that, by 1971, we will attain self-sufficiency and, I think, they were sincere in saying that. In Government some people wanted to make the country self-sufficient and wanted to take some steps, but in the same Government, there are some others who want to scuttle their efforts and who work against self-sufficiency.

There are two sections in the same Government.

AN HON. MEMBER : To which section do you belong?

SHRI CHANGALRAYA NAIDU : Sir, in the Planning Commission they have decided one thing that the agricultural tax should be imposed. Thev want to introduce agricultural income-tax where they do not have it now. Then they want to increase the electricity rates for pumping water for irrigation and also they want to increase the land tax. So many suggestions these wonderful people have made. Sir, I am sorry to say that we had high hopes on our Agriculture Minister, Shri Jagjiwan Ram. I was told that he has agreed to the suggestion to increase agricultural tax and impose this income-tax and other things. Sir, if it is true, he will be only stabbing the agriculturist in the back, and not only stabbing himself, he will find himself in a bad position, if these taxes are imposed.

All these years how was the agriculturist working? What are the facilities that the Government have provided them? These things have to be taken into consideration. Sir, the consumer or the people who think that they are the masters and who want to boss over the agriculturist, they get facilities. The employees get free education to their children and the officers who live in big buildings here in big cities have got all facilities. They can educate their children and they send their children to convent schools. They have got electricity. They have got everything, all facilities. But the agriculturists who live in villages, what facilities do they have? What are their timings of work? Here, while an officer or a labourer puts in only 8 hours of work a day, the farmer has to get up early in the morning. Whether there are snakes in the fields, he has no electric lights, he has to work in the field, risking his life to the snakes and other reptiles. There, not only the farmer, his wife, his children—the entire family—have to work. That is not the case here; only one man works and he feeds his wife and children in the family. But, in the case of the farmer, his entire family has to work to get their livelihood or to get their crop in time. Sir, these people are suffering like this and I cannot understand why the Government wanted to impose so many restrictions on the agriculturists.

It is said that the agriculturist is the backbone of the country. Only a country which is self-sufficient in food, which has got a strong army and good government, will survive. In our country, even when we have got a good government and a good army, if we do not have enough food, we cannot survive. To survive and to be strong in the world, we have to be self-sufficient in food. To make the country self-sufficient, we have to improve the lot of the agriculturist. We should not impose unnecessary taxes on him and kill the agriculture industry.

In Andhra, already the Government, only a few months back, have doubled the land revenue. If it is Rs. 10, it was increased to Rs. 20. We were paying 8 paise per unit of electricity for pumping water for agriculture. Now they have increased to 12 paise per unit. In every respect the cost of agriculture has gone up. If you want to purchase tractors, the cost of tractor has gone up. In diesel oil the price has gone up. Everywhere has gone up. The cost of chemical fertilisers has gone up. But even after the Government putting all these difficulties, the agriculturist was able to produce something. Now the Government want to put a stop to this production. If that is true, then I do not know what will happen to our country. It is the agriculturists who are the strongest supporters of this Government. If Government are going to harm them, I do not think they will support this Govern-

[Shri Changalraya Naidu]

ment at the next elections, and some of us who belong to the ruling party today may not be here next time sitting on these Benches. I am afraid that some people on the Congress Benches and on the Government side and some people on the planning side are playing into the hands of the Opposition. Though they are on this side, they want to help the Opposition by suggesting such things. That will not only ruin the party in power but also ruin the country as well. I would request the Food and Agriculture Minister not to agree to any such suggestion at least till 1971 when we hope to achieve self-sufficiency. At least till that time I do not want Government to harm the food production by imposing these kinds of taxes.

I am very glad that Government have partially decontrolled sugar. Sugar is distributed to the consumers and they are getting some sugar. It is only the agriculturists in the villages who are actually suffering. In the cities and towns, all officers, labourers and others are getting sugar. After the partial decontrol, the consumers in the cities and towns will be getting their usual quota. It is only those who were till now getting special quotas for manufacture of confectionery and sweets who would not be able to get such quotas hereafter and they will have to purchase it in the open market. When they make such huge profits, I think they would not feel any trouble and they can afford to purchase it in the open market. I believe Government have taken this step now only with a view to decontrol the entire sugar production very soon; for the present they have desired to be careful and that is why they have resorted to partial decontrol. I think that in another year or two they will definitely decontrol sugar in the entire country. If this succeeds, then even in regard to rice and other foodgrains also, they can resort to decontrol. They can try this next year by starting with partial decontrol in foodgrains and decontrol fully in another year.

The sugar factories have been allowed to sell 40 per cent in the open market, and by selling it they will be able to get some money. With this money they can give a little more to the cane-grower than what has been fixed by Government. If the Government's price is Rs. 90 they can definitely pay about Rs. 140 to 150 per tonne of cane. Even then, the factory will not lose anything.

At present, we find that Government are supporting the big industrialists but they are not supporting the agriculturists. For instance, the price at which the molasses are sold by the co-operative sugar factories is controlled by Government and they are sold at Rs. 6.80 per ton. But the molasses produced in the khandsari factories are sold in the open market at about Rs. 400 to 500 per tonne. Even after purchasing the molasses at Rs. 400 or 500 they still make a profit. I cannot understand this policy of forcing the factories to sell the molasses at Rs. 6.80 to the big industrialists. I suspect that there must be some connection between the big industrialists and some people in the Government or the administration.

I do not blame the Ministers. There must be redtapism; and there must be some secretary or somebody in Government who is supporting this move. I want Government to decontrol molasses and allow it to be sold in the open market. This will fetch more money to the producer. If this is done, definitely the cost of sugar will come down. If really Government are interested in bringing down the cost of sugar, they must decontrol and allow the factories to sell molasses in the open market. There is no comparison between Rs. 6.80 and Rs. 400—500. So I request the hon. Minister to take immediate steps to decontrol molasses.

Then for tractors, tyres are not available. The tyre manufacturers say that all the tyres are requisitioned for fitting new tractors. If a tyre of a tractor has to be replaced, we could not get a tyre in the market. Is it the intention of Government that every time a tyre becomes unserviceable, we must purchase a new tractor? I cannot understand this. So I want Government to issue

orders tyre companies so that agriculturists are enabled to buy tyres for their tractors.

We are hearing now and then from Government that in famine areas they are undertaking permanent relief measures. But I find evidence of no such action. We have been hearing this for the last two or three years, but nothing has actually been done. In famine areas, when rain fails, we must bore wells deep into the soil and pump the water to our fields. For this we need deep drilling machines and pumps which have to be imported from abroad. For lifting water 40 to 60 feet, we cannot use bullock power. We have to have electricity. If really Government are interested in affording relief to famine areas, they must concentrate on minor irrigation and extension of electricity to rural areas for agricultural purposes. But from the allotments made, I do not think they are serious about giving any permanent relief to famine areas. I have written to the Prime Minister, I have written to the Minister of Irrigation and Power, to take steps to allot some funds for Andhra Pradesh. If money is sanctioned, schemes can immediately be put through and we can get immediate results. Though we have been making requests in this connection, no aid has been given so far. I would only request the hon. Minister to take immediate steps to sanction some funds for permanent famine relief in Andhra Pradesh.

श्री रामसेवक यादव (बाराबंकी): सभापति महोदय, यह सरकार इस देश की खाद्य समस्या की जितनी ही चिन्ता करती है, उतनी ही वह बिगड़ती जा रही है। कई बार घोषणायें हुईं। जो सब से पहले प्रधान मंत्री थे उन्होंने कई बार आत्म निर्भर होने की घोषणायें कीं, लेकिन वह घोषणायें फाइलों में और लोक सभा की जो कार्रवाई होती है उसी तक सीमित रहीं। उन पर अमल नहीं हुआ। जब एक घोषणा की तिथि पूरी हुई तो दूसरी घोषणा कर दी गई। यह स्थिति बहुत ही भयावह है।

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जब तक खाद्य और खाद्यान्न दोनों का बाहर से मंगाया जाना निश्चयात्मक तरीके से बन्द नहीं होगा, तब तक हम अपने पैरों पर नहीं खड़े हो सकते। अगर यह सरकार सचमुच चाहती है कि हम अपनी समस्या का समाधान करें, तो वह दोनों काम फौरन होने चाहियें। हम अपनी समस्या को तभी हल कर सकेंगे जब हम बिल्कुल यह फैसला कर लें कि अब हम एक छटांक अनाज भी और एक किलोग्राम खाद भी बाहर से नहीं मंगायेंगे। जो कुछ हमको करना है, इस देश में करेंगे। अगर सरकार यह नीति नहीं अपनाती तो मंत्री जी चाहे जितनी घोषणायें करें, और हम लोग भी चाहे इस बहस में हिस्सा ले कर आत्म तुष्टि कर लें, लेकिन समस्या का समाधान नहीं हो सकता।

आप जानते ही हैं कि देश में तीन प्रकार के किसान हैं। एक सैकड़ा तो वे किसान हैं जिनके पास ज़मीन ज्यादा है और खाद, सिंचाई आदि के साधन हैं। उनकी हैसियत ऐसी है कि वे बिजली वगैरह भी लगा सकते हैं, खाद का इंतज़ाम भी कर सकते हैं, बीज का इंतज़ाम भी कर लेते हैं। वे इतने प्रभावशाली हैं कि सभी चीज़ों का इंतज़ाम करना चाहें तो आसानी से कर सकते हैं, बीज खाद, पानी आदी सभी का प्रबन्ध कर सकते हैं। लेकिन यह सब कुछ होने के बावजूद भी नतीजा कुछ नहीं निकल रहा है। उतना उत्पादन उनकी भूमि से नहीं होता है जितना होना चाहिये। इसका कारण यह है कि वे स्वयं खेती नहीं करते हैं और उनकी खेती दूसरों पर आश्रित है। इतने अधिक साधन उनके पास होते हुए भी जो अन्न उपजना चाहिये नहीं उपज रहा है।

दूसरी प्रकार के वे किसान हैं जिनकी संख्या 19–20 सैकड़ा होगी जो कि सरकारी साधनों पर निर्भर करते हैं, चाहें सिंचाई के साधन हों, नहरी पानी हो, नलकूप हों या सहकारी या कृषि बीज भंडार हों। उनसे उनको खाद और बीज मिलता है लेकिन सिंचाई, खाद, बीज आदि की व्यवस्था जो करते हैं उनमें इतना

[श्री रामसेवक यादव]

भ्रष्टाचार हो गया है कि उनसे उनको समुचित सहयोग नहीं मिल रहा है और ये जो सुविधायें हैं इनसे वे वंचित रह जाते हैं।

तीसरी प्रकार के वे किसान हैं जिनकी अस्सी सैंकड़ा गिनती है और वे ऐसे किसान हैं जिनकी जोतें अलाभकर हैं। वे छोटे किसान हैं। इन किसानों की तरफ आपकी बिल्कुल तवज्जह नहीं है। उनके पास न खाद है, न सिंचाई के साधन हैं और न ही सरकारी साधनों से वे अपनी जरूरतों को पूरा कर पा रहे हैं। ये जो उपेक्षित किसान हैं ये तीसरी श्रेणी में आते हैं। सवा छः एकड़ के नीचे वाला यह किसान है। अलाभकर जोत वाला यह किसान है। इसको ही आज सब से ज्यादा सहूलियत देने की जरूरत है। उसको सहूलियत तभी दी जा सकती है जबकि आप उसको कर से मुक्त कर दें। आज वह जमीन का मालिक नहीं है। जब उसके लिए लगान से मुक्ति की मांग की जाती है तो तर्क दिया जाता है कि जमीन पर उसकी मिलकियत खत्म हो जाएगी। मैं पूछना चाहता हूं कि इस शहर में रहने वाले जो मकानों के मालिक हैं या जमीनों के मालिक हैं वे अगर टैक्स नहीं देते हैं तो क्या वे मकानों के और जमीन के मालिक नहीं हैं। लेकिन किसान के लिए जब लगान से मुक्ति की मांग की जाती है तो तर्क दिया जाता है कि जब तक उन किसानों को जमीनों का मालिक नहीं बनाया जाता है उनको कर से मुक्ति नहीं दी जा सकती है। मैं समझता हूं कि जब तक उनको कर से मुक्ति नहीं दी जाती तब तक उनकी स्थिति सुधर नहीं सकती है, तब तक ज्यादा अन्न पैदा नहीं हो सकता है।

जहां तक सिंचाई के साधनों का सम्बन्ध है केन्द्रीय सरकार को चाहिये कि वह छोटी सिंचाई योजनाओं को प्राथमिकता दे। सिंचाई के साधन उपलब्ध करते समय प्राथमिकता उनको मिलनी चाहिये जो कि अस्सी सैंकड़ा छोटे किसान हैं, जो अन्न पैदा करते हैं। मेरी निजी जानकारी यह है कि ये छोटे किसान इतना अनाज पैदा करते हैं कि साल भर खुद उसको खाते भी हैं और उसी में से बेच कर अन्य जरूरी वस्तुयें भी खरीदते हैं, अन्य खर्चे भी चलाते हैं। शादी ब्याह वगैरह भी करते हैं। पांच सौ या एक हजार एकड़ वाले किसान पर अगर कभी लैवी लगाई भी जाती है तो दो तीन क्विंटल अनाज भी नहीं उनके पास से निकलता है। वे भांग छानते रहते हैं। जो वास्तव में काम करने वाले अस्सी प्रतिशत किसान हैं आज उनके पास सिंचाई के साधन नहीं हैं, आज उनको कर्ज नहीं मिलता है, बीज नहीं मिलता है। अगर सरकार सचमुच चाहती है कि उत्पादन बढ़े तो उसको एक योजना बनानी चाहिये। उनके लिये इसको नलकूपों, रहटों और सस्ती बिजली की व्यवस्था करनी चाहिये। सरकार को चाहिये कि समय से बंधी हुई एक योजना वह बनाये और निर्धारित करे कि उस समय के अन्दर अन्दर प्राथमिकता दे कर इन अस्सी प्रतिशत किसानों को वह पानी देगी, खाद देगी, बीज देगी तथा दूसरी सुविधायें उपलब्ध करेगी। जिस दिन इस सारी भूमि के मालिकों को ये तीन सुविधायें मिल जायेंगी उस दिन के बाद हमको फिर बाहर से अनाज नहीं मंगाना पड़ेगा और अन्न के मामले में देश आत्मनिर्भर हो जाएगा।

कहां है सरकार का किसानों की तरफ ध्यान? हम तो किसानों को लूट रहे हैं। उनको हम कोई सुविधायें देना नहीं चाहते हैं। मैं आपको एक मिसाल देना चाहता हूं। आप दिल्ली की मिसाल ही लें। अगर मैं राज्यों की मिसाल दूं तो सरकार कहेगी कि हम राज्यों के बारे में कुछ नहीं कर सकते हैं। लेकिन आप दिल्ली की ही मिसाल लें। यहां क्या हो रहा है? यहां दिल्ली में भूमि अर्जन कानून के अन्तर्गत खेती लायक जमीन किस लिए ली जा रही है? मकान बनाने के लिए ली जा रही है। मेरे पास आंकड़े हैं इसके। करीब 64-65 हजार एकड़ जमीन दिल्ली में, खेती लायक जमीन दिल्ली में इसलिए ली गई है कि उस पर मकान बनाये जायेंगे, बस्तियां कायम की जाएंगी, प्लाट डिवेलप

किये जायेंगे। वहां पर सिंचाई के साधन मौजूद हैं, नलकूप हैं, नहरें हैं। ठीक उसके इस तरफ जो पहाड़ी इलाके हैं, जहां पर भूत-पूर्व मंत्रियों ने जमीनें खरीद रखी हैं, फार्म बना रखे हैं, कुछ मौजूदा मंत्रियों ने भी जमीनें खरीद रखी हैं, उन जमीनों को नहीं लिया जा रहा है। पथरीली जो भूमि है, जहां मकान बनाये जा सकते हैं, जो खेती लायक नहीं है उसको तो नहीं लिया जाता है लेकिन जो खेती लायक जमीन है उसको ले लिया जाता है और उस पर हम आबादी बसाते जा रहे हैं। समुचित मुआवजे की अगर मांग की जाती है तो वह भी नहीं दिया जाता है। मुआवजा क्या दिया जाता है? चार सौ रुपये बीघा, पांच सौ रुपये बीघा मुआवजा दिया जाता है। जब अदालत में जा कर इस मुआवजे के बारे में लड़ा जाता है तो वहां से हजार बारह सौ रुपये बीघा के हिसाब से मुआवजा मिल जाता है। फिर उस चीज को दूसरे किसानों पर लागू नहीं किया जाता है। जब ऐसा करने के लिए कहा जाता है तो जवाब दिया जाता है कि जो लड़ेगा वह पाएगा, जो नहीं लड़ेगा वह नहीं पाएगा। कोशिश यह की जाती है कि कम से कम मुआवजा देना पड़े। मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि 186 वर्ग गज जमीन जिसको हासिल करने में, जिसको डिवेलप करने में मुश्किल से चार पांच हजार रुपया खर्च होता है उसको पांच लाख रुपये में बेचा जाता है। जिस देश में खेती करने वाले किसान की इतनी जबर्दस्त लूट चल रही हो वहां सरकार यह कहे कि हम खेती को सुधार पायेंगे, जमीन से हम अधिक अन्न उपजा पायेंगे, यह कैसे सम्भव हो सकता है। यह कभी नहीं हो सकता है। दिल्ली में एक देहात कल्याण समिति है। उसने आन्दोलन चलाया था। हम को बताया गया है कि सात आठ बरस से हजारों एकड़ जमीन ली गई है लेकिन उसको डिवेलेप तक नहीं किया गया। वह पड़ी हुई है। वह खेती लायक भूमि है। अनाज भी उसमें नहीं बोया जा रहा है। जब सरकार की अन्न के बारे में यह नीति हो, भूमि के बारे में यह नीति हो तो कैसे आशा की जा सकती है कि वह अन्न की समस्या को हल कर लेगी।

इतना ही नहीं, आप देखें कि एशिया सुदूर पूर्व आर्थिक आयोग को 25 जुलाई को कहा था कि अगर कृषि योग्य भूमि पर मकान बनाने की योजना इस तरह से चलती रही, शहरों के विस्तार की योजना इसी तरह से चलती रही तो देश की एक दिन ऐसी हालत हो जाएगी कि फिर कभी वह अपने पैरों पर अनाज के मामले में खड़ा नहीं हो सकेगा। तब हमारी स्थिति क्या होगी इसका अनुमान आप लगा सकते हैं। हम एटम बम वगैरह बनाने की बात करते हैं लेकिन चीनी चावल हम पहले ही समाप्त कर चुके हैं।

हम भूमि सुधारों की बहुत बातें करते हैं। लेकिन खेतिहर मजदूर जो है, जो सही मानों में जमीन का मालिक है, उसको आज जमीन नहीं दी जा रही है, उसको आज जमीन का मालिक नहीं बनाया जा रहा है। जो लोग खेती नहीं करते हैं, जो दूसरे देशों में लगे हुए हैं, जो शहरों में रहते हैं, उनके नाम में जमीन चलती रहती है। इन सब बातों के बारे में बार बार कहा जाता है लेकिन कोई ध्यान नहीं दिया जाता है कुछ नहीं हो पाता है। कभी राज्य सरकारों की बात की जाती है और कभी किसी और तरह की बात कर दी जाती है।

अभी सुचेता जी ने चीनी का प्रश्न उठाया है। चार पांच चकार मिले हुए हैं, चीनी, चन्दा, चुनाव और चोरी। ये चार प्रकार हैं और इन्हीं में यह चीनी और गन्ने का मामला बिगड़ा हुआ है। सरकार ने इस चालू साल की नीति निर्धारित की है। चीनी का दाम और गन्ने का दाम, उसका एक हिसाब मैं आपके सामने पेश करूंगा। आपको पता चल जाएगा कि सरकार ने अपनी मौजूदा नीति से कम से कम तीन अरब रुपये का फायदा मिल मालिकों को पहुंचाया है। दस क्विंटल गन्ने में से एक क्विंटल चीनी तैयार होती है। चार रुपये मन अगर गन्ने का दाम दिया जाए जैसा मिल मालिक अब दे रहे हैं, कहीं चार रुपये, कहीं पांच

[श्री रामसेवक यादव]

रुपये और कहीं इससे कुछ ज्यादा, लेकिन औसत अगर चार रुपया मान लिया जाए तो दस क्विंटल गन्ने का दाम 107 रुपया होता है। एक क्विंटल पर एक्साइज ड्यूटी 28 रुपये 65 पैसे है। केन सैस एक क्विंटल चीनी पर 5 रुपये 27 पैसे हैं। आपकी जो सहकारी समिति है उसका खर्च एक क्विंटल पर 1 रुपया 50 पैसा। दूसरे खर्चे जो उत्पादन में होते हैं वे एक क्विंटल पर तीस रुपये होते हैं। इस तरह से 172 रुपये 40 पैसे फ़ी बोरा या एक क्विंटल चीनी पैदा करने में लगते हैं। इस तरह से 10 बोरे का लागत-खर्च 1724 रुपये हो जाता है। उनमें से 6 बोरे चीनी तो सरकार ले लेगी और 4 छोड़ देगी। सरकार द्वारा निर्धारित भाव 139 रुपये फ़ी बोरे, के हिसाब से 6 बोरों की कीमत 834 रुपये होगी और इस हिसाब से 4 बोरे चीनी का दाम 222 रुपये 50 पैसे फ़ी बोरा पड़ता है। जब चीनी के दामों की यह घोषणा की गई थी, तब से जमुना का पानी न जाने कितना बह गया है। जिस चीनी की लागत 222 रुपये 50 पैसे पड़ती थी, उस चीनी का फ़ी सेल में पहले ही 390 रुपये और 400 रुपये फ़ी बोरा के हिसाब से सौदा हो गया था। इस समय वह भाव बढ़ कर 450 रुपये और 500 रुपये हो गया है।

जैसा कि श्रीमती सुचेता कृपालानी ने कहा है, इस वर्ष लगभग पंद्रह लाख टन चीनी पैदा होगी। दस लाख टन चीनी नियंत्रण में चली जायेगी और पांच लाख टन चीनी 450, 500 रुपये फ़ी बोरे के हिसाब से बिकेगी। कोई छोटे से छोटा मिलमालिक भी 70, 80 हज़ार बोरे से कम पैदा नहीं करेगा। अगर आप हिसाब लगायें, तो इस तरह से कम से कम तीन अरब रुपये का नाजायज़ मुनाफ़ा चीनी के मिलमालिकों को होने जा रहा है।

SHRI ANNASAHIB SHINDE: If the account which you are giving is not proved, what next?

श्री रामसेवक यादव: उस पर बहस हो जाये। मैं उसके लिए तैयार हूं। चार रुपये मन गन्ने का जो भाव है, वह सब को नहीं मिलेगा। इससे कम पर मिलेगा। मैं सदन को यह जानकारी देना चाहता हूं कि किस तरह से सरकारी ख़ज़ाने के पैसे से किसान की लूट होती है। कानपुर में वी० आई० सी० के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं चिरंजीलाल बजोरिया। उन्होंने बेनामी से पांच चीनी मिलों के हिस्से खरीदे हैं। यह अन्दाज़ा लगाया जा सकता है कि वे किसके हैं। मैं चाहूंगा कि मंत्री महोदय इस मामले के बारे में हमें जानकारी दें। इस तरह से सरकारी ख़ज़ाने के ज़रिये करोड़ों रुपयों का मुनाफ़ा कमाया जा रहा है।

सरकार ने जो चीनी नीति निर्धारित की है, उससे न किसान को लाभ पहुंचा है और न उपभोक्ता को, क्योंकि सरकार ने किसान को तो 2 रुपये 75 पैसे के भाव पर बांध दिया है। वह बात दूसरी है कि चालीस सैकड़े की छूट के कारण चीनी मिलमालिक किसान को ज्यादा दाम दे रहे हैं—चालीस सैकड़े की छूट के कारण मिलमालिक चार पांच रुपये मन का सौदा कर रहे हैं, लेकिन इसका श्रेय सरकार को नहीं है।

जहां तक उपभोक्ताओं का सम्बन्ध है, उनको चीनी पांच छः रुपये किलो के हिसाब से मिलती है और बहुत से लोग तो इस दाम पर ख़रीद ही नहीं सकते हैं। यह है सरकार की चीनी सम्बन्धी नीति। यह नीति इसलिए चलती है कि इसमें चोरी भी चलती है, चन्दा और चुनाव की राजनीति भी चलती है।

जैसे कि सरकार भी मानती है, इस वर्ष गन्ने की पैदावार कम होगी। आगे भी कम होगी, जब तक कि सरकार किसान को मिलने वाले बुनियादी दाम को नहीं बढ़ाती है। जब तक ऐसा नहीं होता है, तब तक सरकार चाहे कुछ भी करे, गन्ने की पैदावार बढ़ने वाली नहीं है।

श्री अन्नासाहिब शिन्दे: माननीय सदस्य की राय में गन्ने की प्राइस क्या होनी चाहिए?

श्री रामसेवक यादव : मैं आधार बताता हूं। सरकार गन्ने के लागत-खर्च, चीनी के लागत-खर्च, गन्ना-उत्पादकों और चीनी उत्पादकों के मुनाफ़े और उपभोक्ता की स्थिति को देखते हुए जो भी मुनासिब समझे, वह दाम रखे।

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : माननीय सदस्य क्यों नहीं बताते ?

श्री रामसेवक यादव : मैंने उसका आधार तो बता दिया है। एक समय था 1952–54 के आस-पास, जब कि जितने रुपये मन चीनी बिकती थी, उतने आने मन गन्ना बिकता था। सरकार उस नीति को अपना ले, लेकिन सरकार को इस नीति को चलाने में अपने कर के ढांचे में सुधार करना होगा। उससे न किसान पिटेगा और न उपभोक्ता पिटेगा और मिल-मालिक को भी मुनाफ़ा जायज होगा। लेकिन जब हिस्सा-मार होने लगता है, तो मामला बिगड़ जाता है।

पिछले साल, 1966–67 में, गन्ने की उपज घट गई, लेकिन इससे पहले ज्यादा थी। उस समय चीनी ज्यादा पैदा हुई। तो फिर यह संकट कहां से आ गया ? यह कृत्रिम संकट किस ने पैदा किया ? मिलों में चीनी को चोर-बाजारी में बेचने के लिए जो चोरी चलती थी, सरकार ने चालीस सैकड़ा छूट दे कर उस चोरी को बढ़ा दिया है। यह तर्क दिया जाता है कि रिकवरी कम आती है। लेकिन गुड़ की औसत तो वही है। जब गुड़ की औसत गन्ने के रस के हिसाब से वही है, तो चीनी क्यों कम हो जाती है। जब गन्ने के रस की मिठास वही है, तो रिकवरी भी वही होनी चाहिए।

मिलों में जो चोरी चलती है, उसमें शीरे का मामला भी आ जाता है। उस पर कंट्रोल है, इसलिए वह ज्यादा दाम पर मिलता है। शीरा एल्कोहल, स्पिरिट और कई अन्य उद्योगों में इस्तेमाल होने लगा है। आज स्थिति यह है कि लोग शीरे के लाइसेंस के लिए पांच, दस, पंद्रह लाख रुपये रिश्वत देने के लिए तैयार हैं, क्योंकि उसके सहारे चीनी भी निकाल दी जाती है।

खाद्यान्नों के दामों के बारे में एक निश्चित दाम-नीति होनी चाहिए। लागत-खर्च का हिसाब होना चाहिए। साल भर के बीच में दामों में जो उछल-कूद होती रहती है, उस फ़र्क को ध्यान में रखना चाहिए। किसान की उपज और औद्योगिक वस्तुओं के दामों में संतुलन कायम होना चाहिए। आज एक सूबे और दूसरे सूबे में अनाज के दामों में भारी फ़र्क होता है। उसको खत्म करना चाहिए। उसका तरीका यह है कि एक निश्चित दाम-नीति के आधार पर बुनियादी दाम तय किये जायें। एक सूबे से दूसरे सूबे में अनाज भले ही न जाने दिया जाये, लेकिन शर्त यह है कि उस सूबे में सरकार अपनी तरफ़ से निश्चित भाव पर अनाज खरीदे और दूसरे सूबे को दे। अगर इस प्रकार एक निश्चित नीति निर्धारित की जायेगी, तो तात्कालिक और दीर्घकालीन दोनों समस्यायें हल हो सकेंगी, वर्ना अगर आंख मूंद कर चला जायेगा, तो देश गड्ढे में गिरेगा।

SHRI BHAGAVATI (Tezpur) : Mr. Chairman, we, both the Government and the people, may have some satisfaction in the fact that we have been spared of a very great disaster which could have be fallen us because of acute scarcity of food during the last one year or so. But we cannot forget that people all over the country, particularly in deficit States, suffered very much because of scarcity and non-availability of food and also because of soaring prices. We cannot be complacent by feeling that because this time the monsoon has favoured us and there will be a good crop, and we are out of the wood. It may be so temporarily but we cannot say that the difficulties are over so long as we cannot produce enough so that we are self-sufficient and we have not to import food from outside.

Government have estimated that during the year 1967-68 the food production will be of the order of 95 million tons and that it will be required to procure 7 million tons and import 7.5 million tons and have a buffer stock of 3 million tons. From our experience

[Shri Bhagavati]

we can say that it has not been possible for us to keep up the level of procurement.

I would like to say that it is very important that at this time we procure as much as we can. From the global statistical survey we can see that foodgrains produced are enough for all the people in the world at present but because of uneven distribution among countries, within the countries and among the families of different levels of income, there is scarcity and some people do not get what they want. There is acute mal-nutrition and under-nutrition among people. As a matter of fact, the majority of the people in the world are having much less food than they used to get previously. It is the irony of fate that on the one hand there is progress in science and technology and by applying those methods we have produced more but, on the other hand, people all over the world, particularly in the under-developed and developing countries, that is, two-thirds of the humanity is even now having less food than they should. This being so, it is very important that we should have maximum procurement. If we cannot do that, in spite of good crops and in spite of this estimate of 95 million tonnes of record production we may be facing difficulties.

How to make procurement successful ? I have seen in the report that the Chief Ministers' Conference has proposed that the method of procurement should be left to the States. It may be necessary that the States should be given some laxity about procurement. But there should be a national policy regarding procurement. I have not seen that; I have not seen what exactly is the national policy about procurement. Whether it should be through co-operative agencies or by service co-operative societies or by private traders, there should be one clear indication. I think, it is necessary that all procurement should be through only one agency and that that agency should be the co-operative societies.

I would also like to say that procurement may not be successful if the processing industry is left in private hands. If you want to make procurement successful through the co-operative agency, then the processing industry should be taken away from private hands and given to the co-operative institutions. Both these things should go together.

We all know that in this country about 70 per cent of the people live on land. The basic question that arises now is whether it is possible for any country in any age that 70 per cent of the people can be fed by land. Even in this country, it is a historical fact that so many people did not depend on land in the middle ages. In the middle ages in India 70 per cent of the people did not depend on land for their livelihood. The irony of fate is that when the industrial and mechanical revolution made people in Western countries move from land to industry, in this country the reverse process was there and people from industry, handicrafts or village industries, had to go to land. So, the economic condition of the cultivators or farmers is so bad. If we want to improve the economy of this country, and develop agriculture, this basic fact must be kept in mind. We have to shift a substantial percentage of the people from agriculture to industry. There is no other way.

We want to modernise agriculture. How to modernise agriculture ? We cannot apply modern technology to small holdings which we have at present. These holdings are very small uneconomic holdings. If we want to apply modern technology, we must have bigger holdings but not owned by capitalists or big landlords who employ workers on their lands. This is a very important question to which we have to apply our mind and solve it.

It is also necessary that we do some research on agriculture. In this country, even now, we think that by traditional methods, we can make the country self-sufficient. That is not possible at all. We must learn the modern methods of production. How to do that ? The only way to do that is to have more and more research on agriculture. Strangely enough, even now there is not enough agricultural research in tropical countries. Whatever research has been made so far has been

made in the countries with temperate climate. We cannot import agricultural technology from developed countries to developing countries. That is not possible. It may be possible to import a blueprint of a steel plant from some other country in Europe or America and have it here. But it is not possible to import a blueprint of agricultural farm from America or Somewhere and have it here. We must do our own research. We have not given much emphasis on that. I think, that is very important to do.

Then, it is also very important that we give importance to production of non-cereal food. We are having more and more schools and colleges. We want that all our children, boys and girls, go to schools and colleges. What sort of food are we giving to them? Unless we give them balanced food, how will they do intellectual work? Somebody has said that intellectual growth will be retarded in this country if we do not have enough proteins. What have we done in this regard? As the figures with me show, there is no increase milk production, there is no increase in meat or in egg production or even in fruit production in this country. The *per capita* consumption of milk is only 3 kilograms annually; the *per capita* consumption of egg is only 1 gramme per day; the *per capita* consumption of meat is 4 grammes per day and the *per capita* consumption of fruits is 45 grammes per day. With such a small, negligible, protein food how can our boys and girls will do intellectual work? It has been rightly said that one of the most difficult of intellectual tasks is to maintain balance and if our boys and girls can have that intellectual capacity, then only they can do research work and create new things, make new discoveries and innovations. How can they do that? How can they have the intellectual capacity to do all such work unless they have balanced diet. We want all our children to be educated. What sort of education are we going to have if students are starved of all protein food? We have not applied our mind as to how we can give enough protein food, meat, fish, eggs and fruits, to our children and younger generation? By food, the Government always give emphasis on cereal food as if food means only rice and wheat. We have to see that all varieties of food are produced in this country in enough quantities so that everybody, even the poorer sections of the people, can have this sort of food.

We have claimed that out of 100 cultivators, because of our policy of giving land to the tillers, now 76 cultivators own their own lands, 16 are owner-*cum*-tillers and 8 are tillers. But what we have achieved by our land reform measures, has to be judged from another angle. The number of holdings from 20 to less than 50 acres is 2.9 million and the percentage is 5.8, but they have 83.6 million acres, *i.e.*, 25.7 per cent of the whole operated area whereas the number of holdings from 1 to less than 5 acres is 21.3 million, and the percentage is 43.5; but the area operated by them is 57.1 million acres, the percentage is 17.6. It will be clearly seen from these figures that those having bigger holdings have so much of arable land whereas the number of small holdings is much more and they do not have enough land. So, our land reform measures have not taken this aspect into consideration. It is not just enough to see that tillers become owners of the land, but it is also necessary to see that they get enough land. I hope, this aspect of the matter will be looked into.

MR. CHAIRMAN : The hon. Member may conclude.

SHRI BHAGAVATI : I will conclude by referring to one more point. It has been said in a pbulication by the Programme Evaluation Organisation of the Planning Commission that no single agency, Panchayat Samiti, Co-operative Society or the Department, seems to be in an effective and dominant position to meet the various types of credit needs of the cultivators for various programmes. Credit is one of the essential facilities that we have to give to the cultivators and it is, therefore, necessary to see how we can give these credit facilities to our farmers. Big industrialists get facilities from the socialised capital. Whatever capital they have is socialised capital. It is really a tragedy

[Shri Bhagavati]

that the lower middle class people, the poorer section of the people, do not get any advantage even of the socialised capital. The cultivators do not get the advantage of socialised capital at all. Credit should be provided to the cultivators by the State Bank and the other banks. The State Bank should have branches all over the country. I would personally like the banks to be nationalised and their branches should be set up all over the country, so that the agriculturists can get enough credit and can produce more.

In conclusion, I will say this. This is really a gigantic problem—the problem of producing enough for the teeming millions of this country; it is a challenging problem and we have to meet it. I hope, the Government will take adequate measures so that by 1970-71 we can be self-sufficient in food. The Science Advisory Committee of President Johnson has said that, if India wants to be self-sufficient in food by 1976, she would have to increase the crop-yield by 4% annually.

15.59 Hrs.

[MR. DEPUTY SPEAKER *in the Chair*].

We will have to increase 4% annually over 1964 rate of production. Unless we do that, it will not be possible for us to become self-sufficient in food. How we can do that?—that is the problem. Increasing the yield by 4%, will mean that we have to triple the yield from the historical rate which is only 2.36% per year. If we have to do that, we have to irrigate the land, we have to ensure regular, regulated water supply; we have to see that flood is controlled, soil erosion is controlled, fertiliser is supplied, compost manure is supplied as one of my learned friends has just now said or chemical fertiliser is given. All these should go together.

As regards Assam, I would like to say only one thing. Assam's main problem with regard to food production is flood control and conservation of soil. Unless the river Brahmaputra is controlled, it will not be possible for Assam to go ahead. That is a very big task, a major task and I hope Government of India will take it up.

In these scarcity years, particularly some months last year, even in Assam, —where the food condition was not supposed to be so bad, in the tea gardens and certain other places rice could not be supplied and instead of rice, wheat had to be given. But, even in regard to wheat, the supply was very irregular. I am glad that when I took up the matter with the hon'ble Food Minister, he took immediate steps and some wheat was moved to that area and even then, these people suffered very much. So, I would request the Government to see that adequate stocks of wheat are built up in Assam itself so that the people in that State need not have to suffer for want of supply.

MR. DEPUTY SPEAKER : It is Four O'clock. We shall now take up the next motion standing in the name of Shri Prakash Vir Shastri and others.

15.59 Hrs.

MOTION *RE.* PAKISTANI INFILTRATION INTO KASHMIR

श्री प्रकाशवीर शास्त्री (हापुड़) : मैं प्रस्ताव करता हूं :—

> "कि हाल ही में भारी संख्या में पाकिस्तानियों की काश्मीर में घुसपैठ से तथा राज्य में होने वाली अनेक घटनाओं से, जिनसे यह साबित होता है कि पाकिस्तान-समर्थक एजेन्ट राज्य की शांति भंग करने पर तुले हुए हैं, राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए उत्पन्न गम्भीर खतरे से पैदा हुई स्थिति पर विचार किया जाये।"

उपाध्यक्ष महोदय, जिस दिन से भारत स्वतन्त्र हुआ है उसी दिन से पाकिस्तान काश्मीर में तोड़-फोड़ आक्रमण और दुनिया भर में भारत के खिलाफ़ ज़हर फैलाने का काम कर रहा है। योजनाबद्ध तरीके से पाकिस्तान ने 1965 में काश्मीर में कई हज़ार प्रशिक्षित घुसपैठिये भेजे जिसका परिणाम भारत और पाकिस्तान संघर्ष के रूप में हुआ। सरकार का दावा यह था कि 1965 में जो प्रशिक्षित घुसपैठिये आये थे, वे वहां से वापस चले गये या समाप्त हो गये। लेकिन पाकिस्तान ने जैसे ताशकंद में एक हस्ताक्षर करा कर एक चाल और झांसा दिया था। 740 वर्ग-

मील का वह क्षेत्र जो भारत ने पाकिस्तान से लिया था, जिसमें 270 वर्गमील केवल काश्मीर का ही भाग था, उस पर हस्ताक्षर कराने के लिये जो चाल पाकिस्तान ने चली, ठीक उसी प्रकार से पाकिस्तानी घुसपैठियों की स्थिति हुई---सरकार की दृष्टि में ये घुसपैठिये चले गये लेकिन वास्तविकता यह है कि ये घुसपैठिये भूमिगत हो गये और अण्डर-ग्राउण्ड हो कर वहां के राजनीतिक नेताओं और सरकारी अधिकारियों को बरगलाने और दूसरे ढंग से अपना षडयन्त्र पूरा करने का कार्य करते रहे। इससे स्थिति 1965 से भी कहीं अधिक भयंकर हो गई। काश्मीर घाटी में खास कर उन्होंने न केवल छोटी उम्र के बच्चों और किराये के आदमियों को खरीद कर "पाकिस्तान जिन्दाबाद, जिन्ना जिन्दाबाद, अयूब जिन्दाबाद" के नारे लगवाने शुरू कर दिये हैं, बल्कि सच्चाई यह है कि काश्मीर घाटी में जो बाहर के पर्यटक आते हैं, उन पर भी खुल्लम-खुल्ला हमले की घटनायें वहां पर हुई हैं।

16 HRS.

हमारी प्रधान मंत्री की स्वर्गीय बूआ श्रीमती कृष्णा हठीसिंह के साथ क्या घटना घटी थी ? यूगोस्लाविया के राजदूत के साथ क्या घटना हुई ? टाटा के जैनरल मैनेजर के साथ वहां पर क्या घटना हुई ? सरकार को शायद उन घटनाओं की अच्छी तरह से जानकारी होगी। मेरे ऐसा कहने का अभिप्राय यह न समझें, कि हमारे पर्यटन मंत्री श्री कर्ण सिंह देश के दूसरे भागों के पर्यटकों को वहां जाने के लिये उत्साहित करने का जो प्रयास कर रहे हैं, उसमें किसी प्रकार की न्यूनता रही बल्कि जहां काश्मीर में 60-70 हजार पर्यटक प्रतिवर्ष जाते थे, वहां इस वर्ष उनके प्रयास से डेढ़ लाख के लगभग पर्यटक वहां पहुंचे। लेकिन डा० कर्ण सिंह को भी याद होगा कि उन्होंने एक प्रश्न का उत्तर देते हुए 15 नवम्बर को श्री रामगोपाल शालवाले को बतलाया था कि 3 अक्तूबर को दो यात्री बसों पर, पेम्पोर और विजाबिहार में हमला किया गया जिसके कि परिणामस्वरूप वह बसें फिर वापिस श्रीनगर लौट गई। इस तरीक़े से पाकिस्तानियों ने यह भयंकर स्थिति पैदा कर दी है। साम्प्रदायिक तनाव इतना बढ़ा दिया गया है कि जिससे काश्मीर घाटी से हिन्दू छोड़ कर चले जायं। सेना की जो अपनी गाड़ियां हैं जब वह उन सड़कों से निकलती हैं तो उन पर पत्थर फेंकने व थूकने आदि की इसी प्रकार की घटनाएं भारी मात्रा में हुई हैं। पाकिस्तान अब इस प्रकार का प्रयास कर रहा है कि वहां पर हथियार फिर से जमा कर लिये जायं और उसके सहयोग के लिए भी वहां पर एक वातावरण बनाया जा रहा है। मैं अपने इस कथन की पुष्टि में आपको दो-तीन प्रमाण भी देना चाहूंगा। गृह मंत्री श्री यशवन्तराव चव्हाण को शायद स्मरण हो नन्दा जी उस समय गृह मंत्री थे और उस समय भी मैंने इस बात की चर्चा की थी कि कश्मीर पोलिटिकल कान्फ्रेंस के नेता श्री गुलाम मुहीउद्दीन कारा की ओर से किस प्रकार के पत्र पाकिस्तान के लोगों को लिखे जाते हैं और किस ढंग से पाकिस्तान से सहायता मांगी जाती है ? वह पत्र पूरा नहीं पढ़ना चाहता। वह पत्र बहुत बड़ा है। उसकी फोटो कापी भी मेरे पास है जो उनके हस्ताक्षरों से युक्त है। उस पत्र के अन्दर जहां यह है कि आजाद कश्मीर रेडियो से कश्मीर के लिए क्या क्या प्रोग्राम ब्राडकास्ट करें जहां इसमें यह है कि हमने कुछ आदमी इस प्रकार के भेजे हैं जो वहां सहायता करेंगे, वहां उसमें यह भी लिखा है कि आपको कश्मीर के लिए अपने रेडियो से क्या-क्या कार्यक्रम प्रसारित करने हैं ? वहां पर सहयोग के लिए जो उन्होंने उसमें शब्द लिखे हैं और वह भी किस रहस्यमय ढंग से लिखे हैं यह मैं खास तौर से इस सदन को सुनाना चाहता हूं :

"आपने जो दवा भेजी है वह मिल गई है। उम्मीद है कि मरीजों के लिए वह दवा कारगर साबित होगी लेकिन यह दवा न तो हमारी जरूरत के लिए काफ़ी थी और न ही इससे बरक़त मिली। आप जानते हैं कि यहां अच्छे

[श्री प्रकाशवीर शास्त्री]

दवाखानों की कमी है। मरीजों की तादाद में दिनों दिन इजाफ़ा हो रहा है। माजे के अखराजात भी बढ़ते जा रहे हैं। काफ़ी मिक़दार में और बरवक्त दवाई न मिलने की वजह से सख्त परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

इसी तरीक़े से चिट्ठी में आगे लिखा गया है कि दवाई की कमी की वजह से हमें मुश्किल का सामना न करना पड़े इस प्रकार का इंतज़ाम आप करें।..."

चिट्ठी* बहुत लम्बी है मैं चाहूंगा कि इसको सदन की टेबुल पर रख दूं ताकि यह सदन जान जाय और गृह मंत्री जी विशेष रूप से जानें कि वहां कश्मीर में कैसा षडयन्त्र रचा जा रहा है। इसमें कश्मीर पोलिटिकल कान्फ्रेंस की ओर से ईद मुबारक़ के दो कार्डों* के नमूने भी हैं जिनमें एक में मस्जिद का फोटो बना हुआ है और दूसरे पर श्री मुहीउद्दीन कारा की फोटो है। इन कार्डों के ऊपर पाकिस्तान जिंदाबाद आदि पाकिस्तान के पक्ष में नारे लिखे हुए हैं। तीसरा एक और कार्ड का नमूना है जो पोलिटिकल कान्फ्रेंस ने इमदादी फंड के लिए इमदादी रसीदें* जारी की हैं उसमें भी इसी तरह की खतरनाक चीजें लिखी हुई हैं। इकबाल का यह कलाम उसमें लिखा हुआ है कि हमारा चिराग जलता रहेगा और कोई उसे बुझा नहीं पायेगा। इन कार्डों में इसी तरह की और भी खतरनाक चीजें लिखी हुई हैं। इसीसे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आज कश्मीर के अन्दर पाकिस्तान ने क्या स्थिति पैदा कर दी है और पाकिस्तान वातावरण को कितना बिगाड़ना चाहता है?

उपाध्यक्ष महोदय, सन् 1961 की जनगणना के आंकड़े मैं आपसे बतलाते हुए कहना चाहता हूं कि सन् 1961 की जनगणना में जम्मू-कश्मीर राज्य की जो आबादी लगभग 36 लाख थी। इस 36 लाख की आबादी में से करीब 28 लाख 43 हजार 722 की आबादी कश्मीर घाटी की है। इसमें 23 लाख 39 हजार 939 के लगभग मुसलमान हैं। पांच लाख 3 हजार 783 के लगभग हिन्दू हैं। पिछले 20 वर्षों में अब तक कश्मीर घाटी में ही नहीं, पूरे जम्मू व लद्दाख के अन्दर कोई घटना इस प्रकार की नहीं घटी जो कि विशेष रूप से वहां पर साम्प्रदायिक तनाव को बढ़ाने वाली हो या साम्प्रदायिक वैमनस्य को पैदा करने वाली हो। लेकिन 1967 के अगस्त महीने में जो योजनाबद्ध ढंग से अभी पीछे परमेश्वरी नाम की लड़की के अपहरण और मुस्लिम युवक से ज़बरदस्ती विवाह कांड को लेकर जो भयंकर घटना हुई है उसने कश्मीर को ही नहीं, वरन् सारे भारत को पूरी तरह से हिला दिया। उससे लगता है कि कश्मीर का वातावरण जो पिछले 20 सालों में था अथवा कश्मीर राज्य की जो सम्प्रदाय निरपेक्ष स्थिति रही उसको भी आघात पहुंचा है। मैं उस केस की तह में नहीं जाना चाहता क्योंकि वह केस अदालत में है। मैं उसकी मैरिट्स पर नहीं जाना चाहता। लेकिन मैं इतना अवश्य कहना चाहता हूं कि उस लड़की की बूढ़ी विधवा मां ने प्रधान मंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी, श्री यशवन्तराव चव्हाण के दरवाजे से लेकर छोटे से छोटे व्यक्ति तक के दरवाजे को खटखटाया और अपनी नाबालिग़ कन्या को लौटाने की भीख मांगी। 24 अगस्त को जिस समय मैजिस्ट्रेट के कोर्ट में फैसला होने वाला था और यह स्थिति थी कि मैजिस्ट्रेट किसी प्रकार से उस नाबालिग़ लड़की के सम्बन्ध में अपना ठीक निर्णय देंगे तो मैजिस्ट्रेट के कोट को घिरवा दिया गया और मैजिस्ट्रेट वहां पर अपना निर्णय न ले सके। विवश हो कर मैजिस्ट्रेट को अपना कोर्ट श्रीनगर छावनी के अन्दर ले जाना पड़ा। इस सिलसिले में उपाध्यक्ष महोदय, जो बात मैं विशेष रूप से कहना चाहता हूं, वह यह कि 13 अगस्त से लेकर 27 अगस्त तक श्रीनगर शहर में मालूम यह पड़ता था कि कोई राज नहीं है और कोई सरकार यहां पर काम नहीं कर रही है। इन दिनों श्रीनगर में जो लूट, छुरेबाजी, हत्या और बलात्कार की

*The Speaker not having subsequently accorded the necessary permission, the documents were not treated as laid on the Table.

घटनायें हुई हैं, उन घटनाओं ने अमृतसर के जालियांवाले बाग़ के कांड को भी मात कर दिया।

आपको पता होगा कि महिलाओं का जिस समय जलूस निकला उस जलूस के ऊपर तेज़ाब फेंका गया और पत्थर फेंके गये। श्री यशवन्त राव चव्हाण इस बात की साक्षी देंगे कि जब वह श्रीनगर आये थे तो क्या उनको वहां के कुछ लोगों ने बताया था कि तेज़ाब फेंकने वालों में जम्मू, कश्मीर राज्य के एक जिम्मेदार मंत्री का लड़का भी सम्मिलित था। जिसने कि इस प्रकार की घटनाएं वहां पर कीं। जो व्यक्ति पुलिस की गोलियों से वहां पर मरे तो उन मृतकों को जब श्मशान भूमि में जलाने के लिए ले जाया जा रहा था तो मृतकों के जलूस पर भी इसी प्रकार से हमला किया गया और मृतकों को जलाने तक के अन्दर भी इसी प्रकार की बाधा उत्पन्न की गई। इन सब कामों को करने में कश्मीर आर्म्ड पुलिस और होमगार्ड्स का पूरा हाथ था। काश्मीर में होमगार्ड्स को खुली छूट इस तरह की हरकतों को करने की दे रक्खी है। मैं श्री यशवन्त राव चव्हाण की जानकारी के लिए कहना चाहता हूं कि आज श्रीनगर के अन्दर जो एक नई शिव सेना बन गई है उसमें एक का नाम वहां पर होम गार्ड है और दूसरी का नाम फ़ील्ड सर्विस आर्गेनाइज़ेशन है। होमगार्ड्स में 7000 व्यक्ति हैं जिन पर लगभग 60 लाख रुपया व्यय होता है और दूसरी कश्मीर की शिव सेना जिसका नाम फ़ील्ड सर्विस आर्गेनाइज़ेशन है उसके 2000 सदस्य हैं जिन पर कि 30 लाख रुपया व्यय होता है। क़रीब 90 लाख रुपया इन पर खर्च किया जा रहा है। इनका काम क्या है? कांग्रेस के बाहर से गये नेताओं की सभा में हाजिरी बढ़ाना उनकी सभाओं में भीड़ करने का काम वह करते हैं। जनता पर वह दबाव डालते हैं और उसे चुनाव के अन्दर काम में लाते हैं। इसी प्रकार के जो दंगे फसाद वहां होते हैं उसमें अपने एजेंट के रूप में इस्तेमाल करते हैं। कश्मीर ऐक्शन कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर इस लड़की के कांड को लेकर जो वहां पर वारदातें हुई हैं मैं उनके विस्तार में न जाकर संक्षेप में आपको कहूं तो केवल इतना कह सकता हूं कि इस सारे कांड में 57 बार वहां पर लाठी चार्ज हुआ। 143 बार टियर गैस, अश्रु गैस का इस्तेमाल हुआ। 5 बार महिलाओं पर तेज़ाब और पत्थर फेंक कर उन्हें घायल करने की घटनाएं हुईं। 5 बार जलूसों पर पथराव हुआ। 2,075 व्यक्ति घायल हुए। 6 आदमियों की मृत्यु हुई। 15 बार घर और दुकानें जलाई गईं। 12 बार लूटी गईं। इस तरह की घटनाएं यहां पर हो रही हैं और इन तमाम घटनाओं के बाद भी अगर भारत सरकार यह समझती है कि जम्मू कश्मीर की स्थिति बिलकुल ठीक है और पाकिस्तान अपने अनुकूल वातावरण बनाने में सफल नहीं हुआ है तो मैं नहीं समझता कि इससे बड़ी खतरनाक स्थिति और क्या हो सकती है? जहां यह हालत हो गई थी कि जलूसों पर तेज़ाब फेंका जा रहा था, गोलियां चलाई जा रही थीं, लाठियां चलाई जा रही थीं, वहां इंसानियत को भी दया उत्पन्न हो सकती थी। करुणा से मानवता का हृदय भी पिघल सकता था। लेकिन कश्मीर में जहां श्रीनगर की गलियों में यह सारी घटनाएं घटीं वहां इंसानियत ताक में रख दी गई थी। जो सरकारी अस्पताल थे वहां घायलों को भरती करने से इंकार कर दिया गया। जम्मू, कश्मीर की जो रेडक्रॉस सोसाइटी थी उसने घायलों को उठाने से इंकार कर दिया। उनके द्वारा घायलों को ऐम्बुलेंस देने तक से इंकार कर दिया गया।

अब यह कहा जा रहा है कि इस कांड के अन्दर जो घायल हुए थे उन की हम क्षतिपूर्ति करेंगे। लेकिन यह क्षतिपूर्ति उन्हीं लोगों की होगी जो सरकार अस्पतालों में भरती हुए, अन्यों की नहीं। पर सरकारी अस्पतालों में घायल होने वालों के भरती होने का यह नमूना रहा है जो कि मैंने अभी आप से निवेदन किया। वहां के लोगों की सब से बड़ी मांग आज यह है कि सारे कांड की जम्मू कश्मीर राज्य के बाहर के किसी सर्वोच्च न्यायालय के स्तर के निष्पक्ष न्यायाधीश द्वारा

[श्री प्रकाशवीर शास्त्री]

उच्चस्तरीय जांच कराई जाय जिस से कि वस्तुस्थिति का देश को भी पता लगे और सरकार को भी पता लगे। लेकिन इस के साथ-साथ गृह मंत्री श्री यशवन्तराव चह्वाण से एक सीधा सवाल भी मैं करना चाहता हूं कि अब हिन्दू कश्मीर घाटी में रहें या वहां से चले जायें। अगर हिन्दू कश्मीर घाटी में रहें तो उन की सुरक्षा की आप की ओर से क्या व्यवस्था की जा रही है ? आप जब 2 सितम्बर को कश्मीर गये आप ने उन को क्या आश्वासन दिया था ? 3 सितम्बर को आप के और जम्मू कश्मीर के मुख्य मंत्री सादिक साहब का जो संयुक्त वक्तव्य निकला था उस वक्तव्य के अन्दर क्या बात थी ? आप ने किस प्रकार का आश्वासन दिया था ? मैं चाहूंगा कि आज गृह मंत्री श्री यशवन्तराव चह्वाण बतायें कि उन का आश्वासन वहां पर पूरा हुआ या नहीं हुआ ? आज तक उस अभागी विधवा मां की लड़की की स्थिति क्या है और वह कहां है ? ज़रा श्री यशवन्त राव चह्वाण इस सदन के द्वारा जम्मू काश्मीर के निवासियों और देशवासियों को बतायें ? भारत सरकार के गृह मंत्री के आश्वासनों की कोई कीमत है या नहीं ? सरकार की कश्मीर नीति में अगर किसी तरह का कोई परिवर्तन नहीं हुआ है तो मैं गृह मंत्री से कहना चाहता हूं कि आज आप स्पष्ट रूप से संसद और देश को बतलायें कि क्या आप की नीति वही है जो 20 वर्ष पहले थी या 20 साल के बाद आप की नीति में किसी प्रकार का परिवर्तन हुआ है ? अगर श्री राजेश्वर राव की नीति में परिवर्तन हुआ है तो उन की बात तो मैं समझ सकता हूं। क्योंकि आज रूस के अन्दर कोसीगिन हैं आज रूस के अन्दर स्वरुश्चेव नहीं हैं। स्वरुश्चेव के समय में कश्मीर के सम्बन्ध में उन की नीति और थी और आज कोसिगन की नीति कुछ और है।

सादिक साहब की बात भी एक बार समझ में आ सकती है, जिन के चिन्तन की धारा लगभग वही है। यही सादिक साहब थे, याद होगा कांग्रेस के सदस्यों को, डा० रामसुभग सिंह को, जब 20 अप्रैल, 1964 को कांग्रेस एम० पीज़ के अन्दर वह बयान दे कर गये थे कि संविधान की धारा 370 लगी रहने से जम्मू और कश्मीर के अन्दर अनिश्चितता की स्थिति बनी हुई है। उस धारा को एक दम हटाया जाये। आज वही जम्मू और काश्मीर के मुख्य मंत्री सादिक साहब हैं जो कहते हैं कि धारा 370 के हटाये जाने से काश्मीर में बहुत भारी विनाश हो जायेगा। उन की बात समझ में आ सकती है क्योंकि उन के सोचने का ढंग दूसरा है। यह भी मैं समझ सकता हूं जम्मू और काश्मीर राज्य कांग्रेस के अध्यक्ष मीर कासिम ने संयुक्त राष्ट्र संघ में जो वक्तव्य दिया था, वह वक्तव्य सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने छापा है। उन्होंने कहा था कि काश्मीर की जनता ने अपनी किस्मत का फैसला कर लिया है। 31 अक्तूबर को जम्मू और काश्मीर विधान सभा में जो वक्तव्य दिया उस में उन्होंने सारे कांड की ज़िम्मेदारी इस पर डाली कि देश के दूसरे हिस्सों में इसी प्रकार की घटनायें हो रही हैं, यह उसी की प्रतिक्रिया है। कासिम साहब के, जो कि कांग्रेस के अध्यक्ष वहां हैं, इस प्रकार के बयान दें। सुनने वाले और कहने वाले तो यहां तक भी कहते हैं, मेरे पास कोई अधिकृत प्रमाण तो नहीं है कि एक बार क्रोध में आ कर उन्होंने यह भी कह दिया कि हम ने 1947 में कबाइलियों का सामना किया और 1967 में बनिहाल की ओर से आने वाले शत्रुओं का भी सामना करेंगे। परन्तु यह सारी बातें मैं एक बार समझ सकता हूं। लेकिन जो मेरा स्पष्ट सवाल है, श्री यशवन्तराव चह्वाण से, वह यह है कि श्रीमती इन्दिरा गांधी ने मंगला बांध पर अय्यूब साहब को जो बधाई दी, उस का क्या मतलब है ? उप-प्रधान मंत्री श्री मोरारजी देसाई ने मंगला बांध के उद्घाटन समारोह में भारत के हाई कमिश्नर के जाने के सम्बन्ध में वकालत करते हुए यहां पर कहा कि भारत

पाकिस्तान के साथ अपने सम्बन्ध सुधारना चाहता है। आखिरकार आप के इन वक्तव्यों के पीछे क्या रहस्य है ? अगर कोई विशेष रहस्य है तो आप सदन को बतलाइये, देश को बतलाइये कि आप की इच्छा क्या है।

वह जो आप के 16 हजार रुपये माहवार के मेहमान दिल्ली में बैठे हुए हैं जम्मू काश्मीर के क्या उन को आप छोड़ रहे हैं ? अगर आप छोड़ने को तैयार हैं तो सच्ची बात बतलाइये कि आप शेख को छोड़ना चाहते हैं या काश्मीर को छोड़ना चाहते हैं। इरादे आप के क्या हैं ? अगर यह स्थिति आप की नहीं है तो मैं दूसरी बात आप से पूछना चाहता हूं बड़ी स्पष्ट भाषा में कि आज अमरीका और रूस के दबाव के कारण भारत सरकार कहीं अपना मन तो डुलाने नहीं जा रही है ? अपने स्टेन्ड में परिवर्तन करने तो नहीं जा रही है ? कहीं भारत सरकार की नीति यह तो नहीं है कि पहले शेख को छोड़ा जाये, और कुछ दिन के बाद काश्मीर घाटी को उन के हवाले कर दिया जाये। पहले कुछ विशेष विषय दिये जायें और धीरे-धीरे इसी प्रकार से उन के सब इरादे पूरे किये जायें ? अगर यह स्थिति है तो मैं श्री यशवन्तराव चह्वाण से पूछना चाहता हूं, और मैं ही नहीं, देश पूछना चाहता है कि फिर आप ने इस अभागे मुल्क का अरबों रुपया जम्मू और कश्मीर के सम्बन्ध में क्यों पानी की तरह बहाया ? हजारों बहनों के सुहाग का सिन्दूर आप ने क्यों पोंछा ? अगर आप को इसी तरह की स्थिति पर पहुंचना था ? कांग्रेस के माथे पर दो पाप ऐसे हैं, आप जिनको सहस्त्राब्धियों तक नहीं धो सकेंगे। एक पाप भारत के विभाजन का और दूसरा पाप देश में भाषावार प्रान्तों के निर्माण का। बराय मेहरबानी इतिहास का तीसरा कलंक अपने माथे पर मत लगाइये कि इस प्रकार से अरबों रुपये व्यय करने के बाद और इतने बलिदानों के बाद काश्मीर के सम्बन्ध में ऐसी स्थिति भी आ गई। मैं आप से एक बात और कहना चाहूंगा। जम्मू और काश्मीर राज्य की जो स्थिति है वह जहां भारतवर्ष के लिये चुनौती है वहां जम्मू और काश्मीर राज्य का आन्तरिक वातावरण भारत में केन्द्र की कांग्रेस सरकार के लिये एक अग्नि-परीक्षा भी है। मैं अग्नि-परीक्षा का शब्द जान बूझ कर प्रयोग कर रहा हूं। अग्नि-परीक्षा इस लिये कि आज जम्मू और काश्मीर विधान सभा में 75 सदस्य हैं। उन में से दो स्थान खाली हैं। 73 सदस्यों में से विधान सभा में 26 सदस्य वह हैं जो निर्विरोध चुन कर भेज दिये गये हैं। 13 व्यक्ति विरोधी दल के हैं। इस तरह 73 सदस्यों में से चौंतीस शेष आदमियों को बहुमत में मान कर सरकार उन के हाथों में दी हुई है। मैं पूछना चाहता हूं कि आखिर पश्चिम बंगाल और यहां की स्थिति में अन्तर क्या है ? पश्चिम बंगाल के केस का आप इस लिये समर्थन करते हैं कि वहां पर चीन समर्थक नारे लगने लगे थे, हिंसा की घटनायें बढ़ गई थीं। मैं श्री चह्वाण साहब से पूछना चाहता हूं कि क्या जम्मू और काश्मीर में पाक समर्थक नारे नहीं लग रहे हैं ? हिंसा, लूट-पाट, तोड़-फोड़ और बलात्कार की घटनायें वहां नहीं हो रही हैं ? अगर इस प्रकार के काम करने पर आप बंगाल को संभाल सकते हैं, बंगाल का पक्ष ले सकते हैं, तो मैं आप से कहना चाहता हूं कि जम्मू और काश्मीर की स्थिति उस से भी बदतर है। श्री भगवान सहाय, जो इस समय वहां राज्यपाल हैं, उन्होंने कहा कि जम्मू काश्मीर के सम्बन्ध में मैं भारत सरकार को किसी प्रकार की कोई सिफारिश राष्ट्रपति शासन की करने के लिये नहीं जा रहा हूं। मैं बड़ी नम्रता से निवेदन करता हूं कि सरकारी कर्मचारियों को इस प्रकार के राजनीतिक वक्तव्य देने की आदत मत डालिये, वर्ना यह आगे चल कर आप को और देश को भी भारी पड़ने वाली है। वह स्थिति को जान-बूझ कर अपनी आंखों से ओझल करना चाहते हैं। एक ही तरीका जम्मू और काश्मीर को बचाने का है, और वह यह कि भारतीय संविधान की गली-सड़ी धारा 370 को एकदम समाप्त कर के जम्मू और काश्मीर में

[श्री प्रकाशवीर शास्त्री]

राष्ट्रपति शासन लागू किया जाये। यही जम्मू और काश्मीर की समस्या का समाधान है।

मैं अपने वक्तव्य को उपसंहार की ओर ले जाते हुए दो-तीन बातें और भी कहना चाहता हूं। एक तो यह कि राज्य की आन्तरिक स्थिति बिगाड़ने के लिये दोषी हैं कौन? जम्मू और काश्मीर की जो सरकार है उसी की वजह से राज्य के अन्दर इस प्रकार की भयंकर स्थिति उत्पन्न हो गई है। 1965 का संघर्ष क्यों हुआ? 1965 के संघर्ष से पहले के कुछ जिम्मेदार पाकिस्तानी अधिकारियों को जिनमें से मैं एक-एक व्यक्ति का नाम नहीं लेना चाहता, जम्मू और काश्मीर में आने और ठहरने का मौका दिया गया। एक हैं आगा शौकत, जो डिप्टी डाइरेक्टर आफ इन्फर्मेशन, पश्चिमी पाकिस्तान थे, वहां पर आये और आ कर रहे। दूसरे हैं ख्वाजा गुलाम मोहम्मद, यह आजाद काश्मीर के पहले फाइनेन्स मिनिस्टर थे और अब पाकिस्तान के डाइरेक्टर इंडस्ट्रियल डेवेलपमेंट हैं। वह 1965 से पहले आये और आ कर वहां रहे। तीसरे हैं आशिक हुसेन, यह भी 1947 से पहले सोपर में मुंसिफ थे और अब पाकिस्तान में डिस्ट्रिक्ट जज हैं। यह उन दिनों वहां पर आये। चौथे हैं शेख मुहीउद्दीन जो पाकिस्तान में इनकम टैक्स आफिसर हैं, वह भी आये। इसी तरह से गुलाम मुहम्मद, जो पाकिस्तान में जज हैं, वहां आये। इस प्रकार के खतरनाक व्यक्ति वहां आ रहे हैं और खुल्लम-खुल्ला रह रहे हैं तथा जो भी कार्यवाही करना चाहते हैं वह कर रहे हैं। भारत सरकार कानों में तेल डाले हुए बैठी है और समझती है कि जम्मू और काश्मीर में ला एण्ड आर्डर सिचुएशन बिल्कुल ठीक है। क्या यही तरीका है काम करने का?

आप ने जो कांग्रेस वहां बनाई है, उस की स्थिति क्या है? विस्तार से मैं नहीं कहना चाहता किस प्रकार से वहां की कांग्रेस सम्प्रदायवाद और साम्यवाद का गढ़ बन चुकी है। मेरे पास एक लम्बी लिस्ट है, जो कि प्लेबिसाइट फ्रंट के लोगों की है। जम्मू और काश्मीर की तहसील कांग्रेस का प्रेजिडेंट कौन है, मोहल्ला कांग्रेस कमेटी का प्रेजिडेंट कौन है, यह अगर आप देखें तो आप को अनुमान हो जायेगा कि वहां की स्थिति क्या है। अगर आप चाहें तो मैं उस को यहां टेबल पर रख सकता हूं। क्या इस तरह की स्थिति में आप जम्मू और काश्मीर को बचायेंगे। मैं आप से सीधा सवाल करना चाहता हूं कि क्या आप के पास कोई इस प्रकार की सूचना भी है कि 1947 में कुछ इस प्रकार के लोग गिरफ्तार किये गये थे जो कि उस समय पाकिस्तान का साथ दे रहे थे, और आज वही राज्य के अन्दर बड़े-बड़े ओहदों पर बिठला दिये गये हैं? क्या आप के पास इस प्रकार की जानकारी है कि आज जनमत संग्रह मोर्चे के जो लोग हैं वह कांग्रेस में घुस कर पीछे से कमर में छुरा भोंकने के लिये तैयारी कर रहे हैं? क्या आप के पास इस प्रकार की जानकारी है कि साम्यवादियों के बड़े-बड़े नेता आज जम्मू और काश्मीर में जा कर राजकीय मेहमान बनते हैं और वहां जा कर अपनी सारी योजनायें बनाते हैं।

मैं इन तमाम बातों से भी आगे बढ़ कर एक और खतरनाक चीज आप की निगाह में लाना चाहता हूं। आप हिन्दुस्तान से जो भारी मात्रा में अन्न जम्मू और काश्मीर में भेज रहे हैं या जो कपड़ा सस्ते दामों पर भेजा जा रहा है, वह उस के सम्बन्ध में है। मैं आप को एक-एक वर्ष के आंकड़े नहीं देना चाहता फिर भी तीन वर्ष के कुछ आंकड़े जरूर रखना चाहता हूं। उस से आप सही स्थिति का अनुमान लगा सकेंगे। 1963 में राज्य का उत्पादन था 641 हजार टन और केन्द्रीय सरकार ने जो अन्न भेजा वह था 62 हजार टन। 1964 में राज्य का उत्पादन था 603 हजार टन और सेंट्रल गवर्नमेंट से जो अन्न दिया गया वह था 63 हजार टन। 1965 में राज्य का उत्पादन था 533 हजार टन और केन्द्र से गया 1 लाख 51 हजार टन। इसी तरह से 1966 में यहां से गया 1 लाख 29 हजार

टन । अगर आप इस में राज्य से पैदा हुए अन्न और केन्द्र द्वारा भेजे गये गेहूं को मिला लें और फिर काश्मीर की आबादी में उस को बराबर बराबर बांट दें, तो किसी भी व्यक्ति को जम्मू काश्मीर और लद्दाख में दूकानों के सामने लाइन लगा कर खड़े होने की जरूरत नहीं है । मेरा सीधा-सा सवाल है कि वह गल्ला कहां गया जो यहां से सस्ते दामों पर भेजा गया ? आप यहां से भेजते हैं जम्मू और काश्मीर के लिये, लेकिन वह गल्ला या उस का अधिकांश भाग सीमा से हो कर पाकिस्तान को पास हो रहा है जब कि आप यह सोचते हैं कि आप जम्मू और काश्मीर के लोगों की मदद कर रहे हैं ।

आप इस चीज से भी सावधान हो जाइये कि चीन और पाकिस्तान ने एक नया प्लेन तैयार किया है । वह इस्लामाबाद को आक्साई चिन से मिलाने का षड्यन्त्र कर रहे हैं और इस प्रकार की प्लेन से पाकिस्तान और चीन को नये मार्ग से मिलाया जा रहा है । दूसरी तरफ इधर यह स्थिति है कि जो जम्मू और काश्मीर के तपे हुए और परखे हुए नेता हैं, जो कि बगल में कांग्रेस की बेंचों पर बैठते हैं लद्दाख के माने हुए नेता हैं, उन की कोई सुनता नहीं है । कुशक बकुल जैसा व्यक्ति यहां बैठा है । पिछले सत्र में प्रेस को एक वक्तव्य उन्होंने दिया था जो लद्दाख के लोगों के मन की टीस बताता था । मैं जानना चाहता हूं क्यों उन के मुकाबले में 16 साल के लड़के को ला कर उन की पर्सनेलिटी को चैलेन्ज किया जाय और ऐसे व्यक्ति को, जिस के लिये सारा लद्दाख माथा झुकाता है, आघात पहुंचाया जाये ? इन ही तरीकों से आप जम्मू और काश्मीर की रक्षा करना चाहते हैं ? क्या इस तरह से आप देश के मस्तक काश्मीर को बचा सकेंगे ?

मैं ज्यादा आगे न बढ़ता हुआ अपने वक्तव्य को समाप्त करता हुआ कुछ आवश्यक सुझाव देना चाहता हूं । सब से पहला सुझाव यह है कि संविधान की धारा 370 को समाप्त कीजिये, दूसरे काश्मीर में राष्ट्रपति शासन तत्काल लागू कीजिये और अगस्त कांड की निष्पक्ष जांच कीजिये । इस के अतिरिक्त मैं यह सात सुझाव और देना चाहता हूं :

(1) पाकिस्तानी तत्वों का सफाया करने में केन्द्रीय सरकार किसी प्रकार की दया न दिखाए;

(2) जो नाबालिग हिन्दू लड़की है उसे वापस किया जाये, जिससे जम्मू और काश्मीर राज्य के अन्दर साम्प्रदायिक तनाव की जो स्थिति बनी हुई है, उस में कमी हो;

(3) वहां पर जो अकर्मण्य और दोषी अधिकारी हैं, जिन को मंत्री महोदय भी जानते हैं, उन का एकदम तबादला कर दिया जाये, वर्ना राज्य की स्थिति बद से बदतर होती चली जायेगी;

(4) काश्मीर आर्म्ड पुलिस की नये सिरे से जांच कराई जाये और यह देखा जाये कि कहीं देश-विरोधी तत्व तो उसमें प्रविष्ट नहीं हो गए हैं;

(5) होम गार्डज और फील्ड सर्विस आर्गेनाइजेशन को तत्काल समाप्त किया जाये । इस तरह से मुख्य मंत्रियों को नई-नई सेनायें बनाने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिये;

(6) अगस्त कांड के शिकार व्यक्तियों को मुआवजा दिया जाये; और

(7) जम्मू, काश्मीर और लद्दाख को उन की जनसंख्या के अनुपात से नौकरियों में प्रतिनिधित्व दिया जाये, ताकि किसी के साथ किसी प्रकार का अन्याय न हो सके ।

इन शब्दों के साथ मैं अपने प्रस्ताव को उपस्थित करता हूं और उस के साथ ही मैं विशेष रूप से यह निवेदन भी करना चाहता हूं कि बीच में मैंने टेबल पर रखने

[श्री प्रकाशवीर शास्त्री]

के लिये कुछ कागजात भेजे, लेकिन आप ने हाथ हिला दिया । वे इतने गम्भीर डाकुमेंट्स हैं कि अगर देश और सदन उन से परिचित नहीं होंगे, तो उन को जम्मू और काश्मीर की वास्तविक स्थिति का सही ज्ञान नहीं हो पायेगा । मेरा अनुरोध है कि आप उन को सदन की टेबल पर रखने की इजाजत दें । इस में कोई छिपी हुई बात नहीं है । मैं उन को यहां पढ़ चुका हूं । इस लिये उन को सदन की टेबल पर रखने की अनुमति आप को देने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिये ।

MR. DEPUTY-SPEAKER : The hon. Member knows that there are certain rules regarding placing documents on the Table of the House. If the hon. Member so desires, I will ask the office to see them and then they might be kept in the Library, not here on the Table.

SHRI RANGA (Srikakulam) : Placing in the library is not the same thing as placing it on the Table.

MR. DEPUTY-SPEAKER : What I meant was, they will be examined by the Secretary...

SHRI RANGA : Please do not bring in the Secretary in this. Whatever is to be done has to be done in the name of the Chair.

MR. DEPUTY-SPEAKER : All right, the Chair will examine them. The authenticity of the documents, whatever documents are bandied about —some Members say that they will place them on the Table—has to be varified. It will have to be verified whether it is proper or not to place them on the Table. According to rules we have to examine every aspect and then only I can give the final permission. That does not mean automatically I will give the permission. Motion moved :

> "That the situation arising out of the serious threat to national security forced by the recent inflex of Pakistani infiltration into Kashmir and the spate of incidents in the State evidencing a determined bid by pro-Pak agents to sub-vert the peace of the State, be taken into consideration."

SHRI D. N. PATODIA (Jalore) : Mr. Deputy-Speaker, Sir, the problem of Kashmir whether it relates to Pakistani infiltration or anti-social elements can, in my opinion, be best discussed in the broader context of political, social and economic atmosphere prevailing in the Valley for the last twenty years after independence and more particularly, after the Sadiq Government was imposed on the State.

The complicated nature of this Kashmir problem, in my opinion, today reflects the economic frustration and resentment against the corrupt Government in the State, on the one hand, and the weak central administration and the various political blunders made by the Indian Government, on the other, over the last twenty years. Although India has spent crores of rupees in the Valley most of this money has been drained out and spent in the form of giving subsidies and doles, and it is very unfortunate to find, going into the Valley and travelling around, that not even one meaningful employment opportunity has been created in the course of the last twenty years. Kashmiris, by and large, remain today as poor as before. If you go round the Valley you see opportunities of tannery, of timber work, orchards and various other industries which can be developed. But, unfortunately, none of these industries have been developed in twenty years and money has been wasted.

On the other hand, with the growth of population and more and more educated young men coming out of colleges resentment has grown. The educated youth became resentful about not getting employment and became frustrated against the Government. Against this political background, against this economic background, after the recent elections a Congress Government was imposed upon the State. Congress was a new party. On account of the wrong leadership, on account of the party not being associated with the national senti-

ments of the State, it could not get popular backing. Mr. Sadiq, his previous history known to most of us, being sometimes associated with anti-social activities, had permitted himself to be dragged in different directions in order to beg popularity. Sometimes he permitted to be dragged into the direction of favouring a certain particular community, sometimes some other community. As a result, his administration completely failed. Under this administration, we know what happened in the last elections. As my hon. friend, Shri Prakash Vir Shastri has stated, as many as 26 members were elected uncontested. It is known to all the Members of the House, including the Home Minister, Shri Chavan, the manner in which the nominations were rejected, the nomination papers of non-Congress party members were rejected, the manner in which the Government machinery was used only to see that the Congress Party candidate, the party which was imposed upon this State, gets elected into the State Legislature.

SHRI RANGA : Even Dr. Karan Singh had to protest against it.

SHRI D. N. PATODIA : With this background, I will come to the recent events, recent disturbances, recent pro-Pakistani incidents and raising anti-Indian slogans which have appeared there, as a clear reflection of weak and corrupt and ineffective administration. The communal trouble, which never happened in the Kashmir Valley during the last twenty years, why did it happen now ? Pandit community, Muslim community and Hindu community, they used to live together in harmony for the last so many years. Why all of a sudden, about four months back they became so communal in character that there were excesses committed by all the communities ? The problem of the Pandit community, relating to the incident of the girl, pointed out by Shri Prakash Vir Shastri was, in my opinion, a pure and simple administrative problem, which could have been tackled very effectively by acting promptly and taking stern action. It was deliberately, on account of the weak administration, given a communal colour and excesses were committed and brutal assaults were made on females and ladies and children, never heard in the history of democracy anywhere in the world. Similarly, thereafter, when the turn came of the Muslims, equally brutally they were lathi-charged, equally brutally firing was done on that community. It is the Sadiq Government which is unpopular, not only with the Hindus, not only with the Pandit community but also with the Muslims; the entire Kashmir community hates this Government and the entire Kashmir community feels today that the Sadiq Government is not in a position to deliver the goods.

Now, with this background, comes the problem of Pakistani infiltration, comes the problem of new anti-national, anti-social elements raising their heads. It is not very correct to say that the people who crossed over the borders in 1965 are now coming back and they are Indian citizens and, therefore, they are loyal. Their loyalty is very much to be doubted. The people who crossed over the frontiers two years back, who were brain-washed by Pakistan for two years and possibly bribed by paying money, their loyalty cannot be taken for granted. They were waiting for an opportune time. It was a deliberate game to select a proper timing for these anti-social elements to be migrated back to Indian territory, and they found that on account of the weak administration of the Sadiq Government, this is the proper time when they should avail the opportunity to go to the Indian territory. On that provocation, backed by Pakistani money and brain-washed by the Pakistani elements they are coming back to India with the ultimate object of creating trouble and because they are Kashmiris, speaking the same language and having the same habits, they cannot be identified. So, for the first time, anti-national, anti-social, pro-Pakistani elements are raising their heads on such a magnitude in this State, which was never known before. For the first time, people are parading in the streets, shouting "Ayub zindabad", shouting "Indian leaders murdabad", which has never been heard

[Shri D. N. Patodia]

before. But, then, it has been tolerated and the Sadiq Government has proved to be absolutely ineffective.

For the first time, a very peculiar situation arose in Kashmir. The troops and police belonging to the two different States, on account of wrong handling by the administration, were permitted to be carried away by communal frenzy. Still, we are hoping that this Government will be able to deliver the goods. I beg to submit that under these circumstances a grave situation has arisen in this State which demands very effective administrative handling, which demands a clean and pure administration, which demands anti-social elements to be suppressed, checked and curbed.

This Government is not capable of doing it. A situation has arisen when we must all rise above the level of parties. For the sake of Kashmir State a leadership belonging to all the parties, truly national in its character, must emerge. A government under that national leadership must function in that State. That government alone will be effective and will be able to deliver the goods. I hope that the hon. Home Minister will accept these suggestions.

श्री अमृत नाहटा (बाड़मेर) : उपाध्यक्ष महोदय, काश्मीर का नाम लेते ही हमारे दिलों की अंतरतम गहराइयों को वह छू लेता है। सिर्फ इस लिये नहीं कि वह इस धरती पर स्वर्ग है, सिर्फ इस लिये नहीं कि वह हमारे देश का भाग है सिर्फ इस लिये नहीं कि वहां की जनता ने बहादुरी से वहां पर मुजाहिदों से टक्कर ली है बल्कि इस लिये भी कि वह एक जिन्दा जाति का सबूत है हमारे हिन्दुस्तान के सब से शानदार आदर्श का जिसे हम कहते हैं धर्म-निरपेक्षता काश्मीर एक ऐसी धरती है हमारे देश की जहां हमेशा से हिन्दू और मुसलमान सभी जातियों, धर्मों और सम्प्रदायों के लोग बराबर हिलमिल कर रहते आये हैं आज हम सब देशवासियों के लिये एक बड़े शर्म की बात है, जिस से कि हमारा सिर झुक जाता है कि उस साम्प्रदायिक एकता को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। वहां पर एक बार फिर साम्प्रदायिक भावनाओं को उभारा जा रहा है। उपाध्यक्ष महोदय, काश्मीर हमारे देश का एक बहुत ही सेंसिटिव क्षेत्र बन गया है। मैं यह मानता हूं कि काश्मीर में षड्यंत्र हो रहा है न सिर्फ हमारे देश के लोगों द्वारा, न सिर्फ पाकिस्तानी घुसपैठियों द्वारा, पाकिस्तानी जासूसों द्वारा बल्कि अन्तर्राष्ट्रीय पैमाने पर जो कि सक्रिय एजेंसियां हैं, जिसमें सी० आई० ए० भी शामिल हैं वह लोग भी सक्रिय रूप में इस बात की कोशिश कर रहे हैं कि काश्मीर में उपद्रव खड़े किये जायें, साम्प्रदायिक दंगे कराये जायें, साम्प्रदायिक झगड़े फैलाये जायें और ऐसी स्थिति पैदा की जाये कि काश्मीर की स्थिति संभाली न जा सके और फिर यह कहा जाये कि काश्मीर हिन्दुस्तान का नहीं है, काश्मीर पाकिस्तान का है।

उपाध्यक्ष महोदय, मेरे उधर बैठने वाले दोस्त कौटिल्य और मैकाइविले को अपना गुरु मानते हैं। मैं उन को कहूंगा कि वह एक सब से बड़ा सबक कौटिल्य और मैकाइविले से जो लें वह यह कि आप ऐसा कोई काम न करें जिस से कि दुश्मन को फायदा पहुंचे। आप के इस प्रकार के प्रचार से पाकिस्तान की जो प्रापेगेंडा मशीनरी है उस में आप तेल डाल रहे हैं, आप उसकी मदद कर रहे हैं। आप यह बताना चाहते हैं कि आप के दिलों में यह विश्वास नहीं है कि मुसलमान हिन्दुस्तान के प्रति वफादार हो सकते हैं। अगर जो आप दिल में मानते हैं वह सही है तो फिर काश्मीर पर हमारा कोई अधिकार नहीं है। लेकिन हम यह मानते हैं कि हिन्दुस्तान की धरती पर, काश्मीर की धरती पर रहनेवाला चाहे वह हिन्दू हो चाहे मुसलमान हो वह हमारा प्यारा भाई है और वह इस देश पर उतना ही हक रखता है जितना दूसरा कोई रख सकता है और इस लिये काश्मीर हमारा है। अगर आप यह समझते हैं कि काश्मीर में रहनेवाले जो घुसपैठिये हैं वह देश के प्रति सिर्फ वही गद्दार हैं, उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना

चाहता हूं कि गद्दार का कोई मजहब नहीं होता। जो गद्दार है वह न हिन्दू है न मुसलमान है, वह गद्दार है। बहुत मुमकिन है, आज इस खूबसूरत घाटी की साम्प्रदायिक एकता को खत्म करने के लिये जिस प्रकार का जहर उगला जा रहा है, उस के प्रति मैं अपने दोस्तों को सावचेत करना चाहता हूं, हो सकता है, मैं नहीं इनकार करता कि कहीं कुछ ज्यादती हुई हो, पुलिस पुलिस है चाहे वह काश्मीर की हो चाहे बिहार की हो, आप कहते हैं कि राष्ट्रपति शासन स्थापित किया जाये, क्या रांची में जब दंगे हुए, भाषा के सवाल पर और वहां शांति व्यवस्था भंग हो गई और वहां बुरी तरह से लोगों को गोलियों से भुना गया, तो क्या आप कहेंगे कि वहां राष्ट्रपति शासन स्थापित किया जाये ? मैं आप से पूछना चाहूंगा कि कौनसा राज्य है हमारे देश में कि जहां वक्तन-फवक्तन इस प्रकार के सवाल नहीं उठ खड़े होते हैं जहां वक्तनफवक्तन इस प्रकार के कुछ दंगे की या अशांति की स्थिति पैदा नहीं होती ? वहां की सरकार जो संवैधानिक रूप से कार्य कर रही है कौनसी ऐसी अव्यवस्था आ गई, कौनसा ऐसा संवैधानिक संकट आ गया जिससे आप कहते हैं कि राष्ट्रपति शासन स्थापित किया जाये ? सिर्फ यही चाहते हैं न कि पाकिस्तान कल को यह कहे कि देखो हिन्दुस्तान ने काश्मीर में जम्हूरियत को खत्म कर दिया। पाकिस्तान दुनिया के सामने यह कहेगा कि हिन्दुस्तान के लोग हिन्दू साम्राज्यवाद के लोग जम्हूरियत को काश्मीर में जिन्दा नहीं रहने देना चाहते। मैं आप से यह कहना चाहता हूं कि इस तरह आप अपने दुश्मन के हाथ में खेल रहे हैं। आप के पास कोई शिकायत हो, कोई ज्यादती हुई हो किसी के साथ जुल्म हुआ हो तो आप बेशक सरकार के सामने उसे लायें लेकिन ऐसी कोई बात न करें, कोई वातावरण ऐसा पैदा न करें कि जिस से उस घाटी की साम्प्रदायिक एकता खत्म हो और आप अपने दुश्मन के प्रचार की मशीनरी में और अधिक तेल डालें और आप जाने या अनजाने, चाहे या अनचाहे दुश्मन के हाथों में खेलें।

आप कहते हैं क 370 हटा दी जाय। शनैः शनैः बराबर धीरे-धीरे काश्मीर और हिन्दुस्तान की एकता नजदीक आती जा रही है। आज वहां सदरे रियासत नहीं है, गवर्नर है।.....(**व्यवधान**).....सुनिये, सुनिये। बराबर काश्मीर नजदीक आ रहा है। आज एलेक्शन कमीशन का क्षेत्र काश्मीर तक बढ़ाया गया है। आज काश्मीर का प्राइम मिनिस्टर नहीं है जैसे दूसरे राज्यों में मुख्य मंत्री हैं वैसे ही काश्मीर में भी मुख्य मंत्री है। अगर आप चाहते हैं कि वहां की जनता और हिन्दुस्तान की जनता एक-दूसरे के नजदीक आये, और हम दिलों से कह सकें कि काश्मीर की जनता के दिल और सारे हिन्दुस्तान की जनता के दिल एक हैं तो आप उन के दिलों को जीतिये। केवल विधान की धाराओं को मिटाने से आप वहां की जनता का हृदय नहीं जीतेंगे। बल्कि आप अपने इन कार्यों से, अपने इस जहरीले प्रचार से उन लोगों को यह बता रहे हैं कि जैसे वह हमारे नहीं हैं, जैसे वह अपने से दूर हैं। आप अपने कार्यों से यह साबित कर रहे हैं कि आप का काश्मीर की जनता में विश्वास नहीं है। इस लिये उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपने विरोधी दोस्तों से एक बार फिर अपील करूंगा कि वह बहुत गम्भीरता से इस सवाल पर सोचें और ऐसा कोई कार्य न करें कि जिस से वह साम्प्रदायिक आग में और ज्यादा घी डालें।

श्री य० द० शर्मा (अमृतसर) : अध्यक्ष महोदय, मुझे एक बात बड़े दुख के साथ कहनी पड़ती है कि काश्मीर के संबंध में यहां पर पीछे गत 4 अप्रैल की कार्यवाही में विदेश मंत्री सरदार स्वर्ण सिंह और इसी तरह से 17 मई की कार्यवाही में गृह मंत्री श्री नन्दा जी ने कुछ वक्तव्य दिये थे और एक "सब अच्छा है" का बड़ा अच्छा प्रभावशाली चित्र खींचा गया था कि सब घुसपैठिये लौटा दिये गये हैं, अब काश्मीर के अन्दर सब अच्छा है, सब प्रकार की शांति है लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हमारी सरकार कुछ ऐसे कल्पना के जगत में रहने की आदी हो गई है अथवा

[श्री य० द० शर्मा]

इस सारे सदन को या देश के लोगों को धोखा देना उस की आदत का हिस्सा बन गया है, कह नहीं सकता कुछ । स्थिति दिन-प्रतिदिन इस प्रकार बिगड़ती चली जा रही है और आज जैसी काश्मीर के अन्दर विस्फोटक स्थिति है, माननीय सदस्य श्री प्रकाशवीर शास्त्री ने आप के सामने उस का एक चित्र रखा, मैं यह समझता हूं कि सरकार सब प्रकार से वहां की स्थिति को संभालने में असमर्थ है । वहां के प्रदेश की सरकार जो है उसे तो हम निश्चित रूप से वहां की स्थिति को संभालने के लिये अयोग्य, अक्षम और सब प्रकार से अप्रभावी महसूस करते हैं लेकिन बड़ा दुख उस समय होता है जब केन्द्र की सरकार को भी बिलकुल इस मामले में दर्शक के रूप में बैठा हुआ हम देखते हैं। पीछे जितनी स्थिति काश्मीर के अन्दर हुई केन्द्र की सरकार कुछ नहीं कर पाई। हमारे देश की प्रधान मंत्री महोदया पूर्वी योरप की यात्रा पर गई हुई थीं । माननीय गृह मंत्री महोदय यहां किसी मौन व्रत की साधना उन दिनों कर रहे थे और काश्मीर जल रहा था । एक ऐसी विचित्र स्थिति है । मेरे पास कुछ चीजें उन्होंने दी हैं । यह एक पत्र है कहीं किसी विदेश से आया है काश्मीर यूनिवर्सिटी के लिये और इस पर पता लिखा है—काश्मीर यूनिवर्सिटी, श्रीनगर, काश्मीर, पाकिस्तान । अब आप देखिये, पाकिस्तानी एजेंसी किस प्रकार का संसार के अंदर प्रचार कर रही है और हमारे प्रचार विभाग के लोग पता नहीं क्या कर रहे हैं ? वह लोगों को पता नहीं क्या समझा रहे हैं ? माननीय स्वर्ण सिंह ने यहां पर बताया कि सब घुसपैठिये वापस भेज दिये गये । कहीं एकाध इक्के-दुक्के भूले-भटके किसी जंगल वगैरह में बैठे हों तो वह बात दूसरी है लेकिन और वहां सब ठीक है । मगर में समझता हूं कि आज वहां पर जो कुछ हो रहा है, वह बहुत ही सोचनीय है । इस समय कोई भी आदमी श्रीनगर की घाटी में जाता है तो उस को ऐसा पता नहीं लगता कि यह घाटी भारत का हिस्सा है । उसे यह प्रतीत होता है कि यह पाकिस्तान का कोई नगर बन कर रह गया है । ऐसी वहां की स्थिति है । जहां का ऐडमिनिस्ट्रेशन बिलकुल पैरालाइज्ड है । जो चीज श्रीनगर में 4 अक्तूबर को हुई, सेना की तीन गाड़ियों पर खुलेआम बारामूला के पास आक्रमण किया गया, उन गाड़ियों को बचाने के लिये पुलिस ने गोली चलाई और प्रो-पाकिस्तान एलीमेंट के दो व्यक्ति मारे गये तो उस के बाद 4 अक्तूबर की हड़ताल काल दी गई और कांग्रेस के अध्यक्ष श्री मीर कासिम उस काल को देते हैं । लोगों को कहा जाता है कि घाटी को हिन्दू बनाया जा रहा है । उस के अन्दर सारे के सारे नेता शामिल होते हैं और वहां के रीजनल इंजीनियरिंग कालेज के विद्यार्थियों ने जो कुछ वहां किया, जिस तरीके पर श्रीमती कृष्णा हाथी सिंह जी का वर्णन माननीय शास्त्री जी ने किया और जो वहां पर दुर्घटनाएं हुई, मैं समझता हूं कि यह खुला चित्र है खुले तौर पर पर्चों और पोस्टर्स दीवारों पर लगे हैं जिस में न केवल पाकिस्तान जिन्दाबाद बल्कि भारत मुर्दाबाद के भी नारे छपे हुए हैं ।

ये सारी की सारी चीजें हो रही हैं । वहां पर विधान सभा भवन के अन्दर विस्फोट हुए, लेकिन कोई आदमी नहीं पकड़ा गया । आखिर पकड़ा कैसे जाये, क्योंकि वहां के मंत्री-मण्डल के साथ इन पाकिस्तानी एलीमेंट्स की गहरी छनती है, वे आपस में इकट्ठे उठते-बैठते हैं । श्री मोहम्मद दीन बन्दे, वहां एक डिप्टी मिनिस्टर हैं, उन के साथ एक रशीद नाम का व्यक्ति है, जो अभी उड़ी और पुंछ क्षेत्र में गया है, उस व्यक्ति को, हालांकि उस के वारंट निकले हुए थे, अपने मकान के अन्दर रखा गया । उसको मोटर एक्सीडेंट के अन्दर चोट आई, तो उप-मंत्री की कार उस को वहां लेने के लिये गई और उस कार से लाकर उस को अस्पताल में दाखिल किया गया । इसी तरह से लतीफ, अजीज, इतनी कहानियां हैं इतने सारे षड्यन्त्र हैं जिनका वर्णन करके मैं अपना समय नष्ट नहीं करना चाहता । आज इन मामलों की चाहे जितनी

मिसालें गृह मंत्री जी को दीजिये, मैं समझता हूं कि उन के पास भी होंगी, मैं नहीं समझता कि उन की जुबान पर कौनसी मोहर लगी हुई है, अपनी कमजोरियों को वे स्वयं जानते हैं। उन के वहां जाने और बोलने के बाद वहां सारी चीजें जिस तरह से ठप्प पड़ गईं, मुझे पता नहीं कि उन का क्या राजनीतिक इतिहास है, लेकिन वहां पर इस तरह की चीजें चल रही हैं। वहां की सरकार इस स्थिति को काबू में नहीं कर सकी है। केन्द्र की सरकार को अपनी जिम्मेदारी को लेकर आगे आना चाहिये।

जहां तक केन्द्र की सरकार का सवाल है, उसकी नीति कुछ ऐसी विचित्र है कि वह अपने आप यह तय नहीं कर पा रही है कि काश्मीर के बारे में वह क्या नीति ले कर चले। मेरे माननीय मित्र कह रहे थे कि धीरे-धीरे स्थिति ठीक हो जायेगी और इसी तरह से स्वर्गीय प्रधान मंत्री पं० जवाहर लाल नेहरू कहते थे कि धारा 370 की आवाज मत उठाओ, यह अपने आप धीरे-धीरे घिसते-घिसते घिस जायेगी। मुझे इस सम्बन्ध में श्री गोपालस्वामी आयंगर के भाषण का एक हिस्सा आपको सुनाना है। जब धारा 370 लागू की जा रही थी और इस को काश्मीर के सम्बन्ध में लाने की बात की जा रही थी, उस समय श्री गोपालस्वामी आयंगर ने बोलते हुए कहा था—

"The discrimination is due to the special conditions of Kashmir. That particular State is not yet ripe for this kind of integration. It is the hope."

श्री आयंगर नें कहा—

Mark the word 'hope....

"...of everybody here that, in due course even Jammu and Kashmir will become ripe for the same sort of integration as has taken place in the case of other States."

आगे जाकर फिर उन्होंने कहा—

"I would like to assure the House that we can only now establish an interim system."

मेरा यह कहना है कि 20 वर्ष बीतने को आ गये, अभी तक वह धारा घिसते-घिसते घिसी नहीं और आज हालत यह आ गई है कि हमारे देश की सुरक्षा और हमारी एकात्मता घिसते-घिसते घिस रही है—आखिर कब उस का समय आयेगा। आज हमारे माननीय कुशक बाकुल जी जैसे राष्ट्रभक्त और श्रीमान बख्शी गुलाम मुहम्मद जी जैसे देशभक्तों को दुखी होकर इस प्रकार की स्थिति में पड़ जाना पड़ा कि वहां वे अपने को पराया महसूस करें और पाकिस्तानी एजेंट आज वहां पर सब कुछ बन कर बैठे हुए हैं, यहां का गया हुआ माल-खजाना खा रहे हैं और पाकिस्तान के नारे लगा रहे हैं। यह कैसी विचित्र स्थिति है। मैं यह समझता हूं कि इन सारी स्थितियों को दृष्टि में रख कर हमें धारा 370 को समाप्त करना चाहिये और हमें अपनी नीति को स्पष्ट करना चाहिये।

कुछ मित्रों ने इस प्रकार की बात कही है कि वहां चुनाव हो गया है—सवाल यह नहीं है, सवाल तो सरकार के मन और मस्तिष्क की स्पष्टता का है। आज जिस प्रकार का वातावरण वहां पर बना हुआ है—अलगाव का—हमारे जनसंघ के अध्यक्ष बलराज मधोक वहां पर गये, परिस्थितियों ने उन को विवश किया, आपके लोगों ने कहा कि आप इस वातावरण की शांति के लिये कुछ प्रयत्न करें—सादिक साहब ने स्वयं कहा कि आपने बहुत ही ठीक प्रकार से तमाम बातों को कहा है, लेकिन उन्हीं के चारों तरफ के लोगों ने, जो पाकिस्तान के हाथ में खिलौना हैं, उन्होंने उस को इस प्रकार की रंगत दी कि वहां पर हौवा खड़ा कर दिया, साम्प्रदायिकता पैदा हुई है, वहां के मुसलमानों को खत्म किया जा रहा है। कृपा कर के बताइये—धर्म परिवर्तन की घटनायें हिन्दुओं की ओर से कितनी हुईं और अल्पसंख्यकों की ओर से कितनी हुईं। वहां पर इस प्रकार का जो प्रो-पाकिस्तानी एलीमेन्ट है, उस ने इस प्रकार से साम्प्रदायिक मामलों को भड़काया।

[श्री य० द० शर्मा]

इसी स्थिति से सम्बन्धित एक बात और कहना चाहता हूं—वहां पर जम्मू और लद्दाख के जो क्षेत्र हैं—नौकरियों के मामलों में और आर्थिक विकास के मामलों में वहां की जनता के साथ सौतेली मां का-सा व्यवहार किया जा रहा है । आज उस सरकार की अलगाव की बात को समाप्त नहीं किया जा रहा है, यहां पर शिव सेना और दूसरी सेनाओं की चर्चा रोज हो जाती है । मैं यह समझता हूं कि अगर यह धारा वहां पर कायम रही तो इस प्रकार के अलगाव के बीज जो सरकार अपनी नीति के कारण वहां पर बो रही है, उस के बड़े भयंकर परिणाम होंगे । क्यों नहीं काश्मीर को बाकी राज्यों के समान स्तर पर आने दिया जाता, क्यों नहीं वहां के लोगों को बाकी राज्यों के लोगों के साथ एकरस और एकरूप होने की स्थिति में लाया जाता, अगर सरकार उस को समाप्त करे—और सरकार तब समाप्त कर सकेगी जब काश्मीर के सम्बन्ध में उस की नीति और दृष्टि स्पष्ट हो जायेगी—लेकिन सरकार के मन में पाप है, मैं समझता हूं कि सरकार अमरीका या रूस आदि इस प्रकार की विदेशी शक्तियों के दबाव के कारण इस प्रकार के पाप को ले कर बैठी है, जो काश्मीर के सम्बन्ध में स्पष्ट नहीं हो रहा है, इस लिये वहां पर जिन कठपुतलियों को कायम करके बैठाया हुआ है, उन को समाप्त करना होगा, वहां पर राष्ट्रपति राज्य लागू किया जाये, धारा 370 को समाप्त किया जाये, सारे राज्य के अन्दर—चाहे जम्मू हो या लद्दाख—आर्थिक समानता लाने की कोशिश की जाये और जम्मू-काश्मीर को भारत के अन्य राज्यों के स्तर पर लाया जाये ।

SHRIMATI SUSHILA ROHATGI (Bilhaur) : Sir, I would like to thank Shri Prakash Vir Shastri for giving this august House... (*Interruptions*).

AN HON. MEMBER : in Hindi please.

MR. DEPUTY-SPEAKER : That is all right. It is for her to choose in which language she would like to speak.

SHRIMATI SUSHILA ROHATGI : Sir, I would like to thank Shri Prakash Vir Shastri for focussing the attention of this august House on a matter of vital importance because Kashmir enjoys a very peculiar position and especially because Kashmir happens to possess the misfortune of being looked upon by greedy eyes by two very hostile neighbours—China and Pakistan, also because Kashmir had been the arena of two hostile aggressions. Therefore, I would request this House to study this matter in the most dispassionate manner, to have a clear perspective and, at the same time, not to be carried away by emotions.

If my hon. friend thinks that the only remedy for this lies in the repeal of Article 370, I would like to contradict him and tell him that while he wants the repeal of Art. 370, at the same time he wants President's proclamation. President's proclamation can only be introduced by invoking Article 356. Therefore, I would like to ask him : was it not under Mr. Sadiq's Ministry, was it not under Mr. Sadiq's inspiration that this Art. 356 is now in a position to be enforced in Kashmir ? And we should be grateful to this Ministry of Mr. Sadiq for bringing Kashmir under the purview where this article can be extended to Kashmir also. I would like to differ from Mr. Prakash Vir Shastri on this basic constitutional aspect. While enforcing Art. 356 and enforcing President's Proclamation, I would like to draw his attention to two matters of vital importance. First it says that the Governor's report should be such and, secondly, that the situation otherwise should be such that this Proclamation could be introduced. I would like to ask him as to what the present position in Kashmir is. Has a report been submitted by the Governor advocating that there should be President's Proclamation ? To this the reply is a categorical 'No'. Secondly, what is the situation otherwise prevailing in Kashmir ? There is a democratic machinery there, which is functioning

in a democratic manner. Not even the Opposition there has ever, any time, said that it has a doubt in the majority of the present Ministry. I would like to ask : then what is the reason? If there is a democratic machinery functioning, a properly constituted, elected Government functioning, why should the President's Proclamation be imposed there? If you want to compare it with West Bengal, I would very clearly say that the situations are entirely different. What has happened in West Bengal has made us hang our heads down in shame. Irrespective of our Party affiliations and irrespective of whatever ideals we may have, what has happened in West Bengal, I hope, we shall all agree, should not be repeated in any other State whether it is Congress Party or any other Party in power there. In West Bengal there was no Government, there was no administration, there was nothing.

So far as comparison with Haryana is concerned, in Haryana the Governor's report was there.

SHRI JYOTIRMOY BASU (Diamond Harbour) : Let her confine herself to Kashmir.

SHRI PILOO MODY (Godhra) : Otherwise, she will have nothing to say tomorrow.

SHRIMATI SUSHILA ROHATGI : I do not intend to say anything tomorrow.

SHRI BAL RAJ MADHOK (South Delhi) : Let her choose between Ayub and Mao. One side there is Ayub and on the other side there is Mao. If Mao's slogans are bad, Ayub's slogans are equally bad. He has been a student in fact a teacher of constitutional history. Unless I sit down, how can he get up and interrupt?

I was referring to Haryana. I would like humbly to place before the House the situation in Haryana. The situation in Haryana is different from that in Kashmir. The Governor had reported that crossing of the floor by Members was not merely a disease but it had assumed an endemic form and it had become infectious. (*Interruptions*) I had never interrupted any of my friends. May I expect the same courtesy from them?

MR. DEPUTY-SPEAKER : She may, ignore the interruptions from the other side.

SHRIMATI SUSHILA ROHATGI : It is difficult to ignore them because I have great respect for my hon. friends in the Opposition....

SHRI KANWAR LAL GUPTA (Delhi Sadar) : Shri Piloo Mody cannot be ignored.

MR. DEPUTY-SPEAKER : I was not talking of him. He is too much present in the House. I was talking of interruptions.

SHRIMATI SUSHILA ROHATGI : I would like them to give me the same courtesy which I had shown to them. That is the least that I expect of any Member there.

In Haryana, according to the Governor's report, the people had come to power by means which were not very honourable. So, the comparison with Haryana was not proper. In Haryana, there was no question of any stability of government and any stability of administration. So, putting Haryana and Kashmir on the same footing is not a very correct thing to do. May I ask why there is this sudden demand for a Presidential Proclamation like a bolt from the blue? Why are the people who are professed democrats here, who have fought the elections on democratic basis advocating this Presidential Proclamation? In Bihar when similar incidents happened in Ranchi and more than 150 lives were lost there in 48 hours, there was no cry for such proclamation. Again, at Sursand, more than a hundred lives were lost in a couple of hours; no such cry was raised on that occasion. Was it because the Opposition Ministry was in power there? Was it because there was no Congress Ministry there in power and people dare not judge their own Ministry by the same measure or the same yardstick by which they want to measure us? I would expect the same yard-stick to be applied by them everywhere. We are mature people here, and let us not forget today that we are the biggest democracy in the world; let us not forget today that we have the most glorious civilisation as our heritage; let us not forget today that we are one of the most mature and

[Shrimati Sushila Rohatgi]

civilised countries, which have come up to the standard high democratic functioning.

While Shri Prakash Vir Shastri has focussed the attention of this House on this important matter and it must receive the attention of this House and that of the Home Minister, at the same time, I would appeal to him that he must not create an alarmist tendency, especially in a vulnerable place like this, because if he does so, the morale of the people will suffer and when the morale suffers, that will be the first below on our arsenal of defence. Therefore, I would request him to withdraw this motion.

श्री गुलाम मुहम्मद बख्शी (श्रीनगर) : जनाब डिप्टी स्पीकर, कश्मीर पर मुझ से पहले कुछ चन्द एक आनरेबुल मैम्बर्स ने अपने खयालात का इजहार किया लेकिन एक चीज पहले ही मैं अर्ज करना चाहता हूं एक गलतफहमी दूर करने के लिए और वह यह कि कश्मीर में बदकिस्मती से जो 7 जून से सितम्बर तक हुआ तो कश्मीर को उसी माइनारिटी और मेजारिटी के पार्डस्टिक से न नापिये क्योंकि कश्मीर की मेजारिटी और कश्मीर की माइनारिटी हजारहा साल से इकट्ठा रहती आई है। वह सैकुलर रही है और आगे भी सैकुलर रहेगी।

They have lived like that and they can live like that till eternity

वहां जो कुछ हुआ, प्रकाशवीर शास्त्री जी ने या मेरे और दोस्तों ने कहा, कम्युनलिजम वहां पर मुसलमान ने नहीं किया, हिन्दू ने ने नहीं किया, मुसलमान ने हिन्दू पर हाथ नहीं उठाया और हिन्दू ने मुसलमान पर हाथ नहीं उठाया। यह कम्युनलिजम वाली बिलकुल गलत बात है और मैं जोरशोर से इसकी तरदीद करता हूं। अगर वहां कोई आदमी मरा है तो वह पुलिस की गोली से मरा है, लाठीचार्ज से मरा है। वह पुलिस की फायरिंग से मरा है। कश्मीर सैकुलर रहा है, सैकुलर है और वह सैकुलर रहेगा। कश्मीर ने तमाम कंट्रोवर्सीज के बगैर अपना नाम हिन्दुस्तान के साथ जोड़ा है, वह आज जुड़ा है और आगे भी जुड़ा रहेगा यह मैं आप को बतलाना चाहता हूं। बाकी कश्मीर के बारे में कंट्रोवर्सी रहने के कई कारण हो सकते हैं। अब किसी दोस्त का यह सुझाव है कि फलानी दफा को उड़ा दो सब ठीक हो जायगा। मेरा अपना यह खयाल है, मैं ईमानदारी से यह कहना चाहता हूं और इसीलिए मैंने जनाब से पहले मांगा था वक्त। कश्मीर की बदकिस्मती से मौजूदा गवर्नमेंट जो है, मैं किसी नाराजगी या किसी रैंकर की वजह से नहीं कह रहा हूं कि लाल बहादुर जी ने जब मौजूदा गवर्नमेंट को इंस्टाल किया फरवरी 64 में तब भी यह रिप्रेजेंटेटिव नहीं थे इनके साथ पापुलर ओपीनियन नहीं थी और 67 का एलैक्शन जब आया, तीन साल गुजरे 67 में जब एलैक्शन आया और इस एलैक्शन के बारे में लोगों ने उम्मीदें बांधी हुई थीं कि यह एलैक्शंस फ्री होंगे, इम्पारशियल तरीके से होंगे और जो भी गवर्नमेंट पावर में आयेगी यह लोगों की गवर्नमेंट होगी। वह कश्मीर की खिदमत करेगी और अपनी जिम्मेदारियों को निभायेगी लेकिन बदकिस्मती से हुआ क्या? एलैक्शंस से पहले वहां जिसका तजकिरा मेरे फाजिल दोस्त शास्त्री जी ने किया 10,000 होमगार्डस दिसम्बर से ही वहां पर उन्होंने फंक्शन करना शुरू किया। उसके मुताल्लिक मैं ने आनरेबुल होम मिनिस्टर को एक लम्बा चौड़ा खत लिखा कि इस में यह यह हो रहा है और आप इधर जरा तवज्जह दीजिये।

They are breaking meeting of opposition parties.

हम खुद मीटिंग नहीं कर सकते। जहां भी हम मीटिंग करते हैं वहां वह ब्रैक करते हैं और इस सिलसिले में कितने ही हमारे आदमियों को एक, दो को नहीं बल्कि सैकड़ों आदमियों को जख्मी कर दिया। मैंने खुद मि० चह्वाण को लिखा। उसके बाद एलैक्शन कमिशन ने ऐनाऊंस किया ला मिनिस्टर ने यहां पार्लियामेंट में ऐनाऊंस किया कि जम्मू व काश्मीर में

एलैक्शंस होंगे। जम्मू में एलैक्शंस रैस्ट आफ दी कंट्री के साथ होंगे और कश्मीर के हालात सामने रख कर वहां पर ऐंड औफ दी मार्च में होंगे क्योंकि यही शैडयूल पहले भी रहा है। लेकिन हुआ क्या ? इस बारे में एलैक्शन कमिशन का नोटिफिकेशन है लेकिन रूलिंग पार्टी का मैं उन को कोई नाम नहीं देता, जिस तरीके से मैं ने आप से कहा कि रूलिंग पार्टी ने फौरी तौर पर, वह कोई पसन्द नहीं था लेकिन उन्होंने ऐनाऊंस किया, एलैक्शन कमिशन ने ऐनाऊंस किया कि कश्मीर के लिए 21 मार्च और जम्मू के लिए 19 फरवरी होगी पंजाब के साथ-साथ । फौरी तौर पर बदल गये हम ने रिप्रेजेंटेशन किया और बजाय मार्च के अप्रैल कर दिया और जम्मू, कश्मीर में एक साथ कर दिया। एलैक्शन कमिशन ने फैसला क्या दिया ? नहीं कश्मीर में भी 21 फरवरी को ही चुनाव होगा जबकि कश्मीर में 3,4,5 और 6-6 फुट बरफ जमी हुई थी। पहली तो यह बात है फिर उसके बाद 21 जनवरी आई नामिनेशन पेपर्स दाखिल करने थे और सब ने नामिनेशन पेपर्स दाखिल कर दिये। हम ने भी और दूसरी ओर अपोजीशन पार्टीज ने अपने नामिनेशन पेपर्स दाखिल किये और मैं बतलाना चाहता हूं कि हम लोगों के 141 नामिनेशन पेपर्स फिल्मजियस्ट ग्राउन्ड्स पर रिजैक्ट हुए और जिसे कि खुद इलैक्शन कमिशन मानता है ।

Not a single nomination paper of the ruling party was rejected रियल पोजीशन यह है Then we again approached President, the hon. Prime Minister, the Home Minister and other Central Ministres, put all these facts before them.

इस पर हम ने मतालबा किया कि इन होलसेल रिजैक्शंस की वजह और मौसम की खराबी की वजह से एलैक्शन को ऐनल कर दिया जाय या फिर पोस्टपोन ही कर दिया जाय लेकिन न तो उसे ऐनल किया गया और न ही पोस्ट पोन किया गया । मैंने चह्वाण साहब को खत लिखा कि साहब कम से कम यह तवक्को नहीं हो सकती एक ऐसी गवर्नमेंट से और एक ऐसी सरकार से जिसने हिन्दुस्तान की डेमोक्रेसी के लिए अपना हर एक हक न्यौछावर किया हो। उन से यह तवक्को नहीं हो सकती। और चह्वाण साहब ने मुझे खत लिखा। मैं वह खत पढ़ कर सुनाता हूं :

"I have your letter No. ..... dated 7th January I am forwarding a copy of this letter to Sadiq Saheb, with a request that he should look into your complaints personally and satisfy himself that nothing wrong or improper is done. I am very keen that the elections in Jammu and Kashmir, as in the rest of the country, should not only be fair, but should also appear to be so, and that nothing should be done that can be regarded as at all unfair and improper."

17 HRS.

यह है चह्वाण साहब का खत। अब इस से और एक हिम्मत हुई हमें कि एलैक्शन फेयर और इम्पार्शियल होंगे। लेकिन जनाब हुआ क्या ? रिजेक्शंस हुए । 26 आदमी असेम्बली में अनकन्टेस्टेड आ गए स्ट्रेटअवे लिहाजा 26 की स्ट्रेंग्थ बन गई और फिर उस के बाद बाकी जो हुआ वह सब को मालूम है। दीज आर आल ओपेन सीक्रेट्स ।

These are all open secrets. बैलट बाक्सेज, आये, टूटे और लिड्स के बगैर, सील के बगैर, बैलट पेपर एकाउंट के बगैर। हम ने एतराज किया । लेकिन no body just did any thing or cared.

कहा कि ठीक है काउंट किया जावे । एलैक्शन कमीशन ने दो आदमी यहां से भेजे काश्मीर में इसे देखने के लिए with no instructions. वह बिलकुल खड़े रहे भूत की तरह । वह देखते हैं, कहते हैं कि हम क्या करेंगे ? और पर्टीकुलर कांस्टीट्यूएंसी में क्या हुआ, 550 टोटल स्ट्रेंग्थ है उस बूथ की लेकिन उस वक्से में से

[श्री गुलाम मुहम्मद बख्शी]

1185 बैलट्स निकले। यह हुआ । · · · · · (**व्यवधान**) · · · · इस पर भी कुछ नहीं हुआ । हम डाक्टर कर्ण सिंह जो उस वक्त वहां के गवर्नर थे, उन से भी मिले, सब से मिले, वावेला किया, राष्ट्रपति से मिले लेकिन आखिर जो हम को हुक्म हुआ कि कानून इजाजत नहीं देता। हम ऐनल तो नहीं करेंगे क्योंकि बाहर दुनिया में क्या कहा जायगा ? हम ने कहा कि बाहर दुनिया में हमारी तो नाक कट गई। इंडिया के मुताल्लिक यह कहा जाता था कि यहां एलेक्शंस फेयर और इम्पार्शियल होते हैं। चुनावे हमारे शिव कुमार सेन सूडान और ईजिप्ट में एलेक्शन कराने के लिए गए और यहां यह हो रहा है। खुद सुन्दरम् ने यह कहा है :

> "that the nomination papers of a large number of opposition candidates were rejected on flimsy grounds is serious."

और फिर वह कहते हैं :

> "That difference in law is not satisfactory, and I intend recommending to the State Government that the State election law should be brought in line with the general election law on this point as soon as possible."

यह सुन्दरम् कहते हैं कि मामला सीरिअस है। हमें हिदायत दी कि जाओ एलेक्शन पेटीशन करो। हम ने कहा कि बहुत अच्छा। जब और कुछ नहीं होता है तो यही एक ही रेमेडी है कि एलेक्शन पेटीशन करो। That is the law of **the country.** और हम उसके सामने झुके। तो जनाब वह भी माजरा सुन लीजिए कि 57 एलेक्शन पेटीशंस हैं काश्मीर की। आन्ध्र प्रदेश में 12 थीं और बारह डिस्पोज हो गईं। हरयाना में 13 थीं और उसमें से 12 का फैसला अभी तक हो चुका है। महाराष्ट्र में 21 थीं, 20 का फैसला हो चुका। मैसूर में 21 थीं, 13 का फैसला हुआ है जब कि जम्मू और काश्मीर में 57 एलेक्शंस थीं और खुदा के फजल से एक का फैसला हुआ है। रीअल स्टोरी पर आइए। ट्रिब्यूनल बनता है। सुन्दरम् ने कहा—ला बदल दो।

Bring it on a par with the rest of the country—as early as February 67.

असेम्बली मिली मार्च में। उस में ला पास नहीं हुआ। और फिर क्या हुआ ? ट्रिब्यूनल मुकर्रर किया अन्डर दि ओल्ड ला। ट्रिब्यूनल ने काम शुरू कर दिया। एक फैसला दिया। यानी उसका शिड्यूल था वह 26 के फैसले देने वाला था इन दि मंथ आफ सितम्बर। · · · · (**व्यवधान**) · · · · तो फिर क्या हुआ ? 26 जो अनकन्टेस्टेड रिटर्न्स थे इन का फैसला होता सितम्बर तक। काश्मीर असेम्बली में उनका पता लग गया कि एक अनसीट हो गया।

Because of uncontested return rejection of nomination paper.

25 और होंगे। तो उन्होंने एक दिन में ला बदल दिया और वह ला भी एक दिन में असेम्बली बैठी, और उसे बदल दिया। 9 सितम्बर को बदला और 10 सितम्बर को असेंट ले ली गवर्नर से। 11 को लागू कर दिया और एलेक्शन ट्रिब्यूनल जो सरकार ने मुकर्रर किया था वह अदालत में बैठा हुआ था एलेक्शन पेटीशन सुनने के लिए, चपरासी गया और उसको कहा कि

"You are no more an election tribunal; please go. यह 11 को हुआ और 11 को जब यह हुआ, मैं पहुंचा दौड़ते दौड़ते फिर चह्वाण साहब के पास। आखिर कहां जायें ? हाकिम तो यही हैं। हम तो इन्हीं से बतायेंगे, आगे तफतीश इनका काम है। मैं फिर आया। मैंने लम्बा चौड़ा खत लिखा और उन को बता दिया कि यह ला ऐसे पास हुआ और क्या-क्या हुआ इस तरह एक दिन में। एलेक्शन ट्रिब्यूनल खत्म हो गया। मैंने कहा कि ऐड हाक जजेज जल्द से जल्द मुकर्रर कीजिए। इन्होंने कहा कि मैं जल्दी से जल्दी करूंगा। यह बात हुई शायद 14 सितम्बर को। और आज सितम्बर भी गया, अक्तूबर भी गया, नवम्बर भी गया, आज आखीरी तारीख है नवम्बर की। नौ महीने

हो गए हमारी एलेक्शन पेटीशन के। 57 एलेक्शन पेटीशंस में से 1 का फैसला हुआ है और खुदा ने चाहा अगर यही स्पीड रही तो कम से कम 10 साल इन को चाहिए यह फैसले करने के लिए हालांकि कानून है कि विदिन सिक्स मन्थस् होना चाहिए। महाराष्ट्र में 21 में 20 का फैसला हो गया। हरयाना में 15 में से 12 का फैसला हो गया। बाई एलेक्शन भी हो गए। 'लेकिन काश्मीर जिस को कि कहा जाता है कि स्पेशल सबजेक्ट है, 370 है, 380 है, 390 है, मुझे मालूम नहीं और कौन-कौन से सबजेक्ट्स लागू हैं लेकिन यह क्या है कि आज तक इस वक्त तक कोई ऐड हाक जज मुकर्रर नहीं हुआ ? अब हाईकोर्ट में वहां तीन आदमी मुएतकिल हैं।

They are fully occupied with their own work वह नहीं कर सकते। उन्होंने साफ कहा।

लेकिन मैं राष्ट्रपति राज्य के मुताल्लिक कहूं तो उन्हें नामंजूर होगी बात। मैं एक बात कहूंगा कि जो, मेरा खयाल है कि उन्हें पसन्द आयेगी। मैं उन को यह कहूंगा कि यह माइनारिटी गवर्नमेंट जो है जो इस तरह बनी है और जिस के खिलाफ इतने पेटीशंस हैं, इसको डिसमिस कीजिए, यह भी आप नहीं मानेंगे। मुझे मालूम है नहीं मानेंगे आप। काश्मीर स्पेशल सबजेक्ट है। तो फिर मैं अर्ज करूंगा आप से कि आज नौ महीने हो गए हैं, अब दिसम्बर, जनवरी, फरवरी और मार्च चार महीने हैं, मामूली सा सजेशन आप से अर्ज करता हूं, पाजिटिव सजेशन है, इस चार महीने में इन सब पेटीशंस का फैसला करा दीजिए।

And let there be fresh elections in April 68. यह मेरा सजेशन है कि आप ज्यादा से ज्यादा जजेज को एप्वाइन्ट करें, जो कि इन केसेज को जल्द से जल्द डिस्पोज करें। मैं एक्सट्रीमिस्ट नहीं हूं और एक्सट्रीम में नहीं जाऊंगा—यह एक सुझाव है, मेहरबानी कर के इमीडियेट स्टेप्स लीजिये, 141 केसेज को डिसाइड कराइये, खास तौर से 41 केसेज असेम्बली के हैं जिन को जजेज को मुकर्रर करके डिसाइड कराइये। अगर ये केसेज मार्च के आखिर तक डिसाइड हो जायें तो फ्रेश इलेक्शन्स अप्रैल में हो सकते हैं। फ्रेश इलैक्शन्स से मेरा मतलब बाईइलैक्शन से है।

दूसरी बात यहां पर काश्मीर को दी जाने वाली सहायता के मुताल्लिक कहा गया है। काश्मीर आपका एक गरीब साथी है—जहां बम्बई और कलकत्ता जैसे आपके अमीर साथी हैं, वहां काश्मीर जैसा एक छोटा और गरीब साथी भी है, इस लिये सहायता तो उस को देनी ही पड़ेगी। मैं आपकी इत्तला के तौर पर अर्ज करना चाहता हूं कि 1947 से मार्च, 1964 तक टोटल ग्रान्टस और लोन्ज जो काश्मीर को मिले—वह थे तकरीबन 72 करोड़ रुपये, लेकिन 1964 से 1966 के आखिर तक जो नई सरकार को मिले—वह थे 70 करोड़ रुपये, यानी दो साल में उन को 70 करोड़ रुपया दिया गया—मैं चाहता हूं कि आप इस को जरा देखभाल कीजिये। मैं यह जो फिर्स आपके सामने पढ़ रहा हूं—ये मैं फाइनेन्स डिपार्टमेंट के स्टेटमेन्ट से कोट कर रहा हूं, ये मेरी अपनी फिगर्स नहीं है, बल्कि फाइनेन्स डिपार्टमेन्ट से जो फिगज मेरे पास आई है, उन में से बता रहा हूं। काश्मीर पर थोड़ा रहम खाइये। पाटोदिया जी ने एक बड़ी ही कन्स्ट्रक्टिव एप्रोच की बात कही है—लोगों को अपने साथ रखिये, लेकिन उन को काम दीजिये, वहां पर काम धन्धों का एक्सपेन्शन होना चाहिये, इण्डस्ट्रियल डवेलपमेन्ट होना चाहिये, एग्रीकल्चर को बढ़ावा दीजिये—लेकिन होता क्या है ? जैनरल एडमिनिस्ट्रेशन पर 1962-63 में 61 लाख रुपये खर्च हुआ, लेकिन आज चार साल बाद वह बढ़ कर 1 करोड़ 10 लाख हो गया—यह एक्सपेन्शन वहां पर हुआ है। पुलिस पर 1963–64 में एक करोड़ रुपये खर्च था, लेकिन अब वह बढ़ कर पोने तीन करोड़ हो गया है—यह एक्सपेन्शन हुआ है। ये फिगर्स मैं काश्मीर बजट से पेश कर रहा हूं। इंडस्ट्रीज के बजट में हम उस वक्त 2 करोड़ 49 लाख

[श्री गुलाम मुहम्मद बख्शी]

रुपये, तकरीबन ढाई करोड़ रुपये खर्च करते थे, लेकिन अब उस पर 49 लाख रुपये खर्च हुए हैं—यानी जो डवेलपमेंट की चीज थी, उनको रोक दिया गया है। मि० डांगे यहां बैठे थे—वह लेबर के मामले में वहां गये थे। हमारी सिल्क फैक्टरी में जहां चार हजार आदमी काम करते थे, वहां अब पांच सौ से भी ज्यादा नहीं हैं। कोकून्ज 60 हजार मन पैदा होती थी, वहां अब 10–12 हजार मन पैदा होती है—7–8 महीने से वे लोग बेकार हैं। इस लिये जनाब, मैं चाहता हूं कि इन सब चीजों पर तवज्जह दी जाय।

दूसरी बात मैं होमगार्ड्स और फील्ड सर्वे आरगेनिजेशन के बारे में कहना चाहता हूं। यहां पर अभी एफ० एस० ए० का तज़किरा हुआ, जिस पर डेढ़ करोड़ रुपये से ज्यादा खर्च होता है। अगर आप उनको डिस्मिस करेंगे . . .

महन्त दिग्विजय नाथ (गोरखपुर) : वे हिन्दू हैं या मुसलमान ?

बख्शी गुलाम मुहम्मद : हिन्दू-मुसलमान सब हैं। अब अगर इन 10 हजार आदमियों को आप डिसमिस करेंगे तो शायद एक नई प्राबल्म एम्पलायमेंट की खड़ी हो जायगी। लेकिन यह बात ठीक है—कि इनके अन्दर जो एन्टी-नेशनल, एन्टी-सोशल एलीमेन्ट भरे हुए हैं, इन को वीड-आउट किया जाय और जो बाकी बचते हैं, उन को एबजार्ब कर लिया जाये और इन को आप थियेटर-कमाण्डर को हैण्डओवर कर दें। आप उनको कह दीजिये कि सेन्टर इस में ग्रान्ट देता है, 90 फीसदी तक और बार्डर डिफेन्स के लिये उन को रखा गया है और उस के बाद उन को चाइना बार्डर और पाकिस्तान बार्डर पर लगा दीजिये, क्या जरूरी है कि उन को श्रीनगर या अनन्तनाग या बारामुला में ही लगाया जाये। वहां उन का क्या काम है ? इस लिये मैं अर्ज कर रहा हूं कि इस तरह से डिस्मिस करना मुश्किल होगा, लिहाजा आप इतनी कृपा कीजिये कि जिस काम के लिये उनको भरती किया गया है, उन को उस काम पर लगाया जाय और स्ट्रेट-अवे उन से वह काम लिया जाय। उनको लद्दाख भेज दीजिये, चुशूल भेज दीजिये, कारगिल भेज दीजिये—बार्डर पर लगा दीजिये।

यहां पर फूड के सिलसिले में तज़किरा हुआ—वाकई एलार्मिंग पोजीशन थी। जब सैलाब के साल में यानी 1957 से 1959 में 60 हजार टन से 62 हजार टन से ज्यादा गल्ला नहीं गया—हर किस्म का गल्ला—राइस, मेज, ज्वार, बाजरा, व्हीट वगैरह, लेकिन 1965–66 में मेरे एक सवाल के जवाब में, जो कि मुझे कल ही मिला है, बताया गया है कि 3 साल में 5 लाख 58 हजार टन गल्ला गया है—मैं चाहता हूं कि इस की देखभाल की जाये कि ऐसा क्यों हुआ है।

यहां पर किसी दोस्त ने शायद ऐसा कहा कि काश्मीर को सस्ता गल्ला दिया जाता है। मैं इस हाउस की इत्तिला के लिये अर्ज करना चाहता हूं कि काश्मीर को भी उसी कीमत पर गल्ला दिया जाता है, जिस कीमत पर दूसरों को मिलता है। हां, काश्मीर गवर्नमेंट उस में अपनी तरफ से सबसिडी देती है, उसको गवर्नमेंट आफ इंडिया सबसीडाइज नहीं कर रही है। गवर्नमेंट आफ इंडिया 1957-58 तक करती थी, लेकिन अब काश्मीर गवर्नमेंट कर रही है। हां यह बात जरूर है कि काश्मीर गवर्नमेंट पहले टू दी टयून आफ 1,25,000, 1,75,000 और ढाई लाख तक करती थी, लेकिन अब यह हो गया है कि 8 करोड़ रुपये तक किया जा रहा है–इस लिये मेरा खयाल है कि इस तरफ भी तवज्जह देने की जरूरत है।

तीसरी बात मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि जनाब सादिक ने अपने पालिसी स्टेटमेंट में कहा था कि मैं डेमाक्रेसी में बिलीव करता हूं। यकीनन अगर मेरे जमाने में एक बार भी गोली चली, तो मैं उसी वक्त कुर्सी छोड़ दूंगा। लेकिन यह कुर्सी जनाब इतनी प्यारी है कि कोई उसको नहीं छोड़ता। अब

आप देख लीजिये कि कितनी बार वहां पर गोली चली । इस सरकार से हम को तीन चीजें मिली हैं — 1965 में इन्डो-पाकिस्तान कान्फ्लिक्ट हुआ—बहुत बड़ा तोहफ़ा मिला । हमारे चह्वाण साहब उस वक्त 3 अगस्त को श्रीनगर में थे—उन्होंने उस वक्त कहा—

"There is no fear of infiltration and we have sealed the borders". On the 8th of August, on this very hon. House, Shri Nanda announced that 12,000 infiltrations have reached Srinagar and they have surrounded Srinagar.

मैं इसकी डिटेल्ज में नहीं जाना चाहता हूं, लेकिन सवाल पालिसी आफ़ लिब्रलाइजेशन का है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि मेरे जमाने में एक बार भी गोली नहीं चली—1953 से लेकर 1963 तक एक बार भी लोगों पर गोली नहीं चली, एक भी स्ट्राइक नहीं हुई, लेकिन 1964 से ये सब होना शुरू हो गया—अब, आप कह दीजिये कि यह सब तुम करा रहे हो । बख्शी फोबिया कह दीजिये ।

तो मैं अर्ज कर रहा था कि 1965 में पाकिस्तान-इंडिया कान्फ्लिक्ट का तोहफ़ा मिला, 1966 में जम्मू स्टूडेंट्स पर फाइरिंग और किलिंग हुई और 1967 में काश्मीर के हिन्दू और मुसलमान दोनों पर फाइरिंग हुआ—वहां पर दफा 144 को लागू किया गया । दफा 144 तो जनाब काश्मीर के आइने का, किताब का एक स्टेचूट बन गया है —

It is perpetual 144 since 1965 up to this time.

और मैं आपकी आगाही के लिये यह भी अर्ज कर दूं कि पिछले इलेक्शन के दौरान भी दफा 144 को नहीं उठाया गया । हम लोग इजाजत लेकर जल्से करते थे, अगर इजाजत मिल जाती थी तो जल्सा करते थे, अगर इजाजत नहीं मिलती थी तो नहीं कर सकते थे ।

It has become perpetual.

करफ्यू के सिलसिले में भी अर्ज कर दूं । यहां बंगाल की हालत यह है कि अगर 24 घण्टे का भी करफ्यू लगता है तो इतना शोर होता है, लेकिन वहां पांच दिन तक तो करफ्यू के नीचे बिलकुल बन्द ही रहा और अभी तक भी नाइट-करफ्यू चलता है—यह हालत आज वहां की है । आप यह कहेंगे कि मैं वहां की गवर्नमेंट की डिफिकल्टीज को जानता हूं एक दोस्त ने यहां कहा कि जम्मू कश्मीर राज्य में राष्ट्रपति राज्य का मतालबा करने से अगर हम राष्ट्रपति राज्य वहां पर लागू करेंगे तो पाकिस्तान के हाथ में हम एक हैंडिल देंगे तो मेरा कहना है कि हैंडिल तो जनाबवाला हम ने उसी दिन पाकिस्तान को दे दिया जिस दिन कि यह 141 नामिनेशन फोर्म्स रिजैक्ट कर दिये और तब से वह बराबर दिया जा रहा है। मुझे फिक्र है कि डेमोक्रेसी का क्या होगा ? बाकी अब चूंकि वक्त नहीं है इसलिए मैं और ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा । बहरहाल यह एक नक्शा था जो मैंने आप के सामने रखा । मुझे उम्मीद है कि मैं ने कुछ मोडरेट और प्रैक्टिकल सजैशंस दिये हैं और उन को एक्सैप्ट करने में आप को कोई डिफिकल्टी नहीं होनी चाहिए या फिर यह कहिये कि वह आप की उस फारसी के शायर जैसी हालत है जिसने यह लिखा है :

"उम्रे वायद कि यार आयद वकनार" ।

तुम भी रहो हजार साल और यह सिलसिला भी चलता रहे हजार साल । आप ने यह नहीं करना है और न यह हमें हासिल होगा ।

इसलिए मैं आखिर में बस यही अर्ज कर के खत्म करूंगा कि कश्मीर हिन्दुस्तान के साथ है, कश्मीर के मुसलमान, कश्मीर के हिन्दू, जम्मू के हिन्दू व सिख और लद्दाख के बौद्ध सब हिन्दुस्तान के साथ हैं । वह उन तमाम चीजों के बावजूद हिन्दुस्तानी हैं, हिन्दुस्तानी रहे हैं और आगे वह हिन्दुस्तानी रहने वाले हैं और वह उस से दूर नहीं जायेंगे ।

شری بخشی غلام محمد (شری نگر) : جناب ڈپٹی اسپیکر— کشمیر پر مجھ

آگے بھی جڑا رھیگا یہ میں آپ کو بتلانا چاھتا ھوں ۔ باقی کشمیر کے بارے میں کنٹروورسی رھنے کے کئی کارن ھو سکتے ھیں ۔ اب کسی دوست کا یہ سجھاؤ ھے کہ فلانی دفعہ کو اڑا دو سب ٹھیک ھو جائیگا ۔ میرا اپنا یہ خیال ھے ۔ میں ایمانداری سے یہ کہنا چاھتا ھوں اور اسی لئے میں نے جناب سے پہلے مانگا تھا وقت ۔ کشمیر کی بد قسمتی سے موجودہ گورنمنٹ جو ھے میں کسی ناراضگی یا کسی دینکر کی وجہہ سے نہیں کہہ رھا ھوں کہ لال بہادر جی نے جب موجودہ گورنمنٹ کو انسٹال کیا فروری ۱۹۶۴ میں تب بھی وہ ریپریزنٹیٹو نہیں تھے ان کے ساتھ پاپلر اوپنیئن نہیں تھی اور ٦٧ کا ایلکیشن جب آیا ۔ تین سال گزرے اور ٦٧ میں جب ایلکشن کے بارے میں لوگوں نے امیدیں باندھی ھوئی تھیں کہ یہ ایلکشن فری ھونگے امپارشئل طریقے سے ھونگے اور جو بھی گورنمنٹ پاور میں آئیگی وہ لوگوں کی گورنمنٹ ھوگی ۔ وہ کشمیر کی خدمت کریگی اور اپنی ذمہ داریوں کو نبھائگی لیکن بد قسمتی سے ھوا کیا ۔ ایلکشن سے پہلے وھاں جس کا تذکرہ میرے فاضل دوست شاستری جی نے کیا ۱۰۰۰۰ ھوم گارڈس نے دسمبر سے ھی وھاں پر انہوں نے فنکشن کرنا شروع کیا ۔ اس کے متعلق میں نے آنریبل ھوم منسٹر کو ایک لمبا چوڑا خط لکھا کہ اس میں یہ ھو

[شری بخشی غلام محمد]

سے پہلے کچھ چند ایک آنریبل میمبرس نے اپنے خیالات کا اظہار کیا لیکن ایک چیز پہلے ھی میں عرض کرنا چاھتا ھوں ۔ ایک غلط فہمی دور کرنے کے لئے اور وہ یہ ھے ، کہ کشمیر میں بد قسمتی سے جو ۷ جون سے ستمبر تک ھوا تو کشمیر کو اسی مائناریٹی اور مجارٹی کے یارڈاسٹک سے نہ ناپئے کیونکہ کشمیر کی میجارٹی اور کشمیر کی مائناریٹی ھزارھا سال سے اکٹھا رھتی آئی ھے ۔ وہ سیکولر رھی ھے ۔ ھے اور آگے بھی سیکولر رھیگی ۔

They have lived like that and they can live like that till enternity.

وھاں جو کچھ ھوا پرکاش ویر شاستری جی نے یا میرے اور دوستوں نے کہا کمیونلزم وھاں پر مسلمان نے نہیں کیا ھندو نے نہیں کیا مسلمان نے ھندو پر ھاتھ نہیں اٹھایا اور ھندو نے مسلمان پر ھاتھ نہیں اٹھایا ۔ یہ کمیونلزم والی بالکل غلط بات ھے اور میں زور شور سے اس کی تردید کرتا ھوں ۔ اگر وھاں کوئی آدمی مرا ھے تو وہ پولیس کی گولی سے مرا ھے لاٹھی چارج سے مرا ھے ۔ وہ پولیس کی فائرنگ سے مرا ھے ۔ کشمیر سیکولر رھا ھے ۔ سیکولر ھے اور سیکولر رھیگا ۔ کشمیر نے تمام کنٹرو ورسیز کے بغیر اپنا نام ھندوستان کے ساتھ جوڑا ھے ۔ وہ آج جڑا ھے اور

نے فیصلہ کیا دیا - نہیں کشمیر میں بھی ۲۱ فروری کو ہی چناو ہوگا جبکہ کشمیر میں ۳ - ۴ - ۵ اور ۶—۶ فٹ برف جمی ہوئی تھی - پہلی تو یہ بات ہے پھر اس کے بعد ۲۱ جنوری آئی نامینیشن پیپرس داخل کرنے تھے اور سب نے نامینیشن پیپرس داخل کر دئے - ہم نے بھی اور دوسری اور اپوزیشن پارٹیز نے اپنے نامینیشن پیپرس داخل کئے اور میں بتلانا چاہتا ہوں کہ ہم لوگوں کے ۱۴۱ نامینیشن پیپرس فلمزیئسٹ گراؤنڈس پر ریجکٹ ہوئے اور جسے کہ خود ایلکشن کمیشن مانتا ہے -

Not a single nomination paper of the ruling party was rejected.

رئل پوزیشن یہ ہے -

Then we again approached the President, the hon. Prime Minister, the Home Minister and other Central Ministers, put all these facts before them.

اس پر ہم نے مطالبہ کیا کہ ان ہول سیل ریجکشن کی وجہہ سے اور موسم کی خرابی کی وجہہ سے ایلکشن کو اینل کر دیا جائے یا پھر پوسٹپون ہی کر دیا جائے لیکن نہ تو اسے اینل کیا گیا اور نہ ہی پوسٹپون کیا گیا - میں نے چوہان کو خط لکھا کہ صاحب کم از کم یہ توقع نہیں ہو سکتی ایک ایسی گورنمنٹ سے اور ایک ایسی سرکار سے جس نے ہندوستان کی ڈیموکریسی کے لئے اپنا ہر ایک حق نیوچھاور کیا ہو - ان سے یہ توقع نہیں ہو سکتی - رہا ہے اور آپ ادھر اور ذرا توجہہ دیجئے -

They are breaking meetings of Opposition parties.

ہم خود میٹنگ نہیں کر سکتے - جہاں بھی ہم میٹنگ کرتے ہیں وہاں وہ بریک کرتے ہیں اور اس سلسلے میں کتنے ہی ہمارے آدمیوں کو - ایک دوکو نہیں بلکہ سینکڑوں آدمیوں کو زخمی کر دیا - میں نے خود منسٹر کو لکھا - چوہان کو لکھا - اس کے بعد ایک ایلکشن کمیشن نے اینا‌ؤنس کیا لا منسٹر نے یہاں و پارلیامنٹ میں اینا‌ؤنس کیا کہ جموں و کشمیر میں ایلکشنس ہونگے - جموں میں ایلکشنس ریسٹ آف دی کنٹری کے ساتھ ہونگے اور کشمیر کے حالات سامنے رکھ کر وہاں پر اینڈ آف دی مارچ میں ہونگے کیونکہ یہی شڈیول پہلے بھی رہا ہے - لیکن ہوا کیا - اس بارے میں ایلیکشن کمیشن کا نوٹیفکیشن ہے لیکن وہ رولنگ پارٹی کا میں ان کو کوئی نام نہیں دیتا جس طریقے سے میں نے آپ سے کہا رولنگ پارٹی نے فوری طور پر وہ کوئی پسند نہیں تھا لیکن انہوں نے اینا‌ؤنس کیا ایلکشن کمیشن نے اینا‌ئونس کیا کہ کشمیر کے لئے ۲۱ مارچ اور جموں کے لئے ۱۹ فروری ہوگی پنجاب کے ساتھ ساتھ - فوری طور پر بدل گئے ہم نے ریپریزنٹیشن کیا اور بجائے مارچ کے اپریل کر دیا اور جموں کشمیر میں ایک ساتھ کر دیا - ایلکشن کمیشن

وہ بالکل کھڑے رہے بھوت کی طرح ۔
وہ دیکھتے ہیں کہتے ہیں کہ
ہم کیا کرینگے ۔ اور پریٹکلر کانسٹی
ٹیوینسی میں کیا ہوا ۵۵ ٹوٹل
سٹرینگتھ ہے اس بوتھ کی لیکن اس
بکسے میں سے ۱۱۸۵ بیلٹس نکلے ۔
یہ ہوا ۔ . . . . . .
(ویودھان) . . . . . اس پر
بھی کچھ نہیں ہوا ۔ ہم ڈاکٹر کرن
سنگھ جو اس وقت وہاں کے گورنر تھے
اس سے بھی ملے سب سے ملے واویلا
کیا راشٹر پتی سے ملے لیکن آخر کو
ہم کو حکم ہوا کہ قانون اجازت
نہیں دیتا ۔ ہم اپنل تو نہیں کرینگے
کیونکہ باہر دنیا میں کیا کہا
جائیگا ۔ ہم نے کہا کہ باہر دنیا
تو ہماری ناک کٹ گئی ۔ انڈیا
کے مطالق یہ کہا جاتا تھا کہ یہاں
الیکشنس فیئر اور امپارشیل ہوتے
ہیں ۔ چنانچہ ہمارے شو کمار سین
سوڈان اور ایجپٹ میں الیکشنس
کرانے کے لئے گئے اور یہاں یہ ہو
رہا ہے ۔ خود سندرم نے کہا ہے ۔

"that the nomination papers of a large number of opposition candidates were rejected on flimsy grounds is serious."

اور پنر وہ کہتے ہیں ۔

"The difference in law is not satisfactory, and I intend recommending to the State Government that the State election law should be brought in line with the general election law on this point as soon as possible."

یہ سندرم کہتے ہیں کہ معاملہ
سیریس ہے ۔ ہمیں ہدایت دی کہ

[شری بخشی غلام محمد]

اور چوہان صاحب نے مجھے
خط لکھا ۔ میں وہ خط پڑھ کر سناتا
ہوں ۔

"I have your letter No. ..... dated 7th January. I am forwarding a copy of this letter to Sadiq Saheb, with a request that he should look into your complaints personally and satisfy himself that nothing wrong or improper is done. I am very keen that the elections in Jammu and Kashmir, as in the rest of the country, should not only be fair, but should also appear to be so, and that nothing should be done that can be regarded as at all unfair and improper."

یہ ہے چوہان صاحب کا خط ۔
اب اس سے اور ایک ہمت ہوئی ہمیں
کہ ایلیکشن فیئر اور امپارشیل
ہونگے ۔ لیکن جناب ہوا کیا ۔
ریجیکشنس ہوئے ۔ ۲۶ آدمی اسیمبلی
میں انکنٹیسٹیڈ آ گئے سٹریٹ اوے
لہذا ۲۶ کی سٹرینگتھ بن گئی ۔ اور
پنر اس کے بعد جو ہوا وہ سب کو
معلوم ہے ۔ دیز آر آل اوپن سکیریٹس ۔

These are all open secrets.

بیلٹ باکسیس آئے ٹوٹے اور
لاس کے بغیر ، سیل کے بغیر ، بیلٹ
پیپر ایکاؤنٹ کئے بغیر ۔ ہم نے
اعتراض کیا ۔

No body just did anything or cared.

لیکن کہا کہ ٹھیک ہے کاونٹ
کیا جاوے ۔ ایلیکشن کمیشن نے
دو آدمی یہاں سے بھیجے کشمیر میں
اسے دیکھنے کے لئے

with no instructions.

فیصلہ ہوتا ستمبر تک کشمیر اسمبلی میں ان کو پتہ لگ گیا کہ ایک ان سیٹ ہو گیا ۔

Because of uncontested return rejection of nomination paper.

۲۵ اور ہونگے ۔ تو انہوں نے ایک دن میں لا بدل دیا اور وہ لا بھی ایک دن میں اسمبلی بیٹھی ۔ اور اسے بدل دیا ۔ ۹ ستمبر کو بدلا اور ۱۰ ستمبر کو ایسنٹ لے لی گورنر سے ۱۱ کو لاگو کر دیا ۔ اور الیکشن ٹریبونل سرکار نے مقرر کیا تھا وہ عدالت میں بیٹھا ہوا تھا الیکشن پٹیشن سننے کے لئے چپراسی گیا اور اس کو کہا کہ

You are no more an election tribunal, please go.

وہ ۱۱ کو ہوا اور ۱۱ کو جب یہ ہوا میں پہنچا دوڑتے دوڑتے پھر چوہان صاحب کے پاس ۔ آخر کہاں جائیں ۔ حاکم تو یہی ہیں ۔ ہم تو انہیں سے بتائیں گے کہ آگے تفتیش ان کا کام ہے ۔ میں پھر آیا میں نے لمبا چوڑا لکھا اور ان کو بتا دیا کہ یہ لا پاس ہوا اور کیا کیا ہوا اس طرح ایک دن میں ۔

الیکشن ٹریبونل ختم ہو گیا ۔ میں نے کہا کہ ایڈ ہاک جلد سے جلد مقرر کیجئے ۔ انہوں نے کہا کہ میں جلدی کروں گا ۔ یہ بات ہوئی شاید ۱۴ ستمبر کو ۔

جاؤ الیکشن کرو ۔ ہم نے کہا کہ اچھا ۔ جب اور کچھ نہیں ہوتا ہے تو بھی ایک ہی ریمیڈی ہے کہ الیکشن پیٹیشن

That is the law of the country.

اور ہم اس کے سامنے جھکے ۔ تو جناب وہ بھی ماجرا سن لیجئے کہ ۵۷ الیکشن پیٹیشنس ہیں کشمیر کی ۔ آندھر پردیش میں ۱۲ تھیں اور ۱۲ ڈسپوز ہو گئیں ۔ ہریانہ میں ۱۳ تھیں اور اس میں سے ۱۲ کا فیصلہ ابھی تک ہو چکا ہے ۔ مہا راشٹر میں ۲۱ تھیں ۲۰ کا فیصلہ ہو چکا ۔ میسور میں ۲۱ تھیں ۱۳ کا فیصلہ ہوا ہے ۔ جب کہ جموں اور کشمیر ۵۷ الیکشن پیٹیشنس تھیں اور خدا کے فضل سے ایک کا فیصلہ ہوا ہے ۔ ریبل سٹوری پر آئیے ۔ ٹریبونل بنتا ہے ۔ سندرم نے کہا لا بدل دو ۔

Bring it on a part with the rest of the country—as early as February 67.

اسمبلی ملی مارچ میں ۔ اس میں لا پاس نہیں ہوا ۔ اور پھر ہوا ۔ ٹریبونل مقرر کیا انڈر دی اولڈ لا ۔ ٹریبونل نے کام شروع کیا کر دیا ۔ ایک کا فیصلہ دیا ۔ یعی اس کا شڈیول تھا وہ ۲۶ کے فیصلے دینے والا تھا ان دی منتھ آف ستمبر ..... (ویودھان) ..... تو پھر کیا ہوا ۔ ۲۶ جو ان کنٹیسٹڈ رٹرنز تھے ان کا

کیجئے - یہ بھی آپ نہیں مانیں گے - مجھے معلوم ہے نہیں مانیں گے آپ - کشمیر سبجیکٹ ہے - تو پھر میں عرض کروں گا آپ سے کہ آج نو مہینے ہو گئے ہیں - اب دسمبر - جنوری فروری اور مارچ چار مہینے ہیں - معمولی سا سجیشن آپ سے عرض کرتا ہوں - پازیٹو سجیشن ہے - ان چار مہینوں میں ان سب پیٹیشنز کا فیصلہ کرا دیجئے -

And let there be fresh elections in April 68.

یہ میرا سجیشن ہے کہ آپ زیادہ سے زیادہ ججز کو مقرر کریں جو ان کنوننز کا جلد سے جلد فیصلہ کریں - میں ایکسٹر یمسیٹ نہیں ہوں ایکسٹریم میں نہیں جاونگا - یہ ایک سجھاؤ ہے مہربانی کرکے امیڈیٹ اسٹیپس لیجئے - ۱۴۱ کیسز کو ڈیسائڈ کرائیے - خاص طور سے ۲۱ کیسیز اسیمبلی کے ہیں جن کو ججیز کو مقرر کر کے ڈیسائڈ کرائیے - اگر یہ کیسیز مارچ کے آخیر تک ڈسائڈ ہو جائیں تو فریش ایلیکشنز اپریل میں ہو سکتے ہیں - فریش ایلیکشنز سے میرا مطلب بائی ایلیکشنز ہے -

دوسری بات - یہاں پر کشمیر کو دی جانے والی سہایتا کے متعلق کہا گیا ہے - کشمیر آپ کا ایک غریب ساتھی ہے- جہاں بمبئی اور کلکتہ جیسے آپ کے امیر ساتھی ہیں وہاں کشمیر جیسا ایک چھوٹا اور غریب

[شری بخشی غلام محمد]

اور آج ستمبر بھی گیا - اکتوبر بھی گیا - نومبر بھی گیا - آج آخری تاریخ ہے نومبر کی -

نو مہینے ہو گئے ہماری پیٹیشن کے - ۵۷ الیکشن پیٹشنز میں سے ایک کا فیصلہ ہوا ہے اور خدا نے چاہا اگر یہی سپیڈ رہی تو کم سے کم ۱۰ سال ان کو چاہئے یہ فیصلہ کرنے کے لئے حالانکہ قانون ہے کہ ودن سکس منتھس ہونا چاہئے - مہا راشٹر میں ۲۱ میں ۲۰ کا فیصلہ ہو گیا - ہریانہ میں ۱۵—۱۲ کا فیصلہ ہو گیا - بائی الیکشن بھی ہو گئے - لیکن کشمیر جس کو کہ کہا جاتا ہے کہ سپیشل سبجکٹ ہے ۳۷۰ ہے ۳۸۰ ہے - ۳۹۰ ہے مجھے معلوم نہیں اور کون کون سے سبجیکٹس لاگو ہیں لیکن یہ کیا ہے کہ آج تک اس وقت تک کوئی ایڈ ہاک جج مقرر نہیں ہوا ہے - جب کہ ہائی کورٹ میں وہاں تین آدمی مشتمل ہیں -

They are fully occupied with their own work.

وہ نہیں کر سکتے انہوں نے صاف کہا -

لیکن میں راشٹر پتی راجیہ کے متعلق کہوں تو انہیں نا منظور ہوگی بات - میں ایک بات کہونگا - جو میرا خیال ہے انہیں پسند آئیگی - میں ان کو یہ کہونگا کہ یہ مائناریٹی گورنمنٹ جو ہے جو اس طرح بنی ہے اور جس کے خلاف اتنے پیٹشنز ہیں اس کو ڈسمس

خرچ تھا - لیکن اب وہ بڑھ کر پونے تین کروڑ ہو گیا ہے - یہ ایکسپانشن ہوا ہے - یہ فگرس میں کشمیر بجٹ سے پیش کر رہا ہوں - انڈسٹریز کے بجٹ میں ہم اس وقت ۲ کروڑ ۴۹ لاکھ روپیہ یعنی تقریباً ڈھائی لاکھ روپیہ خرچ کرتے تھے لیکن اب اس پر ۴۹ لاکھ روپیہ خرچ ہوئے تھیں - یعنی ڈویلپمنٹ کی چیز تھی ان کو روک دیا گیا - مسٹر ڈانگے یہاں بیٹھے تھے - وہ لیبر کے معاملے میں وہاں گئے تھے - ہماری سلک فیکٹری میں جہاں چار ہزار آدمی کام کرتے تھے وہا اب ۵۰۰ سے بھی زیادہ نہیں ہیں - کوکوئز ۶۰ ہزار من پیدا ہوتی تھی وہاں اب ۱۰-۱۲ ہزار من پیدا ہوتی ہے - ۷-۸ مہینے سے وہ لوگ بیکار ہیں - اسلئے جناب میں چاہتا ہوں کہ ان سب چیزوں پر توجہ دی جائے -

دوسری بات میں ہوم گارڈس اور فیلڈ سروے آرگنیزیشن کے بارے میں کہنا چاہتا ہوں - یہاں پر ابھی ایف-ایس - اے کا تزکرہ ہوا جس پر ڈیڑھ کروڑ روپیہ سے زیادہ خرچ ہونا ہے - اگر آپ ان کو ڈسمس کرینگے -

مہنت دگوجے ناتھ (گورکھپور) : وہ ہندو ہیں یا مسلمان -

شری بخشی غلام محمد : ہندو مسلمان سب ہیں - اب اگر ان دس ہزار آدمیوں کو آپ ڈسمس کرینگے ساتھی بھی ہے- اسلئے سہایتا تو اس کو دینی ہی پڑیگی - میں آپکی اطلاع کے طور پر عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ۱۹۴۷ سے مارچ ۱۹۶۴ تک ٹوٹل گرانٹس اور لونز جو کشمیر کو ملے - وہ تھے تقریباً ۷۲ کروڑ روپیہ - لیکن ۱۹۶۴ سے ۱۹۶۶ کے آخیر تک جو نئی سرکار کو ملے وہ تھے ۷۰ کروڑ روپیہ - یعنی دو سال میں انکو ۷۰ کروڑ روپیہ دیا گیا - میں چاہتا ہوں کہ آپ اس کی ذرا دیکھ بھال کیجئے - میں یہ جو فگرز آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں یہ میں فائننس ڈپارٹمنٹ کے سٹیٹمنٹ سے کوٹ کر رہا ہوں - یہ میری اپنی فگرز نہیں ہیں - بلکہ فائننس ڈپارٹمنٹ سے جو فگرز میرے پاس آئیں ہیں ان میں سے بتا رہا ہوں - کشمیر پر تھوڑا رحم کھائیے -

پاٹودیا جی نے ایک بڑی ہی کنسٹرکٹو ایپروچ کی بات کہی ہے - لوگوں کو اپنے ساتھ رکھئیے لیکن ان کو کام دیجئیے - وہاں پر کام دھندوں کا ایکسپانشن ہونا چاہئیے - انڈسٹریل ڈویلپمنٹ ہونا چاہئیے - ایگریکلچر کو بڑھاوا دیجئیے - لیکن ہوتا کیا ہے - جینرل ایڈمنسٹریشن پر ۱۹۶۲-۱۹۶۳ میں ۶۱ لاکھ خرچ ہوا لیکن آج چار سال بعد وہ بڑھ کر ۱ کروڑ ۱۰ لاکھ ہو گیا یہ ایکسپانشن وہاں پر ہوا ہے - پولیس پر ۱۹۶۳-۱۹۶۴ میں ایک کروڑ روپیہ

[شری بخشی غلام محمد]

تو شاید ایک نئی پرابلم ایمپلائمنٹ کی کھڑی ہو جائیگی - لیکن یہ بات ٹھیک ہے کہ ان کے اندر جو اینٹی سوشل اینٹی نیشنل ایلیمنٹ بھرے ہوئے ہیں ان کو ویڈ آوٹ کیا جائے. اور جو باقی بچتے ہیں ان کو ابزارب کر لیا جائے اور ان کو آپ تھیٹر کمانڈر کو ہینڈ اوور کر دیں - آپ ان کو کہہ دیجیئے کہ سینٹر اس میں گرانٹ دیتا ہے ۹۰ فی صدی تک اور بورڈر ڈفینس کے لئے ان کو رکھا گیا ہے اور اس کے بعد ان کو چائنا بورڈر اور پاکستان بورڈر پر لگا دیجئے - کیا ضروری ہے کہ ان کو شری نگر یا اننت ناگ یا بارا مولا میں ہی لگایا جائے - وہاں ان کا کیا کام ہے - اس لئے میں عرض کر رہا ہوں کہ اس طرح سے ڈسمس کرنا مشکل ہوگا - لہذا آپ اتنی کرپا کیجئیے ان کو بھرتی کیا گیا ہے ان کو اس کام پر لگایا جائے اور سٹریٹ اوے ان سے وہ کام لیا جائے - ان کو لداخ بھیج دیجیئے - چوشول بھیج دیجیئے - کارگل بھیج دیجیئے - بارڈر پر لگا دیجیئے -

یہاں پر فوڈ کے سلسلے میں تذکرہ ہوا - واقعی ایلارمنگ پوزیشن تھی - جب سیلاب کے سال میں یعنی ۱۹۵۷ سے ۱۹۵۹ میں ۶۰ ہزار ٹن ۶۲ ہزار ٹن سے زیادہ غلہ نہیں گیا - ہر قسم کا غلہ رائس - میز - جوار - باجرہ - وھیٹ وغیرہ - لیکن ۱۹۶۵-۱۹۶۶ میں میرے ایک سوال کے جواب میں جو کہ مجھے کل ہی ملا ہے بتایا گیا ہے - کہ تین سال میں ۵ لاکھ ۵۸ ہزار ٹن گیا ہے - میں چاہتا ہوں کہ اس کی دیکھ بھال کی جائے کہ ایسا کیوں ہوا ہے -

یہاں پر کسی دوست نے شاید ایسا کہا - کہ کشمیر کو سستا غلہ دیا جاتا ہے - میں اس ہاوس کی اطلاع کے لئے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ کشمیر کو بھی اسی قیمت پر غلہ دیا جاتا ہے جس قیمت پر دوسروں کو ملتا ہے - ہاں ، کشمیر گورنمنٹ اس میں اپنی طرف سے سبسڈی دیتی ہے - اس کو گورنمنٹ آف انڈیا سبسیڈ ائز نہیں کر رہی ہے - گورنمنٹ آف انڈیا ۱۹۵۷-۱۹۵۸ تک کرتی تھی - لیکن اب کشمیر گورنمنٹ کر رہی ہے - ہاں یہ بات ضرور ہے کہ کشمیر گورنمنٹ پہلے ٹو دی ٹیون آف ۱۲۵۰۰۰-۱۷۵۰۰۰ اور ڈھائی لاکھ تک کرتی تھی لیکن اب یہ ہو گیا ہے کہ آٹھ کروڑ روپیہ تک کیا جا رہا ہے - اسلئے میرا خیال ہے کہ اس طرف بھی توجہ دینے کی ضرورت ہے -

تیسری بات میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جناب صادق صاحب نے اپنی پالسی سٹیٹمنٹ میں کہا تھا کہ میں ڈیموکریسی میں بیلیو کرتا ہوں - یقیناً اگر میرے زمانے میں ایک بار بھی گولی چلی تو میں اسی وقت کرسی چھوڑ دونگا - لیکن

It is perpetual 144 since 1965 upto this time.

اور میں آپ کی آگاہی کے لئے یہ بھی عرض کر دوں کہ پچھلے ایلیکشن کے دوران بھی دفعہ ۱۴۴ کو نہیں اٹھایا گیا۔ ہم لوگ اجازت لیکر جلسے کرتے تھے ۔ اگر اجازت ملتی تھی تو جلسہ کرتے تھے ۔ اگر اجازت نہیں ملتی تھی تو نہیں کر سکتے تھے ۔

It has become perpetual.

کرفیو کے سلسلے میں بھی عرض کر دوں ۔ یہاں بنگال کی حالت یہ ہے کہ اگر ۲۴ گھنٹے کا بھی کرفیو لگتا ہے تو اتنا شور ہوتا ہے ۔ لیکن وہاں پانچ دن تک تو کرفیو کے نیچے بالکل بند ہی رہا اور ابھی تک بھی نائٹ کرفیو چلتا ہے ۔ یہ حالت آج وہاں کی ہے ۔ آپ یہ کہینگے کہ میں وہاں کی گورنمنٹ کی ڈفیکلٹیز کو جانتا ہوں ایک دوست نے یہاں کہا کہ جموں کشمیر راج میں راشٹر پتی راج کا مطالبہ کرنے سے اگر ہم راشٹر پتی راج وہاں پر لاگو کرینگے تو پاکستان کے ہاتھ میں ہم ایک ہینڈل دینگے تو میرا کہنا ہے کہ ہینڈل تو جناب والا ہم نے اسی دن پاکستان کو دے دیا جس دن کی یہ ۱۴۱ نامینیشن فارمس ریجکٹ کر دئے اور تب سے وہ برابر دیا جا رہا ہے ۔ مجھے فکر ہے کہ ڈیمو کریسی کا کیا ہوگا ۔ باقی اب چونکہ وقت نہیں ہے اس لئے میں اور زیادہ کچھ نہیں کہونگا ۔

یہ کرسی جناب اتنی پیاری ہے کہ کوئی اس کو نہیں چھوڑتا ۔ اب آپ دیکھ لیجیئے کہ کتنی بار وہاں پر گولی چلی ۔ اس سرکار سے ہم کو تین چیزیں ملی ہیں ۔ ۱۹۶۵ میں میں انڈو ۔ پاکستان کا کانفلکٹ ہوا ۔ بہت بڑا تحفہ ملا ۔ ہمارے چوہان صاحب اس وقت ۳ اگست کو شری نگر میں تھے ۔ انہوں نے اس وقت کہا ۔

"There is no fear of infiltration and we have sealed the borders."

On the 8th of August, in this very hon. House Shri Nanda announced that 12,000 infiltrators have reached Srinagar and they have surrounded Srinagar.

میں اس کی ڈیٹیلز میں نہیں جاتا ۔ لیکن سوال پالسی آف لبرلائیزیشن کا ہے ۔ میں دعویٰ کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ میرے زمانے میں ایک بار بھی گولی نہیں چلی ۔ ۱۹۵۳ سے لیکر ۱۹۶۳ تک ایک بار بھی لوگوں پر گولی نہیں چلی ۔ ایک بھی سٹرائک نہیں ہوئی ۔ لیکن ۱۹۶۴ سے یہ سب ہونا شروع ہو گیا ۔ اب آپ کہہ دیجیئے کہ یہ سب تم کرا رہے ہو ۔ بخشی فوبیا کہہ دیجیئے ۔

تو میں عرض کر رہا تھا کہ ۱۹۶۵ میں پاکستان انڈیا کانفلکٹ کا تحفہ ملا ۔ ۱۹۶۶ میں جموں سٹوڈینٹس پر فائرنگ ہوا ۔ وہاں پر دفعہ ۱۴۴ لاگو کیا گیا ۔ دفعہ ۱۴۴ تو جناب کشمیر کے آئنے کا ۔ کتاب کا ایک سٹیچوٹ بن گیا ہے ۔

[شری بخشی غلام محمد]

بہر حال یہ ایک نقشہ تھا جو میں نے آپ کے سامنے رکھا - مجھے امید ہے کہ میں نے کچھ ماڈریٹ اور پریکٹکل سجیشنس دئے ہیں اور ان کو ایکسپٹ کرنے میں آپ کو کوئی ڈیفکلٹی نہیں ہونی چاہئے یا پھر کہئے کہ وہ آپ کی اس فارسی کے شاعر جیسی حالت ہے جس نے یہ لکھا ہے۔

''عمرے وائید کہ یار آید بکاد،،

تم بھی رہو ہزار سال اور یہ سلسلہ بھی چلتا رہے ہزار سال - آپ نے یہ نہیں کرنا ہے اور نہ یہ ہمیں حاصل ہوگا - اس لئے میں آخر میں بھی یہی عرض کرکے ختم کرونگا کہ کشمیر ہندوستان کے ساتھ ہے کشمیر کے مسلمان - کشمیر کے ہندو - جموں کے ہندو و سکھ اور لداخ کے بودھ سب ہندوستان کے ساتھ ہیں - وہ ان تمام چیزوں کے باوجود ہندوستانی ہیں - ہندوستانی رہے ہیں اور آگے بھی وہ ہندوستانی رہنے والے ہیں اور وہ اس سے دور نہیں جائینگے -]

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफ़ी कुरैशी) : जनाब डिप्टी स्पीकर, मैं शुक्रगुजार हूं कि मुझे मौका दिया गया कि मैं इस कश्मीर के बारे में कुछ कहूं। बख्शी साहब से मुझे कुछ इख्तलाफ हो सकता है लेकिन कई बातों पर वाकई में उन से सहमत हूं जो उन्होंने यह कहा कि कश्मीरियों पर यह इलजाम लगाना कि वह पाकिस्तानी हैं या पाकिस्तान के एजेंट हैं यह बिल्कुल गलत बात है। वह एक ऐसा इलजाम है जो शायद तौहीन की हद तक पहुंच जाता है।

कश्मीर के हालात को समझने के लिए कश्मीर के इतिहास पर थोड़ी सी नजर डालिये और उससे आपको मालूम होगा कि जो बातें आप कह रहे हैं और जो बातें चन्द एक दोस्तों ने कहीं उनकी कोई बुनियाद नहीं है। यह सब जानते हैं कि कश्मीर में जब तहरीके आजादी शुरू हुई तो उसके सिपाही जो थे उनमें शेख अब्दुल्ला थे, खुद बख्शी गुलाम मुहम्मद थे और गुलाम मुहम्मद सादिक थे। इन लोगों ने वहां पर मुस्लिम कान्फ्रेंस शुरू की। उस वक्त कश्मीर में हमारे यहां के मौजूदा मिनिस्टर कर्ण सिंह के वालिद मरहूम महाराजा हरी सिंह वहां के महाराजा थे .... (**व्यवधान**) मेरी बात सुनिये। उस वक्त 1938 में मुस्लिम कान्फ्रेंस को नेशनल कान्फ्रेंस में बदलने का फैसला किया गया ..... (**व्यवधान**) सुनिये साहब। कोई सियासी दबाव नहीं था जिसकी कि वजह से वह हुआ बल्कि वह इसलिए हुआ कि कश्मीर के लोग जो थे वह बुनियादी तौर पर एक ऐसी आइडियोलिजी के साथ मुत्तफिक थे जिस में कि वह सैकुलरज्म और डेमोक्रेसी को अपनाना चाहते थे। अगर कोई आदमी यह कहे कि मैंने उस वक्त कश्मीर में कोई अलहदा रोल प्ले किया है तो मैं उस को मानता तो जरूर हूं लेकिन बुनियादी बात यह है कि कश्मीरियों की रगों और नसों में यह फिरकापरस्ती का जहर नहीं भरा था और आज भी अगर आप देखेंगे तो पायेंगे कि कश्मीरी मुसलमानों के नाम के साथ हिन्दू का आखिर में थोड़ा नाम जुड़ा होता है और उसी तरह से कश्मीरी हिन्दुओं के नाम के आखिर में थोड़ा मुसलमान का नाम जुड़ा रहता है। जैसे कि मैं आप को बतलाऊं एक वहां जगन्नाथ पीर चीफ इंजीनियर होते थे बख्शी साहब के जमाने में। ऐसे ही काजी प्रेम नाथ नाम है।

7.24 hrs.

[SHRI S. M. JOSHI *in the Chair*]

ऐसे ही मुसलमानों के वहां पर नाम हैं जैसे अब्दुल अजीज नेहरू, गुलाम हबीबुल्ला पंत..... (**व्यवधान**)

SHRI PILOO MODY : Is he naming poets ?

SHRI BAL RAJ MADHOK : What is he aiming at ?

श्री मुहम्मद शफ़ी कुरैशी : आप नाराज मत होइये । मेरा यह सब बतलाने से मतलब यह था कि शुरू से ही कश्मीर के जो रहने वाले लोग थे उन में एकता थी । हर एक नेता जो भी वहां पर आया उसने अपना रोल अदा किया जिसमें शेख अब्दुल्ला का रोल भी है, बख्शी साहब जो यहां पर बैठे हैं उन का भी रोल रहा है । अभी यह कहा जाता है कि कश्मीर में शायद कोई ऐसी समस्या पैदा हो गई है कि वहां नौनमुस्लिम का रहना व जीना बिलकुल दुश्वार है और वहां पर मुसलमान खूनी व खूंख्वार दरिन्दों की तरह नौनमुस्लिम को मारना चाहते हैं जितनी जल्दी इस खयाल को दिलों से हटाया जाय, जितनी जल्दी इस नक्शे को मिटाया जाय वह बेहतर होगा··· (**व्यवधान**) मेहरबानी कर के खामोशी के साथ मेरी बात को सुनते चलिये । मेरा मतलब यह कहने का था कि कश्मीर की जो फ़िज़ा बनी हुई है फिरकेवाराना यगानगत की उस पर किसी को शक नहीं करना चाहिये । अब यह तो हो सकता है कि वहां पर डेवलपमेंट प्लांस अमल में न आये हों, वहां पर कभी कभी कोई खामी आई हो तो उस के लिए हम यह मांग करें कि यह प्रेसीडेंट रूल वहां पर होना चाहिए में समझता हूं कि यह जायज़ बात नहीं है । बख्शी साहब को हजारों शिकायतें हो सकती हैं एलेक्शन के मुताबिक और अभी उन्होंने एक काफी लम्बी चौड़ी तकरीर वहां के एलैक्शंस के मुतालिक की लेकिन मैं समझता हूं कि जब एलैक्शंस पेटीशंस इस वक्त अदालत में हों तो उन पर कोई रायज़नी करना अच्छा नहीं होगा । ····

श्री गुलाम मुहम्मद बख्शी : मैंने कोई राय नहीं दी । मैंने तो एक वाकया बयान किया । वह किसी अदालत में नहीं है । मुझे मालूम नहीं है कि वह कहां है ?

श्री मुहम्मद शफ़ी कुरेशी : बख्शी साहब को अच्छी तरह से मालूम है कि वह कहां पर है । जहां तक कश्मीर की मौजूदा हुकूमत का ताल्लुक है अगर उस हुकूमत के साथ जनता नहीं है, अवाम का साथ उसे हासिल नहीं है तो इसका फैसला ऐवान में किया जा सकता है, असेम्बली में किया जा सकता है । सड़कों पर यह इश्यू नहीं ले जाया जाना चाहिए । असेम्बली यह कहने का अधिकार रखती है है कि वह यह कहे पार्लियामेंट को और सरकार को कि वहां पर मौजूदा हुकूमत को अक्सरियत हासिल नहीं है····

SHRI BAL RAJ MADHOK : The charge is that the Assembly is not representative. It is hen-pecked; it is nominated. (*Interruption*) How can you prove it unless you hold the elections, unless the petitions are settled?

श्री मुहम्मद शफ़ी कुरेशी : अब में एक बात कहना चाहता हूं । अभी जनसंघ के कुछ सदस्यों ने काफी शिकायतें कीं कि कश्मीर में यह हो रहा है और कश्मीर में वह ज्यादती हो रही है तो मैं उन की इत्तिला के लिए आर्गेनाइजर अखबार का सन् 63 का एक आर्टिकल पढ़ता हूं । मेरे दोस्त मेहरबानी करके सुनें : बख्शी साहब ने कहा कि सन् 1953 से लेकर 63 तक एक बार भी 144 दफा वहां पर नहीं लगी तो आर्गेनाइजर इस बारे में क्या लिखता है वह जरा सुनें:

"The occasion was the mammoth public meeting organised by Shri Shafi Qureshi, a leading advocate of Kashmir Bar..... (*Interruptions*) on the minds of thousands of people gathered was Pandit Nehru's decision, in accordance with the Kamraj Plan, that Bakshi Gulam Mohammed should quit his office. Shri Shafi Qureshi's outspoken broad sides have evidently been giving sleep-

[श्री मुहम्मद शफ़ी कुरेशी]

less nights to Bakshi Gulam Mohammad and Co.... (*Interruptions*) Please listen.

SHRI KANWAR LAL GUPTA : That is why you are the Deputy Minister here.

श्री मुहम्मद शफ़ी कुरेशी : मेहरबानी कर के सुनिये :

"Within days of the above described meeting, Shri Shafi Qureshi has been served with a gag order, he has been prohibited for an indefinite period from making any public statement or addressing a public meeting in the State."

I went to the High Court against this order.

This is from the *Hindustan Times* ...

SHRI J. B. KRIPALANI (Guna) : Shall we listen to these personal disputes ?

सभापति महोदय : माननीय सदस्य खामोश रह कर सुनें । उन का वक्त खत्म होने पर मैं कुरेशी साहब को रोक दूंगा ।

श्री य० द० शर्मा : विषय काश्मीर का है, विषय कुरेशी साहब का नहीं है ।

श्री गुलाम मुहम्मद बख्शी : मैं उन से कहता हूं कि वह जहमत गवारा न करें, वह जो कुछ कह रहे हैं वह सही कह रहें हैं । लेकिन आज जो कुछ हो रहा है उसका इलाज क्या है ?

श्री मुहम्मद शफ़ी कुरेशी : आज जो लोग मांग करते हैं कि वहां पर संसद का राज्य होना चाहिये, जैसा कि एक दोस्त ने कहा वह हिन्दुस्तान या कश्मीर के हाथ मजबूत नहीं करते, वह यकीनन दुश्मनों के हाथ को मजबूत करते हैं ।

श्री कंवरलाल गुप्त : माननीय मंत्री जी कैसे करना चाहते हैं, वह बतलायें न ।

श्री मुहम्मद शफ़ी कुरेशी : मैं बतलाऊंगा, अगर आप को सब्र हो । यह जो नफरत फैलाने का तरीका है, हिन्दू और मुसलमान के नाम पर झगड़ा कराने का जो तरीका है उससे आप हिन्दुस्तान की खिदमत नहीं करते, हिन्दुस्तान के वकार को ठेस पहुंचाते हैं ।

काश्मीर में एक वाक्या हुआ, जिसका माननीय सदस्य ने जिक्र किया । एक परमेश्वरी देवी ने शादी कर ली मुसलमान लड़के के साथ । लेकिन हकीकत यह है कि वहां पर मुसलमान लड़कियों ने भी हिन्दू लड़कों के साथ शादियां की हैं । मगर कभी कोई शोर नहीं मचा ।

श्री गुलाम मुहम्मद बख्शी : जहां तक परमेश्वरी देवी का ताल्लुक है, मामला आपने उठाया और यह भी कहा कि मामला सब-जुडिस है इस लिये मैं उसके मेरिट्स में नहीं जाना चाहता ....

श्री मुहम्मद शफ़ी कुरेशी : मैं केस की मेरिट्स में नहीं जा रहा हूं । मैं यह कह रहा हूं कि इस किस्म की चीजें वहां होती रही हैं और यहां भी होती हैं । एक ही कम्यूनिटी में ऐब्डक्शन के केस हो जाते हैं ...

श्री रामावतार शर्मा : (ग्वालियर) : सभापति महोदय, यहां पर जो चर्चा इस समय हम लोग कर रहे हैं वह इस लिये कि श्री प्रकाशवीर शास्त्री की चर्चा का उत्तर आये । लेकिन अब हम यह देख रहे हैं कि वहां पर बख्शी साहब और कुरेशी साहब का मुकाबला किया जा रहा है ।

सभापति महोदय : माननीय सदस्य बैठ जायें, यह प्वाइंट आफ आर्डर नहीं है ।

श्री रामावतार शर्मा : इन दोनों का आपस में मुकाबला किया जा रहा है, यह अपनी कह रहे हैं और वह अपनी कह रहे हैं । इससे क्या फायदा ?

श्री मुहम्मद शफी कुरेशी : मैं अर्ज कर रहा था कि जहां तक इस बात का ताल्लुक है, इसमें एक मजहबी रंगत दी गई । यह बिलकुल

गलत तरीका है । फिर इस के साथ-साथ वहां पर ओवरनाइट एक ऐक्शन कमेटी आर्गेनाइज की जाती है । इस ऐक्शन कमेटी के पीछे कौन है, यह सब जानते हैं । वही लोग जो सब से पहले हमला करना चाहते हैं, हल्ला करना चाहते हैं, उन मर्कजों पर जहां अभी तक कम्यूनिलिज्म फला फूला नहीं है । उन का मकसद यह है कि तमाम उन हिस्सों में जहां शांति और अमन है, जहां के लोग भाई-चारा कायम रखते हैं, वहां मजहब के नाम पर फूट डाली जाये और मजहब के नाम पर इन्सानों को तकसीम किया जाये, और इस के लिये काश्मीर को अड्डा बनाया जाये ।

17.30 HRS.

[MR. DEPUTY-SPEAKER *in the Chair*]

लेकिन कश्मीरियों को एक बार फिर मौका मिला । एक दफा उन्होंने 1947 में अपना मेट्ल जाहिर किया और उसके बाद जब पाकिस्तान ने ऐग्रेशन किया तब उन्होंने अपना मेट्ल जाहिर किया । इस वक्त जो लोग उन पर शक करते हैं वह वही लोग हैं जो जम्मू छोड़ कर पठानकोट चले गये थे । यह ऐसे गैय्यूर और गैरतमन्द लोग हैं । मैं कहना चाहता हूं कि यह एक सीरियस मैटर है । आज हम को श्री बलराज मधोक का सर्टिफिकेट नान-कम्यूनलिज्म के नहीं चाहिये । हम जो कुछ भी हों, हिन्दुस्तान के हैं, हिन्दुस्तानी हैं, हिन्दुस्तान के रहेंगे और हिन्दुस्तान में मरेंगे अगर कोई यह समझता है, कोई जमात यह समझती है····

श्री बलराज मधोक : सर्टिफिकेट हमारा नहीं, अपने दिल का लो । (**व्यवधान**)

श्री कंवरलाल गुप्त : मैं और कुछ जिक्र नहीं करना चाहता, लेकिन यह बतलाइये कि वहां पाकिस्तान जिन्दाबाद के नारे लगाये जाते हैं या नहीं ? अगर लगाये जाते हैं तो आप उसको कैसे रोकेंगे ? यहां पर आयूब साहब जिन्दाबाद के नारे लगाये जाते हैं । आप को इस पर शर्म नहीं आती और आप इसको डिफैन्ड करते हैं । आप के आदमी इस तरह के नारे लगाते हैं । आप बेकार की बातें करते हैं । आप को पता नहीं है । हिन्दुस्तान के इलाके में क्या पाकिस्तान के नारे लगेंगे ? नहीं लगेंगे । अयूब जिन्दाबाद के नारे नहीं लगेंगे ।

MR. DEPUTY-SPEAKER : This is not fair. The House listened to all the speeches so far with rapt attention and it was good. We are discussing the situation in a particular area which is very vital. If the hon. Member goes on interrupting Mr. Qureshi, it would be very difficult. Whatever he wants to say, he can say. The Home Minister will reply at the end and the hon. Member can put questions at that time. So far as this argument is concerned, he may please not interrupt Mr. Qureshi. He has to conclude.

श्री कंवरलाल गुप्त : मेरे सवालों का जवाब दिया जाये (**व्यवधान**)

श्री मुहम्मद शफ़ी कुरेशी : मैं कहता हूं कि अगर किसी भी मुल्क के हिस्से में कोई आदमी वतन से या कौम से गद्दारी करता है, ख्वाह वह किसी भी मजहब से ताल्लुक रखता हो, वह गद्दार है । किसी एक मजहब में नहीं, गद्दार हर मजहब में पैदा होते हैं, हर सूबे में पैदा होते हैं, हर कौम में पैदा होते हैं । किसी भी खास कौम के बारे में यह कहना उस कौम के साथ दुश्मनी करना है, अदावत करना है ।

मैंने साबित कर दिया है, और मुझे याद है, बख्शी साहब को भी भूलना नहीं चाहिये कि जिन लोगों ने देश के लिये अपनी जानें दी हैं, जिन लोगों ने अपना सब कुछ लुटा दिया है, उन पर भी इल्जाम लगाये जाते हैं कि वह पाकिस्तान के एजेंट हैं । इस किस्म की बात का विरोध किया जाना चाहिये । मैं साबित कर के दिखाऊंगा कि जो पहले बख्शी साहब और शेख साहब की तारीफें करते थे, वही आज कहते हैं कि यह लोग पाकिस्तानी एजेंट हैं । मैं कहना चाहता हूं कि इससे बड़ा जुल्म और जुर्म नहीं हो सकता । हम हजार इख्तलाफ रखते हों·····

श्री गुलाम मोहम्मद बख्शी : यहां पर कम्पलिकेशन पैदा हो रहा है काश्मीर के सिलसिले में। मेरे खयाल में न इस तरफ के मेम्बरों को काश्मीरी मुसलमानों से कोई शिकायत है न उस तरफ के मेम्बरों को। किसी ने ऐसी बात नहीं कही। जो काश्मीरी हिन्दू हैं वह रिनेगेड हो सकते हैं, काश्मीरी मुसलमान गद्दार हो सकते हैं, लेकिन यह शिकायत किसी ने नहीं की है।

श्री मुहम्मद शफी कुरेशी : बख्शी साहब ने श्री प्रकाशवीर शास्त्री की तकरीर नहीं सुनी।

श्री कंवरलाल गुप्त : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्वाइंट आफ आर्डर उठाना चाहता हूं।

MR. DEPUTY-SPEAKER : On what point of order?

श्री कंवरलाल गुप्त : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा कहना यह है कि माननीय मंत्री महोदय जो कुछ कह रहे हैं वह एक गलत इम्प्रेशन पैदा कर रहे हैं। किसी ने नहीं कहा है काश्मीरी मुसलमानों को कि वह गद्दार हैं। यहां पर किसी के कहने का मंशा नहीं है कि काश्मीरी मुसलमान गद्दार हैं। इस तरह के कहने का मतलब होगा कि यह गलत इम्प्रेशन पैदा हो जाएगा और सारे संसार में यह बात जायेगी। किसी ने भी नहीं कहा है कि मुसलमान गद्दार हैं।

MR. DEPUTY-SPEAKER : That was cleared by Mr. Bakshi just now. There is no point of order and if that impression is created, he has already disabused the mind of the House. Please continue.

श्री मुहम्मद शफी कुरेशी : मैंने यह बात इसलिये कही कि मेरे मोअज्जिज दोस्त श्री प्रकाशवीर शास्त्री ने कहा कि वहां हिन्दू महिलाओं का सिन्दूर लूटा जा रहा है, वहां उनकी अस्मत लूटी जा रही है लेकिन मैं हाउस से कहना चाहता हूं कि.....

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : उपाध्यक्ष महोदय, फिर यहां गलतबयानी पर मुझे खड़ा होना पड़ रहा है। यहां पर आप के आदमी हैं, जो एक एक शब्द नोट करते हैं, टेप रिकार्ड हैं, जिस पर एक एक शब्द अंकित होता है। मैंने कहा था कि अगर आप ने काश्मीर को इतने अरबों रुपये व्यय करने के बाद और हजारों बलिदान देने के बाद फिर अपने हाथों से छोड़ दिया तो इन हजारों बलिदानों और जिन महिलाओं के सुहाग के सिन्दूर लुटे हैं, उनकी कुर्बानी पर आप धूल डालेंगे। मैंने यह कहा है। यह इसको कहां ले जा रहे हैं। आप उन से कहें कि वह हिन्दी सीखें।

श्री मुहम्मद शफी कुरेशी : मैं अर्ज कर रहा था कि आज यह आदत हो गई है....

SHRI BAL RAJ MADHOK : We are not here to listen to a personal dialogue. Let him reply to the charges.

श्री मुहम्मद शफी कुरेशी : आप खामोश रहें तब तो मैं कुछ कहूं।

SHRI A. K. SEN (Calcutta, North West) : On a point of order, I must support Bakshi Saheb and others. Nobody, whether on the Opposition side or on our side has cast any aspersion on the Kashmir Muslims. They are our brothers; they are part and parcel of this country and it will be a wrong thing to answer a charge like that. It will create confusion in the public mind.

MR. DEPUTY-SPEAKER : In order to avoid further controversy I would like to point out to the hon. Member one thing. I have listened to all the speeches very carefully. The main problem is about the Kashmir administration. Communal aspect of it has nobody highlighted, so far as I understand. As fas as possible avoid that also.

SHRI SURENDRANATH DWIVEDY (Kendrapara) : Is he intervening in the debate as a Member of the Government.

MR. DEPUTY-SPEAKER : He is a Member of the House.

श्री मुहम्मद शफी कुरेशी : जहां तक और बातों का ताल्लुक है कि वहां एडमिनिस्ट्रेशन

नहीं चल रहा है, फंड्ज जो गए हैं उनका दूसरी जगह इस्तेमाल हुआ है, मैं कहना चाहता हूं कि इन बातों को सुन कर मुझे हैरानी हुई है। मुअज्जिज मैम्बर बख्शी शाहब 1963 तक वहां चीफ मिनस्टर थे। उनके वक्त भी कुछ गलतियां हुई होंगी। लेकिन एक बात का मुझे दुख जरूर है। प्रकाशवीर शास्त्री जी ने कहा है कि जो गल्ला काश्मीर में जाता है वह वहां से स्मगल हो कर पाकिस्तान को चला जाता है। उपाध्यक्ष महोदय, आपको याद होगा कि इस वक्त हमारी सरहदों पर हमारी सेनायें बैठी हुई हैं और वही हमारी सरहदों की हिफाजत करती हैं। अगर इस तरह की बात हम कहें कि गल्ला स्मगल होकर पाकिस्तान चला जाता है.... (इंटरप्शन)

SHRI BAL RAJ MADHOK : How is it an aspersion on the Army?

श्री मुहम्मद शफी कुरेशी : अगर उसके होते हुये गल्ला पाकिस्तान चला जाता है....

MR. DEPUTY-SPEAKER : I have followed his arguments very carefully and also the other arguments. Let him not bring in the Army and other such matters.

श्री मुहम्मद शफी कुरेशी : मैं हकीकत बता रहा हूं। अगर यह इलजाम है कि गल्ला वहां से पाकिस्तान को भेजा जा सकता है, जैसा इल्जाम उन्होंने लगाया है तो मैं इस में कौन सी गलत बात कहता हूं कि जब मैं यह कहता हूं कि साहब ऐसी बात नहीं होती है क्योंकि एक एक इंच सरहद की हिफाजत हमारी फौज करती है और हमें इस बात का फख्र है एक मक्खी भी इस तरफ से उधर नहीं जा सकती है और जो हिन्दुस्तान का माल है वह उधर नहीं जा सकता है। इस वास्ते यह जो इलजाम है यह बेबुनियाद है।

SHRI J. B. KRIPALANI : Our Army was there when thousands of infiltrators went into Kashmir. What is the hon. Minister talking about? He is talking through his hat.

MR. DEPUTY-SPEAKER : I have already ruled and pointed out to the hon. Member not to refer to those aspects.

श्री य० द० शर्मा : सरहदों से मक्खियां नहीं आया करतीं, दुश्मन आया करते हैं।

श्री मुहम्मद शफी कुरेशी : एक बात का मुझे निहायत दुख है। हमारे बुजुर्ग मैम्बर बैठे हुये हैं जो शायद मेरी बातको सुनना पसन्द नहीं करते हैं। मैं उनसे नहीं कहता हूं कि वह मुझ से इत्तिफाक करें। उन्हें मुझ से इख्तलाफ राय रखने का पूरा हक है। लेकिन मुझे भी एक मैम्बर की हैसियत से अपनी बात कहने का हक हासिल है। मैं तवक्के करता हूं कि वे मेरी बात को सुनेंगे। मेरी बात कड़वी हो सकती है लेकिन झूठी नहीं हो सकती है।

सादिक साहब ने लिबरलाइजेशन की जो पालिसी वहां शुरू की है उसके मुताल्लिक मैं यह कहना चाहता हूं कि काश्मीर को आप डंडे के जोर से, कोई लालच दे कर या उस पर दबाव डाल कर अपने साथ नहीं रख सकते हैं। काश्मीरियों के दिल ने इस बात को चाहा था कि वे हिन्दुस्तान में आयें। हमें उसी रवायत को बरकरार रखना है। अगर आप समझते हैं कि डंडे के जोर से वहां पर अमन कायम रह सकता है, तो अमन कायम रह तो सकता है लेकिन वह अमन कब्रिस्तान का अमन ही हो सकता है, असली मानों में अमन नहीं हो सकता है। अगर आप चाहते हैं कि काश्मीर के लोग सही मानों में और सही तरीके से महसूस करें कि वे लोग हमारा जुज्व हैं तो फिर हमें चाहिये कि हम उनके लिए कारोबार के दरवाजे, नौकरियों के दरवाजे, आने जाने के दरवाजे खुले कर दें, उनमें एतमाद पैदा करें कि जो फैसला उन्होंने 1947 में किया था वह फैसला सही फैसला था। उनमें यकीन पदा होना चाहिये.....

SHRI KANWAR LAL GUPTA : He is voicing his grievances against the Central Government. This will create a wrong impression in the world.

MR. DEPUTY-SPEAKER : He is concluding. Let him not be interrupted.

श्री मुहम्मद शफी कुरेशी : मैं बिल्कुल गलत इम्प्रेशन नहीं दे रहा हूं ।

SHRI BAL RAJ MADHOK : I would like to make this very clear. Kashmir is part of India, not because of him or anybody else. Kashmir is part of India because of accession; Kashmir is part of India because our Army had gone and cleared most of the areas occupied by the Pakistanis; Kashmir is part of India because it has been so historically and geographically for thousands of years; Kashmir is part of India not because of him or anybody else. So, this kind of impression which the hon. Member is trying to create should not be allowed to go out.

AN HON. MEMBER It is part of India because of the people of Kashmir also.

SHRI SHAFI QURESHI : It is part of India because of the people of Kashmir also. I must say that also.

SHRI BAL RAJ MADHOK : Not at all. Kashmir is part of India. If anybody does not want to live in Kashmir, he can go to Pakistan or anywhere else. Kashmir is part of India. Let it be clear to him.

MR. DEPUTY-SPEAKER : It is a wrong impression that he is creating that Kashmir is part of India because of accession. It is part of India because the people of Kashmir opted for India. That is the main thing. So, let him not over-emphasise the other things.

SHRI SURENDRANATH DWIVEDY : I do not think that the Chair should enter into arguments with Members.

SHRI GULAM MOHAMMAD BAKSHI : The Kashmiris fought the Pakistani Army and infiltrators in 1947 without the help of the Indian Army. The Army came in at the last stage when they had reached up to Srinagar It was the National Conference that fought them and the people of Kashmir that fought them. The people of Kashmir constitute Kashmir; Kashmir with its people is part of India; Kashmir without its people means mountains and snow only.

श्री मुहम्मद शफी कुरेशी : मैं एक बात कम्युनल एलीमेंट्स के बारे में कहना चाहता हूं । बलराज मधोक जी ने जो अभी लफ्ज का इस्तेमाल किया है यही वह लफ्ज था जिसने काश्मीर में आग लगाई । उन्होंने कहा कि जो काश्मीर के लोग हैं वे पाकिस्तान चले·····

SHRI BAL RAJ MADHOK : I have said that anyone who says that Kashmir is not India, can go away from India. Nobody can stop him. Shri Nehru has said this, Shri Chavan has said this, everybody has said this. I have said nothing new. Nobody who is in India and who does not want to live in India can be forced to live in India.

श्री भोगेन्द्र झा (जयनगर) : मैं एक व्यवस्था का सवाल उठाना चाहता हूं । गलत या सही माननीय सदस्य अपनी राय दे रहे हैं । ज्यादा तर गलत ही कह रहे हैं, ऐसा मैं समझता हूं । उन्होंने कहा है कि काश्मीर को बलराज मधोक के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है । बलराज मधोक जी ने कहा था कि मेरे सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है तो अपने दिल पर हाथ रख कर पूछें । मैं चाहता हूं कि यह हटा दिया जाए । इस पर मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं ।

MR. DEPUTY-SPEAKER : I have followed his argument. I have made some observations after that. There is no point of order.

श्री मुहम्मद शफी कुरेशी : बख्शी साहब की नाराजगी को मैं समझता हूं । जनसंघ की नाराजगी को भी मैं समझता हूं । यह वह जमायत है जिसने जम्मू में बड़ी बुरी तरह मार खाई है । जम्मू के मुताल्लिक किसी ने भी नहीं कहा है कि वहां इलैक्शन रिट्स थे । जनसंघ के पंडित डोगरा या बलराज मधोक जी या शास्त्री जी ने जो कुछ कहा है वह वैसो

के बारे में ही कहा है। जम्मू जनसंघ ब्रांच के जो सेक्रेटरी थे श्री ऋषि कुमार कौशल वह वहां पर हार गए .....

श्री कंवरलाल गुप्त : कांग्रेस के जो प्रेजीडेंट हैं वह भी तो हार गए हैं।

श्री मुहम्मद शफी कुरेशी : दुख इस बात का है कि यह जमायत जो कि इतने किलेबन्दी कर रही थी और ख्वाब देख रही थी कि इसके आठ या नौ मेम्बर जीत जायेंगे, इसकी पहले जितनी स्ट्रेंग्थ थी, उतनी स्ट्रेंग्थ में भी यह नहीं आ सकी। बख्शी साहब की नाराजगी का मुझे एहसास है और हाउस को भी मैं समझता हूं होगा। वह बहुत बिटर हैं हम से इस बात पर कि वह समझते हैं कि वहां पर इलैकशंज रिट्स हुए। कैसे इलैकशन हुआ मैं इस बात में अब जाना नहीं चाहता हूं। लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि जो यह कहा गया है कि फलां जगह पर सड़क नहीं बनी, पुल नहीं बना इस वास्ते वहां पर प्रेजीडेंट का राज नाफज किया जाए मैं समझता हूं कि बिल्कुल अनोखी दलील है। अगर इस बिना पर कि किसी जगह पर तरकियाती काम नहीं हुआ है, स्कूल नहीं खुला है वहां पर प्रेजीडेंट का राज्य कायम कर दें तो हमें हर सूबे में प्रेजीडेंट का राज कायम करना पड़ेगा। मैं चाहता हूं कि अपनी आंखों से हमारे इन दोस्तों को रंगीन चश्मा उतार देना चाहिए। इनको चाहिये कि काश्मीर को यह समझें, काश्मीर के लोगों के दिलों की धड़कनों को समझें। अगर उन्होंने ऐसा किया होता तो उन्होंने इस बहस को यहां न उठाया होता।

आखिर में मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि अगर हिन्दुस्तान के वकार के लिए, हिन्दुस्तान की इज्जत के लिए हमें अपने खून का आखिरी कतरा भी बहाना पड़े तो उसके लिए हम तैयार हैं।

श्री एस० एम० जोशी (पूना) : सदन के सामने जो सवाल है इसमें कोई शुबहा नहीं है कि यह एक महत्व का है और इसका हल हम लोगों को निकालना ही पड़ेगा। यहां बताया गया है कि बंगाल में यह हुआ, राजस्थान में वह हुआ। दूसरी जगह और कुछ हुआ होगा। लेकिन काश्मीर की जो हालत है उसकी में हमारे दूसरे जो राज्य हैं उनसे मुकाबला नहीं करना चाहता। हमारे देश की हालत तो खराब है ही और अगर काश्मीर की हालत और ज्यादा खराब हो जाती है तो हमारे देश की आजादी के लिये वह खतरा बन सकती है। इसलिए इस चीज को हम लोगों को गम्भीरता से सोचना चाहिये। संस्कृत में कहा जाता है—

गंडस्य ऊपरी पीटिका संवृत्ता

एक बायल पहले से था और उसके ऊपर एक और हुआ। देश की हालत वैसे ही खराब है। इस बात को हम रोज-रोज कहते रहते हैं। लेकिन काश्मीर की जो बात है उसको हमें ज्यादा गम्भीरता से लेना होगा और उस पर सोच विचार करना होगा।

मैं यह समझता हूं कि इस बारे में कोई एक्स्ट्रीम स्टैप लेने से हम इस समस्या को हल नहीं कर सकते हैं।

यहां कहा गया कि हमलोग सेकुलर है। मैं मानता हूं। मैं भी सेकुलर हूं। लेकिन इस बात का दावा हमें नहीं करना चाहिए कि हम लोग अपने जीवन में, अपने आचरण में, सेकुलरिज्म को अच्छी तरह से ला रहे हैं। यह नहीं होता है। यहां पर कुछ भी कहा जाये, लेकिन जो कोई भी सवाल खड़ा होता है, कोई कहता है कि वह साम्प्रदायिकता का सवाल है, कोई कहता है कि वह प्रान्तीयता का सवाल है, और कोई कहता है कि वह जातीयता का सवाल है, लेकिन आखिर में वह पोलोटिकल सवाल हो जाता है।

काश्मीर का जो सवाल हमारे सामने है, वह एक पेचीदा सवाल है। यहां सब लोगों ने कहा कि काश्मीर के मुसलमान और हिन्दु भारत में रहना चाहते हैं। मुझे भी इस में कोई शुबहा नहीं है। मगर अगर वे भारत

[श्री एस० एम० जोशी]

में रहना चाहते हैं, तो हम लोगों को वहां ऐसा माहोल नहीं पैदा करना चाहिए, जिस के कारण हमारे विरोधियों और शत्रुओं को हमारे विरुद्ध लाभ उठाने का मौका मिले। मैं जानता हूं कि हुकूमत की तरफ़ से बहुत कुछ ग़लत काम हो रहे हैं। जैसा कि श्री बख्शी ने बताया है, रुपया पैसा और अनाज बहुत ज्यादा दिया जा रहा है, लेकिन वहां पर कोई ठोक तरह से प्रबन्ध नहीं होता है। ऐसा क्यों हो रहा है?

मैं समझता हूं कि अगर हम ने काश्मीर के मामले को हल करना है, तो हम को उस का पोलीटिकल सालूशन निकालना होगा। यह तो बिल्कुल मानी हुई बात है कि आज वहां की जो हुकूमत है, उस के पीछे वहां की जनता नहीं है। अगर आज कोई कहे कि ऐसा नहीं है, तो मैं इस को मानने के लिए तैयार नहीं हूं। अगर हम अपने यहां, अपने देश में, जम्हूरियत और लोकतंत्र चाहते हैं, तो हमें पहला कदम यह उठाना चाहिए कि वहां की जनता जिस हुकूमत पर विश्वास करे, ऐसी हुकूमत वहां पर बनाई जाये। अगर हम यह काम नहीं करेंगे और कानून की बाल की खाल निकाल कर कहते रहेंगे कि वहां पर इलेक्शन हुआ है, वहां की हुकूमत के बारे में फ़ैसला वहां की एसेम्बली को करना होगा, तो इस तरह यह समस्या हल होने वाली नहीं है। बंगाल के बारे में यह बात कही गई, वह ठीक है। राजस्थान के बारे में भी यह बात कही गई और हम ने सुन ली। लेकिन अगर काश्मीर के बारे में भी सरकार यही बात कहेगी, तो मैं समझता हूं कि मामला और भी पेचीदा होता चला जायेगा।

मैं यह मानता हूं कि यह सवाल सिर्फ़ अपने तक ही महदूद नहीं है। स्वर्गीय शास्त्री जी ताशकंद में गए और एक श्रद्धा के साथ उन्होंने यह एग्रीमेंट किया कि हम दोनों पाकिस्तान और भारत, एक ऐसा माहौल पैदा करेंगे, जिस से हम भाई-भाई बन कर रहेंगे। उन्होंने श्रद्धा से यह एग्रीमेंट किया। मैं भी वही श्रद्धा वाला आदमी हूं। लेकिन सिर्फ़ कहने से नहीं होगा। उस के लिए हमें माहौल बनाना होगा। शास्त्री जी के चले जाने के बाद हमारे देश में जो माहौल, वातावरण, बन रहा है, वह ताशकंद की स्पिरिट को आगे नहीं बढ़ा रहा है। काश्मीर में जो कुछ हो रहा है, उस से ताशकंद की स्पिरिट आगे नहीं बढ़ेगी। वहां पर राष्ट्रपति की हुकूमत लागू करने से यह मामला तय होने वाला नहीं है। हमें इस समस्या का एक पोलीटिकल सालूशन निकालना होगा, वहां की जनता को अपने साथ लेना होगा।

श्री बख्शी ने इस बारे में कुछ सुझाव दिये हैं। वहां के मुख्य मंत्री, श्री बख्शी और अगर जरूरत हो, तो शेख अब्दुल्ला भी, मंत्री महोदय को इन सब लीगों के साथ बैठ कर कोई सालूशन निकालना होगा। अगर वह कोई सालूशन निकाल सकते हैं, तो मैं समझता हूं कि वह ताशकंद की स्पिरिट को आगे बढ़ा सकते हैं।

मेरा विश्वास है कि हमारे देश का जो बंटवारा हुआ है, वह बिल्कुल अनैसर्गिक है, आर्टिफ़िशल है। वह बहुत देर तक चलने वाला नहीं है। अगर हम लोगों को वह बंटवारा ख़त्म करना है, तो वह हम गोली से नहीं कर सकते हैं। इसलिए आगे का जो हमारा मकसद है, उस को पूरा करने के लिए हम को एक नीति अख्त्यार करनी चाहिए। श्री बख्शी का जो सुझाव है, उस का मैं समर्थन करता हूं। मैं गृह मंत्री से यह प्रार्थना करूंगा कि वह ऐसी तजवीज निकालें, जिस से वहां की हुकूमत को जनता का ज्यादा बहुमत मिले। अगर वह ऐसा कर सकते हैं, तो यह मामला तय हो सकता है।

श्री योगेन्द्र शर्मा (बेगुसराय) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, काश्मीर की जो समस्या है, वह काफ़ी पुरानी, काफ़ी महत्वपूर्ण और एक राष्ट्रीय समस्या है। हमें अफ़सोस है कि जब हम इस राष्ट्रीय समस्या पर विचार करने लगते हैं, तो दलगत, व्यक्तिगत और साम्प्रदायिक भावनायें उभर आती हैं। यदि ऐसा न होता, तो अभी इस सदन में श्री बख्शी

और श्री कुरैशी का जो बाग्युद्ध हम ने देखा, शायद वह न देखना पड़ता और न ही हमारे जनसंघ के भाई कम्युनिष्ट नेताओं के वहां जाने पर आपत्ति प्रकट करते। इस लिए इस सदन से पहले मुझे यह दरख्वास्त करनी है कि हम सब काश्मीर की समस्या को एक राष्ट्रीय समस्या, तमाम दलों की समस्या के रूप में देखें, किसी एक दल की समस्या के रूप में नहीं।

काश्मीर भारत का है, काश्मीर भारत का रहेगा और यदि किसी दूसरे देश ने इस पर महला किया, तो हम भारत के पचास करोड़ आदमी उस का मुकाबला करेंगे। यदि किसी दूसरे देश के लोग वहां पर घुसपैठ करते हैं, तो हम उस का मुकाबला करेंगे। लेकिन मैं समझता हूं और मेरी पार्टी समझती है कि हमारे लिए काश्मीर की जनता के दिल को, मन को और विचार को जीतना बहुत ही आवश्यक है। पिछले बीस वर्षों में कांग्रेस ने जिस तरह के शासन वहां पर लादे हैं, उस से वहां की जनता का एक भारी बहुमत हम से अलग हो गया है, उस का दिल दुख गया है, उस का मन मर गया है। हमें ऐसी कोशिश करनी चाहिए कि राष्ट्रीय हित को सर्वोपरि रखते हुए उस जनता के दिल और मन को जीतें।

कुछ माननीय सदस्यों ने इस बात पर आपत्ति की कि काश्मीर को ज्यादा पैसा दिया जाता है। मैं कहना चाहता हूं कि काश्मीर के लिए हमारी माताओं ने अपनी गोदें खाली की है, हमारी बहनों ने अपने सुहाग लुटाए हैं। अगर हमें काश्मीर की जनता को खिलाने-पिलाने के लिए और उस की उन्नति के लिए कुछ करोड़ रुपया देना पड़ेगा ताकि काश्मीर हमारे साथ रहें, तो वह हम करेंगे और वह हमारा राष्ट्रीय कर्तव्य होना चाहिए।

इस बात पर भी आपत्ति की गई कि कम्युनिष्ट नेता काश्मीर जाते हैं। क्यों? क्या कम्युनिष्टों के लिए काश्मीर जाना अवैध है? वहां पर दफ़ा 144 तो नहीं लगी हैं। जब मधोक साहब का राज होगा और वह दफ़ा 144 लगा देंगे, तो हम देखेंगे—हम उस का मुकाबला कर लेंगे। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि हमारी पार्टी के महामंत्री को काश्मीर जाने की आवश्यकता हुई तब, जब कि 22 अगस्त को जनसंघ के अध्यक्ष ने वहा पर एक ऐसा साम्प्रदायिक उत्तेजना का भाषण दिया,······

श्री बलराज मधोक : मैंने गृह मंत्री को कहा कि वह मेरे भाषण को पढ़ें। क्या माननीय सदस्य ने उस को पढ़ा है?

श्री योगेन्द्र शर्मा : ····जिस से पाकिस्तानियों और पाकिस्तान-पक्षियों को काश्मीर में साम्प्रदायिक भावनायें उभार कर काश्मीर को और भारत को कलंकित करने का मौका मिला। मैं जनसंघ के भाइयों से दरख्वास्त करूंगा कि यदि उन को देश प्यारा है, यदि वे काश्मीर को अपने साथ रखना चाहते हैं, तो वे ऐसी बात न कहें, ऐसा काम न करें, साम्प्रदायिकता की ऐसी भावना न पैदा करें, जिस से पाकिस्तान के भीतर के मुस्लिम सम्प्रदायवाद को उभारने का मौका मिले। मुस्लिम सम्प्रदायवाद और हिन्दू सम्प्रदायवाद दोनों देश के दुश्मन है, काश्मीर के दुश्मन हैं, काश्मीर को भारत में रखने के दुश्मन हैं। काश्मीर और भारत की रक्षा के लिए हमें इन दोनों सम्प्रदायवादों के खिलाफ़ लड़ना पड़ेगा।

काश्मीर पर राष्ट्रपति शासन लाद कर इस समस्या का हल नहीं होगा। वहां पर राष्ट्रपति शासन लादना पाकिस्तन को मदद करना होगा। लेकिन वहां पर शासन में जो भ्रष्टाचार है, वहां पर नागरिक अधिकारों का जो हनन किया जा रहा है, उस का निराकरण करना चाहिए, ताकि वहां पर जनतंत्र विकसित हो सके।

श्री महन्त दिग्विजय नाथ : क्या केवल कम्युनिष्ट ही इस देश के रक्षक है, हिन्दु और मुसलमान नहीं?

श्री योगेन्द्र शर्मा : हम तो सब को मानते हैं। हम तो माननीय सदस्य को भी मानते हैं अगर माननीय सदस्य को शक हो, तो दूसरी बात है।

18 HRS.

MR. DEPUTY-SPEAKER : Shri Ramamurti.

SHRI P. RAMAMURTI (Madurai): Mr. Deputy-Speaker, Sir, I thought....

MR. DEPUTY-SPEAKER : We have already taken two hours and some minutes. We will have to conclude this debate today. May I know how long the House is willing to sit?

श्री महन्त दिग्विजय नाथ (गोरखपुर) : हमें भी तो अधिकार है बोलने के लिए। हमें कब समय मिलेगा ?

उपाध्यक्ष महोदय : आप को भी मिलेगा। जरा आप सब्र करिए।

श्री राम गोपाल शालवाले (चांदनी चौक) : मेरा भी नाम है। और लोगों को समय देते हैं, मुझे क्यों नहीं देते हैं ? मुझे समय मिलेगा या नहीं ?

उपाध्यक्ष महोदय : जी नहीं।

I cannot allow any more.

SHRI P. RAMAMURTI : Mr. Deputy-Speaker, Sir, the scope of the debate on this motion has been widened and the whole gamut of questions including the present position of Kashmir, what should be done and all sorts of things have been referred to here. It has been a very good debate in this sense that Shri Bakshi Gulam Mohamad gave us a very vivid picture of how the elections were conducted and how the election petitions are being disposed of. He also told us what progress the various tribunals have made and how laws are made over-night in order to thwart the judgments of tribunals. All these things have been said here.

Therefore, the picture that emerges is that the present government there is not a democratically elected government. Very good. But in 1964 when there was that Hazarat Bal incident and a lot of trouble was there, at that time also it was stated on the floor of this House that all that trouble was not only because of Hazarat Bal trouble or the 'holy hair' incident, but because of the fact that the people of Srinagar or the people of Kashmir were extremely angry against the then Government, the Government of Shamsuddin Sahib.

The fact is, therefore, very clear—I do not want to go into the history—that section 144 has been there in Srinagar continuously for 14 years. I know even on the day of Prophet's birth day they were not allowed to take a procession because prohibitory order under section 144 was there. This sort of thing has been continuing there.

Is it not necessary for us to understand why is it that the ordinary democratic rights of the people of Kashmir are not accepted? There must be some reason behind it. Why is it so? Why is this Government afraid of the democratic rights of the people of Kashmir? Why do you want to rule them permanently by means of orders under section 144, by means of prohibitory orders?

What is the way out? A way out has been suggested that there must be President's Rule and there must be ever so many other things, section 370 of the Constitution must be made applicable to Kashmir and all that. I would very much appreciate these things if as a result of these things the problem of Kashmir would be solved. But the fact remains that the democratic rights of the people there have been suppressed all these years despite the fact that we have been giving them some Rs. 70 crores as subsidy up to 1964 and subsequently another Rs. 72 crores. Why? As I said, there must be some reason. After all, the Government must be afraid of their democratic rights. Whether it is the Government of Sadiq or Shamsuddin or the Government that existed before it is immaterial, but it is a fact that all these years their democratic rights have been suppressed.

That is the situation with which we are faced. Therefore, it is not a question of imposition of President's Rule. If President's Rule can get them back all those democratic rights—as if that

is going to get them back because we know President's Rule in so many other States—I can understand that. But President's Rule is not going to give the people their democratic rights. Therefore, the problem is more fundamental, much more deep. I agree with my hon. friend, Shri Joshi, who said that there is no use thinking there is no problem of Kashmir. There is a problem. If there is no problem of Kashmir, we will not be discussing this on the floor of the House year after year. Do not shut your eyes to the fact that there is a problem and that problem cannot be solved by simply saying the Constitution should be made fully applicable. That is not the issue here. This problem cannot also be solved by the way in which Shri Madhok wants it to be solved—if anybody is feeling that he is not secure here, let him go to Pakistan. That way also it is not going to be solved. Neither is it going to be solved by telling the Hindus there "be sure of the fact that 40 crores of Hindus of India are behind you." That is not the way in which the Hindu population of Kashmir can be protected. The Hindu population of Kashmir can be protected only if the Muslim population of Kashmir is appealed to once again of the grand traditions of the Muslims who have been non-communal even in the year 1947, even at the time of the dastardly attack from Pakistan, even at that time they had adopted that non-communal attitude, and placing before them the glorious traditions of their non-communalism and secularism. That is the only way in which the Hindu population of Kashmir can earn its security and not by saying that 40 crores of the people of India are behind them "we are there to save you" and all that kind of thing, because that is the way of fanning communalism and not solving the problem.

Therefore, the problem is somewhat more fundamental. How can this problem be solved? I agree with my hon. friend that the only way in which it can be solved is by having some kind of consultation, real consultation, with the leaders of Kashmir itself and, in that leadership, naturally Shri Sheikh Abdulla has an important place. You cannot wish him away by simply shutting him in jail for years together. You cannot say that he has ceased to be the leader of Kashmir. By keeping him in detention you cannot take away the affections of the people of Kashmir for him. So long as he commands the affection of the people of Kashmir, the only way in which it can be solved is by bringing all these people together.

That is the only solution that is acceptable to the people of Kashmir. Win the confidence of the people of Kashmir by doing that and see to it that no outside power is able to take advantage of this particular situation. That is the only way in which I wish this Government to move and I urge upon the government to move on these lines very quickly.

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा (बाढ़): उपाध्यक्ष महोदय, काफी सदस्यों ने बहुत कुछ काश्मीर के बारे में कहा और यह सही बात है कि उसमें से बहुतों ने जो कुछ कहा है उसमें काफी सच्चाई है कि यह समस्या साम्प्रदायिक जितनी नहीं है उतनी आर्थिक है। जो काश्मीरी पंडितों को पिछले दिनों परेशानी हुई या जो उन्होंने आन्दोलन किया या जो वहां के मुसलमानों के बीच में हुआ उसकी बुनियाद में अगर हम जायं तो मैं तो समझती हूं कि इसकी बुनियाद आर्थिक है। अगर हम देखें काश्मीर का इतिहास तो आपको याद होगा, उपाध्यक्ष महोदय, कि 1931 में काश्मीरी जनता ने एक बहुत बड़ा आन्दोलन किया था जब वहां महाराजा का राज था। इसी आर्थिक विषमता को दूर करने के लिए मांग थी। वह उस मसय बिल्कुल ढोर और बकरी का जीवन बिताते थे। इतनी गुर्बत वहां थी और उस गरीबी का अन्दाजा बहुत लोगों को हुआ है जो काश्मीर गए हैं। आप शायद यह भी जानते होंगे उपाध्यक्ष महोदय, कि उन दिनों एक समिति बनाई गई थी, ग्लांसी कमीशन जिसका नाम था और उस ग्लांसी कमीशन ने खुद इस बात का

[श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा]

एकरार किया था कि वहां के मुसलमानों को नौकरी और शिक्षा जिस स्तर पर मिलनी चाहिए वह नहीं मिल पा रही है, इसलिए इसके बारे में विचार किया जाय और आपको यह भी याद होगा कि श्री गोपालास्वामी आयंगर जिस समय वहां के प्रधान मंत्री थे उन्होंने अपने राज्य के कानून में और राज्य के घोषणापत्र में यह परिवर्त्तन किया कि वहां के लोगों को कुछ आबादी के आधार पर शिक्षा और नौकरी की सहूलियत हो। जैसा कि हम आये दिन देखते हैं, हर जगह से मांग होती है, हर जगह पिछड़ी जाति के लोगों की मांग है कि हमें नौकरी मिलनी चाहिए, हमारा प्रतिनिधित्व होना चाहिए और आज देश के कोने-कोने से यह मांग उठ रही है। तो काश्मीरी जनता भी अगर उस स्तर पर या उस स्थिति में कोई मांग करती है तो उसका हल आर्थिक हो सकता है। उसका हल साम्प्रदायिक नहीं हो सकता है। साम्प्रदायिक समस्या का इसको रूप देना उचित नहीं है। यह जो बात है कि कुछ हिन्दू मुसलमानों के झगड़े हुए, तो हिन्दू मुसलमानों के झगड़े कोई काश्मीर में ही हुए हों ऐसी बात नहीं है। रांची में झगड़े हुए और सुरसन बिहार में एक जगह है, वहां यह झगड़े हुए और इसके पहले भी वर्षों से हमारे अन्दर जो फूट का बीज बोया गया था अंग्रेजी शासन के द्वारा उसकी वजह से यह आग कहीं-कहीं सुलग जाती है और कहीं-कहीं उसकी चिनगारी दिख जाती है।

उपाध्यक्ष महोदय, यह चिनगारी अंग्रेजों ने सुलगाई थी—मुझे इसी पर अकबर इलाहाबादी का एक शेर याद आता है—

बूट डासन ने बनाया, मैंने एक मजमूं लिखा,
देश में मजमूं न फैला, और जूता चल गया।

आज भी हमारे अन्दर कहीं-कहीं ऐसी चिनगारी उठ जाती है, हमको उसका समाधान करना होगा, जिसका सुबूत हमको काश्मीर में मिला है।

आज इस बात से कोई इन्कार नहीं कर सकता—मिर्जा अफसल बेग, जिनकी बहुत-सी बातें हम ठीक नहीं समझते, जिनके कई काम हमको पसन्द नहीं हैं, लेकिन उनके इलाके अनन्तनाग में कोई चिनगारी नहीं उठी। उन्होंने इस बात का सुबूत दिया कि हम हिन्दू और मुसलमानों में टक्कर नहीं होने देंगे। क्या यह गलत बात है कि हजरत बल के मन्दिर में, जहां पर हजरत मुहम्मद साहब के बाल रखे हुए हैं, वहां पर पचास हजार मुसलमानों ने करार किया कि हम हिन्दू और मुसलमानों में झगड़ा नहीं होने देंगे। इन बातों को सुबूत मान कर ऐसी शक्तियों को हमें प्रस्फुटित करना चाहिये, ऐसी शक्तियों को लेकर हमें चलना चाहिये, ऐसी शक्तियों की मदद करनी चाहिये ताकि हिन्दुओं और मुसलमानों के झगड़े कम हों।

मैं सिर्फ एक बात और कहना चाहती हूं—श्री प्रकाशवीर शास्त्री ने मंगला बांध की बात कही कि प्रधान मंत्री जी ने श्री अयूब को सन्देश भेजा, ऐसा करना ठीक नहीं था। मंगला बांध का सवाल क्या है— आज यही बात मैं इस सदन के सामने रखना चाहती हूं। इसी सदन में कई बार यह चीज आई, कई बार इस बात की घोषणा की गई कि मंगला डैम बनाने के लिये हमको इतना रुपया देना होगा और इसी सदन के द्वारा वह रुपया दिया गया, इसी सदन ने उसको स्वीकार किया। इन सब बातों का सुबूत क्या निकलता है ? इन सब बातों से यह साफ़ तौर से ज़ाहिर होता है कि मंगला बांध चाहे आज़ाद काश्मीर की सीमा के अन्दर बनाया गया है, लेकिन हमने उसको मान्यता दी। उससे हमको फायदा यह हुआ कि उस बांध के बन जाने के बाद जो पानी पंजाब, हरियाणा और राजस्थान को नहीं मिल रहा था, अब वह पानी हमको मिलेगा। इसलिये मंगला बांध के बारे में इस तरह की गलतफहमी पैदा करने की या इस तरह की बातें कहने की कोई जरूरत नहीं थी।

लेकिन मैं काश्मीर की सरकार से और गृह मंत्री जी से एक अपील जरूर कहना चाहती हूं—आपको याद होगा कि जिस समय काश्मीर

में 144 धारा लागू थी और श्रीनगर में करफ्यू था, तो मैं जानना चाहती हूं कि सात हजार करफ्यू परमिट्स क्यों ईशू किये गये—सात हजार परमिट्स उस दिन दिये गये। यह ढीलपन शासन के द्वारा क्यों दिखलाया गया, वहां का शासन इससे इन्कार नहीं कर सकता है। मैं चाहती हूं कि गृह-मंत्री महोदय वहां के शासन की मजबूती को बढ़ाने की कोशिश करें, परन्तु इसका मतलब यह नहीं है कि राष्ट्रपति के शासन द्वारा ऐसा किया जाय। प्रजातान्त्रिक शासन की मजबूती प्रजातान्त्रिक तरीके से ही बढ़ाई जा सकती है।

MR. DEPUTY-SPEAKER : Do you want to postpone the debate? I do not want to postpone it. This will never conclude unless you restrict yourself to your own time. You have exceeded your time. It cannot go on like this. You have so many things to say to the House but it is not possible. Shri Barua.

SHRI HEM BARUA (Mangaldai): Sir, I would have liked the Government to take into consideration the international relations also because the problem of Pakistani infiltration into Kashmir cannot be studied in an isolated manner for it is a part of the calculated strategy on the part of Pakistan to seize Kashmir by force. The latest statement of President Ayub Khan is that there can be no lasting peace between Pakistan and India unless the Kashmir problem is satisfactorily solved. By "satisfactory solution" what he means, I do not know. If he thinks that India should wrap up Kashmir like an easter egg and present it to Pakistan, he is living in a fool's paradise. But, on the other hand, after the Tashkent Pact was signed we were told here that the Kashmir problem has been solved and that there would not be any discussion about Kashmir. Our Prime Minister subsequently told us that Kashmir is not negotiable. If Kashmir is not negotiable, why is it that Shri Chagla, the ex-Foreign Minister, wrote a letter to his Pakistani counterpart on May 6, 1967, proposing that all the disputes between India and Pakistan, including Kashmir, will be discusssed?

Why did you write like that?

Now, I can give you an account how Pakistan has entered into a pact with China for 120 million dollars for supply of arms and ammunition. China is going to implement the pact by 1968. I will not go into all that. It must be said that the policy that has been pursued by this Government, so far as Kashmir is concerned—I mean internal problems—has been a vacilating policy. And there is no policy about it. What happens? The British rulers used to negotiate with the Kashmiri Hindu rulers there. Now, the present Government is following the same policy of negotiating with certain persons and ignoring the people altogether as the British rulers used to do. What have we done? You do not have any firm policy. You want to boost up certain persons ignoring the people of Kashmir. You try to boost up Sheikh Abdullah; you try to boost up Bakshiji. You have boosted up Mr. Sadiq now. That is the policy you have been pursuing there, an unfortunate policy. There is no policy about Kashmir except that of trying to win over the people of Kashmir through certain persons whom you boost up. When you find that they do not serve the purpose, you ignore them and brush them aside. That is the policy you have been pursuing so far.

Kashmir is in ferment today, Kashmir is in trouble, not only internationally but also internally. There are internal foes also. I do not say Muslims of Kashmir are communal minded. But there is a pro-Pakistani element amongst Muslims of Kashmir as there is communal element amongst Hindus there. How has it come? The pro-Pakistani element, that inspiration, has been imported from Pakistan and the inspiration for Hindu communalists has been imported from somewhere in India. Therefore, I say that there should be a sort of general inquiry commission to find out the people who are responsible for this sort of discord in the State of Jammu and Kashmir.

[Shri Hem Barua]

Now, on the 3rd August, 1965, our Home Minister who was then the Defence Minister made a statement in Srinagar that not a single Pakistani infiltrator had come into Srinagar and that the borders had been sealed. On the 12th August, 1965, on the floor of this House, his predecessor, Shri Gulzarilal Nanda, the then Home Minister, made a statement that 12,000 Pakistani infiltrators had come and surrounded Srinagar. Now, my problem is how could 12,000 infiltrators come into Srinagar and surround Srinagar. Was the State Government there sleeping? Were you sleeping here? After the Tashkent Pact was signed, these people went on crying like a bunch of old women requesting Pakistan to withdraw those infiltrators. Why should Pakistan withdraw those infiltrators? It is upto you—you are the guardian of law and order—to push them out. Therefore, I would say that the Government of India should make an inquiry into it. They have, of late, appointed a commission to enquire into the communal holocaust in Ranchi and Gorakhpur and other parts of India and I would say that this should be extended to Jammu and Kashmir also. The present Government of Jammu and Kashmir has appointed a committee of inquiry like that. But I do not want the Central Government to leave the responsibility to the present Government of Jammu and Kashmir because there are great doubts about the present Government of Jammu and Kashmir. Therefore, Mr. Y. B. Chavan should take the responsibility and then he must try to project his image if he is stern and firm ... (*Interruption*)

THE MINISTER OF HOME AFFAIRS (SHRI Y. B. CHAVAN): I did not say 'No'.

SHRI HEM BARUA: There are some allegations made about the elections also. Shri Bakshiji has just now made the allegations. Those allegations must be enquired into. Wherever there is any pro-Pakistani element in the administration or outside, in the streets, his activities must be curbed and he must be thrown out or else there can be no restoration of peace in the State of Jammu and Kashmir. When the State of Jammu and Kashmir is in torment, is in ferment, the rest of India is, naturally, in torment and in ferment.

श्री महन्त दिग्विजय नाथ (गोरखपुर): उपाध्यक्ष महोदय, मैंने जो स्पीचेज हुई उनको खूब ध्यानपूर्वक सुना। इस देश में एक बहुत बड़ी कांस्पिरेसी चल रही है। कश्मीर के मामले में पाकिस्तान और चीन दोनों मिले हुए हैं और उसके पीछे अंग्रेज हैं और अमरीका भी है। हम और आप यह देख रहे हैं कि जगह-जगह पर वे यह पता लगाना चाहते हैं कि आपकी नसों में पूर्वजों का रक्त बाक़ी है या नहीं। कहीं वह असम में घुस रहे हैं कहीं वह रांची में उपद्रव कर रहे हैं, कहीं गोरखपुर में कर रहे हैं तो कहीं वह कश्मीर में उपद्रव कर रहे हैं। क्या कारण है कि इसके पहले यह बातें नहीं हो रही थीं? आज यह क्यों हो रही हैं तो उसका स्पष्ट कारण यह है कि हम लोग कानमें तेल डाल कर यहां सोये हुए हैं और यह समझ रहे हैं कि विभाजन के बाद हिन्दू, मुसलमानों की समस्या हल हो गयी।

सन् 1947 में जब देश का विभाजन हुआ तो एक मुस्लिम राष्ट्र हो गया। लेकिन यहां हिन्दू राष्ट्र नहीं हुआ और हिन्दू राष्ट्र कहलाने की बजाय वह सैकुलर स्टेट कहा गया। हालांकि उसे आटोमैटिकली हिन्दू राष्ट्र होना चाहिए था। हम हिन्दुओं की हिन्दू राष्ट्रीयता को साम्प्रदायिकता कहा गया।

इस कारण हमारा जो मनोबल है वह घट रहा है। हमारे अन्दर राष्ट्रीयता की भावना भरी नहीं गई यही कारण है कि देश में हम कमजोर होते चले जा रहे हैं। हिन्दू जो इस देश की रीढ़ हैं उनको आपने साम्प्रदायिक कह कर उनके मनोबल को घटाने का काम किया है। मैं पूछना चाहता हूं कि अगर हिन्दू इस देश के राष्ट्रीय नहीं हैं तो कौन हैं? लेकिन हिन्दू राष्ट्रवाद को साम्प्रदायिक कह कर उनके मनोबल को आप घटा रहे हैं।

अर्थात् राष्ट्रीय भावना को घटा रहे हैं और विदेशी तत्व बढ़ते चले जा रहे हैं। इसलिए सब से बड़ा कर्त्तव्य इस देश का यह है कि देश अपने यहां के नागरिकों को चाहे वह हिन्दू हों, मुसलमान हों या कोई और अन्य हों, मुसलमान आदि भी इस देश के हो सकते हैं जब वह इस देश को अपनी मातृभूमि व पितृभूमि समझें लेकिन उनकी निष्ठा दूसरे देश के प्रति है तो वे इस देश के नागरिक नहीं हैं और दूसरे देश के माने जायेंगे।

सन् 1947 में जब भारत विभाजन हुआ और पाकिस्तान राज्य का निर्माण हो गया तो यह समझा जाता था कि हिन्दू, मुसलमानों की समस्या हल हो जायगी, लेकिन हमने देखा कि वह समस्या वैसी की वैसी मुंह बायें खड़ी है और वह हल नहीं हो सकी है। पहली ग़लती जो कांग्रेस सरकार ने कश्मीर के बारे में की वह यह कि भारत में आए रैफ्यूजीज़ को ले जा कर वहां पर नहीं बसाया। अगर कहीं इन रैफ्यूजीज़ को कश्मीर में ले जाकर बसा दिया गया होता तो आज वहां के अल्पसंख्यक हिन्दुओं को यह दिन न देखना पड़ता। और आज यह कश्मीर की समस्या न होती। आपको मालूम होना चाहिए कि चीन ने सिक्यांग से मुसलमानों को निकाला और उन निकाले गये मुसलमानों को यहां कश्मीर में रैफ्यूजीज़ की हैसियत से बसाया गया है . . .

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य का समय समाप्त हो चुका है। मैंने कृपालानी जी को बुलाया है।

श्री महन्त दिग्विजय नाथ : मुझे बहुत ही कम समय दिया गया। खैर, जैसी आपकी मरजी।

इसके अलावा वहां कश्मीर में एक और क़ानून बना हुआ है जिसके कि कारण हम वहां पर कोई भी सम्पत्ति व जायदाद आदि नहीं खरीद सकते लेकिन वहां के लोग इधर आकर जो चाहे खरीद सकते हैं . . .

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य का भाषण समाप्त हो गया। श्री जी० भा० कृपालानी।

श्री जी० भा० कृपालानी (गुना) : उपाध्यक्ष महोदय, आप ने मुझे इतनी देरी से बुलाया है कि जो मैं कहना चाहता था वह मैं भूल गया हूं।

कश्मीर के बारे में पहले दिन से हम लोगों की जो पालिसी रही है वह गलत रही है। जब हम ने कहा कि प्लैबिसिट होगी उस दिन से फिर बहुत सी बातें हुई। वहां एक कांस्टीटुएंट असेम्बली भी बुलायी गयी। कांस्टीटुएंट असेम्बली ने भी कहा कि Accession of Kashmir with India is complete. फिर भी हम लोगों ने यह कहा That is without prejudice to our promise of plebiscite. अब आप समझिये कि दूसरे आदमी यह बात कैसे समझ सकेंगे जबकि हम खुद ही ऐसा कहते हैं। कांस्टीटुएंट असेम्बली जो एक देश को बनाती है वह कहती है कि Accession is complete. लेकिन हम अमरीका आदि देशों से वहां कहते हैं It is not complete; it is without prejudice to our promise of plebiscite. इसके तरीके से कई गफलतें हम ने की हैं। फिर क्या करते हो? हम समझते हैं कि वहां एक चीफ मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर बनाया जायगा तो हमारा सारा सवाल हल हो जायगा। पहले हम ने इतना विश्वास रक्खा शेख अब्दुल्ला में जो यहां यह जो सेक्रेटेरियरट है, यह जो साउथ ब्लाक है, यह जो सारा सेक्रेटेरिट का ब्लाक है वहां जाकर वह सेक्रेटरीज़ को कहते थे कि यह करो और वह न करो और धमकी देकर काम कराते थे कि अगर हमारे कहे के मुताबिक नहीं करोगे तो हम भाई के पास चले जाते हैं। जो भी शेख अब्दुल्ला चाहते थे यहां सेक्रेटेरियट में वह होता था . . . .

एक माननीय सदस्य : भाई कौन ?

श्री जी० भा० कृपालानी : भाई आप हम सब जानते हैं कि उन का कौन है ? फिर उस से काम नहीं चला तो दूसरे भाई को शेख साहब के जो दूसरे भाई थे बक्शी साहब, उस को बुलाया और जब इन से भी काम नहीं चला तो एक और ही नया आदमी उस जगह पर बुला लिया है। अब जहां तक शेख अब्दुल्ला का सवाल है या वह दूसरे भाई बख्शी गुलाम मुहम्मद का सवाल है तो यह दोनों जने तो जनता के आदमी हैं लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि यह जो नया आदमी इन के बाद लाया गया है वह किस का आदमी है ? उस को जनता से कोई वास्ता ही नहीं है। उस को जनता पहचानती नहीं है। वह माना कि पहले दोनों आदमियों ने बहुत गलतियां कीं, बहुत जुल्म किये तब भी यह जनता के आदमी तो थे लेकिन वह तीसरा जो लाया गया है वह तो जनता का आदमी ही नहीं है। वह तो आप लोगों ने उसे बना दिया क्यों बनाया वह भी समझ में नहीं आता है।

पी० एस० पी० वाले वहां एक अपनी ब्रांच निकालना चाहते थे। उन दिनों मैं पी० एस० पी० का अध्यक्ष था। मैंने कहा कि भाई सुनो, मैं कश्मीर को जानता हूं वहां हम को ब्रांच बनाने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन यह जो सोशलिस्ट हैं यह बड़े आइडिलिस्ट हैं, अशोक मेहता ने कहा कि नहीं हम वहां पर ब्रांच बनायेंगे। खैर वह बनायी गई और नतीजा यह हुआ कि मार खाकर आया। वह तो वही बात है जैसे हम अंग्रेजी में कहते हैं:

"Fools rush in where angels fear to tread".

मुझ को अपनी जान बचानी थी मैंने कहा कि वहां पर नहीं जाऊंगा। मैं 1946 के बाद कश्मीर नहीं गया हालांकि मेरे गांधी आश्रम की ब्रांच वहां पर है। वहां गरम खादी बनती है सारे हिन्दुस्तान में जाती है। लेकिन इस दफे मैंने खयाल किया कि 20 साल के बाद मैं उधर जाऊंगा। मैंने वहां जो मेरे काम करने वाले हैं उन को लिखा तो उन्होंने कहा कि दादा आप यहां मत आइए। दरअसल आप लोग या हम लोग इस कश्मीर की पालिटिक्स को समझ नहीं सकते हैं। इसमें समझिये अशोक मेहता को मार मिली और हमारा एक बड़ा आदमी वहां पर खत्म हो गया मेरा मतलब श्यामाप्रसाद मुकर्जी से है। इसलिए भाई अगर आप लोगों को भी खत्म होना है तो इन बातों में पड़ियेगा। यह बेचारे हमारे होम मिनिस्टर वह भी जल्दी से वहां से भाग आये कि कहीं कुछ हो न जाय। दरहकीकत जैसी यह एक नेटिव स्टेट थी वैसी वह नेटिव स्टेट अभी तक है। यह हमारी गलती ही है कि हम कुछ चंद आदमियों के ऊपर विश्वास रखकर बैठते हैं। हम समझते हैं कि इस चीफ मिनिस्टर को हटा दिया दूसरे को उस की जगह ले आये हमारा सवाल हल होगा और हम जनता को एप्रोच नहीं करते। पैसा तुरन्त हम देते हैं बाकी वह कहां जाता है उस का हम को खयाल नहीं है। 6 आने किलो चावल मिलता है काश्मीर में और यहां डेढ़ रु० किलो भी नहीं मिलता है। वहां एम०ए० तक फ्री एजुकेशन है, लेकिन यहां नहीं है। इस ब्राइबरी से आप काम नहीं चला सकते। अगर कोई कहता है कि काश्मीर में कम्यूनलिज्म नहीं है, तो यह झूठ है। कम्यूनलिज्म वहां है। और कैसे नहीं हो सकता है ? जब 12 हजार इन्फिल्ट्रटर्स वहां आ गये तब भी आप समझते हैं कि वहां की जनता में कोई कम्यूनलिज्म नहीं है ? यह हो ही नहीं सकता। करोड़ों रुपये पाकिस्तान खर्च करता है तो क्या वह बेवकूफ है ? वहां उस के एजेन्ट्स बैठे हुए हैं। आप तो उन को जानते भी नहीं हैं। वह वहां पर काम कर रहे हैं। शायद वह आप की आर्मी में भी काम करते हों। यह कहना कि वहां कम्यूनलिज्म है ही नहीं, यह असलियत से आंखें बन्द करना है। यह जरूर है कि काश्मीर में कम्यूनलिज्म शुरू से रहा नहीं है। काश्मीर के हिन्दू मुसलमान आपस में भाई चारा कर के रहते थे। लेकिन यह कहना कि वहां अभी कम्यूनलिज्म है ही नहीं, यह ठीक नहीं है।

To say that the Muslim mind has not been affected at all by the propaganda of Pakistan is to close one's eyes to the facts. It is a fact and it is there. But how are we to counteract it? हम इस तरह से काउंटरऐक्ट कर सकते हैं कि हमारे आदमी वहां बसाये जायें, आप जो पैसा खर्च करते हैं वह वहां के आदिमियों के पास जाये, हम गरीबों को आगे बढ़ायें। लेकिन वह आप करेंगे कैसे? जब आप यहां नहीं कर सकते हैं तो वहां कैसे करेंगे?

यहां भी हम कुछ खास-खास आदमियों पर भरोसा कर के बैठे हुए हैं। यह तो हमारी डिमोक्रेसी का नमूना है। यूनिवर्सल वोट विद ए-यूनिवर्सल इग्नोरेंस, ऐसा हमारा हाल है। अगर आप इस सवाल का सोल्यूशन चाहते हैं तो यह प्रेजिडेंट्स राज्य से नहीं होगा। आज एक कालम को संविधान में से निकाल देने से कुछ नहीं होगा। जनता के पास आप के आदमी जायें, उन की खिदमत करें। सोशल रिफामर्स जायें, कंस्ट्रक्टिव वर्कर्स जायें, उन लोगों की गुरबत दूर करें, तब यह मसला हल हो सकता है। खाली एक चीफ मिनिस्टर के बदलने से काम नहीं चलेगा। इस से तो रजवाड़ों की पालिटिक्स चलती है यह आप जान लीजिये। वहां रजवाड़ों की पालिटिक्स चलती है, वहां डिमोक्रेसी नहीं चलती है। इस को आप लोग नहीं जानते हैं, लेकिन हम अच्छी तरह से जानते हैं। बख्शी यह बात सच कहते थे कि वहां डिमोक्रेसी नहीं है, लेकिन उन के जमाने में भी कहां डिमाक्रेसी थी? माफ कीजिये, क्योंकि हम तो अपना आइना रखते हैं। उन का ही जमाना था कि जब हमारा गुजराती भाई वहां पीटा गया अशोक मेहता। अशोक मेहता को पीटने में क्या लगता है? कोई भी पीट सकता है। इस में कौन सी बहादुरी है? (हंसी) जब मैं कोई रास्ता बतलाता हूं तो उस पर यहां लोग हंसने लगते हैं। मैं क्या करूं? मैं आप से कहूंगा कि मेहरबानी कर के जो पैसा आप खर्च करते हैं उस को ठीकसे खर्च कीजिये। वह फुजूल खर्च होता है। आप इस तरह से खर्च करें कि जनता के पास जाये।

दूसरी बात जो आप को करनी है वह यह कि आप के जो फर्स्ट क्लास ऐडमिनिस्ट्रेटर्स हैं उन को आप काश्मीर में भेजिये। अगर काश्मीरियों को जगह देनी है तो यहां ला कर बिठलाइये। अगर आप यह करेंगे तो मैं दावे से कहता हूं कि आप किसी न किसी तरह का सोल्यूशन हासिल कर लेंगे। अगर आप यह नहीं करेंगे और काश्मीरी अफसरों के हाथ में सब चीजें दे देंगे तो आप का काम नहीं चलेगा।

Let them go to the people and send their best administrators from here to that place and employ those people who want some employment, here. There is no other solution.

THE MINISTER OF HOME AFFAIRS (SHRI Y. B. CHAVAN): The motion moved by Shri Prakash Vir Shastri was, really speaking, connected with the situation arising out of the serious threat to national security posed by the recent influx of infiltrators into Kashmir. But on the basis of this Motion, naturally this discussion covered a very wide area. It was quite useful to know the views of all the most important parties and also some important leaders such as Dada Kripalani.

I do not propose to reply to all the points raised because it is difficult to reply to them in a small debate like this in a very short speech. The basic point I would like to touch upon concerns some of the issues raised by Shri Prakash Vir Shastri and Bakshi Ghulam Mohammed. The first question Shri Shastri asked me was: what have I done or what is being done in regard to some of the assurances I gave when I visited Kashmir during the Pandits' agitation? I had assured him on two or three important points. One was that the question of excesses committed by the police during the agitation should be inquired into by an officer to be nominated by me from here. I would like to tell the House that the

[Shri Y. B. Chavan]

Director of the CBI, Shri Kohli, has been nominated by me, and the nomination has been accepted by the Chief Minister of Kashmir, to go into this question of police excesses during the agitation.

The other point was that there were certain grievances of the Pandits. On the question of imbalances, economic imbalance, imbalances in employment etc. it was necessary that some sort of a high power committee should go into them. It is now common knowledge that a Committee under the chairmanship of Shri Gajendragadkar has been appointed to be assisted by two other colleagues of his, which will go into this question. Naturally, they will go into the question of the imbalances in development, economic questions and so on. People with the experience of Justice Gajendragadkar, Shri Shankar Prasad and Shri Tyabji are on the Committee and I think the recommendations made by this Committee will be a very useful document both for the Government of Kashmir and also for public opinion in India as a whole. These were the two basic issues on which I gave an assurance and this has been acted upon.

Naturally, I do not want to go into the question of the Hindu girl being married to a Muslim gentleman because it is *sub judice.*

SHRI HEM BARUA : It is a natural thing.

SHRI J. B. KRIPALANI : May I suggest that in such cases the girl is always kept with neutral persons ? Has that been done in this case ?

SHRI Y. B. CHAVAN : If it were done, I would certainly have welcomed it.

SHRI J. B. KRIPALANI : He must use his influence to have that done.

SHRI BAL RAJ MADHOK : He wanted to do, but could not get done.

SHRI Y. B. CHAVAN : The court was seized of the whole matter. The court could do that. But my difficulty was that I could not interfere with the judicial processes when the court had taken cognisance of the matter. Naturally the judicial processes had to be allowed to proceed further.

SHRI J. B. KRIPALANI : What I mean to say is that such a step is customary. When there is a dispute about a girl, for the time being the girl is kept in some neutral place.

SHRI Y. B. CHAVAN : I understand that.

SHRI JAGANNATH RAO JOSHI (Bhopal) : What is the use of understanding if it is not executed ?

SHRI Y. B. CHAVAN : I do not want to go into the facts of the case. These are matters on which there are two different views. As the matter is before the court, I do not want to express any view on this matter.

SHRI J. B. KRIPALANI : It is a question of procedure only.

SHRI Y. B. CHAVAN : I know it is a question of procedure. Naturally they follow it. I certainly would welcome Acharya Kripalani's suggestion, which really speaking, if the court accepted it, would have saved many troubles not only for the girl, but possibly for the whole of Kashmir. This is one aspect of the matter to which he made reference.

I would like to mention another aspect, and that is about elections that the hon. member mentioned. Shri Bakshi was not then a Member of Parliament, but, as an old colleague, he wrote to me about it, and naturally I conveyed our feelings about it, our thinking about it, to the Chief Minister of Kashmir. This whole question is now in a way before the tribunals, before the High Court Judges, because most of these matters are the subject matter of election petitions.

I know that election petitions are delayed, I quite concede that point. I do not want to hold a brief for anybody. Delay is delay, and delay in election petitions is not very good, I must concede that, but after these allegations

were made, the representatives of the Election Commissioner went to Kashmir, Shri Bakshi himself made a reference to it, and they themselves suggested that it is much better that the election law of Kashmir is brought in line with Indian law, with the law of the rest of the country. Naturally that could not be done during the election period, that was undertaken immediately after that. As to why it was not done in the March or June session, we know the fate of the legislative programmes in our sessions.

SHRI GULAM MOHAMMAD BAKSHI : That was passed in the August-September session.

SHRI Y. B. CHAVAN : Possibly they might have thought of it, but merely the desire of the Government does not help it, but it was certainly completed in September, and I must say that though some delay was involved in it, this is perhaps the most welcome thing that has happened in Kashmir, that their election law is now on the lines of the all-India election law.

SHRI NATH PAI (Rajapur) . On the lines, or on a par with ?

SHRI Y. B. CHAVAN : On a par, in all respects, particularly in matters of election petitions. Formerly it was a tribunal, but it is the High Court Judge who is going to hear all these petitions.

श्री जी० भा० कृपलानी : बक्शी जी बहुत दूरअंदेश हैं। वह जानते थे कि असैम्बली के वास्ते खड़े होंगे तो उनके कागज रद्द हो जायेंगे, इसी लिए यहां भाग आए ।

SHRI Y. B. CHAVAN : About that wisdom, I am not making comments. It was Acharya Kripalani's comment, it was not my comment.

So, after this election law was amended, we received proposals from the Kashmir Government recently. I had assured hon. member Shri Bakshi that immediately I received these proposals, within ten days I will see that they are through, and I want to tell him that the President has issued the necessary orders about the appointment of those Judges. I do not know if those Judges will be the only Judges who will look after the election petitions, these are the additional Judges, they are called *ad hoc* Judges. Whether they will deal with only election petitions or other normal judicial work, I do not know, but these appointments have been made. As far as this point is concerned, I have acted on that, and I wanted to make it clear.

About the development programme of the Jammu and Kashmir Government, many aspects were raised, why expenditure was made on this and that. I have not got all the information from the Jammu and Kashmir Government to reply to all the points. Therefore I am not saying one way or the other, but I know one thing which I must say, and that is about the attitude of the Jammu and Kashmir Government about infiltrators, because I really came prepared for that, because this was the major aspect on which the motion was moved.

There I must say that this is a fact of life which has to be accepted, it is no use saying whether there is any communalism or not, I would not go into that. Acharya Kripalani has said much about it, it is much better that we take a realistic attitude. It is very difficult to say that there is no communalism, but one thing that must be said is that when there were violent communal clashes in the other parts of India, even though there were communal feelings— I cannot say there were no communal feelings when I visited Kashmir—there was absolutely no communal clash between Hindus and Muslims. That must be accepted. No Hindu was attacked by a Muslim; no Muslim was attacked by a Hindu. There is something in the Kashmir tradition which we must accept, Who can say that there may not be communal feelings ? But the point is, so far as day to day work with each other is concerned, Kashmir has some lesson to offer us. That must be conceded.

[Shri Y. B. Chavan]

At the same time, I must say that so far as I have understood the Kashmir situation, certainly there is some sort of minority complex among the people. I had long talks and of course, it is rather very risky to make some sort of a general assessment about this. But I found everybody in Kashmir suffering from some sort of minority complex. A Hindu in Jammu feels he is a minority in Kashmir. Muslim in Kashmir feels he is a minority in Jammu. A Muslim in Kashmir Valley feels he is a minority in India. That sort of peculiar complex is there, which needs some sort of treatment and some sort of understanding. Therefore, I would say that any easy solutions suggested here and there are not the right solutions.

I am not going into the other aspects of it like the defence aspect, etc. I do not know who was a better Prime Minister there or Chief Minister there—Sheikh, Bakshi or Mr. Sadiq. I do not want to go into comparisons. But one must concede that Mr. Sadiq is a completely secular person, who has faith in secularism. Politically he is a liberal person. I know there are certainly some restrictions in civil liberty, because of certain inherent conditions in Kashmir. It is not something which I can say is very ideal. That is also because of certain local conditions there. But Mr. Sadiq is certainly a democrat and a liberal person. I must say after Tashkent Declaration, nearly 35 spy rings were broken by the Kashmir Government and a large number of people were arrested for spying activities. Some illegal arms which were dumped in different parts of Kashmir were also unearthed and confiscated. Some prosecutions have also been launched. Therefore, as far as the national security aspect is concerned, Mr. Sadiq himself is taking as keen an interest as any of his predecessors. This must be said to the credit of the present Kashmir Government. What are the other defects of the Kashmir Government, this is not the occasion to go into them. But it cannot be said that they have done nothing about development. As Defence Minister, in 1965 I had occasion to discuss many developmental aspects of those areas. I must say that it is not merely a question of what happens in Srinagar. Really speaking, the most important thing was what was happening in the interior, rural areas and in those border areas from which the infiltrators were threatening to come in. From that point of view, the Sadiq Government certainly has taken more important steps and definite progress has been achieved in those areas. I have seen it with my own eyes. It is not merely a question of quoting statistics here and there. He has got that democratic approach.

I entirely agree with Acharya Kripalani that the only solution to solve the Kashmir problem is to go to the people. I have no doubt about it; it is not only through this man or that man that we can solve the problem. Ultimately we have to go to the people and win their hearts. It is the people of Kashmir who are more important, not some small document to which Mr. Madhok referred. He may be believing in that. He has every right to believe in what he thinks to be right.

SHRI BAL RAJ MADHOK : I do not minimise the importance of the people, but the legal position also is there. We cannot ignore that.

SHRI Y. B. CHAVAN : I am glad that you do that. Talking about political and democratic matters how can you forget the people. How can you say, if you do not want you go to Pakistan? No. They will have to remain in India. If they are less patriotic we will have to work with them, create a feeling of friendliness and make them believe in India's future and further participation in the Indian common life. That is, really speaking, what will have to be done. This is the approach we have to pursue in these matters. I am not holding any brief for any particular government,, but my only point is that as far as the national security aspect is concerned we are alive.

I must make a personal explanation because a reference was made to what I said before the infiltrators came in August 1965. I think it was on the 1st or 2nd.

SHRI HEM BARUA : It was on 3rd August.

SHRI Y. B. CHAVAN : You must have read it on the 3rd. I made the speech on the 1st or 2nd. The only question that I answered was, what was the trend of infiltrators in the last two weeks. I had explained that time, in that statement that I made, that in recent weeks there was a reduction in the infiltrators.

SHRI KANWAR LAL GUPTA : Fine clarification.

SHRI Y. B. CHAVAN : It is not a question of fine explanation. I was giving an explanation based on facts. That was a matter of fact. At the same time I had said, it does not mean there is no danger of infiltrators. Somebody cannot just try to take a sentence out of context and throw it at my face just now. But the fact remains.

Sadiq's one contribution we must accept. When there was such a very serious threat to Kashmir in 1965, when such a large number of infiltrators came in, during that time he maintained law and order position in Kashmir in such a way that it is something very creditable. We must give him whatever is due to him.

श्री राम गोपाल शालवाले : उसका श्रेय तो भारतीय सेना को है ।

श्री यशवन्त राव चव्हाण : लेकिन भारतीय सेना के साथ लोगों का जो को-आपरेशन रहा है, वह भी मानना चाहिए।

श्री राम गोपाल शालवाले : आज की स्थिति में सादिक साहब की मौजूदगी में हिन्दुओं पर जो अत्याचार हो रहे हैं, उसके बारे में मंत्री महोदय क्या कहते हैं ?

SHRI Y. B. CHAVAN : I must say that this way of putting problems is creating further problems. It is not a question whether this Government is pro-Muslim or pro-Hindu. That is why I made an assertive statement in the very beginning that one good thing about Sadiq is that he is hundred per cent secular (*Interruption*). I know there are feelings of grievances of pandits. I never say no to it. The question of pandits need to be handled more carefully, more sympathetically. There is that feeling. I understand that that feeling is there. I do not want to say that Sadiq has this feeling and therefore the pandits have got this grievance.

SHRI BAL RAJ MADHOK : The grievance is not against Sadiq as such, it is against Sadiq Government.

SHRI Y. B. CHAVAN : Ultimately the attitude of the leader of the Government is reflected in the Government also.

SHRI KANWAR LAL GUPTA : What about Pakistani slogans raised in Jammu and Kashmir ?

SHRI Y. B. CHAVAN : As I said, I do not say there are no people who certainly would not welcome Ayub's regime in Kashmir. I have not said that. That would be closing eyes to realities in Kashmir. There are some people.

SHRI KANWAR LAL GUPTA : Why don't you deal with them firmly ?

SHRI Y. B. CHAVAN : Certainly they will have to be dealt with firmly. The existence of a few such people need not excite us to feel that everybody thinks the same way. There are some people. I do not take the position that there is nobody in Kashmir who does not want Pakistani infiltration in Jammu and Kashmir. There are some such people. But we must know them, we must shake them, we must persuade them, we must try to convert them, not in the other sense, but converting their point of view. We should know who they are and carefully watch them. That also we are doing. And I would like to tell you that; not that we are unaware of it.

श्री राम गोपाल शालवाले : सादिक के रहते हुए वह विचार-धारा नहीं बदल सकती है ।

SHRI Y. B. CHAVAN : There I disagree with my hon. friend. On whether there should be President's Rule, I was, really speaking, very sad when this suggestion came from the hon. Member, Shri Bakshi.

SHRI GULAM MOHAMMAD BAKSHI : I did not suggest the dismissal of the Sadiq Government because you would not accept it.

मैंने जो तीसरी बात कही है, उसके साथ तो आपको इत्तिफाक होगा ।

SHRI Y. B. CHAVAN : I only wanted to know it. You did not make that suggestion because I would not accept it or because you did not believe in India?

SHRI GULAM MOHAMMAD BAKSHI : That is politics.

SHRI Y. B. CHAVAN : That is my main point. I certainly would not accept such a suggestion. Of course, if there is a constitutional failure, that is a different matter.

श्री गुलाम मुहम्मद बख्शी : क्या वहां भी हम डिफेक्शन शुरू करें ? वहां भी हो सकते हैं ।

SHRI Y. B. CHAVAN : I would never advise anybody to defect or start defections.

SHRI GULAM MOHAMMAD BAKSHI : I do not want to enter into an argument. My submission is that President's Rule will not be acceptable to you and the dismissal of that Government is difficult for you, as you are placed. So, my suggestion is this.

मैं ने यह अर्ज़ किया है कि आप इलैक्शन पैटीशन्ज़ का फ़ैसला मार्च के एंड तक करा दीजिए ।

SHRI Y. B. CHAVAN : I started with that. But he stated that the bye-elections should be held within a certain time, presuming that the election petitions are already disposed of. The election petitions are yet to be heard. Naturally, when they are heard, the provisions of the rules will apply. The Election Commissioner will . . .

SHRI GULAM MOHAMMAD BAKSHI : It has already taken 9 months.

SHRI Y. B. CHAVAN : I gave you the reasons for it. But I do not justify the delay. I said that delay in an election petition is the worst thing that can happen in a democracy. But I gave you the exact reasons. The Act had to be amended. After amending the Act, within two months two judges are appointed, who can look into the election petitions.

SHRI BAL RAJ MADHOK : Would you make a request to the Sadiq Government to expedite it now ?

SHRI Y. B. CHAVAN : Now it is not in the hands of the Sadiq Government; it is now in the hands of the High Court Judges. In this matter the judiciary is completely separate; it is completely independent. Therefore, it is not a question of telling Sadiq about it. Now, it is a question for the High Court Judges to expedite this thing, and I have no doubt that they will certainly do whatever is necessary to expedite these things.

SHRI D. N. PATODIA : How do you explain the widespread emergence of pro-Pakistani elements in Kashmir ?

SHRI Y. B. CHAVAN : There is no widespread emergence of such elements.

SHRI D. N. PATODIA : They are parading in the streets with such slogans.

SHRI KANWAR LAL GUPTA : Pro-Pakistani slogans have been raised in the streets of Srinagar.

SHRI Y. B. CHAVAN : That is not true. And I am sure that even Bakshi cannot claim that during his regime there were no pro-Pakistani slogans raised by anybody. That would be an incorrect statement to make.

SHRI HEM BARUA : It is reported that in Kashmir pro-Pakistani slogans are raised by some people. It is also reported that in Calcutta pro-Mao

slogans are shouted by some people. But suppose a man in the streets of Peking says "Chavan Zindabad" he would be reduced to pulp by the Red Guards. What are you doing in the matter ?

SHRI Y. B. CHAVAN : I share the feelings of my hon. friend. But the only point that I would like to stress is this, that it would be wrong to say that the pro-Pakistani slogans have started only now because, then, it becomes party politics. There is something like Kashmir politics. There is something like Indian politics which is involved in Kashmir, and party politics is something different. Therefore, if you want to criticise the Kashmir Government today, I can understand a criticism based on national issues. That certainly one can do. But when there is this partisan attitude, as far as politics is concerned, I would like to say that the criticism was very unfair.

19 hrs.

SHRI J. B. KRIPALANI : Will you take into consideration my last suggestion ?

SHRI Y. B. CHAVAN : I am glad, he has reminded me of it. I forgot that point about sending the best administrators to Kashmir. This has been continuously done in the last two years. The best officers have been selected by the Sadiq Government. It is not that we send them there but the Sadiq Government themselves have asked for the best officers and they have always welcomed the good officers.

SHRI D. N. PATODIA : I would not like to name the persons but I have been told by authoritative sources . . .

MR. DEPUTY-SPEAKER : No, please. Shri Shastri.

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : उपाध्यक्ष जी, पंचतंत्र में पंडित विष्णु शर्मा ने लिखा है कि बिल्ली को आते हुए देख कर कबूतर आंखें मींच कर बैठ गया और सोचने लगा कि उसका खतरा टल गया . . (**व्यवधान**) . . . ठीक यही स्थिति इस सरकार की है।

भारत सरकार जानबूझ कर अगर खतरे की ओर से अपनी आंखें बन्द कर ले और यह समझे कि कोई संकट नहीं है तब तो कोई भी युक्ति देने की आवश्यकता ही नहीं है और इतना लम्बा चौड़ा वाद-विवाद करने की भी यहां आवश्यकता नहीं थी। लेकिन यदि भारत सरकार संकट को संकट समझती है और संकट का उपाय ढूंढने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर प्रयास किया जाता है दलीय स्तर पर प्रयास नहीं किया जाता तो मैं समझता हूं कि गंभीरता से सोचना देश के हित में भी होगा और आने वाले भविष्य के हित में भी होगा।

इस वाद-विवाद में और सदस्यों की चर्चा छोड़ते हुए जो सरकारी कुर्सियों से दो मिनिस्टर बोले हैं मैं केवल उन्हीं की चर्चा करना चाहता हूं। कांग्रेसी सदस्यों की बात को मैं छोड़ता हूं। इस में जो वाणिज्य मंत्रालय में मंत्री हैं श्री कुरेशी साहब उन का जो भाषण था वह मैंने बड़े ध्यानपूर्वक सुना क्योंकि वह काश्मीर के निवासी थे। मुझे इस बात को कहने की कोई आवश्यकता नहीं कि उनका निर्विरोध वहां पर निर्वाचन हुआ है। जिन लोगों के नामिनेशन पेपर रिजेक्ट किए गए हैं उन में उपाध्यक्ष जी, आप को याद होगा इसी सदन के एक माननीय सदस्य थे जिन का नाम था पंडित श्याम लाल सर्राफ उन का नामजदगी पत्र केवल इस आधार पर रद्द किया गया कि उन्होंने इलेक्शन आफिसर के सामने खड़े हो कर शपथ नहीं ली जब कि उनका वह शपथ पत्र पहले वहां था। उस को किस ढंग से हटाया गया, यह सब बातें कहने की कोई आवश्यकता नहीं। उन के स्थान पर यह साहब चुन कर आये हुए हैं जो काश्मीर की ओर से खड़े हो कर और यहां वकालत कर रहे थे। मैं उन के पुराने इतिहास में भी नहीं जाना चाहता कि पीछे जो चार पांच साल तक जेल के अन्दर वह रहे किस आधार पर रहे ? वह बात तो छोड़ता हूं। लेकिन आज मैं दो तीन बातें बहुत स्पष्ट पूछना चाहता हूं खास तौर से गृह मंत्री श्री चह्वाण से कि इधर से अगर किसी सदस्य की ओर से भूल से भी कुछ

[श्री प्रकाश वीर शास्त्री]

ऐसा कह दिया जाता—जिसका पाकिस्तान उलटा अर्थ करता तो आपको कष्ट होता । जहां तक मेरा संबंध है मैं अपने एक एक शब्द की जिम्मेदारी लेता हूं । क्योंकि मैं यह जानता हूं कि यहां जो कुछ आज कहा जा रहा है वह भारत के समाचारपत्रों और जनता के लिये ही नहीं है । इस के एक-एक शब्द को पाकिस्तान देखेगा कि हमारे हित में कौन से शब्द का प्रयोग हो सकता है ? इसी आधार पर मैंने इस चर्चा में एक-एक शब्द को बड़ा नाप और तोल कर प्रयोग किया । अगर मेरे किसी शब्द से या मेरे पूरे भाषण में यह झलक आई हो कि काश्मीर के अन्दर मुसलमानों में इस प्रकार की भावना आ गई है कि काश्मीर के पूरे मुसलमान प्रो-पाकिस्तानी हो गए हैं या काश्मीर के हिन्दुओं में इस प्रकार की भावना हो गई है तो मैं भरी सभा में, भूल से भी कोई ऐसी बात अगर आ गई हो, तो उसे वापस लेने के लिये तैयार हूं । मैंने इन शब्दों का जान-बूझकर प्रयोग किया था कि पिछले 20 वर्षों में काश्मीर में कोई साम्प्रदायिक उपद्रव नहीं हुआ । काश्मीर के अन्दर हिन्दू-मुसलमान भाई-भाई की तरह मिल कर रहते रहे इस अगस्त 1967 के कांड के पहले मेरे इन सारी बातों को कहने के बावजूद आप के पीछे बैठे हुए मिनिस्टर कहलाने वाले व्यक्ति कुरेशी ने इस सारी चर्चा को इस रंग में रंगने की कोशिश की कि काश्मीर के मुसलमानों को बदनाम किया जा रहा है, उन की नीयत पर शक किया जा रहा है । क्या इसी प्रकार के वकील आप तैयार करके लाते हैं अपने पक्ष को बचाने के लिए ? यहां तक भी वह वकील साहब कह गए यहां पर खड़े हो कर जिन्हें बहुत जिम्मेदारी का ओहदा आप ने सौंप रखा है, कि अगर काश्मीर के लोगों का दिल आप को जीतना है तो उन को आने-जाने की सुविधा दीजिए, उन को नौकरी की सुविधा दीजिये । क्या कहलवाना चाहते हैं आप उन के मुंह से कि काश्मीर के लोगों को नौकरी की सुविधा भारत में नहीं है ? यह आप के पीछे बैठा एक मिनिस्टर यह कह रहा है और उस को आप अपना पक्ष लेने के लिये यहां पर खड़ा कर रहे हैं ? मैं फिर आप को कहता हूं कि मित्र की पहचान करना सीखिये । हृदय से मित्र कौन है ? इस तरह के मित्रों की पहचान से आप को भी लाभ होगा, देश को भी लाभ होगा । मैं इस बात को और इस से अधिक विस्तार में नहीं कहना चाहता ।

जहां तक श्री यशवंत राव चह्वाण का संबंध है उन्होंने जितने भी प्वाइंट्स मैं ने या दूसरे सदस्यों ने मुख्य रूप से रखे, मैं नहीं कह सकता कि विस्तार-भय से उन्होंने उन को नहीं छेड़ा या क्या वजह थी ? लेकिन मैं तो उस को यों मानता हूं कि उस के अन्दर बहुत कुछ सच्चाई है और इसीलिये उन बातों को खोलना उन्होंने उचित नहीं समझा प्याज के छिल्के को हटाने से बदबू ही आयेगी उस के अन्दर सुगन्ध नहीं आ सकती । वह इन तमाम बातों को जानते हैं । लेकिन इन सारी बातों के जानने के बावजूद भी गृह मंत्री श्री यशवंत राव चह्वाण ने अपने तीन आश्वासनों की ओर इस सदन का ध्यान दिलाते हुए उसे अपने विश्वास में लेने की कोशिश की यदि वह 2 सितम्बर को और 3 सितम्बर को श्रीनगर के अन्दर उन लोगों को जो कह कर आये थे, आज कम से कम इतने दिन बाद यह भी कह देते कि अभी तक अगर उस लड़की का न्यायालय से कोई निर्णय नहीं हो पाया है तो क्योंकि काश्मीर एक भारत का अंग ही नहीं है बल्कि अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति का केन्द्र है और वहां की इस प्रकार की घटना का भारत पर ही नहीं पूरे विश्व पर प्रभाव पड़ सकता है । हम प्रयत्न करेंगे कि जल्दी से जल्दी उस का समाधान हो और जब तक न्यायालय उस का निर्णय नहीं देता तब तक उस लड़की को किसी निष्पक्ष व्यक्ति या निष्पक्ष आश्रम के अन्दर रखा जायगा । अगर यह बात कह देते तो मालूम पड़ता कि गृह-मंत्री को उस का ध्यान है । सादिक साहब की प्रशंसा के शब्द कहते जाना, सादिक साहब को प्रमाण-पत्र देने जाना यह क्या है ? जब आप ने उन को बैठाया है तो आज आप उन को प्रमाण-पत्र नहीं देंगे तो क्या मैं उन को प्रमाण-पत्र दूंगा ।

जब आप ने उन को बैठाया है तो आप तो उन को प्रमाण पत्र देंगे ही।

परस्पर प्रशंसन्ति अहो रूपं अहो ध्वनि : आपने उन को बैठाया और आप ही आज बैठा करके उनकी प्रशंसा करें इस का क्या अर्थ होता है? हमें भी इस बात से प्रसन्नता नहीं होती कि देश में किसी हिस्से पर राष्ट्रपति शासन लादा जाय। लेकिन जब जनता की भावनाओं का प्रतिनिधित्व करने वाली सरकार वहां पर विधिवत गठित न हुई हो और जनतंत्र वहां पर कलंकित हो रहा हो, लोगों के हितों की सुरक्षा वहां पर न हो और इस प्रकार का वातावरण बनता चला जाय जो आज नहीं कल, कल नहीं परसों विस्फोटक स्थिति पैदा कर दें या पाकिस्तान के हाथ मजबूत करे, तो क्यों आप ने अपने विधान में यह धारा लगायी थी कि जम्मू काश्मीर में आवश्यकता पड़ने पर राष्ट्रपति को भी हस्तक्षेप करने का अधिकार होगा, या राष्ट्रपति अपने अधिकारों का प्रयोग कर सकता है? क्या इस से बढ़ कर भी भयंकर स्थिति वहां पर हो सकती है? मैं अंत में केवल एक ही लाइन कह कर बैठ जाता हूं कि गृह-मंत्री श्री यशवंत राव चह्वाण इस बात का विचार करें कि वह यह वक्तव्य दे कर सदन को सन्तुष्ट नहीं कर रहे हैं, बल्कि आने वाले इतिहास में अपनी बुद्धिमत्ता की कुछ पंक्तियां वह जोड़ रहे हैं। भारत सरकार की इस उपेक्षा भरी नीति को आज नहीं तो कल आने वाली हमारी संतति कभी क्षमा नहीं कर सकती।

19.10 Hrs.

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Friday, December 1, 1967/Agrahayana 10, 1889 (Saka).

L83LSS/67 –1011 –5-3-68 –Sec. II (D)—G PF.